राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 01] सोलहवीं विधान सभा के पहले सत्र का इकतालीसवां दिवस [संख्या: 06

सोमवार,

29 जनवरी 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : विराजिए। प्रश्न काल। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की कार्ययोजना

38. श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार खाद्य सुरक्षा के तहत हटाये गये नामों को पुन: जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): जी नहीं। खाद्य सुरक्षा योजना से किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं हटाया गया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही नहीं पुकारा गया है।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): बोल दिया है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। प्रश्न संख्या बोल दी है। श्री छगनसिंह राजपुरोहित ने बोल दिया।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): बोल दिया।

श्री अध्यक्ष: बोल दिया। थोड़ा आपको वह भेज देता हूं लगाने के लिए सुनाई नहीं दे रहा हो तो हैडफोन भेज देता हूं। मंत्रीजी आप बोलिए।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): जी नहीं। खाद्य सुरक्षा योजना से किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं हटाया गया है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नये पात्र व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में समावेशन करने के लिए अपीलीय प्रक्रिया लागू है, जिसके तहत पात्र व्यक्ति निर्धारित आवेदन पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर सम्बन्धित क्षेत्र के उप खण्ड अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन अपील प्रस्तुत कर सकता है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा योजना में राज्य में वर्तमान जनसंख्या के अनुसार चयन किये जाने एवं सीलिंग सीमा तक क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या खाद्य सुरक्षा योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा में सीलिंग वृद्धि किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्य किया गया या क्या कुछ लिखा गया है या नहीं?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आहोर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की ओर से अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-9 के प्रावधान के अनुसार किसी भी राज्य की जनसंख्या, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, उसी को आंकड़ा मानते हुए कवरेज क्षेत्र में तब ही संशोधन किया जा सकता है जब आंकड़े नई जनसंख्या के अनुसार प्रकाशित होंगे।

दूसरा प्रश्न इन्होंने यह पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा इसमें क्या कार्यवाही की गयी है? मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा 29 दिसम्बर, 2023 को केन्द्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर इसमें जो जनसंख्या बढ़ी है, उसमें 15 प्रतिशत इसकी वृद्धि करने का निवेदन माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा किया गया है।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह

(श्री टीकाराम जूली)

जानना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों से केन्द्र सरकार ने इसमें जो गेहूं आबंटन है, वह एक परसेंट भी नहीं बढ़ाया है, लगातार वह ही चलता आ रहा है।

आप बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना की और अब आ गया है 2024, तो क्या वर्ष 2011 से आज तक जनसंख्या नहीं बढ़ी? इस रेश्यो के अन्दर जब हमारी पिछली सरकार थी उसने मुख्य मंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, राज्य सरकार के कोटे के तहत इसके अन्दर नई एप्लीकेशन मांगी थी तो कितने लोगों को वह गेहूं दिया गया और आने वाली सरकार, क्या भारत सरकार इसके अन्दर सीमा नहीं बढ़ाती है तो क्या राजस्थान सरकार अपनी तरफ से लोगों को गेहूं देना चाहेगी?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष को यह बताना चाहूंगा कि इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 9 के अनुसार एक सीलिंग दी गयी है जनसंख्या के हिसाब से, राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख की सीमा है, उसके अनुसार 2 करोड़ 30 लाख मैट्रिक टन गेहूं होते हैं, उससे ऊपर सीलिंग सीमा को जब तक नई जनसंख्या के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं होते, तब तक इसमें कोई भी संशोधन खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रोत।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब तो उनके क्वेश्चन में ही दे दिया। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब नहीं दिया। क्या राज्य सरकार अपनी तरफ से इसमें बढ़ाना चाहेगी? दूसरा, भारत सरकार से आप बात कीजिए। अब तो डबल इंजन सरकार है न। 2011 के आंकड़े आप कब तक चलाएंगे? अब तो 2024 आ गया है।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 29 दिसम्बर, 2023 को ही पत्र लिखा है, वह मैंने आपको बताया कि 29 दिसम्बर, 2023 को ही पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने जनसंख्या की बढ़ोतरी को देखते हुए 15 प्रतिशत वृद्धि करने का निवेदन केन्द्र सरकार के माननीय खाद्य मंत्रीजी से किया है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। दो प्रश्न हो गये आपके।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह

(श्री टीकाराम जूली)

मामला कोई राजनीतिक मामला नहीं है। यह प्रदेश की आठ करोड़ जनता, जो गरीब लोग हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। इस चीज का जवाब नहीं आया कि भारत सरकार तो मान लीजिए आंकड़े नहीं बढ़ा रही है, अब तो डबल इंजन सरकार है, पहली बात तो क्यों नहीं बढ़ा रही? आंकड़े जारी करे जनसंख्या के, पहले नम्बर की बात।

दूसरे नम्बर की बात यह है कि वहां से नहीं बढ़ता है तो जैसे पहले हमारी सरकार ने अपनी तरफ से नाम जोड़े थे तो क्या आपकी सरकार भी नाम जोड़ना चाहती है या नहीं चाहती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय, बैठिए। चाहती है या नहीं चाहती, हां या ना में उत्तर दे दीजिए।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसका बिलकुल आगे हम प्रयास करेंगे जो आपने बात कही और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करके इसमें जरूर किया जायेगा। जनता के लिए डबल इंजन की सरकार बनी है तो काम भी डबल इंजन की तरह होगा और आपको अहसास भी होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है। आप बैठिए।

श्री राजकुमार रोत। अब दूसरा किसी का नहीं है।

अनुसूचित क्षेत्र में संचालित छात्रावासों में वार्डनों के स्वीकृत पद

39. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में कुल कितने बालक, बालिका छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय संचालित हैं? उक्त में कुल कितने वार्डनों के पद स्वीकृत हैं तथा उक्त पदों को कितने समय के लिए किस प्रक्रिया से भरने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संचालित सभी छात्रावासों में वार्डन को पांच वर्ष से अधिक प्रतिनियुक्ति पर नहीं रखने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त छात्रावासों में ऐसे कितने वार्डन हैं जिनको पांच वर्ष से अधिक समय हो गया है? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजकुमार रोत)

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय से विभाग के कार्मिकों के लिए एक अलग कैडर बनाने की प्रक्रिया विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त कैडर कब तक बना दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में 304 आश्रम छात्रावास (152 बालक व 152 बालिका), 9 कालेज छात्रावास (2 बालक व 7 बालिका), 4 बहूद्देशीय छात्रावास (4 बालिका) 13 खेल अकादमी (7 बालक व 6 बालिका) एवं 5 आवासीय विद्यालय (2 बालक व 3 बालिका), 2 मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूल (1 बालक व 1 बालिका) तथा 23 एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (17 बालक, 3 बालिका एवं 3 सह शिक्षा) संचालित हैं।

उक्त छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में कुल 379 वार्डन के पद स्वीकृत हैं। विभाग द्वारा जनजाति छात्रावासों में रिक्त पदों को भरने हेतु समय-समय पर वाक-इन-इन्टरव्यू आयोजित कर शिक्षा विभाग के कार्मिकों को छात्रावासों में रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की कार्यवाही की जाती है।

(2) विभागीय छात्रावासों में नियमानुसार 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर साक्षात्कार के द्वारा नये अधीक्षक लगाये जाते हैं, लेकिन नवीन चयनित कार्मिकों के लिए मूल विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त नहीं होने से 5 वर्ष से अधिक समय हेतु पूर्व पदस्थापित वार्डन कार्य करते हैं। वर्तमान में 5 वर्ष से अधिक कार्यरत वार्डनों की जिलेवार संख्यात्मक सूचना निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**जिला**	**5 वर्ष से अधिक कार्यरत वार्डनों की संख्या**
1.	उदयपुर	38
2.	बांसवाड़ा	21
3.	डूंगरपुर	31
4.	प्रतापगढ़	24
5.	आबूरोड	07
6.	पाली	0
7.	चित्तौड़गढ़	0
योग		**121**

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(3) गत सरकार की वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के क्रम में कार्मिक (क-ग्रुप2) विभाग द्वारा दिनांक 31.01.2022 को विभागीय छात्रावासों के वार्डन के विभागीय कैडर बनाये जाने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में 2400 पे-ग्रेड (एल-5) में स्वीकृत अधीक्षक ग्रेड-II के 470 पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती हेतु प्रस्ताव दिनांक 08.09.2023 को सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को भिजवाये गये हैं।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया है, आपकी अनुमति हो तो सवाल कर लूं।

श्री अध्यक्ष: पूछिए। माननीय मंत्रीजी, उन्होंने कहा है कि प्रश्न का उत्तर मेरे पास आ गया है। आप पूछिए। अब आप पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आदिवासियों के कल्याण के लिए टी.ए.डी. विभाग बना हुआ है, लेकिन आज तक इस विभाग का ही कल्याण नहीं हो पाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन लगाने का उद्देश्य ही यही था कि इस विभाग में जितने कार्मिक हैं, वे सारे कार्मिक विशेषकर वार्डन हैं, टीचर हैं, वे एजुकेशन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाते हैं। उनका जो भुगतान है वह टी.ए.डी. फंड से होता है और हम कैडर बनाने के लिए लम्बे समय से डिमांड कर रहे हैं। कैडर नहीं बनने की वजह से टी.ए.डी. विभाग को प्रत्येक साल लगभग छह से सात करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

मेरा फर्स्ट सवाल यह है कि पांच साल तक प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रावधान है और जवाब में यह आया है कि 121 वार्डन ऐसे हैं जिनको पांच साल से अधिक यहां पर हो गये। विभाग का यह नियम है कि पांच साल तक ही रखना है और उसके बाद उनको हटाना है और नये सिरे से लेना है तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या तत्काल इन 121 वार्डन, जिनके पांच साल से ऊपर हो गये हैं, उनको हटाने का विचार रखते हैं?

दूसरा सवाल मेरा यह है कि 31.01.2022 को विभागीय छात्रावासों के वार्डन के विभागीय कैडर बनाने की अधिसूचना जारी कर दी, 31.01.2022 को जारी कर दी तो अभी तक इसमें क्या प्रगति हुई है? 08.09.2023 को वार्डनों के 470 पदों पर कैडर बनाकर नई भर्ती करने का प्रावधान किया गया और

(श्री राजकुमार रोत)

इसका प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा गया तो यह भर्ती कब तक की जायेगी? ये दो मेरे सवाल हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा कि ये जो वार्डन हैं जो कि आप शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेते हैं, पांच वर्ष का अनुबंध होता है और पांच वर्ष से अधिक समय हो गया तो उनको क्यों रखा गया है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको हमने इसलिए रखा है कि हमने विभाग से अनापत्ति पत्र मांगा है तो उन्होंने समय पर वह दिया नहीं है, जिसके कारण से वे अभी भी चल रहे हैं। अब आपने कहा कि उनको हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? अब निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि ये अध्यापक वापस अपने मूल विभाग में जायें। एक इनका यह कहना है कि ये लोग वापस छह महीने में आ जाते हैं तो वह तो उनका अधिकार है, एक बार वे जाते हैं और वापस आ जाते हैं तो नियमानुसार वापस आ सकते हैं।

दूसरा, इन्होंने यह पूछा कि वार्डन का जो कैडर बनाने का विषय था, यह आपकी जानकारी में भी होगा कि पिछली बार मैंने ही यह सवाल उठाया था और मंत्रीजी ने यह जवाब भी दिया था कि हम कैडर बना रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी की जो बजट घोषणा थी उसके अनुसार आपने कार्यवाही करके, कैडर बनाने की जो भी प्रक्रिया थी, वह सारी मैंने इसमें लिखी है, वह आपने पढ़ी होगी। अब उस कार्यवाही को हमने करके कैडर के लिए, विभागीय कार्यवाही के लिए हमने भेज दिया। अब वहां से उनको यह भर्ती करनी है, उनको विज्ञप्ति जारी करनी है और विज्ञप्ति जारी करने के बाद में फिर उनकी परीक्षा करवानी है, परीक्षा के बाद में परिणाम आयेगा और परिणाम आने के बाद में उनको लेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा वह ही सवाल करूंगा कि जो 121 अतिरिक्त रूप से लगे हुए हैं, जिनके पांच साल पूरे हो गये हैं, विभाग का यह नियम है कि पांच साल तक ही रखना है तो क्या मंत्री महोदय, उनको हटा कर नये सिरे से प्रतिनियुक्ति पर लेने का विचार रखते हैं या नहीं? विचार रखते हैं तो कब तक?

सैकण्ड चीज, यह कैडर कब तक कम्प्लीट बन जायेगा और कैडर के तहत भर्ती कब तक की जायेगी? ये दो चीजें मैं जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, एक सैकण्ड।

मेरा भी यह अनुभव है कि जिनको पांच साल हो गये, नियम सरकार का यह है तो पांच साल के बाद वे लोग नहीं रहें और दूसरा टाइम पर यह हो जाये। आप अभी आये हैं, लेकिन इसको गति देनी चाहिए कि पांच साल बाद भी कुछ लोग जान बूझकर टिके हुए रहते हैं तो विभाग/सरकार इस पर तुरंत कार्यवाही करे।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आपका निर्देश है तो निश्चित रूप से, पांच साल से जो ज्यादा हैं उनको हटाकर नये लोगों को हम ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष: चलिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कैडर बना रहे हैं इसमें स्वच्छ परियोजना के जो कार्मिक हैं, उनको भी सम्मिलित किया जायेगा या नहीं किया जायेगा?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): कैडर का मतलब ही यह है कि वह तो खुली भर्ती है। उसमें जो व्यक्ति आयेगा और परीक्षा में पास होगा। कैडर बना रहे हैं, उसमें भर्ती तो होगी।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, टी.ए.डी. के तहत ही वह कार्मिक लगे हुए हैं। स्वच्छ परियोजना एक विंग बनी हुई है। स्वच्छ परियोजना जो विंग है, उनको भी कैडर में शामिल किया जाए।

श्री अध्यक्ष: जो नियम बनेंगे, इसको भी देख लेना।

श्री डूंगरराम।

सूरतगढ़ में भूमि की खातेदारी के लम्बित प्रकरण

40. श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में टी.सी. भूमि व पुख्ता आबंटन भूमि के खातेदारी के प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पंचायतवार विशेष राजस्व अभियान चलाकर उक्त को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के पीपासर, हिन्दौर, मालर, रंगमहल, किशनपुरा, राजपुरा, पिपेरन, ठुकराना, पदमपुरा आदि गांवों के नक्शों

(श्री डूंगरराम गेदर)

में काश्तकारों की भूमि खसरा व मौके काश्त अनुसार फिटिंग कर चकबंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ में परियोजना क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र में टी.सी. भूमि व पुख्ता आबंटित भूमि के सम्बन्ध में गैर खातेदारी के कुल 5,208 प्रकरणों में से 4,151 प्रकरणों में खातेदारी दी जा चुकी है। शेष 1,057 प्रकरण विभिन्न कारणों से लम्बित हैं। (विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है) गैर खातेदारी से खातेदारी देने के सम्बन्ध में पेरिफेरी क्षेत्र, उपनिवेशन क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र सम्बन्धी कतिपय जटिलताओं के कारण विभाग स्तर पर समीक्षा की जाकर गाइडलाइन जारी किया जाना प्रस्तावित है, ताकि लम्बित प्रकरणों का भी नियमानुसार निस्तारण किया जा सके।

(2) तहसील सूरतगढ़ क्षेत्र के गांव पीपासर, हिन्दौर, राजपुरा, पिपेरन में जारी सर्वे-रिसर्वे का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही चकबंद का कार्य किया जाना सम्भव है। ग्राम रंगमहल, किशनपुरा व पदमपुरा में परियोजना क्षेत्र नहीं होने से चकबंद प्रस्तावित नहीं है। ग्राम ठुकराना से नवसृजित चक 191.500 आरडीएल-ए व 191.500 आरडीएल-बी तैयार हो गये हैं। ग्राम मालेर में 02 नवसृजित चक 11 पीएचएम व 01 एमआरएम तैयार हो गये हैं और 07 चकों का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जिनको खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं, पैंडिंग प्रकरण जो आपने बताये हैं, वे लगभग 20 परसेंट हैं। उनको अभी खातेदारी अधिकार क्यों नहीं दिये गये? ये लोग 30-40 साल से वंचित क्यों हैं? जब ये जमीन जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, सारी किश्तें भर दीं, फिर क्या कारण हैं? क्या सरकार इनको खातेदारी अधिकार देने के लिए राजस्व अभियान चलाकर खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है?

दूसरा, आपने पीपासर, हिन्दौर, राजपुरा और पिपेरन के बारे में बताया है, यह चकबन्दी का कार्य, सर्वे-रिसर्वे का कार्य कब तक पूरा होगा? किस कम्पनी को यह कार्य दिया गया है? यह बताने का कष्ट करें।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ क्षेत्र के

(श्री हेमन्त मीणा)
गांव पीपासर, हिन्दौर, राजपुरा, पिपेरन में सर्वे-रिसर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है। यह कार्य पूर्ण होने के उपरान्त चकबन्दी का कार्य किया जाना सम्भव है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): मैं यह पूछ रहा हूं कि कौनसी कम्पनी इस काम को कर रही है?

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): ग्राम रंगमहल, किशनपुरा व पदमपुरा में परियोजना क्षेत्र नहीं होने से चकबन्दी प्रस्तावित नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले इनका उत्तर सुन लीजिए। आप विराजें।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): ग्राम ठुकराना से नवसृजित चक 191.500 आरडीएल-ए व 191.500 आरडीएल-बी तैयार हो गये हैं। ग्राम मालेर में 02 नवसृजित चक 11 पीएचएम व 01 एमआरएम तैयार हो गये हैं और 07 चकों का कार्य प्रक्रियाधीन है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो उत्तर पहले दिया था, उसी को दुबारा पढ़ रहे हैं ये। वही की वही लाइनें आपने दुबारा पढ़ दीं।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): कारण यही है न।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): मैं यह पूछ रहा हूं कि कौनसी कम्पनी सर्वे-रिसर्वे का काम कर रही है? यह काम कब तक पूरा होगा?

श्री अध्यक्ष: ये कम्पनी का नाम और समय सीमा पूछ रहे हैं।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): वेपकोस कम्पनी द्वारा इसका काम किया जा रहा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, यह बड़ी विडम्बना है कि संसदीय कार्य मंत्री खुद जा रहे हैं और वहां से पर्ची लाकर मंत्रीजी को दे रहे हैं। जवाब देने के लिए मंत्रीजी सक्षम नहीं हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बोल रहे हैं, आप विराजें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): संसदीय कार्य मंत्रीजी जाकर पर्ची लाकर दे रहे हैं अधिकारियों से। हद हो गयी। कुछ तो कहिए इनको।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। माननीय मंत्रीजी, कम्पनी का नाम और समय सीमा बता दीजिए।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): कम्पनी का नाम है वेपकोस।

(श्री हेमन्त मीणा)

वेपकोस कम्पनी इसका सर्वे कर रही है और साल भर के अन्दर इसका सर्वे करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

कृषि कनेक्शन हेतु उपलब्ध सामग्री

41. श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा कृषि कनेक्शन के कार्य संवेदकों के माध्यम से करवाये जाते हैं? यदि हां, तो उक्त हेतु सामग्री (तार, ट्रांसफार्मर इत्यादि) किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): कृषि कनेक्शन नीति-2017 (संशोधित दिनांक 31.01.2022 तक) में वर्णित प्रावधानानुसार मांगपत्र जमा कराते समय कृषि कनेक्शन आवेदक के पास यह विकल्प होता है कि उसके कनेक्शन के लिए स्थापित होने वाले विद्युत तंत्र की स्थापना अनुमोदित संविदाकार से वह स्वयं के स्तर पर करवाना चाहता है अथवा विद्युत निगम द्वारा करवाना चाहता है।

विद्युत वितरण निगमों द्वारा कृषि कनेक्शन जारी किये जाने हेतु करवाये जाने वाले कार्य टर्नकी माध्यम से तथा लेबर रेट हेतु पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से निर्धारित ए.आर.सी. दरों पर करवाये जाते हैं।

टर्नकी माध्यम से जारी किये जाने वाले कृषि विद्युत कनेक्शनों हेतु आवश्यक सामान जैसे तार, ट्रांसफार्मर, केबल इत्यादि अधिकृत ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं तथा ए.आर.सी. के तहत लैबर रेट पर पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा किये जाने वाले कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक सामान विद्युत वितरण निगमों द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। विद्युत वितरण निगमों की मैटेरियल मैनेजमेन्ट शाखा द्वारा केन्द्रीयकृत क्रय प्रक्रिया के माध्यम से सामान का प्रबन्ध किया जाता है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि कृषि कनेक्शन नीति, 2017 (संशोधित दिनांक 31.01.2022 तक) के प्रावधानानुसार मांग पत्र जमा कराते समय कृषि कनेक्शन आवेदक के पास यह विकल्प होता है कि उसके कनेक्शन के लिए स्थापित होने वाले विद्युत तंत्र की स्थापना अनुमोदित ठेकेदार से वह स्वयं अपने स्तर पर करवायेगा।

(श्री जुबेर खान)
मंत्रीजी, हमें समझा दीजिए कि इसके मायने क्या हैं? स्वयं कहां से करायेगा? सामान कहां से आयेगा? आप बता दीजिए कि इसका अर्थ क्या है, जो आपने जवाब दिया है?

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मांग पत्र जिस किसान को जारी किया गया है, उसके अनुसार उसको विकल्प पत्र भर कर देना होगा। अगर वह स्वयं के स्तर पर, तार, खम्भे और अन्य सामग्री उसको निगम से इश्यु होगी, लेबर का काम वह खुद अपने स्तर पर करा सकता है जो सरकारी लेबर कान्ट्रेक्ट के आधार पर सरकार का काम करता है। उसी तरह से किसान को यह ऑप्शन होगा कि वह लेबर कांट्रेक्टर को भुगतान नहीं होकर सात सौ पचास रुपये पर-पोल का भुगतान किसान को निगम द्वारा कराया जायेगा, ताकि वह अपने स्तर पर इस काम को करवा सके।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जो कथन कह रहे हैं यह सत्यता नहीं है आजकल। यह पुराना सर्कुलर है। आजकल पूरा सामान ठेकेदार अपने आप खरीदता है। विभाग से भी नहीं लेता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब ठेकेदार, अलवर में ऐसे केसेज हैं, जिन्होंने डिमाण्ड नोट जमा कराये हुए 6-6 महीने हो गये, लाइन खिंच गयी, लेकिन उनको ट्रांसफार्मर नहीं दिये जा रहे हैं। ठेकेदार यह कहता है कि मेरे पास सामान उपलब्ध नहीं है। इसमें कृषक आवेदकों का क्या कसूर है? या तो विभाग करे या वह करे। कहीं न कहीं आपको निर्णय करना पड़ेगा। जिस आदमी का डिमाण्ड नोटिस जमा है, उसको सामान नहीं मिल रहा है। एस.ई. से बात करते हैं तो वह कहते हैं पहले सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग होती थी, हम ठेकेदार को इश्यु करते थे। अब नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसके बारे में आप स्पष्ट करें कि क्या आज की तारीख में यह ऑप्शन अवेलेबल है?

श्री अध्यक्ष: हां, यह स्पष्ट करें।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): देखिए, तीनों ऑप्शन हैं। आप समझिए। पहला ऑप्शन है, किसान निगम से सामान लेकर अपने स्तर पर उनको लगा सकता है। (व्यवधान) आप सुनिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ऑप्शन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सदस्य, यह प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बोल रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना है।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): दूसरा प्रावधान है निगम ...(व्यवधान) डिस्कॉम अपने स्तर पर सेंट्रल पर्चेजिंग करता है और वह अपने लेबर कांट्रेक्टर को ए.आर.सी. कांट्रेक्टर को सामान इश्यू करता है। लेबर कांट्रेक्टर को केवल लेबर का ही भुगतान होता है, बाकी सामान अपने स्टोर से दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन, आपकी सरकार ने किया, वह टर्नकी पर किया है और टर्नकी के आधार पर सामान खुद ही ठेकेदार खरीदेगा, लेबर भी उसी की रहेगी। वही लगायेगा और वही सब काम करेगा, जिसमें कम से कम 30 से 40 प्रतिशत रेटें ज्यादा आयी हैं आपकी सरकार में। यह भ्रष्टाचार हुआ है आपका। निगम पहले करता था, उसमें रेट कम है और आपने जो प्रावधान किये हैं, जो ठेकेदार आपने नियुक्त किये हैं, उनकी रेटें ज्यादा आ रही हैं, इसकी हम जांच करायेंगे और अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और अधिकारियों को भी कार्रवाई को भुगतना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम सवाल।

श्री अध्यक्ष: आपके दो प्रश्न हो गये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अंतिम सवाल। (व्यवधान) नहीं-नहीं, मैं रिपीट नहीं कर रहा।

श्री अध्यक्ष: आपके दो प्रश्न हो गये। अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रिपीट नहीं कर रहा।

श्री अध्यक्ष: आपका हो गया। (व्यवधान) आपने दो बार रिपीट कर दिया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय, आप मध्य प्रदेश बोर्डर के पास से आते हैं। जो मध्य प्रदेश में व्यवस्था है कि बिजली फ्री देंगे, सामान किसान अपना लगायेगा। आज स्थिति यह है कि आज अकेले अलवर में 32 करोड़ के ट्रांसफार्मर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भाषण नहीं, प्रश्न का उत्तर आ गया। श्री गोविन्द प्रसाद। (व्यवधान) गोविन्द प्रसाद कहां है? (व्यवधान) यह प्रश्न काल है, बहस नहीं है। आप बैठिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिए। सब बैठिए। (व्यवधान) मुझे नाम पुकारना पड़ेगा। बोहरा जी, हर समय आप खड़े हो जाते हैं बिना पूछे। (व्यवधान) यह बकवास नहीं सुनूंगा। (व्यवधान) आप बैठिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिए। आसन पांवों पर है। बैठिए। (व्यवधान) आप एक बार बैठिए। श्री गोविन्द प्रसाद। श्री गोविन्द प्रसाद नहीं है तो अगला प्रश्न पुकार रहा हूं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो यह पूछना चाहते हैं, यह कृषि नीति 2017 की जो प्राइवेट ठेकेदारों को दे रखी है, जांच कराकर क्या इसको निरस्त करेंगे? क्योंकि आज भी 36 और 40 प्रतिशत अबॉव प्रीमियम पर काम हो रहा है। (व्यवधान) 40 प्रतिशत अबॉव प्रीमियम पर काम हो रहा है। अगर सरकार चाहती तो 2012 से 2015, 2018 और 2021 तक, तीन-तीन साल के काम निकालकर सी.आर.सी. में करा सकती थी। क्या उस नीति को खतम करके सरकार वापस सी.आर.सी. पर देना चाहेगी? आज उपभोक्ता को 36 से 40 प्रतिशत अबॉव देना पड़ रहा है।

प्रश्न संख्या 42

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री ललित मीना। बैठे-बैठे न बोलें। माननीय सदस्य, बैठे -बैठे न बोलें। (व्यवधान) बैठे-बैठे कोई भी सदस्य न बोलें। (व्यवधान) श्री ललित मीना।

किशनगंज को टी.एस.पी. का दर्जा

43. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगंज को सहरिया आदिवासी बहुल होने के कारण टी.एस.पी. क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है?

(2) टी.एस.पी. क्षेत्र घोषित करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? क्या सरकार पूर्व में निर्धारित मानदण्डों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के निवासियों द्वारा

(श्री ललित मीना)
टी.एस.पी. क्षेत्र की मांग किये जाने के उपरान्त भी सरकार द्वारा अब तक उक्त को टी.एस.पी. क्षेत्र का दर्जा नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसील "सहरिया आदिम जाति क्षेत्र" अन्तर्गत सम्मिलित है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये जाने की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जाती है। भारत सरकार की अधिसूचना 19.05.2018 (परिशिष्ट-अ) द्वारा राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार किया गया है।

(2) भारत सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं-

1. जनजातीय जनसंख्या का बहुल 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।
2. सघनता तथा क्षेत्र का उचित आकार।
3. व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे जिला, ब्लॉक या तालुका।
4. निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित क्षेत्र के मापदण्ड जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 22.01.2013 (परिशिष्ट-ब) के अनुसार निर्धारित हैं। अत: संशोधन भी भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है।

(3) वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किशनगंज व शाहबाद तहसील की कुल जनसंख्या 2,72,739 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1,02,124 है, जो कि कुल जनसंख्या का 37.44 प्रतिशत ही है एवं वर्तमान अनुसूचित क्षेत्र से लगा हुआ नहीं है। अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करते हैं। किशनगंज व शाहबाद तहसील सहरिया आदिम जाति क्षेत्र अन्तर्गत सम्मिलित है। सहरिया जाति भारत सरकार द्वारा Particularly Vulnerable Tribal Groups (P.V.T.G) के रूप में चिन्हित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि किशनगंज-शाहबाद 2018 में, 2011 की जो जनगणना थी, उसके अनुसार 1,02,124 जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, जिसके अनुसार 37.44 प्रतिशत आपने उत्तर में बताया, वह जनसंख्या का आधार है। आपने प्रतिशत में माना है। जबकि 2018 में बड़ी सादड़ी को 37.36 प्रतिशत होते हुए उसको टी.एस.पी. क्षेत्र में लेने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि किशनगंज-शाहबाद में 0.8 प्रतिशत ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार और अभी 2024 चल रहा है। उसके आधार पर आप किशनगंज-शाहबाद में दुबारा सर्वे करवाकर टी.एस.पी. में लेने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाने का विचार रखते हैं क्या?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की मंशा बहुत अच्छी और साफ है। 2011 की जनसंख्या उस समय 37.44 प्रतिशत थी। अब जनसंख्या भी बढ़ी है तो निश्चित रूप से हम सर्वे करवाकर इस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेंगे। आपकी मंशा के अनुसार हम भारत सरकार से आग्रह भी करेंगे, क्योंकि काफी एरिया है, जहां आबादी बढ़ गयी है और वास्तव में उनको आवश्यकता भी है तो निश्चित रूप से हमारी तरफ से प्रस्ताव भेजेंगे और केन्द्र सरकार से आग्रह करेंगे कि इसको टी.एस.पी. क्षेत्र में जोड़ा जाए।

श्री ललित मीना (किशनगंज): मैं मंत्रीजी से यह भी पूछना चाहूंगा कि आपने खण्ड (2) में यह चौथा पाइंट दिया कि निकटवर्ती क्षेत्र की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन। किशनगंज-शाहबाद में आपने पी.वी.टी.जी. के अन्तर्गत विशेष समुदाय, सहरिया समाज को वहां लिया है, पर उस क्षेत्र में एस.सी., ओ.बी.सी. और जनरल के भी बहुत पिछड़े और गरीब तबके के लोग हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो चौथा पाइंट है, क्योंकि केन्द्र सरकार का आपने इसमें दिया है कि जनसंख्या का बाहुल्य 50 प्रतिशत होना चाहिये, तो जो चौथा पाइंट है, उसके आधार पर आर्थिक क्षेत्र की जो अन्य समाज की है हमारी, जो जनजाति की है, उनके अलावा जो और समाज हैं, उनका भी बहुत आर्थिक पिछड़ापन है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इसको भेजे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इसको कब तक भेजेंगे और कब तक इसको लागू करवायेंगे?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): देखिये, आपकी

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

मंशा के अनुसार ही जल्दी ही इसको दिखवाकर, अगर नियमों में है तो हम निश्चित रूप से भेजकर केन्द्र सरकार से आग्रह करेंगे कि जितना जल्दी सम्भव हो उतना जल्दी लागू करें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय स्पीकर साहब, यह 42 नम्बर का क्वेश्चन था गोविन्द प्रसाद जी का। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं, वे नहीं आयीं और यह सदस्य भी बी.जे.पी. का था, इसको बाहर करवा दिया।

श्री अध्यक्ष: ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या मंत्री नहीं आयेगा तो वह बी.जे.पी. का सदस्य..(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह आरोप पूर्णत: गलत है। (व्यवधान) यह आरोप पूर्ण रूप से गलत है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसे मिला-जुली नहीं कर सकते आप। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह आरोप ही पूर्ण रूप से गलत है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका मंत्री नहीं आया तो आपने अपने सदस्य को बाहर करवा दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसा नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हमने किसी सदस्य को बाहर नहीं कराया। आपका आरोप गलत है। (व्यवधान) इस आरोप की भर्त्सना की जाती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। आप बैठिए। आसन पांवों पर। माननीय मंत्रीजी ने ..(व्यवधान) आप सुनिये, मैं जवाब दे रहा हूं। माननीय मंत्रीजी ने दो दिन छुट्टी ली है। दूसरे मंत्री को अधिकृत कर रखा है, चूंकि वह सदस्य नहीं है, इसलिये वह प्रश्न नहीं पूछा गया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदस्य को गायब कर दिया।

(श्री गोविन्द सिंह डोटसरा)

(व्यवधान) सदस्य को गायब कर दिया कि आप पूछोगे नहीं। मेरा आरोप है। मेरा आरोप है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): किसी को गायब नहीं किया। यह आदत आपकी होगी। किसी ने गायब नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदस्य को गायब कर दिया कि आप पूछोगे नहीं। मंत्री जवाब देने में सक्षम भी हैं। (व्यवधान) यह पूरी सरकार पर्ची की सरकार है।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर, आसन पांवों पर है ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बार-बार खड़े होते हैं, आप बैठिए। बैठिए धारीवाल जी, बैठिए। धारीवाल जी, धारीवाल जी बैठिए। मैं तीन बार कहूंगा, बैठिए। वरना मुझे अगला कदम उठाना पड़ेगा। बैठिए, बैठिए, माननीय सदस्य, बैठिए। प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता, फिर भी मैंने अनुमति दे दी। आप बैठिए।

अगला प्रश्न। श्री बाबूसिंह राठौड़।

शेरगढ़ में पटवारियों के रिक्त पद

44. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर के कौन-कौनसे राजस्व कार्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त में से कितने कार्यरत व कितने रिक्त हैं? तहसीलवार, पटवार मण्डलवार, आर.आई. क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कार्यरत पटवारियों को एक से अधिक पटवार मण्डल का कार्यभार दिया हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब से?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) जिला जोधपुर/जोधपुर ग्रामीण में तहसीलवार, पटवार मण्डलवार, आर.आई. क्षेत्रवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। अतिरिक्त कार्यभार दिये गये पटवार मण्डलों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राजस्व मंत्री)

क्र सं.	तहसील का नाम	रिक्त पटवार मण्डल का नाम जिसका अति. कार्यभार दिया गया	कब से रिक्त (अवधि)
1	शेरगढ़	1. गुमानसिंहपुरा	जनवरी, 2023 से
		2. सांई	03 जुलाई, 2023
		3. हिम्मतपुरा	जनवरी, 2019
		4. खिरजा तिबना	31 जुलाई, 2018
		5. सियांदा	26 जुलाई, 2023
		6. भाण्डू जाटी	जुलाई, 2021
		7. चाबा	28 जुलाई, 2023
		8. चुतरपुरा	07 जुलाई, 2023
		9. गडा	10 जुलाई, 2023
		10. रायसर	01 मार्च, 2023
2	बालेसर	1. खारीबेरी	19 अप्रैल, 2023
		2. निम्बो का गांव	28 दिसम्बर, 2023
		3. बस्तवा माताजी	12 सितम्बर, 2022
		4. ढाढणिया सांसण	25 जनवरी, 2023
		5. हनवन्तनगर	13 मार्च, 2023
		6. जुडिया	09 दिसम्बर, 2022
		7. जलंधर नगर	19 जनवरी, 2023
		8. ढाढणिया भायला	25 जनवरी, 2023
3	सेखाला	1. केतु कलां	06 माह से अधिक
		2. भालू अनोपगढ़	06 माह से अधिक
4	चामू	1. नाथडाउ	16 अगस्त, 2023
		2. लोडता अचलावता	16 अगस्त, 2023
		3. गोदेलाई	
		4. देवातू	

(राजस्व मंत्री)

(3) रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती रहती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार भविष्य में पद रिक्त होने से पूर्व ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? एक तो यह स्पष्ट करें।

साथ ही, क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में कार्यालय पद 59 में से 23 पद रिक्त हैं। फील्ड के पद 691 में से 175 पद रिक्त हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक 80 में से 29 और 133 में से 52 पद रिक्त हैं। चामू में तहसीलदार का पद रिक्त है। नायब तहसीलदार के 5 पद शेरगढ़ में रिक्त हैं। राजस्व लेखा में 14 में से 11 पद रिक्त हैं। सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 28 में से 19 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ सहायक के 28 में से 19 पद रिक्त हैं। कनिष्ठ सहायक के 56 में से 27 पद रिक्त हैं। चतुर्थ श्रेणी के 179 में से 139 पद रिक्त हैं। क्या मैन पावर के कारण आम जन के कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं? यदि हां, तो आप क्या कार्यवाही अमल में लाना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: हो गया, दो प्रश्न हो गये। एक बार पूछ लिया। उत्तर आ जाने दीजिए। माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय सदस्य महोदय ने जो पूछा है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सदस्य ने पूछा है।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): हां। जोधपुर जिले में भू-अभिलेख निरीक्षक के कुल 133 पद स्वीकृत हैं व 51 पद रिक्त हैं।

श्री अध्यक्ष: यह बता चुके हैं। आप तो उत्तर दीजिए जो उन्होंने पूछा है, उनके पूरक प्रश्न का। नये हैं। अभी नये हैं।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): जो पद खाली हैं उनको भरने की एक सतत प्रक्रिया है। उसको विभाग के माध्यम से पूरा करके आने वाले समय में इन सभी पदों को भरने का काम किया जायेगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

नहीं आया है। मैंने यह पूछा है कि रिक्त पद होने से पहले आप इनको भरने की मंशा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? पहले कोई प्रक्रिया करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: इनको जल्दी से जल्दी भरेंगे, इन्होंने कहा है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): यह सतत प्रक्रिया कब तक चलेगी? 5 साल में तो पूरी हुई नहीं सतत प्रक्रिया।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, जल्दी से जल्दी भरें।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। बैठे-बैठे न बोलें। हां, खड़े होगे तो मुझे भी आयेगा। आप अपने आपको सम्भालें। आया कि नहीं आया, यह मुझे तय करना है। आपको नहीं करना है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट से सी.एस.आर. के तहत स्वीकृत कार्य

45. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला बारां में माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2023 तक छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट से सी.एस.आर. के अंतर्गत कहां-कहां पर कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत हुए? उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): बारां जिले में छबड़ा तापीय विद्युतगृह इकाई 1 से 4, प्रत्येक इकाई 250 मेगावाट एवं छबड़ा सुपरक्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना इकाई 5 एवं 6 प्रत्येक इकाई, 660 मेगावाट की स्थापित है। उक्त विद्युत गृहों के अन्तर्गत जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक सी.एस.आर. के अन्तर्गत कुल राशि रु. 1,301.75 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मैंने पढ़ लिया।

श्री अध्यक्ष: चलो, पूरक प्रश्न पूछें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि मेरे प्रश्न पूछे जाने के पश्चात् इन कार्यों की प्रगति की जानकारी के लिए अधीक्षण अभियंता द्वारा कार्यकारी एजेंसी को पत्र क्रमांक 385 दिनांक 10.01.2024 को लिखा गया। इससे पूर्व दो साल तक इन कार्यों की किसी ने सुध नहीं ली। इसके क्या कारण हैं? नम्बर वन।

नम्बर टू, परिशिष्ट-अ क्रम संख्या (5) में ग्राम कचनारियां कलां में सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यों के लिए राशि 10 लाख स्वीकृत की गयी, किंतु जमीन वन विभाग की होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया। इसके लिए दूसरी जगह जमीन लेने के लिए विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

नम्बर तीन, परिशिष्ट-अ क्रम संख्या (8) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गूगोर में विद्यालय भवन की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपये का कार्य स्वीकृत किया गया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। संक्षेप में प्रश्न पूछें। आपका उत्तर भी आ जाये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): बताना तो पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, ये जानते हैं। आप तो पूछिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): ये नहीं जानते हैं। 60 किलोमीटर का फर्क है।

श्री अध्यक्ष: जानकारी है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): अभी तक इसका कार्य शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या कारण हैं? कारण बता दीजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि जिन किसानों ने या जिन गांवों की जमीन गयी।

श्री अध्यक्ष: आपने पूछ लिया न, उत्तर देने दीजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने पूछ लिया। उत्तर देने दीजिए। आपने दो प्रश्न पूछ लिए। इतना लम्बा मत पूछिए। हां या ना, दो लाइनों में पूछिए। आप माननीय, पुराने सदस्य हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): जिन किसानों की थर्मल के लिए जमीन अवाप्त की गयी थी, उन गांवों का डवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ, उसके क्या कारण हैं?

श्री अध्यक्ष: हां, क्या कारण हैं? कारण बता दीजिए संक्षेप में।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सी.एस.आर. के कार्यों के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में क्षेत्रीय सांसद और विधायक उसके सदस्य होते हैं। उनकी सिफारिश पर ही सी.एस.आर. के कार्य करवाये जाते हैं। थर्मल इकाई का काम वहां जो उनको सी.एस.आर. के लिए निर्धारित अंशदान देना होता है, वह जहां-जहां भी कमेटी रिकमंड करती है, वहां पर वह पैसा देने का काम उस संस्था का है। उस संस्था में माननीय सदस्य भी स्वयं उसके सदस्य हैं। सांसद महोदय भी हैं और जिला कलेक्टर भी हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): कोई हो या नहीं हो पर मुझे तो आज तक किसी मामले में सी.एस.आर....

श्री अध्यक्ष: उत्तर सुनिये। माननीय सदस्य, आप पुराने हैं। मंत्री जी का पूरा उत्तर सुनिये। माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनिये, फिर आपका कोई प्रश्न होगा तो पूछें।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): वह जिस विभाग के लिए आपने बताया कि 5 लाख का काम स्वीकृत हुआ है और वहां पर जमीन नहीं मिल रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दीजिये। कुछ काम मेरे पर छोड़िये।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अगर माननीय सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप से लिखकर के देंगे कि उसमें क्या समस्या है, तो वहां जमीन के लिए जिला कलेक्टर से बात करके और उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डॉ. ऋतु बनावत।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न पूछा था।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या बोलिए।

बयाना के ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने की कार्ययोजना

46. **डा. ऋतु बनावत** (बयाना): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. ऋतु बनावत)

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बंध बारेठा पर वाटर एक्टिविटीज प्रारम्भ करने की सरकार की कोई कार्ययोजना है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के स्थलों यथा विजय दुर्ग, ऊषा मन्दिर, रूपवास स्थित प्राचीन तालाबों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) (पर्यटन मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बयाना में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु बंध बारेठा क्षेत्र में साहसिक पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिए वर्ष 2022-23 में 2 करोड़ रु. के कार्य यथा वॉच टावर, सुलभ सुविधाएं व अन्य कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर है। साथ ही Water based पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए EOI (expression of interest) जारी की गई थी, परन्तु एकल प्रस्ताव प्राप्त होने पर उचित प्रतिस्पर्द्धा न होने के कारण EOI निरस्त की गई।

(2) विजयदुर्ग, ऊषा मन्दिर, रूपवास स्थित प्राचीन तालाब ASI के संरक्षित स्थल हैं। इन स्थलों के संरक्षण एवं विकास के कार्य ASI द्वारा कराये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा उक्त स्थलों पर वर्तमान में कार्य नहीं कराये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डा. ऋतु बनावत (बयाना): मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जो जवाब मुझे मिला है, उसमें मैंने बंध बारेठा...

श्री अध्यक्ष: आपको पूरक प्रश्न पूछना है?

डा. ऋतु बनावत (बयाना): हां। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ रही हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, पूछिए।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): जो जवाब मेरे पास आया है, उसमें यह कहा है कि बंध बारेठा में वाटर एक्टिविटीज के लिए पिछली सरकार ने योजना बनायी थी, मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने तो ऐसी टिपिकल शर्तें रखी थीं वाटर एक्टिविटीज के लिए कि वह किसी भी व्यापारी के लिए पूरा करना पोसिबल नहीं था।

(डा. ऋतु बनावत)

मैं यह पूछना चाहती हूं कि ASI के 13 पाइंट भरतपुर जिले में चिह्नित हैं, जिनमें विजयगढ़ दुर्ग, लाल महल, रूपवास, शाही तालाब, ऊषा मन्दिर तथा अन्य हैं, लेकिन उनमें से 7 केवल बयाना विधान सभा में हैं, जो अभी जर्जर स्थिति में हैं, उनको डवलप करने के लिए, क्योंकि ASI की कोई निगरानी नहीं रहती है, वहां पर स्थिति ऐसी है कि वह धराशायी होने की तरफ हैं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): मैं विभाग से पूछना चाहती हूं कि क्या आप वहां पर क्षेत्र का डवलप करने के लिए, उन पाइंटस को डवलप करने के लिए क्या मंशा रखते हैं? कोई कार्ययोजना आपकी है? अगर है तो कब तक है?

दूसरा, झरनों के लिए प्रसिद्ध दर बराना बुआलको धाम, इमलिया कुण्ड, सप्त कुण्ड को विकसित करने के लिए रास्ता बनाने की आवश्यकता है और इसलिए राज्य सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं और स्थानीय लोगों के लिए डवलपमेंट के लिए आप क्या सोचते हैं, ऐसा अगर किया जाना है तो कब तक किया जाना है?

श्री अध्यक्ष: बैठिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्याजी को बताना चाहता हूं कि इन्होंने बंध बारेठा के वाटर बेस्ड एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस के संचालन के लिए ई.ओ.आई. जारी करने की बात की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधायक महोदयाजी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम खुले दिमाग से ई.ओ.आई. की समीक्षा करेंगे और जरूरत हुई तो ईओ.आई. के प्रावधानों को ऐसा बनाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें और अच्छा कम्पीटिशन हो सके, उसमें भाग ले सकें, इसके लिए हम जरूर हमारे विभाग को निर्देशित करेंगे कि इसको बनाएं, वहां लोग आएं।

दूसरा, आपने कहा कि इन मोन्यूमेंटों को विकसित किये जाने को, विजय दुर्ग, ऊषा मन्दिर, रूपवास स्थित प्राचीन तालाब, ये हमारे ए.एस.आई. के संरक्षण स्थलों में हैं, ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.एस.आई. ने पिछले दो-तीन वर्षों में काफी काम यहां कराये हैं। इन कामों की पूरी लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है, ये

(श्री कन्हैयालाल)

सूची विधायक महोदय को हम उपलब्ध करवा देंगे। ए.एस.आई. के अधिकारियों और इंजीनियर्स के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें राज्य सरकार का पूरा सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

विधायक महोदय से जो भी सुझाव मिलेंगे, उन्हें ए.एस.आई. की योजनाओं में शामिल करेंगे, वे बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी जानकारी में होगा, ए.एस.आई. के क्षेत्राधिकार वाले स्थलों का संरक्षण एवं विकास ए.एस.आई. द्वारा ही किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी मुझे है लेकिन जो जर्जर स्थिति में हैं, उनके लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी, यह मैं पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने कह दिया कि सरकार ए.एस.आई. को लिखेगी।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): इन्होंने क्वेश्चन के जवाब में जितना पैसा मिला बताया है, लेकिन आज भी रूपवास का जो तालाब है, ए.एस.आई. के अंडर में तो आ रहा है, लेकिन वो आज बुरी तरह से सड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): हमारे अधिकारी ए.एस.आई. के अधिकारियों से बात आपको साथ बैठाकर, जो-जो आप बताएंगे, करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सामने बैठे प्रतिपक्ष के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि गोविन्द प्रसाद जी क्यों नहीं आए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वो बात मेरी है, वो बात मैं कहूंगा।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): वो जवाब मैं दे रहा हूं। वो आते तो आपके चिट्ठे खोलता मैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपने पी.डब्ल्यू.डी. के अन्दर बजट का प्रावधान किया 6 हजार और टेंडर लगा है 11 हजार का ...(व्यवधान) मैं जवाब देता आपको।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) अगला प्रश्न। श्री रतन देवासी। (व्यवधान) अब हो गया। क्वेश्चन ऑवर में इस तरह की बात नहीं होती। श्री रतन देवासी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्रीजी, इस बात का जवाब दीजिए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन ऑवर में किसी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपकी ही व्यवस्था है। मैं पुरानी व्यवस्थाएं बता रहा हूं आपको।

श्री अध्यक्ष: मुझे वो बदलना होगा तो मैं बदल दूंगा। (व्यवधान) आप बैठिए। आपको अनुमति नहीं है। (व्यवधान) बिना अनुमति के आप खड़े नहीं हो सकते।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैंने अनुमति मांगी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने नहीं दी है। अनुमति देने का अधिकार मेरा है। (व्यवधान) अनुमति देने का अधिकार मेरा है, आपका नहीं है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): तो क्या अनुमति नहीं है?

श्री अध्यक्ष: हां, नहीं है। आप विराजो।

नवगठित सांचौर जिले का पुनर्सीमांकन

47. श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सांचौर को जिला बनाने के उपरांत तहसील रानीवाड़ा एवं आर.आई. सर्किल चितरोडी के ग्रामवासियों द्वारा अपने-अपने गांव, ढाणियों को जिला जालौर में रखे जाने हेतु जिला प्रशासन को मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? मांग पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्रामवासियों की मांग पर नवगठित सांचौर जिले का परिसीमन, पुन:सीमांकन कर राजस्व गांवों को जिला जालौर में ही रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा) (1) नवीन जिला सांचौर के अधिसूचित होने के उपरान्त उप खण्ड व तहसील रानीवाड़ा को यथावत जिला

(राजस्व मंत्री)

जालौर में रखने हेतु स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किये गये थे। उक्त प्राप्त सभी पत्र जिला कलेक्टर द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग को भिजवाये गये थे। उक्त प्राप्त मांग पत्रों/ज्ञापनों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में नवीन जिलों के गठन उपरान्त जिलों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में स्थानीय जन प्रतिनिधियों, आमजन से प्राप्त विभिन्न मांग पत्रों पर विचार कर उनके निस्तारण करने हेतु मंत्रिमण्डल की आज्ञा 246/2023 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा तत्कालीन माननीय राजस्व मंत्री को अधिकृत किया गया था। माननीय राजस्व मंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना अनुसार राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक प. 9(18) राज-1/2022, दिनांक 06.10.2023 व 07.10.2023 जारी कर नवीन जिलों की सीमाओं में आंशिक परिवर्तन किया गया तथा शेष ज्ञापनों का परीक्षण करने हेतु अध्यक्ष, उच्च स्तरीय समिति (जिला गठन) को भिजवा दिये गये। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र दिनांक 17.12.2023 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक प.9(18)राज-1/2022, दिनांक 18.12.2023 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति (जिला गठन) को समाप्त किया जा चुका है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है, मैंने इसको पढ़ लिया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, पूरक प्रश्न पूछें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब के खण्ड (2) में माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल यह था कि जो नव गठित जिले हैं, जिनमें नव गठित सांचौर जिले की बात है, उसमें आपको जो ज्ञापन प्राप्त हुए, उनमें सीमाओं में जो छूट मांगी है, वापस एक्सरसाइज करके आपको उसका परिसीमन करना है, पुन:सीमांकन करना है उसके बारे में पूछा है। आपने जवाब में लिख दिया कि यह बात ठीक है कि 04 अक्टूबर, 06 अक्टूबर, 07 अक्टूबर, 2023 को राज्य सरकार ने माननीय राजस्व मंत्रीजी को अधिकृत किया था उसमें उन्होंने 06 अक्टूबर और 07 अक्टूबर को आंशिक परिवर्तन

(श्री रतन देवासी)

कर दिया, शेष ज्ञापन हमने अध्यक्ष, उच्च स्तरीय समिति को भेज दिया और उसके पश्चात् आपने यह लिख दिया कि 18 तारीख को आपकी सरकार का गठन होने के पश्चात्, 18 दिसम्बर, 2023 को हमने उस उच्च स्तरीय समिति को भंग कर दिया, खतम कर दिया। जो उत्तर आपने मुझे दिया है, उसमें लिखा है कि ज्ञापन उच्च स्तरीय समिति को भेज दिया है और उस समिति को ही आपने खतम कर दिया है। मेरे इसमें तीन प्रश्न हैं, पहला यह कि ज्ञापन जो आपने उच्च स्तरीय समिति को भेजा है, समिति को भंग कर दिया है तो उसका स्टेटस क्या है? नम्बर दो, प्रश्न यह है कि मैंने यह जवाब मांगा था कि उन ज्ञापनों में परिसीमन, पुन:सीमांकन या आंशिक संशोधन की जो मांग की गई है, जिसके लिए धरना दिया गया था, आपके लोगों द्वारा कमिटमेंट किया गया था, सरकार होने के एक महीने में हम कर लेंगे तो क्या आप उसमें परिसीमन, पुन:सीमांकन या फिर आंशिक संशोधन उन ज्ञापनों के आधार पर करेंगे या नहीं करेंगे? ये दो प्रश्न मेरे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): जो यह कमेटी है, जिसको भंग कर दिया गया था, जो ज्ञापन और ये सब आए थे, इस उच्च स्तरीय कमेटी को दिनांक 18.12.2023 को समाप्त किया जा चुका है। आने वाले समय में...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य पूछना चाह रहे हैं कि उन ज्ञापनों का अब क्या होगा। यह पूछ रहे हैं, इसका उत्तर दे दीजिए कि ज्ञापन का क्या होगा?

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): क्या आप करना चाहते हो कि नहीं? क्या करना चाहते हो, यह बताइए आप।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): अब चूंकि जिलों का गठन कमेटी के माध्यम था, उस कमेटी को भंग कर दिया गया है। आने वाले समय में उस कमेटी का गठन करके इस बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। (व्यवधान) अगला प्रश्न। श्री रामनिवास गावड़िया। (व्यवधान) कमेटी अलग गठित होने पर आपका उत्तर आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): आपने उस कमेटी को भंग किया है तो आने वाले समय में कमेटी का गठन करेंगे, एक तो सवाल यह हो गया कि

(श्री रतन देवासी)

राजस्थान में जिन जिलों का गठन हुआ, ज्ञापन आए, उनमें पुन: सीमांकन, आंशिक संशोधन करना है उसके लिए राज्य सरकार वापस कमेटी बनाने जा रही है, इस बात का तो जवाब आ गया फ्लोर पर। मुझे इसके साथ माननीय मंत्रीजी से पूछना था कि कमेटी को आपने ज्ञापन भेज दिए, वो उस पर तय करेगी। क्या सरकार की भी यह मंशा है कि कमेटी गठन करने के पश्चात् ये चाहेगी कि उसमें संशोधन करेंगे कि नहीं करेंगे? यह दूसरी बात है।

श्री अध्यक्ष: यह तो कमेटी पर निर्भर होगा। (व्यवधान) यह तो कमेटी पर निर्भर होगा।

अगला प्रश्न। श्री रामनिवास।

नागौर व डीडवाना में घरेलू व कृषि कनेक्शन के लम्बित आवेदन

48. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर-डीडवाना में घरेलू व कृषि कनेक्शन के कितने आवेदन पत्र विगत छह माह से लम्बित हैं तथा कितने आवेदन पत्रों के डिमाण्ड नोटिस जारी किये गये? तहसीलवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील परबतसर में कितने घरेलू व कृषि उपभोक्ता हैं जिनके डिमांड नोटिस जारी होने के उपरांत भी कनेक्शन जारी नहीं किये गये हैं? सरकार द्वारा लम्बित विद्युत कनेक्शन कब तक जारी कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर में आई.पी.डी.एस. योजनान्तर्गत परबतसर शहर में अण्डरग्राउण्ड केबलिंग किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो अब तक कितनी केबलिंग अण्डरग्राउण्ड हो चुकी है व कितनी शेष है? क्या सरकार शेष कार्य को पूरा करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक विभिन्न योजनाओं में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने जी.एस.एस. स्वीकृत हुए तथा उक्त में से कितनों का निर्माण पूर्ण हो चुका व कितनों का शेष है? शेष का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) नागौर-डीडवाना जिले में कृषि श्रेणी की छह माह पुरानी 1,960 पत्रावलियां लम्बित हैं जिनमें से 361 के मांगपत्र 30.06.2023 तक जमा हैं। 1,179 पत्रावलियों के मांगपत्र पिछले छह माह में जारी कर दिये गये हैं जिनमें से 959 मांगपत्र जमा हुए है तथा 420 आवेदन 22.02.2022 से 30.06.2023 तक के हैं, जिनके मांगपत्र आगामी कट आफ डेट के अनुसार जारी किये जायेंगे। तहसीलवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध हैं। घरेलू श्रेणी की कोई पत्रावाली छह माह से पुरानी लम्बित नहीं है।

(2) तहसील परबतसर में जमा मांगपत्र वाले घरेलू श्रेणी के 38 एवं कृषि श्रेणी के 127 उपभोक्ता हैं, जिनके कनेक्शन शीघ्र ही वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में आई.पी.डी.एस. योजना संचालित नहीं है। उक्त योजना 31 मार्च 2019 तक ही संचालित थी, जिसके तहत परबतसर विधान सभा क्षेत्र में 33 केवी अण्डर ग्राउण्ड कैबलिंग 0.94 किलोमीटर तथा नई 11 के.वी. लाइन 2.44 किलोमीटर अण्डर ग्राउण्ड लाइन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं वर्तमान में उक्त योजनान्तर्गत कोई कार्य शेष नहीं है।

(4) परबतसर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक किसी भी श्रेणी का कोई जी.एस.एस. स्वीकृत नहीं हुआ। यद्यपि उक्त अवधि में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत सब-स्टेशनों में परबतसर बाईपास, झालरा, किनसारिया तथा रिड, चार 33/11 के.वी. सब-स्टेशन स्थापित किये गये हैं। वर्तमान में परबतसर विधान सभा क्षेत्र में स्थापित विद्युत तंत्र आवश्यक विद्युत भार अनुरूप होने के कारण तकनीकी रूप से नवीन जी.एस.एस. या 33/11 के.वी. सब स्टेशन के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब लम्बे-चौड़े दे रहे हैं सारे। जब से सदन चल रहा है, लगातार सवाल पूछ रहा हूं। बीस-बीस पेज के ये जवाब दिए जा रहे हैं। मंत्री महोदय के इनके अधिकारी गुमराह करके जो असत्य आंसर शीट हम सब लोगों को यहां दी जाती है, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मैंने पूछा था कि परबतसर और नागौर जिले में जबर्दस्ती बाहर की विजिलेंस के द्वारा

(श्री रामनिवास गावड़िया)
वी.सी.आर. शीटें भरी जा रही हैं, जबकि जवाब में आया, जी नहीं, जबकि रोजाना भरी जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जब आपके मैनिफेस्टो में है कि 24 घंटे हम लोग बिजली उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आज काश्तकार की बिजली की समस्या का कहीं समाधान नहीं हो रहा है। जब सवाल पूछा जाता है तो आपके अधिकारी...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): प्रश्न से ज्यादा जरूरी यह है कि हम लोगों को आपके माध्यम से जवाब मिल रहे हैं...(व्यवधान) जवाब सही नहीं मिलता है और मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जब भी सवाल पूछा जाता है कि इनके अधिकारी हम लोगों को फोन करके कहते हैं कि माननीय, पूरक सवाल मत पूछना, यह जवाब हम आपको दे रहे हैं। मैंने कहा कि आप तनख्वाह लेते हैं मोटी-मोटी और उसके बाद ये जवाब दिए जाते हैं, इतने लम्बे-चौड़े जवाब दिए जाते हैं फिर भी हम लोग आपसे संतुष्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: आप अभी तो प्रश्न पूछिए।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि आपने लिखा है कि घरेलू श्रेणी के 38 और कृषि श्रेणी के 127 उपभोक्ताओं को वरीयता अनुसार जारी किये जा रहे हैं। ये वरीयता अनुसार इनके अधिकारी उपभोक्ता को बार-बार चक्कर कटवाते हैं और हर बार यही कहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए। यह भाषण का मुद्दा नहीं है, प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दिला रहा हूं।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि विजिलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है? डीडवाना जिले में और परबतसर विधान सभा क्षेत्र में अघोषित बिजली ट्रिपिंग हो रही है, उसकी समस्या का समाधान करने की चेष्टा रखते हो कि नहीं रखते हो? आपसे यह सवाल रहेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो ट्रिपिंग अभी हो रही है, सरकार की यह मंशा है कि कृषि में 6 घण्टे बिजली उपलब्ध करायी जाए और आम उपभोक्ता को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध करायी जाये। (व्यवधान) आप जवाब सुनिये न।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): मंशा का क्या अर्थ हुआ?

श्री अध्यक्ष: आप भी यही करते थे। यह होता है। आपकी मंशा क्या थी, वह भी सुनी है मैंने। आप उत्तर सुनिये।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच सालों में बिजली तंत्र में जिस तरह से डवलपमेंट किया जाना चाहिये था, आग्मेंटेशन किया जाना चाहिये था, प्रसारण का विस्तार किया जाना चाहिये था, इस कांग्रेस के राज में कोई भी काम नहीं किया गया। (व्यवधान)

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। बार-बार बात को घुमाया जा रहा है। (व्यवधान) आप यह बताने का कष्ट करें कि बार-बार ट्रिपिंग क्यों हो रही है?

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप अपनी सरकार के कारनामे तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष: क्या आपका कोई पूरक प्रश्न है? अगला प्रश्न, श्री चन्द्रभान सिंह। (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, आप लोग बैठिए। क्या आप अपने नेता को मानते नहीं हैं?

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं धरना)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह जो जवाब दे रहे हैं, यदि पांच सालों तक कोई व्यवस्था नहीं थी तो पांच सालों तक बिजली पूरी कैसे आ रही थी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। आपके नेता बोल रहे हैं। उन्हें अनुमति दी है मैंने। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, इस प्रकार से सदन में शोर मचाकर मंत्री जवाब देने से बचते हैं। इन्होंने एक रटी-रटायी बात पकड़ रखी है कि पिछले पांच सालों में किसी तंत्र में सुधार नहीं हुआ। मैं यह चाहता

(श्री टीकाराम जूली)

हूं कि आप इस सदन में बिजली पर चर्चा कराइये कि कांग्रेस के राज में बिजली तंत्र कितना मजबूत हुआ और बी.जे.पी. के राज में बिजली तंत्र कितना मजबूत हुआ।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): बिजली पर चर्चा कराएंगे तो सदन में आपकी हालत खराब हो जाएगी। फिर तो आपकी पोल खुल जाएगी। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। दो महीने से लगातार वीसी.आर. भरी जा रही है, लगातार बिजली की कटौती की जा रही है। (व्यवधान) किसान परेशान हैं और ये ऐसे जवाब दे रहे हैं। ऐसे सदन नहीं चलेगा, मंत्रियों से जवाब दिलाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जवाब दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मुझे मजबूर मत करिये कि मुझे कुछ और कदम उठाना पड़े। मुझे मजबूर मत करिये कि मैं किसी का नाम लेकर कोई कदम उठाऊं। प्रश्न काल को प्रश्न काल के रूप में रहने दीजिए। श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली का विषय सबसे महत्वपूर्ण है, राजस्थान की आम अवाम से विशेष रूप से सम्बन्धित है, अगर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य चाहते हैं तो सरकार चर्चा के लिए, जवाब देने के लिए तैयार है। आप जो चाहें, सरकार तैयार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए सभी। (व्यवधान) आप अपने पांच सालों का भी देख लीजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह।

चित्तौड़गढ़ में विजिलेंस द्वारा वी.सी.आर.

49. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक जिला चित्तौड़गढ़ में विजिलेंस द्वारा कितनी वी.सी.आर. भरी गयीं तथा कितनी राशि का संग्रहण किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में सरकार को फर्जी वी.सी.आर. भरने की कितनी

(श्री चन्द्रभान सिंह चौहान)

शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उक्त में से कितनी का निस्तारण कर दिया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) चित्तौड़गढ़ जिले में दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2023 तक कुल 27,697 वी.सी.आर. भरी गयीं एवं 3,155.87 लाख रुपये का संग्रहण किया गया। विधान सभा क्षेत्रवार भरी गयी विद्युत सतर्कता जांच रिपोर्ट एवं संग्रहण की गयी राशि का विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) उक्त अवधि में सरकार को फर्जी वी.सी.आर. भरने की कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री घनश्याम।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन है न। मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। (व्यवधान) ये कांग्रेस वाले इनके कर्मों के कारण यहां बैठे हुए हैं। मंत्री जी, आपने जो टार्गेट दे रखे हैं, क्या आगे भी आप इन्हें जारी रखेंगे या खतम करेंगे, क्योंकि गरीब लोग, जो बी.पी.एल. में, ए.पी.एल. में हैं ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

श्री अध्यक्ष: घनश्याम जी, प्रश्न पूछें।

टोडाभीम में सड़कों का मरम्मत कार्य

50. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विगत पांच वर्षों में गारंटी समयावधि में बनवायी गयी सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में समयावधि गारंटी में बनवायी गयी सड़कों का पुन: मरम्मतीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री श्री कन्हैयालाल जी, घनश्याम जी के प्रश्न का उत्तर दें।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) (सार्वजनिक निर्माण मंत्री के स्थान पर): (1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में गारंटी समयावधि में

(श्री कन्हैयालाल)

बनवायी गयी सड़कों की कोई श्रेणी नहीं है। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में गत पांच वर्षों में संवेदक की गारंटी अवधि में रही सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में संवेदक की गारंटी अवधि की सड़कों पर मरम्मत/रख-रखाव का कार्य संवदेकों द्वारा समय-समय पर करवाया जा रहा है। वर्तमान में संवेदक की गारंटी अवधि की सभी सड़कें संतोषजनक स्थिति में हैं।

गारंटी अवधि पार क्षतिग्रस्त सड़कों का पुन: मरम्मतीकरण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। (व्यवधान)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: कोई पूरक प्रश्न?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले दो महीनों से लगातार सड़कों का कार्य बंद है। पिछले दो महीनों से किसी भी सड़क का कार्य चालू नहीं है ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पहले भी कहा है, बिजली पर, पानी पर सरकार जवाब देने को तैयार है। आधे घण्टे, दो घण्टे की चर्चा रखें, सरकार जवाब देने को तैयार है। सरकार हर बिन्दु पर जवाब देने को तैयार है। इन्हें जवाब सुनना नहीं है। अपनी कमजोरी, अपनी लालफीताशाही, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये आकर वैल में खड़े होते हैं। जो भी ये चाहें, हम तैयार हैं। (व्यवधान) इन्हें कहिये, अभी चर्चा कीजिये, अभी तैयार हैं हम।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ। कालीचरण जी, प्रश्न पूछें।

छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताओं की रोकथाम

51. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को विगत एक वर्ष में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों की जांच किस-किस से करवायी गयी? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित की गई कार्रवाई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालीचरण सराफ)

(2) क्या सरकार छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताएं रोकने हेतु कोई उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश गहलोत, उत्तर दीजिये।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) जी हां। विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्ति वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच निदेशालय स्तर पर समितियां बनाकर करवायी गयी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त जांचों में दोषी पायी गयी शिक्षण संस्थाओं को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है एवं उनके खिलाफ एफ.आई.आर. भी दर्ज करवायी गयी है। आरोपित एक कार्मिक को एफ.आई.आर. दर्ज होने एवं गिरफ्तार होने के कारण निलम्बित किया गया है। इसके अतिरिक्त आरोपित विभागीय अधिकारियों/ कार्मिकों को "कारण बताओ नोटिस" जारी किये गये हैं। जांच रिपोर्टों की प्रतियों सहित की गयी कार्रवाई का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। छात्रवृत्ति राशि वितरण में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा की गयी पुख्ता व्यवस्था का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय मंत्री महोदय, बैठिए। मेरा पूरक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

(समय: 12.00 बजे)

शोकाभिव्यक्ति। सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर जायें। अब हो गया, आप इनसे बाद में मिल लेना। अब हो गया। शोकाभिव्यक्ति। माननीय मंत्री जी, इधर देखिए।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

हरिशंकर भाभड़ा, श्री, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्य मंत्री एवं पूर्व सांसद

माननीय सदस्यगण शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री हरिशंकर जी भाभड़ा के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

इस विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्य मंत्री श्री हरिशंकर भाभड़ा का जन्म 06 अगस्त, 1928 को नागौर जिले के डीडवाना कस्बे में हुआ। आपने बीए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कर वकालत को पेशे के रूप में अपनाया। आपके संसदीय जीवन की शुरुआत वर्ष 1978 में राज्य सभा सांसद के रूप में हुई। आप राजस्थान विधान सभा में आठवीं, नौवीं और दसवीं विधान सभा में रतनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। श्री भाभड़ा नौवीं एवं दसवीं विधान सभा के दौरान वर्ष 1990 से 1994 में विधान सभा अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे।

आपने अपने संसदीय अनुभव एवं ज्ञान, धीर-गम्भीर व्यक्तित्व, संसदीय प्रक्रिया एवं संवैधानिक मामलों की गहरी समझ एवं प्रशासकीय प्रतिभा से पद की गरिमा को बढ़ाते हुए राज्य विधान मंडलों के तत्कालीन अध्यक्षों में एक विशिष्ट एवं सम्मानजनक पहचान बनाई। अध्यक्ष पद पर रहते हुए श्री भाभड़ा ने विधान सभा की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को अक्षुण्ण रखा। आपने सदन की कार्यवाही के सुचारु रूप से संचालन के लिए प्रक्रियागत नवीनता की दृष्टि से अनेक नवाचारों की शुरुआत की। श्री भाभड़ा की पहल पर राजस्थान विधान सभा में नई परम्परा के रूप में 16 सितम्बर, 1992 को सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' से की गई तथा सत्र का समापन राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' से किया गया। यह परम्परा आज भी जारी है। श्री भाभड़ा के निर्देशन में वर्ष 1993 में विधान सभा की त्रैमासिक शोध पत्रिका "विधान बोधनी" सहित अन्य प्रकाशन शुरू किये गये।

दसवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान श्री भाभड़ा के सभापतित्व में राजस्थान में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए एक समिति का भी गठन किया गया। जून, 2004 में आपको आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद् का उपाध्यक्ष बनाया गया। आप भारतीय जनसंघ के विभिन्न पदों पर आसीन रहने के उपरान्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। आप अनेक सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के विभिन्न पदों पर भी आसीन रहे। श्री भाभड़ा ने अध्यक्ष पद पर आसीन रहते हुए पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलनों में राजस्थान विधान सभा का प्रतिनिधित्व किया।

आपने वर्ष 1990 से 1992 तक जिम्बाबवे, नई दिल्ली एवं नसाऊ में

(श्री अध्यक्ष)

आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सी.पी.ए.) के वार्षिक सम्मेलनों में राजस्थान शाखा के प्रेसीडेंट के रूप में भाग लिया। इसके अलावा आपने अनेक देशों की अध्ययन यात्राएं भी कीं।

श्री भाभड़ा विधान सभा के इस वर्तमान भवन के स्वप्नदृष्टा रहे। आपके सद्प्रयासों से ही 10 अगस्त, 1998 को इस नये विधान सभा भवन की आधारशिला तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत एवं आपके द्वारा रखी गई।

श्री भाभड़ा के बहुआयामी व्यक्तित्व में एक प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रिय राजनेता और कुशल प्रशासक के साथ-साथ मानवीय संवदेना से युक्त एवं प्रखर चिन्तक एवं मनीषी के तत्व भी सन्निहित थे।

आपके इन्हीं गुणों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 06 अक्टूबर, 1994 को आपको राजस्थान का उप मुख्य मंत्री बनाया गया। इस दौरान आपके पास वित्त विभाग का कार्यभार रहा।

श्री भाभड़ा की एक कुशल वक्ता, भारतीय संस्कृति के गहन अध्येता और सामाजिक महत्व की घटनाओं एवं मुद्दों के कुशल विश्लेषक के रूप में विशेष पहचान रही।

अध्ययन एवं लेखन में गहरी रुचि होने के कारण संसदीय लोकतंत्र एवं संवैधानिक विषयों तथा अन्य समसामयिक मुद्दों पर आपके लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। आपके चुनिन्दा लेखों एवं भाषणों का संकलन वर्ष 1994 में विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा का दिनांक 25 जनवरी, 2024 को निधन हो गया।

मैं अपनी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।)

(श्री अध्यक्ष)

ओम शान्ति, विराजिए।

माननीय सदस्यगण प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि भाभड़ा जी जैसे, जो उप मुख्य मंत्री रहे, विधान सभा के अध्यक्ष रहे, उनके सम्मान में कम से कम आधे घंटे विधान सभा की कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: इसके लिए हमने विधान सभा को परसों स्थगित कर दिया था।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हम सभी माननीय सदस्यों का निवेदन है कि आधे घंटे तक के लिए स्थगित करें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। उनके सम्मान में सभी के विचारों को ध्यान में रखते आधे घंटे के लिए हम सदन स्थगित करते हैं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12:07 बजे 12:37 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय: 12.37 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत प्राप्त स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों की सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री रफीक खान, सदस्य की ओर से पूर्ववर्ती सरकार की चिरंजीवी योजना के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर की नोहर फीडर, रसलाना वितरिका एवं एन.टी.आर. नहरों में हरियाणा से राजस्थान के हिस्से का सम्पूर्ण पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में बंदरों के आतंक के कारण आम जनता को हो रही परेशानी एवं व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री टीकाराम जूली, सदस्य की ओर से राज्य में आये दिन महिलाओं एवं नाबालिग बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार एवं सामूहिक दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं से जनता में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

...(व्यवधान) जब मैं खड़ा हूं, माननीय सदस्य, आप पुराने हैं, वहीं खड़े हो जाओ। वापस वहीं जाकर खड़े हो जाओ। जब बैठूं उसके बाद आइये। भेज दिया। यह मेरा काम है। (व्यवधान) वहीं पर खड़े रहो। जब मैं बैठूं, तब आना। सबके लिए नियम एक है। सब माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि जब आसन पांवों पर है तो कोई भी सदस्य न तो सदन से बाहर जायेगा, न बाहर से अन्दर आयेगा। चाहे कोई भी हो। (व्यवधान) आप फिर आ गये। आपको ध्यान नहीं है क्या? माननीय सदस्य, बाहर जाइये। बाहर जाओ। माननीय सदस्य, बाहर जाइये। माननीय सदस्य, आपको कह रहा हूं। खड़े होइए। आप सुन नहीं रहे क्या? बाहर पधारो। जब मैं बैठ जाऊं, तब आ जाएं। सबके लिए नियम एक है।

(5) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा डायलिसिस मशीनों व आर.ओ. की खरीद में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रफीक खान, श्री मनीष यादव एवं श्री हनुमान बेनीवाल को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री कैलाश चन्द्र वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बगरू में मांस की अवैध दुकानों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में पेयजल एवं सिंचाई हेतु समुचित पानी उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की नवगठित नगरपालिकाओं में कर्मचारियों का पदस्थापन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से डी.डी.पी. क्षेत्र के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में सरकार द्वारा समुचित जलापूर्ति करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में जल जीवन मिशन के तहत किये जा रहे कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री अरूण चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में पेयजल की समस्या का समाधान किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर में वल्लभगढ़-वैर रोड से श्री देव बाबा मंदिर तक जाने वाले मार्ग की चौड़ाई बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री गोपीचन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनःनिर्माण करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री कुलदीप, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के बांधों को ई.आर.सी.पी. योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री शंकरसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की ग्राम पंचायतों के निवासियों से रायल्टी के नाम पर अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से चिकित्सा विभाग में कतिपय रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री शंकरलाल डेचा, सदस्य की ओर से माही भीखा भाई नहर से पेयजल एवं सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(14) डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से चौमूं शहर में सुभाष सर्किल रावण गेट से तेजाजी मंदिर की मुख्य सड़क का निर्माण पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री लादु लाल पितलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में बंद पड़ी धागा मिल को पुनः शुरू करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

आज वैसे भी अपना काम बहुत अधिक होने के कारण 295 को पढ़ा हुआ माना जाए।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)

श्री रफीक खान।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री अध्यक्ष: पहले मेरे को लिख कर भेजिए, क्या है, उसके बाद मैं अनुमत करूंगा। (व्यवधान) स्लिप आ जाए तो मैं अनुमत करूंगा। श्री रफीक खान। (व्यवधान) आप बैठिए, आप लिखकर भेजिए, बाद में मैं अनुमत करूंगा। स्लिप भेजिए विषय क्या है, मैं देखूं तो सही। (व्यवधान) यह बीच में नहीं आता, पहले यह हो जाये, उसके बाद। आपको समय मिलेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

पूर्ववर्ती सरकार की चिरंजीवी योजना

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने विपक्ष के साथियों को समय दिया और मैं आपके न्याय के प्रति पूरा आश्वस्त हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछली सरकार की चिरंजीवी योजना ने न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश और दुनिया को नई दिशा दी, आज उस स्कीम का बेनिफिशियरी अस्पतालों के चक्कर खाने को मजबूर है। किसी आदमी का इलाज नहीं हो रहा है। हर अस्पताल में आदमी अपना कार्ड लेकर धक्के खा रहा है। न तो आपने यह बोला है कि चिरंजीवी योजना बंद कर दी गई है और न आप यह कह रहे हो कि चिरंजीवी योजना चालू है। मैं सदन से गुजारिश करता हूं कि इस पर संज्ञान लें। चिकित्सा मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि इस पर संज्ञान लें और एक आर्डर जारी करें कि जब तक आप कोई नया अमेंडमेंट नहीं कर देते तब तक चिरंजीवी योजना के बेनिफिशियरी को इलाज दिया जाये और राजस्थान के हर आदमी को वे बेनिफिट्स, जो पिछली सरकार ने पांच साल तक दिये, उन बेनिफिट्स को दिया जाये, उनका इलाज फ्री कराया जाये। अध्यक्ष महोदय,

(श्री रफीक खान)

यह योजना केवल राजस्थान का रोल मॉडल नहीं बनी, इसने पूरे देश और दुनिया को नई दिशा दी। पूरी दुनिया इस बात को सोचने को मजबूर हो गई कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना जैसी स्कीम पूरी दुनिया में लागू होनी चाहिये, जहां आम गरीब आदमी जेब में बिना एक पैसे के इलाज करा सकता है। इसमें 25 लाख रुपये तक की बीमारी का इलाज फ्री हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि इसमें 25 लाख की सीमा को बढ़ाया जाये और इस स्कीम को जैसी थी, उसी तरीके से चालू किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, आपने दो मिनट का समय दिया है, सिर्फ दो मिनट में एक और बात कहकर अपनी बात खतम करूंगा। +++ ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मुद्दे पर बोलिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विषय पर बोलिए (व्यवधान) माननीय सदस्य, विषय पर बोलो। (व्यवधान) जो विषय पर नहीं होगा, वह एक्सपंज हो जायेगा। विषय पर बोलिए। (व्यवधान) जो विषय पर नहीं है, उसको एक्सपंज कर दो। (व्यवधान) जो विषय पर नहीं है, वह अंकित नहीं होगा। आप विषय पर बोलिए। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री अध्यक्ष: ....(व्यवधान) श्री मनीष यादव। (व्यवधान) मैंने कह दिया, जो विषय से सम्बन्धित नहीं है, वह एक्सपंज किया जाय।

शाहपुरा में बंदरों के आतंक से आमजन को हो रही परेशानी

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा और विशेष रूप से शाहपुरा नगरपालिका और मनोहरपुर नगरपालिका के वार्ड एवं आस-पास की ग्राम पंचायतें, जिनमें खोरी, बिदारा, राजपुरा, लोचुकाबास, निठारा, नवलपुरा, मामटोली, अमरपुरा, चिमनपुरा, देवन, काठ लाखनी, खाटोलाई, धवली, महार, इनमें विशेष रूप से बंदरों का बहुत ज्यादा आतंक है और यह वहां के निवासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंदरों के आतंक की वजह से पिछले चार-पांच वर्षों में लगभग 2,000 से अधिक लोगों को मंकी बाइट की वजह से सरकारी

(श्री मनीष यादव)

अस्पतालों में एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाने पड़े। विशेष रूप से 2023 में हमने हमारे सरकारी अस्पतालों का रिकार्ड लिया है, 230 लोगों को वहां पर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर बुजुर्ग, महिलाएं एवं बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हैं। छत पर अगर कोई सामान रखा है, पानी की टंकी है, वस्त्र हैं, उनको बंदरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष रूप से इस विषय पर कोई कार्यवाही करें। अभी तक कलेक्टर की अनुमति से लोकल बाडीज को नगरपालिका स्तर पर केवल इस प्रकार की व्यवस्था है, ग्राम पंचायत स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर एक सघन अभियान चलाया जाये और उनको अन्यत्र कहीं पर छोड़ा जाये, ताकि लोगों को इससे निजात मिल सके। कई लोगों की तो छतों पर से गिरने से जान भी जा चुकी है। यह बहुत संवेदनशील विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, इस विषय पर ध्यान दें और हमारे विधान सभा क्षेत्र में इसकी मानिटरिंग करके हमको बंदरों के आतंक से निजात दिलाएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह केवल शाहपुरा का मुद्दा नहीं है। ऐसा कई जगह है। मेरे अजमेर में है। जरा इस पर गम्भीरता रखकर इस पर कार्यवाही की जाए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वे तो हनुमान जी का रूप हैं, आप उनको क्यों भगाना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। आपको बोलने की अनुमति नहीं है। आपका जब आये, तब आप भी बोलना। हो गया। इस पर जवाब नहीं होता। श्री हनुमान बेनीवाल।

मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा डायलिसिस मशीनों व आर.ओ. की खरीद में हुई अनियमितता

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान मेडिकल सर्विस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में डायलिसिस मशीनों व

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आर.ओ. की महंगी खरीद में भारी भ्रष्टाचार से जुड़े लोक हित के अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर बोलने की अनुमति प्रदान की, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, आचार संहिता के अन्दर जब पूर्ववर्ती सरकार के समय, चुनाव की घोषणा हो गयी थी, आचार संहिता के अन्दर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 182 सी.एच.सी. सहित जिला अस्पतालों में आर.ओ. सहित दो-दो डायलिसिस मशीनों की खरीद हेतु बिड वैल्यू 17.25 लाख रुपये रखी गयी, जो कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की तुलना में 02 लाख रुपये से लेकर 06 लाख रुपये तक ज्यादा थी। अध्यक्ष महोदय, खास बात यह है कि प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना में वे ही मशीनें, जिनकी कम्पनी, मॉडल और तीन साल मैंटिनेंस वाली, जिन्हें हमारे पड़ौसी राज्यों ने खरीदी है, उनकी कीमत 6 से 10 लाख रुपये तक कम थी।

अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों ने आचार संहिता में तत्काल इलाज देने के नाम पर यह करतूत करके कार्यादेश भी दे दिया, लेकिन दो महीनों में 180 स्वास्थ्य संस्थानों के स्थान पर केवल बस्सी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंची, जहां ट्रेंड स्टाफ ही नहीं है और ताले के अन्दर मशीन पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे मामले में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मंत्री जी यहीं बैठे हैं। मेरा पहला सवाल है कि अन्य राज्यों की तुलना में 10 से 15 करोड़ रुपये अधिक चुकाकर मशीनों की खरीद क्यों की गयी? आपको अचानक कैसे याद आ गया कि आचार संहिता लगने वाली है और हमें डायलिसिस मशीन की आवश्यकता है? सैकण्ड, टेंडर शर्त के मुताबिक बिडर व मूल निर्माता को तीन साल का अलग-अलग जगह का सप्लाई का अनुभव होना जरूरी था, लेकिन जिम्मेदारों ने इसी सिंगल फर्म का चयन किया, जो शर्त को पूरा नहीं करती। मशीन को आथोराइजेशन, मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, लेकिन जिस फर्म का चयन किया गया, उनसे निप्रो मेडिकल, जापान का आथोराइजेशन लगा दिया था।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप स्वास्थ्य मंत्री जी को निर्देशित करें। गम्भीर मामला है। इसमें मरीजों को तत्काल इलाज के नाम पर जो खरीद हुई, उसमें भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री थे, वे इस बात को लेकर यह कह रहे हैं कि मेरे तो साइन ही नहीं, फाइल के अन्दर सिग्नेचर नहीं हैं जबकि मेरे पास जो कागज

(श्री हनुमान बेनीवाल)

है, उस फाइल पर सिग्नेचर उनके, और उन्होंने आनन-फानन के अन्दर यह मामला दिया। मेरी मांग है कि तमाम मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से आप जांच करायें। चूंकि आपने चुनाव से पहले कहा था कि जहां भी भ्रष्टाचार पकड़ में आयेगा, हम उनको छोड़ेंगे नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसके अन्दर कुछ अफसर, आर.एम.एस.सी. के एम.डी., आपके अतिरिक्त मुख्य सचिव और जो मंत्री थे, अध्यक्ष महोदय, मैं इतना-सा कहूंगा कि मंत्री जी के वहां तो एक ही बात थी कि कोई जाता तो कहते थे कि +++ से मिल लो। एक भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अन्दर हुआ है। हम उससे परेशान थे, पीड़ित थे। कोई जाता ही नहीं था, खुली दुकान थी। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप इस मामले में जवाब दिलायें। इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ है और सामने दिख रहा है। करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार, इस मामले को आप ए.सी.बी. को दिलवायें। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस मामले में सरकार से जवाब दिलवाएं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि आप मंत्री जी को फरमायें। जवाब दें, गम्भीर मामला है। मामला इतना गम्भीर मामला है, फ्रॉड मामला है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। क्या मंत्री देना चाह रहे हैं? कोई मंत्री देना चाहे तो दे सकता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम लिया गया है, वह पहले एक्सपंज करायें, उसके बाद बात करें।

श्री अध्यक्ष: जो सदस्य नहीं हैं, उसका नाम एक्सपंज किया जाये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ही एक प्रमुख समाचार पत्र में मैंने भी पढ़ा था, जो कि मेरे सामने है। समाचार पत्र में मैंने जैसे ही पढ़ा, मैंने चार बजे मीटिंग बुलायी। सब फाइलें मंगवायीं। यह जो समाचार-पत्र ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह मंत्री की फैलियर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, उत्तर तो सुनिये। उत्तर तो सुनो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदन समाचार पत्रों से नहीं चलता।

श्री अध्यक्ष: आपको बोलने की अनुमति नहीं है। बैठिए। आप भी बैठिए, किसी को अनुमति नहीं है। मंत्री जी के अलावा कोई नहीं बोलेगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बिना कोई कारण के खड़े हो जाते हैं, बिना उचित कारण के...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप बोलिए, संक्षेप में बोलिए।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समाचार पत्र ने मंत्री जी को कोट किया है कि उन्होंने फाइल पर साइन ही नहीं किया था, लेकिन जब इनकी सरकार थी, मैंने फाइल पर देखा, मंत्री जी के सिग्नेचर्स थे। समाचार-पत्र में उनका इंटरव्यू हुआ, एक्चुअल में क्या बात थी, यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम इसकी पूर्ण जांच करेंगे। इसकी पूर्ण जांच करेंगे। यह जो पूरा मामला आया है, यह कांग्रेस सरकार का है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जांच किससे करायेंगे, यह तो बताओ। ए.सी.बी. से कराओ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ए.सी.बी. को देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हां, ठीक है।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री गजेन्द्र सिंह। अब मैंने बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद।

श्री गजेन्द्र सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गृह विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

गृह विभाग

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की निम्नांकित 02 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्याः एफ.2/8(110) गृह-5/81 एस.ओ.524 दिनांक 04.01.2024 जिसके द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना दिनांक 19.07.2020 को अधिक्रमित किया गया है; एवं

(श्री गजेन्द्र सिंह)

2. अधिसूचना संख्या: प.4 (10) गृह-7/2004पार्ट दिनांक 01.08.2023 जिसके द्वारा राजस्थान गृह रक्षा नियम, 1962 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री गजेन्द्र सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सदन चल रहा है और पूरे मंत्रिमण्डल की जिम्मेदारी, दायित्व सदन के प्रति है। ऐसे समय में ई.आर.सी.पी. योजना का एम.ओ.यू. हमारी सरकार ने किया है।

श्री अध्यक्ष: यह अभी का विषय नहीं है। अभी विधायी कार्य हो जाएं। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत जरूरी हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह कौनसा विषय आ गया है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अनुमति नहीं है। (व्यवधान) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

एक माननीय सदस्य: पांच साल तक इसको लटकाये रखा।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, दोनों पक्ष बैठिए। दोनों माननीय सदस्य, बैठिए। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। श्री गजेन्द्र सिंह प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, यह विषय नहीं है। नया विषय नहीं आ सकता। आज की कार्यसूची में नहीं है, अनुमति नहीं दी जा सकती।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाए।

सदन कूप में

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव। श्री रोहित बौहरा। बोलना है?

श्री ललित यादव।

श्री विकास चौधरी।

श्री जुबेर खान।

श्री मनोज कुमार।

श्री रफीक खान।

डॉ. सुभाष गर्ग। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(समय : 13.00 बजे)

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 6, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड । - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री गजेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित किया गया।

शासकीय संकल्प। श्री संजय शर्मा

शासकीय संकल्प

यह सदन एतदद्वारा यह संकल्प करता है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) में संशोधनों के सम्बन्ध में विषयों को संसद द्वारा राजस्थान राज्य में विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करता हूं:

"यतः संसद ने जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वास्थ्यप्रदता बनाए रखने या पूर्वावस्था में लाने के लिए, पूर्वोक्त प्रयोजनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्डों की स्थापना के लिए उनसे सम्बन्धित शक्तियों और कृत्यों को ऐसे बोर्डों को प्रदत्त और समनुदेशित करने के लिए और उनसे संसक्त विषयों के लिए उपबंध करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) अधिनियमित किया था।

(श्री संजय शर्मा)

और यतः, विधि के प्रवर्तन में कुछ कमियां ध्यान में आई हैं जिसके लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) में संशोधन अपेक्षित है।

और यतः, ऐसी विधि की विषय-वस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II राज्य सूची के अधीन उपबंधित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबंधित के सिवाय, संसद को उपरोक्त विषयों के सम्बन्ध में राज्यों के लिए विधि बनाने की कोई शक्ति नहीं है।

और यतः, इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा विधि में उपर्युक्त संशोधन राजस्थान राज्य की विधि में संशोधन करके किये जाने चाहिए

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल के अभिभाषण के समय आप लोग बोलना। (व्यवधान)

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): "अतः, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सदन एतदद्वारा यह संकल्प करता है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) में संशोधनों के सम्बन्ध में विषयों को संसद द्वारा राजस्थान राज्य में विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए।"

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वन राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पत्र पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.04 बजे 13.34 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय: 13:34 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। विराजिये। मुझे व्यवस्था देनी है। व्यवस्था देनी है, आप बैठिए।

(श्री अध्यक्ष)

आज शाम को पांच बजे से पहले, मैंने सरकारी पक्ष से भी बात की है, यहां विपक्ष के लोगों से भी बात हुई है, पांच बजे से पहले इसकी व्यवस्था दे देंगे कि कब चर्चा अपन इस मुद्दे पर करवाएंगे।

तब तक आज अपन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो वाद-विवाद चल रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करें। कई नये सदस्य भी आये हैं, सबको उसमें भाग लेने का मौका मिले, इसलिए मेरा यह आग्रह है कि इस पर बहस शुरू की जाये, तो सबसे पहले डॉ. जसवन्त सिंह यादव।

सूचना

ब्यावर में रहस्यमयी बालक समूह की मौजूदगी

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: बैठिए।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: हो गयी, इन्फोर्मेशन हो गयी। मैंने इनका नाम पुकार लिया।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का टाइम दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में कल एक ऐसी घटना घटी है, जो राम मन्दिर के नाम पर पर्दा लगा हुआ था भगवान राम का, उस पर्दे को उतार कर एक व्यक्ति ने ...(व्यवधान) क्या?

श्री अध्यक्ष: यह मुद्दा नहीं है। आपने जो लिखा है, यह उसमें नहीं है। आपको जो सूचना देनी है, आपने जो लिखा है वह चार लाइनों में बोल दो। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): हां, वह ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अलग विषय नहीं।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): ...(व्यवधान) अवैध कब्जा रूपी 100 बच्चे अन्दर हैं। तीन और चार साल के बीच के वे सौ बच्चे कहां से आये और कहां पर गये? कौन उनका मालिक है? उनके मां-बाप कहां के हैं?

दूसरा, उसमें कोई मानव तस्करी से जुड़ा हुआ तो मैटर नहीं है? क्या यह नगर परिषद की सीमा पर इतना कब्जा जमाकर बैठे हुए हैं, आप इनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। विषय आ गया। सरकार ने संज्ञान ले लिया। बैठिए। डॉ. जसवन्त सिंह यादव।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): इसमें दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए। सदन के ध्यान में आ गया। डॉ. जसवन्त सिंह यादव।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इस सरकार को बने हुए डेढ़ महीना ही हुआ है और मैं विपक्ष के जो हालात देख रहा हूं मैंने लोक सभा भी देखी, विधान सभा भी देखी, जिला परिषद् भी देखी, पर पहली बार शायद या तो आप लोगों से यह पच नहीं पा रहा है कि एक-डेढ़ महीना भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप पांच साल कैसे निकालेंगे? आपका पांच साल में क्या हाल होगा?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह हमें भी दु:ख है कि आपको मंत्री नहीं बनाया, हमें भी इस बात की तकलीफ है। ऐसे वरिष्ठ और इतने अनुभवी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया। (व्यवधान)

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ...(व्यवधान) आप मेरी अगर सिफारिश करेंगे तो निश्चित रूप से बन जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका नम्बर आये तब आप बोलना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये छेड़ रहे हैं।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं छेड़ नहीं रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा है कि विपक्ष जरा-सी बात होती है तो उसी में वैल में आ जाता है। इस तरह का स्तर तो कभी विपक्ष का देखा ही नहीं। न तो ये लोक सभा जीत सकते हैं, इस तरह के आचरण से। आप यह सोच रहे हो कि लोक सभा तक

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

ऐसे ही हंगामा मचाते रहेंगे तो इस तरह से ...(व्यवधान) एक मुख्य मंत्री को बने हुए, एक सरकार को बने हुए डेढ़ महीना ही हुआ है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): डाक्टर साहब, भाषण पर आओ।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): भाषण पर ही आ रहा हूं। वह भाषण आपसे जुड़ा हुआ है। भाषण आपसे जुड़ा हुआ है कि सरकार को बने हुए डेढ़ महीना ही हुआ है। अभी आप ईआर.सी.पी. पर हल्ला मचा रहे थे, डेढ़ महीने के अन्दर समझौता कर लाये। अब बजाओ तालियां मुख्य मंत्रीजी के लिए। करो मुख्य मंत्रीजी की बड़ाई कि एक मुख्य मंत्री ने डेढ़ महीने में ई.आर.सी.पी. का समझौता लागू कर दिया जो आप पांच साल तक नहीं कर पाये। बजाओ ताली। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे मत बोलिये। माननीय सदस्य, आपका भी बोलने का नम्बर है। कोई भी सदस्य बोल रहा है तो आप शांतिपूर्ण सुनिये। नहीं तो इधर के बोलेंगे तो ये डिस्टर्ब करेंगे और उधर के बोलेंगे तो ये डिस्टर्ब करेंगे, तो कृपया आप बीच में नहीं बोलें। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आप बोलिये। यह व्यवस्था ठीक नहीं है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): साहब, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही बोल रहा हूं। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स बना देना डेढ़ महीने में ही, डेढ़ महीने के अन्दर ही एस.आई.टी. बना देना, एंटी रोमियो स्क्वॉड को तत्काल रूप से मजबूती से लागू कर देना और मोदीजी की जो गारंटी है, जिसकी गाड़ी राजस्थान में घूम रही है कि हर घर को छत मिले, हर इंसान को अन्न मिले, साढ़े चार सौ रुपये में सिलेंडर कर देना, जो अच्छे काम हैं उनके लिए आप तालियां बजाएं। आपके कार्यकाल में हुआ क्या? आपस में लड़ते रहे, विधायकों को खुश करने के लिए जो मांगा विधायकों ने वह ही दे दिया। जो मांगा वह दे दिया। आपने एक बार भी सोचा क्या कि राजस्थान के हित में जो फैसला हो रहा है, उस टाइम तो आप मंत्री थे, सरकार थी आपकी, एक बार तो सोचते। मैं मेरे अपने जिले से ही लेता हूं कि मेरे जिले के तीन टुकड़े कर दिये। तीन टुकड़े कर दिये, अब अभी तक भी यह नहीं पता कि उन तीन टुकड़ों के अन्दर आदमी जिला परिषद् के लिए अलवर जाता है, कलेक्टर से मिलने जाता है तो कोटपूतली, खैरथल का कहां जाता है? यह इतनी भारी परेशानी हो रही है और उसका नुकसान हम लोगों को हो रहा है। वे रोज कहते हैं कि, साहब, कुछ करो, कुछ करो। अब हम करें क्या? आपका सारा बिगाड़ा

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

हुआ काम है, वह सुधारें कैसे? आप थोड़ा तो उस टाइम ध्यान दे देते कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? वह आपका बोझा तो ढोना पड़ेगा क्योंकि हमें तो राजस्थान चलाना है, पर आपके ही विभाग के अन्दर नगरपालिका बना दी। सरपंच को हटा कर चेयरमैन बना दिया। उसके पास कोई साधन नहीं। न ई.ओ. है, न स्टाफ है और न कुछ और है। बना दिया, जगह-जगह खोल कर खड़ी कर दी। डैली मुसीबतें खड़ी हो रही हैं वहां पर। नगर परिषद् बना दी, नगर निगम बना दिया, पर कम से कम यह तो देखते कि लोगों का काम कैसे निपटेगा। पंचायत समितियां खोल दीं। ताज्जुब की बात यह है कि तहसील खोल दी और एक तहसील के अन्दर दो-दो, तीन-तीन तहसीलों की जवाबदारी है। यहां हमारे विपक्ष के नेताजी बैठे हैं। इनकी भी एक तहसील माण्डन आती है। वहां के तहसीलदार का ही पता नहीं होता। पूछते हैं तो कहते हैं कि उस तहसील में गया है, उस तहसील में गया है। उस टाइम बोलना चाहिए था। यह हम क्या कर रहे हैं? न तो हमारे पास में स्टाफ है, न इन्फ्रास्ट्रक्चर है। इस कारण से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लोगों को कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है?

अध्यक्ष महोदय, खोल दिये इन्होंने इंग्लिश स्कूल, महात्मा गांधीजी के नाम पर। कहां गये पढ़ाने वाले? कहां गये पढ़ने वाले? क्या हाल हो रहा है उन स्कूलों का? एक बार तो सोचते। केवल डेढ़ महीने में इतनी बड़ी उपलब्धि एक मुख्य मंत्री ने कर ली। आप अपने कर्मों को देखो। सच कह रहा हूं मैं। जितने जिले खोले थे, मेरे ख्याल से 19 जिले खोले थे या 15-16, मुझे याद नहीं है, वहां के सभी हार गये। एक खैरियाजी पता नहीं कैसे जीत गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उम्र का असर है इसलिए याद नहीं है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हां, उम्र तो हो ही ली। उम्र का तो क्या कर सकते हैं। उम्र का इलाज तो मेरे पास भी नहीं है, पर यह है कि मेरा दिमाग शायद आपसे बैटर हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ये रोजाना योग करते हैं। इसलिए इनका दिमाग अच्छा चल रहा है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हां, वह टेक्निक मेरे पास नहीं है, जो आपके पास थी। मैं तो आपको यही एक बात कहूंगा।

मुख्य मंत्रीजी सदन में आ गये, करो माननीय मुख्य मंत्रीजी का

स्वागत। ई.आर.सी.पी. लागू करा कर लाये हैं। ताली तो बजा दो, डोटासराजी। मेज तो थपथपा दो। कुछ तो थोड़ा लिहाज कर लो। बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला करके आये हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप भाग्यशाली हो कि आप मुख्य मंत्रीजी की तारीफ कर रहे हो और वे सुनने आ गये, वरना तो आपका भाषण बेकार जाता।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बेकार क्यों जाता? जुबेर खानजी, आप यों और कहें तो ठीक ही रहेगा। कुछ न कुछ मुझे फायदा ही मिलेगा। जब डेढ़ महीने में इतने काम हो सकते हैं तो आप लगा लो कि पांच साल में कितने काम होंगे।

माननीय विपक्ष के नेताजी, मेरा आपसे आग्रह है, एक चीज निश्चित है, आपको बहुत छोटी-सी उम्र में बहुत बड़ा पद मिला है और अभी तो आप बहुत आगे तक जायेंगे। सबके भाग्य में यह नहीं होता है, पर हर मिनट के अन्दर वेल में आ जाना, यह रिकार्ड होता है। इसका मैसेज कुछ दिनों बाद 'नौटंकी' का मैसेज चला जायेगा कि ये तो नौटंकीबाज हैं। एक गम्भीरता होती है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ये आपसे ही सलाह लेते हैं। सलाह आप दे दिया करो।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरा और इनका सम्बन्ध तो पारिवारिक है, लेकिन पार्टी और सिद्धान्त अलग-अलग हैं। मेरे जो दिमाग में आया, वह अच्छे काम के लिए अच्छी सलाह तो दे ही सकता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने सिद्धान्त कब बदले, वह बताओ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, किसी के भी भाषण में बीच में न बोलें।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैंने सिद्धान्त उस दिन बदले जब डोटासराजी ने अपने महकमे में नकल करायी। नकल करवाकर चुप हो गये तो मैंने सिद्धान्त बदल दिये।

अनेक माननीय सदस्य: नाथी का बाड़ा।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आज मुख्य मंत्रीजी ने एस.आई.टी. बनायी, उस समय आप भी गठित कर सकते थे। यदि आप पाक-साफ थे, कार्यवाही करने में क्या दिक्कत थी? लेकिन तब तो आप चुप रह गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम पाक-साफ नहीं होते तो यहां नहीं बैठते। अगर आप लोगों में दम हैं न, वह कर लेना। पाक-साफ थे, पाक-साफ रहेंगे।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, आपकी सारी जांच अगर हमारे मुख्य मंत्री महोदय खोल जाएं तो कम से कम विधान सभा तो सही चलती रहे। आप जांच के डर के मारे हर मैटर में वैल में आ रहे हो, एक मिनट भी काम नहीं करने दे रहे हो। मुख्य मंत्रीजी का एयरपोर्ट पर स्वागत हो रहा है, रास्ते में स्वागत हो रहा है, आप यहां हल्ला मचा रहे हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह अभिभाषण है क्या?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अभिभाषण ही है। इसके अन्दर और क्या होता है?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप चौथी बार खड़े हुए हैं। पांच मिनट में चौथी बार खड़े हुए हैं। विराजें आप। पांच मिनट के भाषण में चार बार खड़े हुए हैं, यह ठीक नहीं है। इनका समय सीमित है। समय होने पर मैं बैठाऊंगा।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह अभिभाषण में नहीं आता है क्या? मुझे तो आश्चर्य होता है कि नेता, प्रतिपक्ष को आप इस तरह दबाते रहोगे। ये एस.सी. के हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इनको दबाते रहोगे और अपनी दादागीरी दिखाते रहोगे? उनको बोलने का अधिकार है। आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने मुझे इंगित किया। मैं न कोई दबने वाला हूं और न मैं दबा हूं।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वेरी गुड। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए। टोका-टोकी होगी तो इनका समय जाया होगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इन्होंने मेरा नाम लिया इसलिए खड़ा हूं।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय विपक्ष के नेता, ये पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनको यहां बोलने का अधिकार नहीं है। आप तो इनको बोलने ही मत दिया करो। ये जानबूझ कर आपको दबा रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यहां जो सदन में आये हैं, उन सबको बोलने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलो। आपका समय खतम हो रहा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक चीज का धन्यवाद मैं आपको भी देना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप सदन में आज पधारे हैं पहली बार, तो कम से कम कोई मुख्य मंत्री की तारीफ कर रहे हैं, नहीं तो यहां मुख्य मंत्रीजी से ज्यादा प्रधान मंत्री की चर्चा हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्य मंत्री का जिक्र ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए। कृपया टोका-टोकी नहीं करें।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): प्रधान मंत्रीजी की तो देन है ही। आज सारे काम प्रधान मंत्री मोदीजी के कारण ही हो रहे हैं। मोदीजी की गारंटी पर ही काम हो रहे हैं।

अध्यक्षजी, मेरा तो आपसे आग्रह यह है कि एक तो मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि मोदीजी की गारंटी पर ही सब कुछ हो रहा है। दुनिया का पहला प्रधान मंत्री है जो एक-एक गली तक पहुंच रहा है, एक-एक गली तक पूछ रहा है कि आपकी क्या परेशानी है? आपका रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ, के.वाई.सी. हुई या नहीं? आज तक दुनिया के किसी प्रधान मंत्री ने नहीं पूछा। राम मन्दिर बने तो आपको दिक्कत। राम का नाम लें तो आपको दिक्कत। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में मत बोलो, वरना आपका नम्बर आयेगा तो फिर ये बोलेंगे। माननीय सदस्य, आपका भी नम्बर आ रहा है। आप उस समय बोल लेना।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): राम मन्दिर बने तो आपको दिक्कत। कोई और चीज हो तो आपको दिक्कत। आप कम से कम आपने आचरण को, इस तरह हल्ला मचाने से, जैसे मोदीजी की गारंटी है न, मेरी भी गारंटी है कि लोक सभा में इससे वोट में फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोगों ने जो तय कर रखा है न, बिना बात के वैल में आ कर शोर मचा देना, आपके दिमाग में किसी ने गलत चश्मे चढ़ा दिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): यह अभिभाषण है क्या?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इससे बढ़िया भाषण हो ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष: आप भी ऐसे ही देते थे। मुझे पता है। बैठो आप। आपका भी सुन रखा है मैंने। इनको टाइम दिया है। माननीय सदस्य, आपके भाषण का रिकार्ड निकाल लूंगा।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अभिभाषण में जो कुछ आयेगा, वही तो बोलूंगा। जो मेरी समझ में आयेगा कि राज्यपाल महोदय का जो विजन है, राज्यपालजी का विजन यही है कि राजस्थान आगे बढ़े, सरकार पारदर्शिता से काम करे, सरकार तुरन्त फैसले ले। वह ले रही है। आगे लेते रहेंगे, पर जांच जरूर करायेंगे। मानेंगे नहीं, जांच कराये बिना। उससे जो-जो घबरा रहे हैं, वे बार-आते रहो। जांच तो होनी है।

श्री अध्यक्ष: जल्दी खतम करिये। दस मिनट दिये हैं आपकी पार्टी ने आपको।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपके आदेश की पालना करूंगा। इतना ही है कि इससे अच्छी सरकार बन नहीं सकती। इससे अच्छे मुख्य मंत्रीजी, मंत्रिमण्डल हो नहीं सकता। डोटासराजी, मुझे मंत्री बनाने की बात कर रहे हो, आप जिस दिन मन से सिफारिश कर दोगे, उसी दिन बन जाऊंगा मैं। करनी पड़ेगी मन से। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि कुछ शिक्षा लो, अपने कर्मों को भूलने की कोशिश करो, सरकार का सहयोग करो। आपके कर्मों की सज़ा मिल रही है आपको, उधर बैठने का मौका मिला है।

इससे यह सीखो कि निश्चित रूप से आपसे गलतियां हुई हैं। आपने पूरे राजस्थान को चरमराकर रख दिया, भ्रष्टाचार का माहौल था, किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। हर विधायक को मुख्य मंत्री बनाकर बिठा दिया था। हर चीज के अन्दर हिस्सेदारी तय हो चुकी थी। इससे बड़े और कोई घोटाले नहीं हो सकते।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं। रोजाना आये दिन जो घटना घटती है, इससे नौजवान गुमराह होते हैं। बेरोजगार आदमी हमेशा गलत रास्ते पर जायेगा और उसका मुख्य कारण है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के अन्दर राजस्थान के जो बेरोजगार हैं, उनको यह कहकर गेट से वापस कर दिया जाता है, आपके कार्यकाल में इस तरह का वातावरण कर दिया था कि आप लॉक कर लो, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। मेरी विनती है इनसे भी, आपसे भी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज सम-अप करिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): और माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी, कि निश्चित रूप से आप बेरोजगारों के लिए लोकल इंडस्ट्रीज के अन्दर रोजगार दिलाने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना हरियाणा की तर्ज पर। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री हरीश चौधरी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: अभी नहीं, बीच भाषण में नहीं। आप स्लिप भेज दो, मैं देख लूंगा। आप बैठिए। जो बोलना चाह रहे हैं, वह लिखकर दे दो।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): दो लाइन का एक शेर है।

श्री अध्यक्ष: आपका जब भाषण होगा तो शेर बोल लेना।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो महीने से लगातार एक ही बात राजस्थान में सुनाई दे रही है और जसवन्त सिंहजी ने भी वही बात दोहरायी कि राजस्थान के अन्दर सरकार इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी के कारण बनी। देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने विधान सभा के चुनावों के अन्दर हर भाषण के अन्दर दो मुद्दे उठाये। वे दो मुद्दे क्या थे? वे दो मुद्दे थे- पेपरलीक और लाल डायरी। पेपरलीक के सन्दर्भ में प्रधान मंत्रीजी के...(व्यवधान) हां बता रहा हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्दर मुझे अधिकार दिया है बताने के लिए और मैं बता रहा हूं। आपको सुनने की जिम्मेदारी दी है और आप सुनो। जब आपको बोलने का अवसर मिला तो मैंने भी सुना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपरलीक के सन्दर्भ में पिछली सरकार ने एस.आई.टी. बनायी हुई थी और वापस फिर एस.आई.टी. का गठन हुआ। लगातार प्रधान मंत्री जी के मुंह से यह बात कही गयी कि सियासत में बैठे हुए लोगों ने पेपरलीक करवाया। दो महीने हो गये। हमारे सदन के नेता और हमारे खुद के अध्यक्ष लगातार यह बात कह रहे हैं। कुछ भी हो तो यही कहते हैं, पर अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आरोप लगाने की नहीं है, आप राजस्थान में सरकार में हो और केन्द्र में सरकार में हो। सिर्फ बातों से नहीं, अगर कुछ है तो वह कार्रवाई करने का अधिकार आपके पास में है और आप वह कार्रवाई करो। ये बातें करने के लिए नहीं और यह लच्छेदार बातें और शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं। जो लच्छेदार बातें आप कर रहे हो, इससे राजस्थान का भला नहीं होगा। जो जिम्मेदारी आपको दी गयी है, उस जिम्मेदारी को आप निभाओगे तब जाकर राजस्थान का भला होगा।

लाल डायरी, लाल डायरी, सदन के अन्दर किस-किस तरह की चीजें देखी गयीं और एक षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र के तहत एक नाम लाल डायरी। क्या हुआ उस लाल डायरी का? जो लगातार प्रधान मंत्री और तमाम लोग, जो पैरा सात के अन्दर आप लोग बता रहे हो, जिसके कारण राजस्थान

(श्री हरीश चौधरी)

में सरकार बनी है, उस लाल डायरी के सन्दर्भ के अन्दर क्या हुआ? इस तरह की कोई लाल डायरी थी ही नहीं। (व्यवधान) गजेन्द्र सिंहजी, मुझे बोलने की इजाजत दी है तभी तो मैं बोल रहा हूं। कोई लाल डायरी नहीं थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर हम सबसे ज्यादा विश्वास किस पर कर सकते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने हुए देश के प्रधान मंत्री के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं, उसी प्रधान मंत्री के मुंह से असत्य बुलवाया गया। राजस्थान के अन्दर सिर्फ वोट लेकर सरकार बनाने के लिए असत्य बुलवाया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दोनों पक्षों से आग्रह है कि बीच में न बोलें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): राजस्थान के लोग जवाब मांग रहे हैं। प्रधान मंत्रीजी की तो जो सोच थी, वह दस साल से राजस्थान ही नहीं, पूरा देश देख रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल हमको राजस्थान की सरकार क्या संदेश दे रही है? राजस्थान की सरकार संदेश दे रही है कि निवेशक ही हमारे एकमात्र वी.आई.पी. हैं। आज निवेश कौन कर सकता है? इस निवेश की ताकत किसके पास है, अडाणी और अंबानी के पास है। वोट लेते वक्त तो युवा वी.आई.पी., वोट लेते वक्त किसान वी.आई.पी. और सरकार में बैठने के बाद वी.आई.पी. निवेशक हो गये। यह राजस्थान के अन्दर नहीं होने देंगे। राजस्थान में एक मजबूत और सशक्त विपक्ष दिया है। राजस्थान के अन्दर आपका सपना, कि राजस्थान को उन निवेशकों अडाणी और अंबानी के पास गिरवी रख दोगे, यह नामुमकिन है। यह सोच, कल्पना और संदेश धरातल पर नहीं उतरने देंगे, क्योंकि यह जिम्मेदारी हम लोगों को विपक्ष के तौर पर सौंपी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शब्द भी...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य से नम्र निवेदन है कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं और वैल के अन्दर से जाते हैं, माननीय सदस्य और आसन के बीच में से न जाएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इधर से जाइए। आप पीछे से जाइए। कोई भी सदस्य वैल के बीच में से नहीं आयेगा।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर एक शब्द भी सामाजिक न्याय पर नहीं बोला गया। यह इनका अधिकार है जिसको जहां बिठाना है, जोगाराम जी, आपका सौभाग्य

(श्री हरीश चौधरी)

है 50 प्रतिशत की आबादी से ज्यादा की आबादी का इस फ्रंट बैंच के ऊपर एक प्रतिनिधित्व जोगाराम जी पटेल के तौर पर ही हम लोगों को मिल रहा है, पर सामाजिक न्याय के बारे में एक शब्द भी इस अभिभाषण के अन्दर नहीं। आने वाले समय के रोडमैप, आज मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। आपके मंत्री राज्यवर्धन सिंहजी क्या बोलते हैं? एक मंत्री नहीं बोलता, मंत्री बोलता है तो पूरी सरकार बोलती है। वह क्या बोल रहे हैं कि 2018 के आरक्षण के अन्दर जो परिपत्र जारी हुआ था, वह वापस जारी करेंगे। 2018 के अन्दर हम लोगों के साथ न्याय की जगह अन्याय किया। आप लोगों ने 50 प्रतिशत की आबादी से ज्यादा में हम लोगों को 21 प्रतिशत आरक्षण दिया तो वह कोई भीख नहीं दी, संविधान ने हम लोगों को दिया। उसके सामने एक प्रतिशत भी नहीं और कई भर्तियों में शून्य प्रतिशत हम लोगों को नौकरी मिली है, और आप वापस बात कर रहे हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर ऐसे हालात नहीं बनाओ। इन हालातों से बहुत बड़े संघर्ष की परिस्थिति आ जायेगी। यह महाभारत किन परिस्थितियों के अन्दर हुआ, सिर्फ पांच गांव मांगे गये। 50 प्रतिशत से अधिक की आबादी के लिए जो उनका हक और अधिकार है, वह आरक्षण भी आप पूरे तरीके से नहीं दे रहे हो और सरकार की तरफ से यह बोला जा रहा है कि वह आरक्षण की व्यवस्था वापस खतम करके जिस व्यवस्था के अन्दर शून्य और एक प्रतिशत, वोट लेते वक्त तो यह 50 प्रतिशत की आबादी याद आती है और सरकार में बैठने के बाद यह आपकी सोच और विचारधारा है। यह राजस्थान के अन्दर, हमारी सरकार के अन्दर रहते हुए भी हम लोगों ने संघर्ष करके यह नहीं होने दिया और अब भी मैं आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, राजस्थान के अन्दर हम लोगों के साथ यह अन्याय नहीं होने देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की स्थिति दक्षिण के अन्दर बनी। पेरियार ने कोई शौक से आन्दोलन नहीं किया। उस समय मजबूर कर दिया गया। इसी तरह की सोच ने मजबूर कर दिया पेरियार को कि वह आन्दोलन किया और उस आन्दोलन का क्या नतीजा निकला, आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि राजस्थान में आप इस तरह की परिस्थिति पैदा नहीं करो। (व्यवधान) जोगाराम जी।

श्री अध्यक्ष: आप मेरी ओर देखकर बोलें। आप मुझे सम्बोधित करें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): मैं आपकी ओर ही सम्बोधित कर रहा हूं, ये बीच में बोल रहे हैं। एक सरकार को यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से वंचितों के साथ दक्षिण के अन्दर उस वक्त स्थिति पैदा की, वह स्थिति आप सरकार में रहकर हम लोगों के साथ नहीं करो वरना हम लोगों को भी उसी तरह से आन्दोलन करना पड़ेगा। हमारा हक और अधिकार हम लेना जानते हैं, यह कोई भीख नहीं है। माननीय सभापति महोदय ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: 'अध्यक्ष महोदय' बोलो।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, अपने सबके अध्यक्ष हैं। पूरे सदन के अध्यक्ष हैं। इकलौते आपके अध्यक्ष नहीं हैं। गलती तो होती है। इंसान से गलती होती है। इतना अहंकार नहीं रखो। मैं इंसान हूं।

(समय: 14.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिए।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): जे.जे.एम. के बारे में बात की गयी राज्यपाल के अभिभाषण में। राजस्थान के साथ जे.जे.एम. में जो धोखा हुआ उसकी चर्चा नहीं की। रेगिस्तान के इलाकों में केन्द्र की योजना के अंतर्गत 90 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार देती थी और राज्य सरकार सिर्फ 10 प्रतिशत देती है। आज भी पहाड़ी इलाकों में 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार दे रही है और 10 प्रतिशत राज्य सरकार दे रही है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा मंत्री होते हुए हमें धोखा दिया गया। सिर्फ 45-45 प्रतिशत का फैसला किया गया। 10 प्रतिशत पैसा हम लोगों से लिया जाये। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए वह पैसा कितना होता है? वह दर्द और तकलीफ राजस्थान की सरकार ने समझी और यह फैसला किया कि वह पांच प्रतिशत पैसा भी राजस्थान की सरकार देगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि जो पांच प्रतिशत का फैसला किया, उससे पहले जो पैसा राजस्थान की जनता ने दिया वह पैसा भी राजस्थान की सरकार की तरफ से देकर उनको राहत पहुंचानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस जे.जे.एम. के अन्दर आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार हुआ है, गुणवत्ता में कमी हुई है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है गुणवत्ता में कमी हुई है तो कार्यवाही करो। जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ कार्यवाही करो, लेकिन हम हर ढाणी, हर घर के अन्दर पानी कैसे पहुंचा सकें और उसके अन्दर क्या-क्या बाधा आ रही है, उसके बारे में मंत्री महोदय आप पता करो। पानी का सोर्स हम रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए, अगर उस

(श्री हरीश चौधरी)

पानी के लिए कहीं बूस्टिंग की जरूरत हो, क्योंकि हम समतल इलाके में नहीं रहते हैं, 200-200, 300-300 फीट धोरे हैं। गजेन्द्र सिंह जी अच्छी तरह से जानते हैं। इनके फलौदी के अन्दर भी वही की वही स्थिति है। वहां अगर डिजाइन के अन्दर, सर्वे में कुछ कमी है तो वापस सर्वे कराकर जो टूंटियां हैं, उनको भी कम करें, खतम करें। हमारे लिए सोर्स सबसे बड़ी चुनौती है।

ई.आर.सी.पी. के लिए आपने बोला कि तालियां बजाओ। ई.आर.सी.पी. के अन्दर राजस्थान को अगर ज्यादा पानी मिलेगा तो तालियां नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग धन्यवाद भी देंगे। अगर राजस्थान को पानी के बंटवारे में हम लोगों के साथ न्याय नहीं होगा तो फिर आप लोग कहोगे कि तालियां बजाओ, कोरोना की तरह थालियां बजाओ तो राजस्थान तालियां और थालियां नहीं बजायेगा। राजस्थान के साथ धोखा हुआ तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ई.आर.सी.पी. के सन्दर्भ में आप ही ने बोला कि तालियां बजाओ।

यह जो सोर्स है, इसके अन्दर हम कमियां कैसे दूर कर पायें? जहां अंडरग्राउंड वाटर है उसके सन्दर्भ में और आई.जी.एन.पी. के सन्दर्भ में, जोधपुर के अन्दर तो आई.जी.एन.पी. से वापस एक समानान्तर नहर आ चुकी है, लेकिन क्या आज समय नहीं आ चुका है कि इस आई.जी.एन.पी. के समानान्तर हम लोग नहर बनाकर राजस्थान में भविष्य के अन्दर पानी की कमी को दूर करें। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में भी हम लोगों को सामूहिक तौर पर चर्चा करके, विचार करके इसका फैसला करना चाहिए, क्योंकि स्थितियां ठीक नहीं हैं। पानी के सन्दर्भ में आई.जी.एन.पी. में किसानों की क्या स्थिति है, वह हम लोगों से छिपी हुई नहीं है। जैसलमेर के अन्दर हम लोगों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं। पेयजल में हम लोगों की क्या स्थिति है, वह भी आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। सरकार से मेरा यही निवेदन है।

बाबूसिंह जी राठौड़ ने बिजली के सन्दर्भ में बोला। बाबूसिंह जी राठौड़ के बिलकुल पड़ौस में मैं रहता हूं। बिजली के काम नहीं हुए। मेरे बायतू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर राजस्थान सरकार ने 40 हजार विद्युत कनेक्शन किये। कितने? 5 सालों के अन्दर 40 हजार विद्युत कनेक्शन किये। आप पड़ोसियों का ही ध्यान नहीं रख रहे हो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): कौनसी योजना में हुए?

श्री हरीश चौधरी (बायतू): योजना? योजना के सन्दर्भ में आप फिर? हमीर सिंह जी, हमीर सिंह जी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): मैं सभी बता रहा हूं। आप मुझे समय दिला दो।

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं माननीय सदस्य। समय हो गया। सम-अप करिये।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): बाड़मेर के पूर्व लोक सभा सदस्य की 100वें वर्ष की जयन्ती आप लोगों ने मनाई। मैं तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके विचार और विचारधारा के सन्दर्भ में आपने आयोजन किये हैं। आप लोगों ने यह बात भी कही क्षत्रिय संघ में हम राम के वंशज हैं। आपको गर्व है। हमारे पूर्वज शूद्र हैं। उन पर भी हमारे को फख्र है। यह जो व्यवस्था क्षत्रिय और शूद्र के सन्दर्भ में है, योगदान हम लोगों ने भी दिया है।

श्री अध्यक्ष: समय हो गया।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): हमारे पूर्वजों ने राजस्थान में संघर्ष किया है। भूमि अधिकार में संघर्ष किया है। राजस्थान के अन्दर कांग्रेस ने हम लोगों को भूमि स्वामित्व दिया, इस कारण हम लोग यहां खड़े हैं। जो संघर्ष और विचारधारा की बातें हैं, यह भी बात कही गयी मेरे जिले के निवासी और पड़ोस के, पोकरण विधान सभा क्षेत्र के विधायक महोदय ने कि राम कण-कण में हैं। हम तो दिन भर, दो-दो बार राम का नाम लेते हैं। राम-राम, राम-राम। नहीं लेते हैं क्या? आप अच्छी तरह से जानते हो। हमारे जिले के ही हैं, पर कबीर दास जी ने क्या कहा? कल आप यह संदेश दे रहे थे कि दशरथ पुत्र राम, कण-कण में राम, ऊर्जा के स्रोत राम।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 15 मिनट दिये थे। 15 मिनट हो गये।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): जिसकी परिकल्पना और व्याख्या नहीं कर सकते, वह राम।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हरीश जी, अयोध्या जा रहे हैं आपके बड़े नेता लोग?

श्री अध्यक्ष: आपका समय हो गया।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): अयोध्या तो चले जायेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अयोध्या तो जा ही नहीं रहे हैं आप लोग।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): आपके पूर्वज राम हो सकते हैं, पर हमारी आस्था भी उन राम जी में है। दो-दो बार बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप वरिष्ठ हैं। आपका समय हो गया। सम-अप करिये।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): गजेन्द्र सिंह जी, आपके पूर्वज हैं राम जी। हमारी आस्था के हैं। जायेंगे, आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिलाया। अगर आप मुझे निमंत्रण दिलाते...

श्री अध्यक्ष: चलिये।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): लेकिन राम जी की अयोध्या में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। हम जायेंगे। राम जी सिर्फ आपके नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: चलिये। श्री सुरेन्द्र सिंह जी राठौड़। आप शुरू करें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): राम जी तो वह हैं जो कबीर दास जी ने राम की व्याख्या की है। धन्यवाद। जय हिन्द। राम-राम सा।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, हमें समय कब मिलेगा?

श्री अध्यक्ष: आपका समय तय है। मुझे पता है, आप लिखकर भेज दीजिये। आप यहां हाउस में नहीं बोलेंगे। यहां नाम जिन निर्दलियों के आये हैं, उनको बुलाऊंगा। आपका नाम नहीं आया। आपने दिया ही नहीं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था है। आप लिखकर के भेजो।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। सोलहवीं विधान सभा के नव निर्वाचित सभी माननीय सदस्यों को मैं बहुतबहुत बधाई देता हूं।

सदन में इस पर चर्चा का आज तीसरा दिन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी माननीय सदस्य जो यहां बोला है, मैंने किसी को नहीं टोका है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे कोई टोकेगा नहीं। 22 जनवरी को 500

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

वर्षों का जो इंतजार था, वह समाप्त हुआ और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोतम रामलला के मन्दिर की प्रतिष्ठा, प्राण-प्रतिष्ठा हुई। केवल अयोध्या में ही नहीं, पूरे देश का हर गांव अयोध्या बन गया। हर मन्दिर पर, गांव में छोटे से बड़ा मन्दिर हो, सब जगह लोगों ने राम धुनी बोली। हनुमान चालीसा पढ़ी। मैं करीब 20 गांवों में गया हूं।

अध्यक्ष महोदय, 1992 में कारसेवा में जो गये थे, उनका सम्मान समारोह मन्दिर की चौपाल पर किया गया। उसमें आपकी विचारधारा के कार्यकर्ता भी थे। उनकी भी आंखों में से आंसू आ रहे थे कि हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे नेताओं ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया लेकिन हमें गांव की चौपाल पर आना पड़ता है। हमने उनका भी सम्मान किया कि आप चिंता मत करो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप लोग तो यह ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): आप बैठिए, बैठिए। मैं कभी नहीं बोलता हूं आपके बीच में।

श्री अध्यक्ष: आपका नाम मैं फिर नहीं बुलाऊंगा। फिर बोलने को आपको अनुमति नहीं होगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): मैं नहीं बोलता हूं बीच में। आप बोलोगे तब मैं सुनूंगा बहुत शांति से। आप बहुत वरिष्ठ हैं। आप बहुत सालों बाद आये हैं।

मैं इस मौके पर देश के प्रधान सेवक का, विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ताओं का, आर.एस.एस. का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो उन्होंने इस ऐतिहासिक आंदोलन में सक्रिय होकर काम किया है। यही नहीं अभी शून्यकाल में, माननीय सदस्य को पता था कि मुख्य मंत्री जी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, सदन में पधारने वाले हैं उसके पहले आपने यहां हल्ला मचाया कि ई.आर.सी.पी. का क्या होगा, जे.जे.एम. का क्या होगा? ई.आर.सी.पी. योजना में जब 13 जिलों के लिए यह योजना थी, सदन के नेता ने यहां पर घोषणा, उन्होंने यात्राएं निकालीं, रोजाना यात्राएं करते थे कि यदि केन्द्र सरकार हमें पैसा नहीं देगी तो राज्य सरकार अपने बलबूते पर इस योजना को पूरा करेगी, लेकिन आपकी गारंटी नहीं मानी जनता ने और मोदीजी जब यहां राजस्थान आए और उन्होंने जब

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

गारंटी दी कि हम इसमें कुछ संशोधन चाहते हैं, वह होने के बाद ही हम देंगे, लेकिन आप नहीं चाहते थे कि चुनाव के पहले इस योजना की घोषणा हो जाए। वोट बैंक के कारण आप दौड़ते रहे और यात्राएं करते रहे। आज आप यहां सवेरे पधार गए कि हंगामा करके इस माहौल को खराब किया जाए। मैं इस योजना को लाने के लिए आदरणीय सदन के नेता, आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा। अभी आप इंतजार करो, अभी तो दो महीने होने आए हैं, 58 महीने और बाकी हैं, अभी आप इंतजार करो, इंतजार करो, अभी और फैसले आएंगे। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनके हल्ला करने से रुकूंगा नहीं। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं।

सदन के नेता यहां विराजमान हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माही-जाखम परियोजना पर यहां कई बार मेजें थपथपाई गई हैं, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने जिस तरह से यह योजना मंजूर कराई है उसी तरह से माही-जाखम परियोजना उदयपुर-चित्तौड़गढ़-राजसमन्द की, 1,474 गांवों की पेयजल योजना है। इस योजना की जब यहां मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, डी.पी.आर. भी तैयार करवाई थी, लेकिन कुम्भलगढ़ के 70 गांवों को जानबूझकर निकाल दिया। क्यों हुआ यह? क्योंकि पिछले तीन चुनावों से लगातार वहां कांग्रेस हार रही थी। मेरा आपसे निवेदन है कि उन 70 गांवों के साथ न्याय हो, वे इस योजना से जुड़ें। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सरकार इस योजना को प्रारम्भ करेगी और पूरा भी करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से यहां पर सदन में पिछले पांच साल में कम से कम पांच बार मैंने यह बात रखी है कि कुम्भलगढ़ की बेड़च नाका परियोजना जो 2018 में स्वीकृत हुई डी.एम.एफ.टी. योजना में और 2019 में आकर आपने उसको निरस्त कर दिया। आपने देखा कि यह बेड़च नाका नहीं बनेगा तो यह विधायक चुनाव हार सकता है, लेकिन पहले से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत कर आया हूं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बेड़च नाका को सरकार स्वीकृत करेगी और इसका उद्घाटन भी करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे दस मिनट पूरे हो जाएंगे। पांच वर्ष तक आप लोग आपस में लड़ते रहे और अभी सुबह एक आरोप ओर लगाया था प्रश्न काल में कि विधायक को गायब कर दिया प्रश्न में। यह गायब करने की आदत तो आप लोगों की पड़ी

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

हुई है पिछले चार सालों से। पता ही नहीं चलता था कि कब सरकार होटलों में चली जाएगी। एक खेमा जाता था दिल्ली की तरफ तो दूसरा खेमा जाता था जैसलमेर की तरफ, चार साल लड़ते रहे, पांचवां साल आया तो घोषणाओं का अम्बार लगा दिया, लेकिन अब ध्यान रख लेना, जमाना चला गया है, तीस साल पहले का जमाना अलग था, जब गांवों में पोल डालकर वोट ले लेते थे। टंकी बनाकर वोट ले लेते थे। अब तो लोकतंत्र मजबूत हो गया है। नेताओं से ज्यादा जनता होशियार हो गई है। कितना भी प्रयास कर लो, चुनावी हथकण्डे कर लोगे चार साल, लेकिन यदि पांचवें साल में घोषणा कर दो तो जनता मानती नहीं है।

हमारी सरकार में भजन लाल जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद इसीलिए इतनी बड़ी-बडी घोषणाएं हो रही हैं, बड़ी-बड़ी योजनाओं को जल्दी हाथ में लो, पांचवें साल में सारी योजनाओं के उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूं, उसके बाद अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में रखें।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): सर, एक मिनट नहीं, दो मिनट।

आपको पता नहीं है कि सबसे ज्यादा नुकसान आपको क्यों हुआ और उधर क्यों गए आप? तुष्टीकरण की नीति के कारण गए हो आप। जुबेर खान जी, आप मेरे मित्र हो, सुन लेना।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं तो परमानेंट इधर ही हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): मैं तो चाहता हूं कि आप जीतते रहें, आप जब भी जीतते हैं तो आप 'ना पक्ष' में बैठते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुम्भलगढ़ में 23 सितम्बर, 2023 को केवड़ा कस्बे में मेवाड़ का गौरवमय धार्मिक परम्परागत गवरी नृत्य, वो गवरी नृत्य चल रहा था, एक समाज विशेष के लोगों का जुलूस उधर आया, कभी भी पिछले पचास साल में वो जुलूस उस रास्ते से नहीं गया, लेकिन सरकार होने की वजह से वहां दंगे कराने का प्रयास किया गया। यही नहीं, मैं इनकी तुष्टीकरण की नीति के बारे में और बताऊं, इनका जो उम्मीदवार था, एक दिन पहले वो ज्ञापन देकर आता है कि जो गलत बोला उसको गोली से उड़ा दो। दूसरे दिन जब हम गए ज्ञापन देने के लिए तो वहां पर आचार संहिता के एक घण्टे पहले सुरेन्द्र सिंह राठौड़ पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। क्या

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

सुरेन्द्र सिंह राठौड़ आपके मुकदमे से डर जाएगा? लेकिन जनता ने इसका जवाब दिया कि आपने जो तुष्टीकरण किया है उसका जवाब यह है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपसे एक बात और निवेदन करूंगा कि कुम्भलगढ़ के बारे में आप स्वयं जानते हैं, आप इतिहास के जानकार हैं, अजेय दुर्ग रहा है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गत 15वीं विधान सभा के कार्यकाल में पहली बार कुम्भलगढ़ के किले में इन्होंने अजान पढ़ने की परमिशन दी। आजादी के बाद कभी वहां पर अजान नहीं पढ़ी गई, आजादी के पहले कभी अजान नहीं पढ़ी गई थी, लेकिन इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण जनता ने आपको ठुकराया है। आपको बधाई कि आप वहीं विराजे रहेंगे अगले 25 साल तक। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर मेरी पार्टी ने और आपने दिया, उसके लिए हृदय के गहन तल से आभार।

राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद चल रहा है और उसी सन्दर्भ में मैं अपनी बात आपसे निवेदन कर रहा हूं। आपने राज्यपाल के अभिभाषण में पैरा नम्बर 20 में अनेक वादे किये हैं। उन वादों को मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, गरीबी उन्मूलन से लेकर सरकार का संकल्प एक वास्तविक संकल्प है जो राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। हमारी सरकार का हर गरीब को नि:शुल्क अन्न की गारंटी, हर सिर पर छत की गारंटी, हर घर में नल से जल की गारंटी, हर हाथ को काम की गारंटी, हर घर में बिजली की गारंटी, हर खेत को पानी की गारंटी। ये वादे किये हैं आपने। सम्भव हैं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हां।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): कतई सम्भव नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बिलकुल सम्भव है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 15 लाख रुपये का वादा प्रधान मंत्री जी ने किया था, वो नहीं हुआ। दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो नहीं हुआ। आपने तो इसके ठीक विपरीत, ठीक विपरीत यह काम करना तो दूर, लेकिन आपने अन्नपूर्णा पैकेट, जो गरीबों को जा रहे थे वे भी बंद कर दिये। बेरोजगारों को जो सौ दिन का भत्ता बकाया था, वह भी आपने देना बंद कर

(श्री हरिमोहन शर्मा)

दिया। इन्दिरा रसोई का नाम तो हटाया, लेकिन आपने वहां आने वाले गरीबों की संख्या भी मौखिक आदेश से आधी कर दी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मौखिक आदेश कहां से सुन लिया आपने?

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपने संख्या आधी कर दी। मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि यहां से फोन करके कहा गया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मौखिक आदेश का आपने कहा तो सदन के पटल पर प्रमाण रखिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप बैठिए। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप मुख्य मंत्री जी के सामने ज्यादा परीक्षा मत दें। वे जानते हैं, आप उनके वफादार हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई आपस में टोका-टोकी न करें। आप भी धीरे-से बोलेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप हर घर को छत देने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत जो मकान बने हैं, दो-ढाई साल से उनके पैसे भी नहीं पहुंच रहे हैं। पंचायती राज का पैसा पंचायतों में नहीं पहुंच रहा है। चिरंजीवी योजना का 25 लाख तक का लाभ भी आपने बंद कर दिया है। उसे भी बंद कर दिया है। आप उठा करके देख लीजिये, जा करके देख लीजिये। आप 5 लाख का झुनझुना पकड़ाकर 25 लाख की योजना को बंद करना चाहते हैं।

आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने मिनिस्टर्स को एक नयी सोच दी है, "टिफिन विद आफिसर्स।" मान्यवर, इसका मतलब क्या है? साथ बैठकर भोजन करें, साथ बैठकर खाएं। मैं इस मान्यता का हूं कि अगर कोई अधिकारी मंत्री के यहां अपनी योजना रखता है और मंत्री उससे असहमत है तो मंत्री को गम्भीरता से उस अफसर की आलोचना करके या अफसर के ठीक विपरीत अपनी टिप्पणी लिखनी चाहिये। यह समझौते की बात नहीं है, वरना मंत्री का अधिकार समाप्त हो जायेगा। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार की असत्य घोषणा करने की बजाय आप ऐसी घोषणा करें जो पूरी की जा सके।

अब मैं दूसरी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, रामराज्य की बात। रामराज्य की स्थापना की बात हो रही है, राम मन्दिर की बात हो रही

(श्री हरिमोहन शर्मा)

है, राम की मूर्ति पूजा की बात हो रही है, राम मन्दिर के बारे में अति उत्साह से बात हो रही है। राम जी की मूर्ति का अभी जो वहां पर हुआ, हम सब हृदय के गहन तल से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आपने राम का पेटेंट करवा लिया, आपने उसे अपना ट्रेडमार्क मान लिया और आप यह मानते हैं कि जब तक कोई मोदी जी का भक्त नहीं होगा, तब तक वह राम का भक्त नहीं होगा। आप मोदी जी के भक्त ही अपने आपको राम भक्त मान रहे हैं।

जो राम की बात करते हैं, राम की आराधना करते हैं, जिनके घट-घट में राम हैं, उन्हें आप सनातन धर्म से अलग कर एक नया रूप देकर, एक नयी योजना बनाकर, ट्रेडमार्क बनाकर राम का उपयोग न करें। मेरा आपसे निवेदन है, रामराज्य की मूल भावना, रामराज्य की जो मूल अवधारणा थी, आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी और जिन लोगों ने लड़ी, पं. जवाहर लाल नेहरू ने लड़ी और जब संविधान पीठ बनी, उस संविधान पीठ में केवल मात्र गांधी के दर्शन के आधार पर रामराज्य की स्थापना की बात की गयी है।

चैप्टर 3 पढ़ा आपने, कभी देखा किसी ने? कभी किसी ने सोचा कि संविधान में गांधी दर्शन के हिसाब से रामराज्य की स्थापना, इसलिए कि सबको समान अधिकार मिलें, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, उसे समान अधिकार मिलें। यह गांधी की सोच की अवधारणा है। संविधान सभा, जिसमें अल्संख्यक वर्ग के मौलाना अबुल कलाम आजाद, पं. जवाहर लाल नेहरू, अम्बेडकर, सब थे, उस चैप्टर 3 में, आपकी जानकारी में हो या न हो, उसी समय राम का, सीता का और लक्ष्मण का एक ओरिजिनल चित्र लगाया है।

रामराज्य की कल्पना आप नहीं कर रहे हैं, आपका तो योगदान ही नहीं था आजादी की लड़ाई में, आप क्या कल्पना करेंगे? रामराज्य की कल्पना महात्मा गांधी के दर्शन में की गयी है। रामराज्य की बात कर रहे हैं। राम मन्दिर की बात, अयोध्या की बात, आपके शाहनवाज खान साहब, जो आपके प्रवक्ता हैं, उनका आप भाषण सुनिये, उन्होंने क्या कहा, जिस समय वहां पर ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): रामराज्य की कल्पना राम जी से ली गयी है, गांधी जी के दर्शन से नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप पांच बार की विधायक हैं, बैठिए। आप बीच में मत टोकिये। आपको अपने भाषण में जो कहना था, वह कह दिया। आप विराजें। (व्यवधान) आप चिन्ता मत करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): रामराज्य की कल्पना का मूल स्रोत महात्मा गांधी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, मैंने आपको कहा था, आप मत टोकें, नहीं तो आपको भी टोकेंगे। (व्यवधान) कोई सदस्य किसी को न टोके। बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): राम को पेटेंट करा रखा है क्या? ट्रेडमार्क हैं क्या राम? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, बैठिए। माननीय सचेतक महोदय, उन्हें बैठाएं। बार-बार खड़े मत होइये, एक बार बहुत है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आदरणीय, आपको याद नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज खान ने 2022 में सार्वजनिक रूप से पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया और उसमें यह कहा कि जिस समय बाबरी मस्जिद में नमाज चल रही थी, उस समय के प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू थे, जिन्होंने वहां मूर्ति की स्थापना करायी। याद है आपको? आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, शाहनवाज खान। उनका स्टेटमेंट है कि उस समय का कोई दोषी आदमी है, जिसने राम के सम्बन्ध में कोई वाद-विवाद पैदा किया है अयोध्या में तो पं. जवाहर लाल नेहरू हैं। याद है आपको? याद है आपको कि दूरदर्शन पर रामायण का सीरियल किसने चालू किया था? याद है आपको? राजीव गांधी ने।

श्री अध्यक्ष: आप सम-अप करिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपको याद है कि वहां मन्दिर में दर्शन करने पर जो ताले लगे हुए थे, उन तालों को खुलवाकर दर्शन कराने का काम किसने किया? उनका नाम है राजीव गांधी। आपको याद है यह? (व्यवधान) क्या आपको याद है कि विश्व हिन्दू परिषद् को उस स्थान पर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका टाइम हो गया। आप सम-अप करिये। (व्यवधान) कोई भी सदस्य किसी के भाषण में टोका-टाकी न करे। कोई भी सदस्य दूसरे के भाषण में व्यवधान नहीं डाले। आप भी न डालें, ये भी न डालें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): क्या आपको याद है कि मन्दिर के दर्शन करवाने के लिए ताले किसने खुलवाये? क्या आपको याद है, शिलान्यास किसने करवाया? फर्जी राम भक्त बनकर आप राम का पेटेंट कराकर,...(व्यवधान) आप बैठ जाइये। सनातन धर्म का डिविजन करने वाले हैं आप लोग।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया आपका टाइम। एक मिनट ज्यादा हो गया।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नहीं, नहीं, यह मैं बोलूंगा साहब, आप नोट मत करना। क्यों नहीं बोलूंगा?

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी ने जितना समय दिया है, उतना दिया है मैंने। एक मिनट में समाप्त करिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आश्चर्य करेंगे आप। राम जन्म भूमि ट्रस्ट के जो सचिव थे, उन्हें यह कहते हुए शर्म नहीं आयी कि मोदी जी ईश्वर का, विष्णु का अवतार हैं। शर्म करें। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): काहे की शर्म करें। शर्म तो आपको आनी चाहिये। ख्याल करें अपनी उम्र का। यह कौन-सा विषय है, कौन-सा अभिभाषण है? इसे डिलीट करें।

श्री अध्यक्ष: इनका समय पूरा हुआ। श्री हरिसिंह रावत।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसे तुरन्त डिलीट कराया जाये।

श्री अध्यक्ष: सब विराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मोदी जी विष्णु का अवतार हैं क्या? कोई इन्सान ईश्वर हो सकता है क्या? मोदी जी ईश्वर का अवतार हैं? शर्म तो करो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): शर्म करो। राम को काल्पनिक बताने वालों, आज राम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): कोई भी व्यक्ति ईश्वर हो सकता है क्या? आप सब कह दो। मुख्य मंत्री जी से कहला दो कि हां, वे विष्णु के अवतार हैं। आपको शर्म भी नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय हरिसिंह जी खड़े हों, आप बोलें। अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आपका हो गया है। माननीय हरिसिंह रावत।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने 19 जनवरी, 2024 को अभिभाषण दिया, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। आपके सदस्य बोल रहे हैं। आपका हो गया है। अब अगली बार।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी ने जितना टाइम दिया है, उससे दो मिनट ज्यादा दिये हैं। इनका अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अध्याय और जुड़ गया। महोदय, 20 वर्षों से जो ईआरसीपी योजना....(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्ष: आप पुराने माननीय सदस्य हैं। आपका अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्ष: हरिसिंह जी, आप बोलिये। आप कन्टीन्यू रखिये। आपसे निवेदन कर रहा हूं, उनका बोलना शुरू हो गया है। मैंने अगला नाम पुकार लिया है, बैठिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको चुप कराइये।

मैं आज हमारे मुख्य मंत्री सम्माननीय भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने 20 साल से लम्बित ई.आर.सी.पी. योजना को लागू करवाया। राजस्थान में एक नया अध्याय शुरू हुआ।

अध्यक्ष महोदय, महामहिम के भाषण पर मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस भाषण में राजस्थान में जो जंगलराज था और रामराज्य की स्थापना की, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाये थे। कहा था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, भत्ता नहीं दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि दो लाख रुपये तक का हम कर्जा माफ करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप बोलेंगे और फिर दूसरे बोलेंगे तो फिर आपका भाषण भी नहीं होगा। इसलिए शान्ति से दोनों को अपने-अपने विचार रखने दीजिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): इनके +++ से कहा गया। +++ आप घोषणा और +++ ने घोषणा की। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, दो लाख की घोषणा माफ। शर्म करो, शर्म करो। जनता को गुमराह किया। फिर +++ गायब हो गया। +++ का पता ही नहीं चला, +++ कहां गया? राजस्थान की जनता +++ को ढूंढती रह गई।

श्री अध्यक्ष: कोई भी बैठे-बैठे नहीं बोलें, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): हरिसिंह जी, +++ कौन हैं?

(समय : 14.33 बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): +++ आप समझ ही गये होंगे। यह तो अंडरस्टूड है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। +++ तो एक ही नेता है, कौन है, आप खुद ही समझदार हो। ये वे ही हैं, जो स्टोव में कोयला डालते हैं और आलू से सोना बनाते हैं। अब तो आप समझ ही गये होंगे, +++ कौन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपना बोलना जारी रखें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का लालच दिया। किसानों को लालच दिया कि किसानों का दो लाख का कर्जा माफ करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसको +++ बना रहे हो क्या? अभी अभी एक +++ बाहर गये हैं, राजस्थान के, सदन से। अभी बाहर गये हैं।

श्री सभापति: ये अंकित नहीं होगा। इस तरह की भाषा सदन में उपयुक्त नहीं है। कृपया आप विराजिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): कर्जा तो माफ हुआ नहीं।

श्री सभापति: इसे हटाया जाये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, उनके साथ कुठाराघात किया गया। कर्जा तो माफ हुआ नहीं, लेकिन उन गरीबों के घर बिक गये। उनके खेत नीलाम हो गये, लेकिन उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। सभापति महोदय, इन्होंने तो भय, भूख, भ्रष्टाचार, आतंकवाद का एक ऐसा तांडव रचा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठिए। आपका नम्बर आयेगा, तब बोलियेगा। माननीय सदस्य, आपका भी क्रम से नम्बर आयेगा। आप बोलिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, दूसरी बात बताना चाहता हूं कि 19 बार पेपरलीक हुआ। इस सरकार ने गरीबों के साथ कुठाराघात किया। वे शायद इनको कभी माफ नहीं करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये और आप जारी रखिये। यह वाद-विवाद हो रहा है या क्या हो रहा है? एक सदस्य बोल रहे हैं, उन्हें आप भी बोलने दें। फिर वे बोलेंगे तो आप भी शान्ति से सुनिये और यदि कोई ऐसी बात लगती है तो वह वैसे ही अंकित नहीं होगी। इसलिए आप अपना बोलना जारी रखें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, इन्होंने भय, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, भू-माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया सब माफिया पैदा कर दिये। इनके माफियाओं के साथ ही साथ मुख्य मंत्री जी ने हर विधायक को बोला कि वहां का हर विधायक मुख्य मंत्री अशोक गहलोत है। इनको खुली छूट दे दी और ऐसी छूट दी कि आज राजस्थान की जनता त्राहि-त्राहि करने लगी। एक कहावत चरितार्थ होती है, बरबाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर डाल पे उल्लू बैठे हैं अंजाम ए गुलिस्तां क्या होगा। वह स्थिति इस सरकार ने कर दी थी।

सभापति महोदय, आप खुद समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, इनको मिर्ची क्यों लग रही, क्योंकि इन्होंने खुद ऐसे कर्म किये हैं। इसलिए इनको यह अहसास हो रहा है।

श्री सभापति: आप एक मिनट में समाप्त करिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, मैं शराब माफिया की बात कहना चाहता हूं। पूर्ववर्ती सरकार के नुमाइंदे, जो हमारे ई.ओ. हैं, सी.आई. हैं एक्साइज के, पी.ओ. हैं, आपको ध्यान होना चाहिए पूर्ववर्ती सरकार ने इनको बदला नहीं, उनका वही तंत्र लगा हुआ है। शराब माफियाओं से तार जुड़े हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, 26 जनवरी को ड्राई डे होता है। ड्राई डे के दिन उन्होंने खुलेआम शराब बेची। जब हमने शिकायत ई.ओ., पी.ओ. और सी.आई. को की, इनके जूं तक नहीं रेंगी और शराब की दुकानें चलती रहीं।

(श्री हरिसिंह रावत)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव है कि ड्राई डे होने के बावजूद भी शराब की दुकानें चलती हैं? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल एक्साइज ई.ओ., पी.ओ. और सी.आई. को सस्पेंड किया जाए। जब मैंने उनको एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए बोला तो बोले कि यह तो हमारी कार्यवाही में होता ही नहीं है। एक दुकान वैध है और उसके बाद दस-दस शराब की दुकानें चल रही हैं। ये पूर्ववर्ती सरकार के नुमाइंदे और ठेकेदार बैठे हुए हैं। उनका तत्काल लाइसेंस सस्पेंड करने को बोला, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के नुमाइदों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर तत्काल कार्यवाही की जाये।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल। आप विराजिये। आपका समय हो गया है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, अभी मेरा समय ही नहीं हुआ है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, अच्छा बोल रहे हैं, एक मिनट दे दीजिये। फिर मैं बोल लूंगा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, आपको ध्यान होना चाहिए, उदयपुर में एक कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था। मेरे भीम में उन हत्यारों को पकड़ा गया। पकड़ा गया तो कांग्रेस के नुमाइंदों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे विहि.प. के, संघ के, बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उनको ऐसी यातनाएं दीं जैसी जानवरों को भी नहीं दी जातीं। साठ लोगों को करीब तीन महीने तक जेल में बंद रखा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे निर्दोष व्यक्तियों को तत्काल छोड़ा जाये। उनके खिलाफ जो केस दायर किये गये हैं, उन्हें वापस लिया जाये। यह एक अशोभनीय घटना है। मैं समझता हूं कि हम हिन्दुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। जो इस तरह की घटना हमारे यहां होती है तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया। खाली हो-हुल्लड़ में मेरा समय पूरा करवा दिया।

श्री सभापति: वक्ता काफी सारे हैं। वक्ताओं की संख्या खूब है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि दूसरी जो हमारी सरकार की योजना है इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। हमारी सरकार ने एक योजना आयुष्मान भारत योजना लागू की, जिसमें पांच लाख रुपये तक का इलाज फ्री है। इसमें वह इंडिया के किसी भी कोने में जाकर इलाज करा सकता है और जो निवर्तमान सरकार है उसने केवल थोथी घोषणा करके और कोई काम किया नहीं, केवल लोगों को भ्रमित किया। दूसरा, उज्ज्वला योजना, सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने बोला था कि जो हजार रुपये था तो हम पांच सौ रुपये कम करेंगे उन्होंने कम नहीं किया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी को, जिन्होंने तत्काल घोषणा करके साढ़े चार सौ रुपये सिलेण्डर का किया, यह हमारे लिए बहुत बड़ी सराहनीय बात है और गरीब तबके को एक बहुत बड़ी राहत मिली है।

श्री सभापति: प्लीज विराजिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, मैं दो चीजें और कहना चाहता हूं एक प्रधानमंत्री आवास योजना और एक खाद्य सुरक्षा योजना।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय हो गया। समय से ज्यादा बुलवा दिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बाकी लिख कर दे दो आप।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, इनका जो पोर्टल बंद है उस पोर्टल को तत्काल प्रारम्भ किया जाये, ताकि जो हमारी योजना है वह आमजन तक जा सके और गरीब को कुछ राहत मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। 83 बिन्दुओं का जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय से पढ़वाया गया यहां पर, राज बदल गया, लेकिन रिवाज नहीं बदला। अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार में चल किसकी रही है। जो ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची आयी, जो कलेक्टर्स की सूची आयी, किसकी चल रही है? बिलकुल, राजस्थान की जनता यह जानना भी चाहती है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मेरा यह आग्रह है कि अभिभाषण पढ़ने से और सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। बहुत सी जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हैं। जिन मुद्दों को लेकर राजस्थान की जनता ने इन पर भरोसा किया, राजस्थान के नौजवानों ने भरोसा किया, किसानों ने भरोसा किया और पिछले 6 महीने के अन्दर जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ इन्होंने आन्दोलन किये सड़कों पर, चाहे पेपर लीक की घटनाएं थीं, दूसरी घटनाएं थीं, एक-एक करके मैं बिन्दुवार, सभापति महोदय, मुझे आप थोड़ा समय देंगे और मैं बिन्दुवार एक-एक बात पर आऊंगा।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो मेरे से पूर्व में सदन के वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी दोनों पक्षों ने, और अच्छी बहस हो रही है, लेकिन कई बार देखते हैं कि छोटा-मोटा आपस में वाद-विवाद भी चलता रहना चाहिये, ताकि यों लगे, हाउस में ऐसा नहीं लगना चाहिये कि कोई क्लास रूम में बैठे हैं, यह भी लगना चाहिये, लेकिन मैं कई बार देखता हूं कि जो लोग वरिष्ठ हैं मंत्री नहीं बने और वो अपनी उपस्थिति मुख्य मंत्री के सामने दर्ज कराना चाहते हैं, उनका माइक बंद कर दिया तो हमारा यह है कि एक बार, जैसे ही वो खड़े हों, माइक खोल दें तो नजर आ जायें कम से कम ताकि उनके मन की यह है न कि हम दिख गये सदन में, नहीं तो घर पर जाकर बतायेंगे क्या। पापा मंत्री तो नहीं बने, आप बोल भी नहीं पा रहे हो। यह भी एक प्रोब्लम है तो इसमें भी मेरा थोड़ा यह आग्रह है आपसे।

सभापति महोदय, एक मैं उदाहरण दूंगा इस सरकार का कि मुख्य मंत्री जी थाने में गये रात को यह बहुत अच्छी बात है। पुराने जमाने में भी राजा-महाराजा अकस्मात थाने चैक किया करते थे, पब्लिक के बीच जाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के होम सैक्रेटरी, राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी और डी.जी.पी. जयपुर में होते हुए भी, तीन घंटे तक मुख्य मंत्री थाने में रहते हैं। कमिश्नर जरूर जाते हैं, लेकिन उनका नहीं जाना इस ओर इंगित करता है कि वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। यह मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि मुख्य मंत्री इस बात को ध्यान से सुनें कि दुबारा से ऐसा मामला नहीं हो। गणतंत्र दिवस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के मध्य, यह सही है कि राजस्थान अपराध में एक नम्बर आ गया। यह कोई एक साल से नहीं आया, लगातार 2000 से लेकर 2023 तक तो शासन की व्यवस्था थी कि एक बार ये और एक बार ये। हम तो लड़ते ही रहे। बीच में रहे। 2013, 2018, 2023 दिल्ली गठबन्धन से गये, फिर भी आवश्यकता पड़ गई, छोड़कर सड़कों पर आ गये।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, राजस्थान जो हमारा एक प्रान्त है, विश्वविद्यालय में हम राजनीति करते थे तो 1995, 1996, 1997, 1998 का जमाना था जब बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर से जयपुर आते थे। राजस्थान विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा नाम था। हमारे अजमेर की मेयो देख लें, एम.जी.डी. देख लें, सोफिया देख लें, बच्चों को पढ़ाने आते थे, लेकिन दुर्भाग्य से अब लोग यहां आना नहीं चाहते। यह अपराध के अन्दर नम्बर एक राज्य हो गया। महिला उत्पीड़न के अन्दर नम्बर एक हो गया। दलितों के उत्पीड़न में नम्बर एक हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बतायें मुझे। एक बार ये आ गये, ये आपकी बात कर लेंगे, जनता परेशान होकर विकल्प नहीं मिलेगा, वापस वोट डाल देगी। ये लोग वापस आ जायेंगे। वह की वह बात हो जायेगी तो फिर राजस्थान की जनता क्या करे? यह मुझे बतायें।

सभापति महोदय, हमने तो प्रयास किया था, लेकिन दस लाख पर अटक गया मामला। पिछली बार साढ़े आठ लाख वोट आये थे और इस बार दस लाख वोट। मैं तो इस मामले में भी सौभाग्यशाली हूं कि राजस्थान में एक व्यक्ति ने पार्टी बना कर प्रयास किया। यह भी कम बात नहीं है। लड़ाई तो लड़ी किसी व्यक्ति ने। बिना उस गठबन्धन के वह लड़ाई लड़ी और प्रयास किया। सीटें हमारी तीन से जरूर एक आ गयी, लेकिन एक आ तो गयी। (व्यवधान) सुनो मेरी बात। लोक सभा के चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो नौजवानों की सबसे पसंदीदा पार्टी है वह जिधर रहेगी अगर आप ज्यादा करोगे तो आपका दिमाग ठीक कर देंगे, ये ज्यादा करेंगे तो इनका कर देंगे। यह तो तयशुदा बात है। आप छोड़ो इन बातों को, देखी है हमने लड़ाइयां। कई लोग पहली बार आये हैं उनको पता नहीं है। आपको तो पता ही नहीं कब पिछला गठबन्धन हुआ था और कब टूटा था। आपके आधे से ज्यादा तो दिल्ली में मेरे से मिलने का समय मांगते थे उस समय।

सभापति महोदय, मैं 26 जनवरी की आपको एक घटना बताऊंगा कि कड़ी सुरक्षा के बीच मध्य जयपुर शहर की कालवाड़ रोड पर बदमाश छात्रा को साठ फीट घसीट कर ले जाते हैं। दो दिन तक पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जाती है। बीकानेर जिले के नोखा थाने में खाकी को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया। एक बदमाश के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची युवती के साथ थाने में मौजूद पुलिसकर्मी बदसलूकी कर डालते हैं। दोनों घटनाओं का जिक्र समाचार पत्रों में हुआ है। ऐसा मैं सवाल इसलिये

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कर रहा हूं कि आपकी सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन तो किया, लेकिन जब मुख्य मंत्री द्वारा थाने के निरीक्षण के बाद थाने के ये हालात हैं तो यह गैंगवार संगठित अपराध को रोक पायेगी, यह बहुत बड़ा सवालिया निशान आपके ऊपर है। आप निश्चिन्त नहीं हो जायें कि 115 सीट्स आ गयीं। बहुत सी सीट्स पर कड़ा मुकाबला हुआ था, आप लोग ये भी सारी बातें जानते हैं। खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि 25 पूरा कर लेंगे। 25 पूरा करने में इस बार आपको बहुत जोर आयेगा।

सभापति महोदय, बिजली को लेकर जिस तरह विपक्ष ने यहां हल्ला मचाया, यह इनका काम है और सही बात है अभी बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन बिजली कम्पनियों की ऑडिट अगर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार कराती, आप कराते, किसान को चोर बताया जा रहा है कि किसान बिजली चोरी करता है। किसान बिजली चोरी नहीं करता। कम्पनियां जब से बनी हैं 2000 से और 2023 तक एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा घाटा बिजली कम्पनियों का हो गया। कहां से आया? खरीद में सरकार में ऊपर बैठे वो ही लोग तय करते हैं कि बिजली किस दर पर खरीदनी है, कब खरीदनी है। कभी कोयले की आपके यहां कमी आ गयी तो उसको लेकर, मुख्य मंत्री जी, शायद हमारे बिजली मंत्री जी गये भी थे, लेकिन मेरी आपसे मांग है कि सिंगल फेज बिजली चौबीस घंटे मिले और थ्री फेज बिजली, आपने जो सात घंटे घोषणा पत्र में कही थी कि रबी में 7 घंटे और खरीफ में 6 घंटे, यह पूरी बिजली आप सुनिश्चित करें, क्योंकि किसान के पास जहां नहरी इलाका है उस कोटा डिविजन को छोड़ दें और हनुमानगढ़ व गंगानगर को छोड़ दें तो बाकी राजस्थान में कुएं, ट्यूबवैल से ही लोग सिंचाई करते हैं। किसान के पास दूसरा कोई साधन नहीं है, जोत घट गयी है।

सभापति महोदय, मेरी यह मांग है बिजली के मामले में आप करें और वी.सी.आर., आप कम से कम यह करें कि बदले की भावना से जो काम कर रहे हों कि चुनाव में यह मेरे साथ नहीं था, इसका ट्रांसफार्मर उतार लो, इसकी वी.सी.आर. भर लो, यह बड़ा मन आप लोग रखेंगे तो मेरे हिसाब से सारा ठीक हो जायेगा।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक इस ओर दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने पिछली जो सरकार थी, इंटिग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को निजी हाथों में देने की तैयारी की थी उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विरोध

(श्री हनुमान बेनीवाल)

किया था कि ट्रेजरी, राजकोष और ई-ग्रास जैसी वित्तीय व्यवस्था चल रही थी उसे बदलने का जो प्रयास हुआ और सी.ए.जी के रडार पर था। भा.ज.पा. ने विपक्ष में रहते हुए इसका विरोध किया, लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि उसी सॉफ्टवेयर को, जिसका विरोध भा.ज.पा. ने किया, उसको भा.ज.पा. लागू कर रही है। ये मंत्री जी बैठे हैं यहां पर, मंत्री जी, गजेन्द्र सिंह जी, मैं कह रहा हूं कि जिसका विरोध पार्टी ने किया था, उसको लागू करने का शायद मानस बना रहे हैं तो आप एक बार कृपया इन चीजों को लागू नहीं करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो फिर वो ही बात हो गयी मिलाजुली का खेल हो गया। फिर दोहराना चाहता हूं कि सरकार बदली है, रिवाज नहीं बदला। मिलाजुली का खेल आप खतम करें।

सभापति महोदय, पैरा नं. 6 व 7 में आपने लिखा कि ये चुनावी यात्राएं, उन यात्राओं में प्रधान मंत्री की गारंटियों का जिक्र तो कर दिया, परन्तु राज्य का युवा, जो देश का कर्णधार है उनके साथ किये गये वादों पर आपकी सरकार का खरा उतरने का मन नहीं है, क्योंकि यदि मन होता तो विधान सभा चुनाव से पूर्व आपकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा आर.पी.एस.सी. को भंग करने की बात की थी, पिछले एक-डेढ़ साल में, मैं लोक सभा में था, आप यहां लड़ाई लड़ रहे थे, आपके कुछ नेता सड़कों पर लड़ रहे थे, डाक्टर साहब यहां नहीं हैं, वे लड़ाई लड़ रहे थे युवाओं की, आर.पी.एस.सी., माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, सारे पेपर लीक हो रहे थे और आपने यही कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आयेंगे, सी.बी.आई. जांच करायेंगे। यह मामला राजस्थान की विधान सभा में मेरा पहला सवाल था उसमें भी उठा था, लेकिन सी.बी.आई. जांच की कहीं बात नहीं आयी। आपने एस.आई.टी. का गठन कर दिया। एस.ओ.जी. से जांच करा रहे हो, लेकिन जिनको एस.ओ.जी. का चेयरमैन आपने बनाया है, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वे तो खुद आर.पी.एस.सी. चेयरमैन के यहां करीब-करीब जगह, इंटरव्यू लेकर खुद आये हैं और आर.पी.एस.सी. के अन्दर जो चेयरमैन हैं, वे मुख्य मंत्री के नजदीकी थे पहले और वे तो कह रहे हैं कि सारे लोगों के ट्रांसफर, पोस्टिंग मैंने की, मेरा कोई क्या कर लेगा, इसलिये हम मांग कर रहे हैं कि जितनी भी पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं आप उदाहरण के तौर पर दो-तीन घटनाओं की सी.बी.आई. जांच करा लें। इससे मछलियां तो आप पकड़ रहे हो, लेकिन बड़े मगरमच्छ तभी पकड़े जायेंगे जब सी.बी.आई. की एंट्री होगी।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, ई.डी. की एंट्री आप करा रहे हो, लेकिन ई.डी. की एंट्री आप कहां करा रहे हो? आपको लगता है कि कोई ज्यादा बोल रहा है तो उसके यहां ई.डी. भेज दो। देखो ई.डी. या तो भेजो मत और ई.डी. भेज कर किसी को बदनाम कर रहे हो तो फिर सबूत के साथ गिरफ्तारी भी होनी चाहिये। यह मजाक नहीं कि हम चाहे जिसकी मजाक उड़ा लें, ई.डी., सी.बी.आई. भेज दें और फिर क्लीन-चिट दे दें। एक बार आदमी अगर बदनाम हो जाता है, जैसे मैंने देखा, हमारे कटारिया जी गृह मंत्री थे, एक सवाल था कि हिस्ट्रीशीटर कितने हैं? इसमें भा.ज.पा. के एक विधायक का नाम आ गया, उनका पुराना इतिहास था। एक आदमी एच.एस. बन जाता है तो वह फिर कितना ही कुछ कर ले, उसका नाम रिकार्ड में आ जाता है। आप कृपया ई.डी., सी.बी.आई. का दुरुपयोग न करें, यह मेरी आपसे मांग है। आपको लगे कि वास्तव में जल जीवन मिशन में लाखों-अरबों रुपयों का घोटाला हुआ है, लेकिन घोटाला करने वालों को तो आपने सरकार में ओ.एस.डी. लगा दिया, फिर कैसे जांच करोगे? क्या फर्क रह जायेगा आप में और हम में? क्या फर्क रह जायेगा आप में और इस सरकार में?

हां, ठीक है, राम मन्दिर का आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया, हम बधाई देते हैं। राम मन्दिर के ये लोग भी पक्ष में हैं, अगर ये लोग कोई विरोध की बात करते हैं तो गलत है। गांव में हम तो राम-राम ही करते हैं। बी.जे.पी. का गठन तो 1980 में हुआ था, 1980 से पहले भी लोग राम-राम ही करते थे। (व्यवधान) मैं आपके साथ रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखो। शंकर सिंह जी, रुको आप। आपको मंत्री तो बनाया नहीं, बैठे-बैठे बोल रहे हो आप। मैं यह कह रहा हूं, साहब, राम मन्दिर का निर्माण किया, अच्छी बात है। होना तो उसमें यह चाहिये था कि जिस तरह लोक सभा चालू होने से पहले प्रधान मंत्री जी सर्वदलीय बैठक करते हैं, उसी तरह सर्वदलीय बैठक करके आप सारी पार्टियों के नेताओं को बुलाते, यह आपको करना चाहिये था, तभी लोग जाते। अब आप कह रहे हो कि आप नहीं गये। जायें कहां, वहां कोई धक्के थोड़े ही खाने थे, अन्दर कौन घुसने देता, बताओ मुझे? मेरा कहना है कि राम जी के नाम से इस देश में कोई परहेज नहीं है। (व्यवधान) नहीं, इनको बिलकुल नहीं है, यह तो राम नाम से ही यहां तक आये हैं। मैं जानता हूं डोटासरा जी को, हम तो सब गांव के लोग हैं और हमारे तो पहले राम-राम ही कहते हैं। कुछ कांग्रेस के लोग अगर इस तरह की मानसिकता के साथ बात करें कि हम राम मन्दिर का विरोध करते हैं, वह भी गलत है। हमें तो यह भी याद है और

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आपको भी नहीं भूलना चाहिये कि जब बाबरी मस्जिद गिराई थी, उस समय आपके प्रधान मंत्री नहीं थे, इनके प्रधान मंत्री थे जो गोली लेकर सो गये थे। दुबारा गोली नहीं चली, यह भी ध्यान रखना चाहिये आपको। उनका भी योगदान है, नरसिम्हाराव जी का योगदान है कि 2-4 बजे सो गये और आपने अपना काम कर दिया। (समय-समाप्ति- सूचक घंटी।) एक मिनट में समाप्त करूंगा।

बिन्दु संख्या 31, 32, 33, 34 में जो भी घोटाले हुए, उनकी जांच कराने की आपने बात की। बिन्दु संख्या 33 में युवाओं में हताशा और अवसाद के कारण आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों में चिंता आपने जाहिर की। चिंता तो जाहिर कर दी, लेकिन उसको रोकोगे कैसे, उसके बारे में भी आपको विचार करना होगा। आपके दल ने और इन्होंने अपने चहेतों को आर.पी.एस.सी. का मैम्बर बनाया, चेयरमैन बनाया। मेरी मांग है कि आर.पी.एस.सी. को भंग करके इसका पुनर्गठन करें और यू.पी.एस.सी. की तर्ज पर जो राजस्थान की आर.पी.एस.सी. का भरोसा था, वह भरोसा पूरे देश में वापस कैसे स्थापित हो, इस दिशा में आपको काम करना होगा।

युवाओं का जिक्र आया, मैं एक मांग करना चाहूंगा। मैं केन्द्र में था, किसान बिल के मामले में मैं एन.डी.ए. से अलग हो गया, लेकिन फिर आप अग्निवीर लेकर आये। किसान बिल आपने वापस ले लिये, किसानों ने बड़ा आंदोलन किया। अग्निवीर के मामले में मेरी मांग है कि राजस्थान के हमारे शेखावाटी अंचल, मारवाड़ अंचल से, पूरे राजस्थान से आजादी से पहले आजाद हिन्द फौज में भी शेखावाटी के जवान थे। 1962, 1965, 1971 व कारगिल की लड़ाइयों में और आज भी पैरामिलिट्री फोर्स में हमारे जवानों ने बड़ी शहादत दी। मेरी मांग रहेगी कि आपकी दिल्ली में सरकार है, आप लोग मांग करें, हम भी मांग कर रहे हैं कि बिना बड़े आंदोलन के, आंदोलन पहले हुआ था, युवा भटक गये थे, ट्रेनों में आग भी लगाई थी, हमने भी अग्निवीर के विरोध में आंदोलन किया है। मेरी मांग है कि चार साल वाले अग्निवीर को बंद करके पूर्व की भांति सेना भर्ती चालू करें। यह दिल्ली में आप बात कहेंगे तो निश्चित रूप से लोक सभा का चुनाव है...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट में कन्क्लूड करें, प्लीज।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं कर रहा हूं।

आपने सरकार में आते ही कहा कि सी.बी.आई. के अनुसंधान का आदेश हमने वापस ले लिया। सी.बी.आई. का अनुसंधान तब ही होता है जब

(श्री हनुमान बेनीवाल)
या तो स्टेट गवर्नमेंट अनुशंसा करती है या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को दिल्ली को देता है। कांग्रेस सरकार ने बंगाल के बाद यहां रोक लगाई थी कि जयपुर में जो सारे के सारे दिल्ली के महकमे हैं, उन पर सी.बी.आई. जांच हमारी अनुशंसा के बिना नहीं करेगी। वह तो आपने वापस ले लिया, लेकिन उसके वापस लेने से भ्रामक प्रचार हो गया, जनता में यह मैसेज चल गया कि सी.बी.आई. पेपर लीक के मामलों में खुद क्यों नहीं आ रही है? सी.बी.आई. खुद नहीं आयेगी। आप अनुशंसा करें और कुछ मामले, जो वहां पड़े हुए हैं, जैसे आपका मनोहर राजपुरोहित का एक मामला सी.बी.आई. के पास पेंडिंग है। सरकार ने दिया तो था, लेकिन अभी तक उसकी जांच नहीं हुई। लवली कंडारा फर्जी एनकाउंटर के मामले में मैंने भी आंदोलन किया था। वह स्टेट गवर्नमेंट ने दिल्ली भेज दिया, लेकिन जांच नहीं हुई।

बिन्दु संख्या 39 में आपने महिला उत्पीड़न की बात कही। यह सही है पांच सालों में राज्य में महिला उत्पीड़न के इतने मामले सामने आये कि राजस्थान को शर्मसार होना पड़ा। इसमें मेरी इतनी ही मांग है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत दें। बिन्दु संख्या 47 में यह कहा गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा राजनीतिक कार्य नहीं।

श्री सभापति: आपका समय हो गया, प्लीज।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट में कर रहा हूं।

आप यूनिवर्सिटी, कालेज से निकले हैं, थोड़ा ध्यान रखें। मेरा कहना है कि अभी बी.जे.पी. जो केन्द्र की योजनाओं के कैम्प लगा रही है, वहां पर कम से कम इतना तो कहें कि कैम्प में सम्बन्धित विधायक को बुलाएं। आप बुलाते नहीं हैं। लिखित में शायद आपके पास भी कागज नहीं आया होगा, हमारे पास भी नहीं आया। (व्यवधान) हमें जाना नहीं, जायेंगे थोड़े ही.... (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव 2004 में बंद हुए थे, जब आपकी सरकार थी। 2009 में हम जीत कर आए, आप भी थे, हमने यहां पर धरना दिया। मुख्य मंत्री जी ने सदन में घोषणा की और 2010 में वापस चालू हुए। फिर वसुन्धरा जी की सरकार में

(श्री हनुमान बेनीवाल)

छात्र संघ चुनाव बंद करा दिये, फिर वापस चालू हुए। पिछली बार आपने राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव बंद कराये और मैंने एक महीने तक बड़ा आंदोलन किया। 8 रैलियां कीं, यहां भी रैली की। मैं कह रहा हूं कि सरकार को छात्र संघ चुनाव चालू कराने चाहिये। छात्र संघों के माध्यम से....(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, बहुत धन्यवाद। श्री हरीश चन्द्र मीना (अनुपस्थित)।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): छात्र संघ चुनाव की घोषणा करनी चाहिये। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री अभिमन्यु।

श्री अभिमन्यु (संगरिया): सभापति महोदय, केन्द्र की सरकार को 8 वर्ष से ज्यादा हो गये और अभी दुबारा देश में लोकतंत्र के चुनाव होने जा रहे हैं। देश के प्रधान मंत्री जी ने जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 15 लाख रुपये खातों में डलवाने का जो वादा किया, आज तक रोजगार के नाम पर 20 लाख से ज्यादा रोजगार केन्द्र सरकार नहीं दे पाई है। घोषणा कर युवाओं को ठगा गया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसानों के लिए जो घोषणा की कि हम 2,700 रुपये गेहूं पर एम.एस.पी. देंगे, मात्र 2,275 से 2,400 रुपये करके आपने किसानों के साथ कुठाराघात किया है। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों और जवानों ने राजस्थान को सींचा है, किसानों और जवानों के मुद्दे पर राज्य सरकार को गम्भीर होना पड़ेगा। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में 10 हजार क्यूसेक पानी आना चाहिये, क्योंकि जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं निर्वाचित होकर आया हूं, वह किसान बहुल क्षेत्र है। वहां पर आई.जी.एन.पी. से 7,500 क्यूसेक पानी आता है, जो कि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। 6 घंटे बिजली के नाम पर जो बिजली दी जाती है, उसको बढ़ाया जाये। भाखड़ा नहर में हर बार 1,200 क्यूसेक पानी के नाम पर राजस्थान को पानी दिया जाता है, लेकिन एक बार भी पूरा पानी नहीं दिया जाता। वह क्षेत्र हरियाणा-पंजाब बोर्डर क्षेत्र है, पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है। वहां पर बड़ी संख्या में सफेद पाउडर के नाम पर, चिट्टे के नाम पर वहां के नौजवान साथी उसमें लिप्त हैं। कहीं न कहीं प्रशासन की गम्भीरता नहीं रहती और खुलेआम नशे का व्यापार किया जाता है। अभी पिछले 40 दिन से एक गांव में खुलेआम नशा बेच रहे हैं, लेकिन प्रशासन गम्भीर नहीं है।

हमारी मीरा शिक्षा समिति का सरकारीकरण कांग्रेस की सरकार में बार-

(श्री अभिमन्यु)

बार हुआ। जैसे ही सरकार बदलती है, उसका सरकारीकरण रद्द किया जाता है। महिलाओं का सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के नाते मैं आपसे कहूंगा कि उसके सरकारीकरण पर आप गम्भीरता से विचार करें।

(समय: 15.00 बजे)

सहकारी समितियां, जो कि गांव की सोसाइटी कही जाती हैं, किसान साथी उसके अन्दर अपने रुपये जमा करवाते हैं, अपनी दिनचर्या सोसाइटी से चलाते हैं। पूरे विधान सभा क्षेत्र में दस गांव हैं, दस पंचायतों के अन्दर सौ करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार कभी भी सोसाइटी पर गम्भीर नहीं रहती है। आपसे, राज्य सरकार, मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पांच हजार युवा साथी, युवा मित्र 50 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं, उनकी तरफ आप सोचने का काम करें। राजीव गांधी नहीं, आप अटल जी का नाम कर दीजिये, लेकिन उनको रोजगार दीजिये। कहीं न कहीं उनके रोजगार की व्यवस्था करने का काम करें। फार्मासिस्ट, ओ.पी.डी. के नाम पर संगरिया और टीबी के जो अस्पताल हैं, सर्जन नहीं हैं, डाक्टर नहीं है, ओ.पी.डी. की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी के अंगुली पर चोट आ जाती है तो उसको तीस किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ में भर्ती होने के लिए भेजना पड़ता है। ऐसी अव्यवस्था है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते, संगरिया और टीबी में, आपसे और सरकार से उम्मीद भी रखता हूं कि हास्पिटल को सुधारने का काम, युवाओं को नशे से सुधारने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे।

हमारे साथी यूथ कांग्रेस से निकलकर, सीनियर साथी आज भा.ज.पा. से विधायक बने हैं। सुभाष मील जी ने कहा कि पार्टी खतम हो जायेगी, कांग्रेस खतम हो जायेगी। आप भी यूथ कांग्रेस से निकलकर, पिछली बार कांग्रेस ने टिकट दी, चुनाव हारे। इस बार आप जरूर दूसरी विचारधारा में चले गये, आपका किसी व्यक्ति से वाद-विवाद हो सकता है, लेकिन पार्टी और राहुल गांधी जी की सोच है, तभी जाकर आप आज भा.ज.पा. में विधायक बने हैं। दिल्ली से जो पर्ची आयी और युवाओं को हटाना, युवाओं को रोजगार नहीं देना, रोजगार दो, न्याय दो। हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री अभिमन्यु (संगरिया): हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार और न्याय देने पर काम करने का काम करें।

श्री सभापति: श्री संजीव कुमार।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): साहब, हमारा नम्बर आयेगा या नहीं आयेगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। नम्बर आयेगा, आपसे जरूर बुलवायेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, इनकी पर्ची भी खुलवा दें। पर्ची आयेगी तभी तो नम्बर आयेगा।

श्री सभापति: आप बोलिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। 19 जनवरी, 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। अभिभाषण के माध्यम से कई बिन्दुओं पर इसमें चर्चा की गयी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 5 बजे का समय दिया था कि ई.आर.सी.पी. पर 5 बजे व्यवस्था देंगे। 5 बजकर 3 मिनट हो गये, व्यवस्था दे दीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभी 3 बजकर 3 मिनट हुए हैं। आप विराजें।

एक माननीय सदस्य: अभी 3 बजे हैं। क्या आप नींद में हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं दिमाग टेस्ट कर रहा हूं। क्या आपके तकलीफ है? चेयर का दिमाग टेस्ट कर रहा हूं। क्या आपके दिक्कत है?

श्री सभापति: डोटासरा साहब, समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जायेगी।

श्री संजीव कुमार (भादरा): बिन्दु संख्या 27 पर किसान कर्जा माफी का जिक्र किया गया। 2018 के चुनाव के समय कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने नहीं, बल्कि इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर पधारकर चुनावी सभा के माध्यम से और वह भी हमारे हनुमानगढ़ में आकर यह बात कही थी। 1 से 10 तक की गिनती गिनकर उन्होंने कहा कि 10 दिन के अन्दर-अन्दर किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन कहते हुए तकलीफ है कि पूरे 10 दिन निकल गये, 5 साल भी

(श्री संजीव कुमार)

निकल गये। इनके कार्यकाल के दौरान पूरे पांच साल में राजस्थान प्रदेश का किसान कर्जा माफी के लिए तरस गया और एक तरह से कर्जा माफी के स्थान पर 19 हजार से ज्यादा लोगों की जमीनें उसमें कुर्क हुईं उसमें नीलाम हुईं। राजस्थान प्रदेश में कई स्थानों पर आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह स्थिति पूरे पांच साल के दौरान इनके शासन में रही।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ बिन्दु संख्या 31 में युवाओं का भी जिक्र किया गया है। निश्चित रूप से जो वादा बेरोजगार युवाओं के साथ इन लोगों ने किया कि बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम, बनने वाली सरकार करेगी, लेकिन पूरे कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी भत्ता देने की बात दूर रही, प्रतियोगी परीक्षाओं के लगातार पेपर लीक होते रहे। पेपर लीक माफिया सक्रिय रहे और परीक्षाओं की पारदर्शिता समाप्त होती गयी। युवाओं का भविष्य एक प्रकार से अंधकारमय बनाने का काम इन लोगों ने किया। पेपर लीक का बार-बार जिक्र हम लोग यहां करते हैं। लीक का जहां तक सवाल है, एक तो होता है कि पाइप से पानी लीक हो गया, किसी ट्यूब से कोई हवा लीक हो गयी, प्रेशर लीक हो गया। साहब, इसमें लीक का सवाल क्या है, यह तो निश्चित तौर से पेपरों पर डाका डालने का काम, चोरी करने का काम पूरे पांच साल के कार्यकाल के दौरान इन लोगों ने किया है।

पूरे देश भर में आर.पी.एस.सी. का एक बड़ा नाम था। पूरे देश में इस तरह की चर्चाएं होती थीं कि राजस्थान प्रदेश में जो प्रतियोगी परीक्षाए होती हैं, आर.पी.एस.सी. की जो परीक्षाएं होती हैं, वे साफ-सुथरी होती हैं। परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है, लेकिन निश्चित रूप से इनके शासन के दौरान इन लोगों ने आर.पी.एस.सी. जैसी संस्था को दागदार करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से पांच साल के कार्यकाल के दौरान ये लोग आपस में लड़ते रहे और इनकी खींचतान की वजह से शासन की गाड़ी लगातार बेपटरी होती गयी। कई बार इनको पांच सितारा होटलों में बैठकर फैसले लेने पड़े।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आगाज करके एक बहुत बड़ी योजना इस देश के किसानों को दी थी। निश्चित रूप से पूरे देश के किसानों को इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ, बीमा क्लैम का लाभ मिलना शुरू हुआ। निश्चित तौर से राजस्थान प्रदेश की पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान इनकी किसान विरोधी नीतियों के चलते

(श्री संजीव कुमार)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक बड़ी भारी बाधा उत्पन्न करने का काम इन लोगों ने किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जिले के अन्दर, हमारे भादरा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों ने जगह-जगह आन्दोलन इनके कार्यकाल के दौरान किये, जगह-जगह धरना-प्रदर्शन करने के लिए किसानों को मजबूर होना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो बीमा क्लैम, जोकि क्रॉप कटिंग के आधार पर दिया जाता था, उस बीमा क्लैम को सैटेलाइट के आधार पर इसलिए दिया गया, क्योंकि सरकार में बैठे लोगों ने बीमा कम्पनी से सांठ-गांठ कर ली, बीमा कम्पनी मिलीभगत कर ली और बीमा कम्पनी से मिलीभगत की वजह से निश्चित रूप से जो बीमा क्लैम किसान को क्रॉप कटिंग से दिया जाना चाहिए था, उसको सैटेलाइट के आधार पर दिलाकर इन लोगों ने पांच साल तक राजस्थान प्रदेश के किसान का, हमारे क्षेत्र के किसान का गला काटने का काम किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शीघ्र समाप्त करें।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, बोलना शुरू ही किया है और आप कहते हो, समाप्त करो।

श्री सभापति: जो समय इसमें अंकित है, उतना ही समय मिल पाएगा।

श्री संजीव कुमार (भादरा): बीच में माननीय सदस्य ने डिस्टर्ब करके कुछ समय इन्होंने भी ले लिया।

श्री सभापति: वक्ता बहुत हैं।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने, हर घर को शुद्ध पानी दिया जाए, नल के द्वारा जोड़ा जाए, एक तरह से उन्होंने जल जीवन मिशन योजना का आगाज किया है। पिछली राजस्थान प्रदेश की जन विरोधी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना में भी बड़ी भारी बाधा उत्पन्न करने का काम किया। जल जीवन मिशन योजना में पिछली राजस्थान सरकार के कार्यकाल के दौरान जगह-जगह जमकर भ्रष्टाचार हुआ। अमानक और घटिया सामग्री का उसमें इस्तेमाल किया गया। विशेषकर हमारे ज़िले में, हमारे क्षेत्र

(श्री संजीव कुमार)

में, गांव-ढाणियों में जल कनेक्शन दिये जाने थे, उनमें भेदभाव करने का काम, बड़ी भारी अनियमितता करने का काम इन्होंने किया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान आक्या।

श्री संजीव कुमार (भादरा): इनकी जन विरोधी नीतियों की वजह से... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री संजीव कुमार (भादरा): रैकिंग के आधार पर भी...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री संजीव कुमार (भादरा): 000

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): साहब, एक काम करो, दो मिनट इनको बुला दो। इनका एक शेर है, वह बुला दो।

श्री सभापति: आपके बाद बुला लेंगे, पहले आप बोलिए। इनके बाद बाबा बोलेंगे फिर आप बोल लेना। मैं बताना चाह रहा हूं, वक्ता काफी संख्या में हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष के सचेतक ने जो समय दिया है, उसी समय में अपनी बात रखें। (व्यवधान) अपन कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहने का प्रयास करें, क्योंकि बोलने वाले वक्ता अधिक हैं। श्री चन्द्रभान आक्या।

श्री संजीव कुमार (भादरा): 000

श्री सभापति: मैंने आपको आठ मिनट की बजाय दस मिनट बुलवा दिया। आपके सचेतक जी द्वारा यहां आपका समय आठ मिनट लिखा हुआ है। आठ मिनट में ही अपने को अपनी बात पूरी करनी है।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये मंत्री लोग यहां चर्चा कर रहे हैं, अगर अपने चैम्बर में करें तो अच्छा रहेगा। यहां चैम्बर नहीं है, दिलावर साहब, गजेन्द्र जी साहब।

सभापति महोदय, जब अपन विपक्ष थे तो काफी धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, रोज हो-हल्ला करते थे। आज वही वादे, वही चीज़ें। मंत्री महोदय, दिलावर साहब, बात सुन लीजिए। आपके काम की बात है, आपके काम आएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन की ओर देखकर बोलिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, हर चीज के लिए अपन धरना प्रदर्शन करते थे, ज्ञापन देते थे। पांच साल तक धरना, ज्ञापन, सब कुछ किया। सबसे बड़ा मुद्दा डीजल व पेट्रोल का है, वेट कम करने का मामला है। राजस्थान में महंगाई काफी छू गई है। जब कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने से वादा किया था कि सरकार बनेगी हम वेट कम करेंगे, दूसरे राज्यों के बराबर डीजल पेट्रोल की रेट रहेगी, इसलिए वेट कम करें। राजस्थान में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तब घटेगी जब हम डीजल व पेट्रोल का वेट कम करेंगे, तो डीजल व पेट्रोल का वेट कम करें।

सभापति महोदय, 450 रुपये में सिलेण्डर चयनित को दिया जा रहा है, इसलिए 450 रुपये में सरकार सब्सिडी दे, केन्द्र सरकार दे, राज्य सरकार दे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। सभी को 450 रुपये में सिलेण्डर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग भी काफी कमजोर है, इसके बारे में भी चर्चा करे। मंत्री महोदय बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माइनिंग की फ्लाइंग चल रही है। सरकार का 10-15 दिन का अभियान था, उसमें कोई बड़ा आदमी नहीं मर रहा है, छोटे-मोटे ट्रैक्टर-डम्पर वाले, जो किसान लोग हैं, वे मर रहे हैं। इसमें बड़ी मछली नहीं मरने वाली, छोटी-छोटी मछलियों का हनन हो रहा है, इसलिए आप माइनिंग पर भी ध्यान दें। दिलावर साहब, गजेन्द्र जी साहब यहां विराज रहे हैं, सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं, इस माइनिंग अभियान को आप खतम करें। ऐसा अभियान चालू करें कि बड़े हाथियों को मारें, छोटे-छोटे आदमी नहीं मरें। छोटे-छोटे ट्रैक्टरों के लिए दो-दो ढाई-ढाई रुपये लग रहे हैं। इस प्रकार का अभियान चलाने से पहले देखें, छोटे आदमियों को, किसानों को नहीं मारें, आप इस प्रकार की चर्चा करें।

अस्पतालों में डाक्टर्स की काफी कमी है। मेरे वहां 4-5 सी.एच.सी. हैं। वहां एक भी डाक्टर नहीं है। आपने ए.पी.ओ. कर रखे हों, इधर-उधर कहीं पड़े हों, ऐसी कोई चीज हो, इसलिए मेरे वहां भर दें तो अच्छा रहेगा। अभी उप मुख्य मंत्री विराज रहे थे। कल परिवहन विभाग का वीडियो भी आया। भास्कर में बढ़-चढ़कर आया, परिवहन विभाग की जहां-जहां भी गाड़ियां खड़ी हैं, प्राइवेट लोग उसमें गाड़ी रखकर, ट्रकों से 500-1000 रुपये वसूल कर रहे हैं। मैं चित्तौड़ की बात करता हूं, मैं वीडियो सहित आपको प्रूफ कर दूंगा। मंत्री

(श्री चन्द्रभान सिंह चौहान)

महोदय, इस बात पर ध्यान दें, परिवहन विभाग में उडन दस्ते हैं, अवैध वसूली के नाम पर कैसे न कैसे इन पर लगाम लगाई जाए, चाहे परिवहन विभाग के अन्दर लाइसेंस बनाने का हो। इस प्रकार से पैसे की लूट-खसोट हो रही है। उस पर आप अंकुश लगाने की कोशिश करें, वरना आने वाले दिनों में सरकार की बहुत बदनामी होगी। उप मुख्य मंत्री बैरवा जी के पास यह है। यह भास्कर ने उजागर किया है, आने वाले दिनों में इसको देखें। नेशनल हाईवे भीलवाड़ा बाईपास पर आप निकले हो तो बैरिकेड लगाकर लूट-खसोट कर रहे हैं, इस बारे में आप सोचें, चित्तौड़ के बारे में सोचें।

सभापति महोदय, यू.आई.टी. में, नगरपालिका में रिटायर्ड कर्मचारी व अधिकारी थे, उनको हटा दिया। कोई बात नहीं अच्छा काम किया है, पर यू.आई.टी. व नगरपालिका में आज काम बंद से हो गए हैं। आप कैसे भी वहां अधिकारियों व कर्मचारियों की व्यवस्था करवाएं। यू.आई.टी., नगरपालिकाओं के सभी काम बंद पड़े हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए व्यवस्था करके वापस यू.आई.टी. व नगरपालिकाओं के काम चालू करवाएं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) साहब, ऐसे मत करो।

श्री सभापति: समय की सीमा है।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय, बिजली की वी.सी.आर. भरी जा रही है। मेरा आज क्वेश्चन भी था, पर मैं बोल नहीं पाया। बिजली मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वी.सी.आर. के टार्गेट नहीं दें। बिजली की कमी है। छीजत को रोकने के लिए दूसरे उपयोग हो सकते हैं, इसलिए दूसरे उपयोग से रोकें। छोटे-छोटे किसान हैं, उनके घरों की वी.सी.आर. 40 हजार, 50 हजार, 01 लाख भर देते हैं, उनकी वी.सी.आर. नहीं भरें। बड़े हाथी जो वी.सी.आर. भरने वाले हैं, वह भी क्या कर रहे हैं, आपके सामने है। बड़ी मछलियों को मारने की कोशिश करें। छोटे किसानों की बिजली की वी.सी.आर. नहीं भरें।

कर्ज माफी की बात की थी। कर्ज माफी में भी 19 हजार किसानों ने आत्म हत्या की, उनका पैसा माफ करके, उनको वापस ज़मीनें रिलीज कराएं, इसके बारे में भी सोचें। युवा बेरोजगारी भत्ते के मामले में अभी काफी आंदोलन हुए, काफी बातें हुई हैं इसलिए सभी युवा बेरोज़गारों को भत्ता दें। उनके फार्म रिजेक्ट नहीं करें।

(श्री चन्द्रभान सिंह चौहान)

पेपर लीक माफिया में दूध का दूध और पानी का पानी हो। उनकी सी.बी.आई. से जांच होकर, कार्यवाही होनी चाहिए, युवा बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। गायों के बारे में काफी बातें बोलती है। गायों को 12 महीने का अनुदान दें। गोचर को खाली करवाएं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): ज्यादा से ज्यादा प्रति व्यक्ति नरेगा से जोड़कर...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, बैठें।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): सभापति जी, एक मिनट।

श्री सभापति: प्लीज, बैठे।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): लास्ट है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो-चार मांगें हैं।

श्री सभापति: आज समय की विवशता है।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): दो मिनट। गायों को अनुदान वाली बात भी करें।

श्री सभापति: दो मिनट नहीं हैं। श्री महंत बालकनाथ।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): लास्ट, एक मिनट। मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोरकटियावली रोड है।

श्री सभापति: श्री महंत बालकनाथ।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): कपासन-मानपुरा रोड चित्तौड़ की...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत स्पष्ट रूप से समय की पालना करने के लिए कह कर गये हैं इसलिए मेरी यह विवशता है, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): कपासन-मानपुरा रिंग रोड चित्तौड़ की ...(व्यवधान) एक सैकण्ड, एक कपासन-मानपुरा रोड के बारे में सोचें। कनेरा-बस्सी रोड जो बंद पड़ा है, उसके बारे में सोचें, पी.डब्ल्यू.डी. के रोड के जो काम बंद पड़े हैं, उनके बारे में सोचें। पुरानी रोड्स की मरम्मत कराएं और पानी की जो समस्या है, जो माही और चम्बल से पानी आ रहा है, उसको जल जीवन मिशन के तहत टेंडर करके पूरा करें।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बाबा बालकनाथ।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आप सभी को पहले तो मैं राम-राम बोलता हूं। चलो यह तो अच्छा लगा कि विपक्ष के लोग भी राम-राम बोलना सीख गये हैं और धन्यवाद देता हूं मेरी तिजारा की जनता को कि जिनके माध्यम से मुझे आज राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बोलने का अवसर मिला है और जनता की मांग उठाने का अवसर मिलेगा।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। महामहिम ने जो अपने वक्तव्य में कहा है उस वक्तव्य के माध्यम से आने वाले पांच वर्षों में जो हमारी सरकार राजस्थान की जनता ने चुनकर भेजी है, एक बड़े बहुमत के साथ में, यह सरकार आने वाले पांच वर्षों में उन सभी आयामों को प्राप्त करते हुए राजस्थान की जनता को एक सुखद जीवन का अनुभव करायेगी।

जिस प्रकार से इस सदन के अन्दर यह कहा गया कि यह चुनाव माननीय प्रधान मंत्रीजी श्री नरेंद्र मोदीजी के नाम पर लड़ा है तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से लड़ा है और दुनिया के एक मात्र नेता वे ऐसे हैं जिनके नाम से केवल विधान सभा, लोक सभा ही नहीं, अपितु वार्ड पंच का चुनाव भी उनके नाम से लड़ा जाता है और जीता जाता है। दुनिया के एक मात्र नेता माननीय प्रधान मंत्रीजी हैं। आज हमें यह गर्व है हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी पर, हमारी पार्टी पर, हमारी विचारधारा पर कि राजस्थान की जनता ने जो पिछले पांच साल भ्रष्टाचार, गुंडाराज, महिलाओं के साथ में अपराध, शोषण, महिलाओं के साथ में बलात्कार और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि वह सरकार तो थी ही नहीं, जो पिछले पांच साल सरकार थी, वह कोई जनता के मैन्डेट की सरकार नहीं थी। वह पूर्णरूप से बहुमत प्राप्त सरकार नहीं थी, वह जोड़-तोड़ की सरकार थी, रिश्वत पर चलने वाली सरकार थी क्योंकि उसने विधायकों को खरीद-खरीद कर सरकार चलायी थी। जो खुद खरीदकर चलती हो, वह सरकार राजस्थान प्रदेश को कैसे चला सकती है? उस सरकार ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में किया, राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से गुंडागर्दी बढ़ी, सरे आम बलात्कार की घटनाएं हमें नित-रोज सुनने को मिलती थीं और राजस्थान में अशांति का माहौल था, उसी से त्रस्त

(महन्त बालकनाथ)

आकर राजस्थान की जनता ने उस सरकार को मुक्ति का रास्ता दिखाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनाई है और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार वचनबद्ध है राजस्थान की जनता के प्रति और निश्चित रूप से संकल्प-पत्र में एक-एक बात जो कही गयी है, आने वाले पांच वर्षों में नहीं अपितु आने वाले इस पहले वर्ष में ही वे सभी बातें पूरी होंगी और राजस्थान की जनता को न्याय देते हुए विकास के पथ पर राजस्थान को आगे बढ़ाएगी।

मैं यह कहना चाहता हूं, इस सदन में कई बार मुझे यह सुनने को मिला कि यह पर्ची की सरकार है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह पर्ची की नहीं, ये सौभाग्यशाली हमारे कार्यकर्ता हैं जो एक छोटे से गांव में रहते हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम करते-करते यहां तक पहुंचते हैं और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को ऐसा अवसर देती है कि उसको राजस्थान का मुख्य मंत्री बनाती है।

विपक्ष की सरकार, जो पिछले पांच वर्षों में रही, यह वैसी सरकार नहीं है कि जिसके अन्दर जिसके नेता, जो आज सड़क पर हैं, उनकी जी-हुज़ूरी करें, उनके वहां पर मन्नतें करें और जो ज्यादा जितना चढ़ावा देकर आयेगा, वह उतना बड़ा पद पाएगा। ऐसी परम्परा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में या भारतीय जनता पार्टी के अन्दर नहीं है।

हम यह जानते हैं और पूरे राजस्थान की जनता, प्रदेश की जनता यह जानती है कि आपने किस प्रकार से पिछले पांच वर्ष सरकार चलाई है। विधायकों की खरीद-फरोख्त के बहुत से आरोप हमें सुनने को मिले हैं। हमने लोगों से सुना है कि जिस प्रकार से प्रलोभन देकर जो सरकार चली हो, रिश्वत देकर जो सरकार चली हो, वह रिश्वत कैसे न खाये? हमने तो आजाद भारत के अन्दर इस स्वतंत्र देश के अन्दर जन्म लिया है और कांग्रेस के बारे में यह सुना है कि कांग्रेस की कुंडली ही भ्रष्टाचार से बनी है। कांग्रेस कभी भ्रष्टाचार से मुक्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके अन्दर, कुंडली के अन्दर सारा दोष ही भ्रष्टाचार का है। जिस प्रकार से आपने पिछले पांच वर्ष भ्रष्टाचार किया, चाहे वह पोषाहार का मामला हो, चाहे आपने पांच वर्षों के अन्दर इंदिरा रसोई की बात कही कि हमने इतनी अच्छी योजना चलाई थी, उस योजना के वीडियो और फोटो अखबारों में हमने भी देखे थे कि किस प्रकार से वहां पर जानवर, भोजन जो इंसान खाते हैं, उस भोजन के अन्दर जानवर घूम रहे थे। उनके अन्दर मैं यह कहना नहीं चाहता कि कुत्ते हैं, चूहे हैं, इन सबके प्रकाशित फोटो हमने देखे हैं।

(महन्त बालकनाथ)

आपने आगे चलकर चुनाव के प्रलोभन के माध्यम से राशन किट की योजना चलाई। उसके अन्दर भी हमने अखबारों के माध्यम से यह जाना है कि किस प्रकार से उसके अन्दर भी आपने मिलावट करके राजस्थान की जनता को दूषित राशन खिलाने का प्रयास किया। मैं सीधे शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि योजनाएं जो कांग्रेस बनाती हैं, योजनाएं आज से तो देश में बनी नहीं हैं, आजादी के बाद से अनेकों योजनाएं बनती आयी हैं इस देश में, लेकिन कांग्रेस ने सदैव जो योजनाएं बनाईं, वह केवल उन योजनाओं के माध्यम से कैसे वे पैसा खा सकते हैं, योजनाएं ही नहीं, इन लोगों ने तो 'भ्रष्टाचार करो' योजनाएं बनाई हैं कि कैसे ये योजनाएं बनायें और उन योजनाओं के माध्यम से कैसे पैसा खाया जा सकता है? राशन किट के अन्दर भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। उसी के साथ में आगे चलते हुए राजीव गांधी युवा मित्र हम तो खायें ही खायें, हमारे कार्यकर्ता भी खायें। उनको भी कैसे खिलाया जा सकता है, यह सब दिमाग का काम कांग्रेस के अन्दर ही है और किसी दल के अन्दर, देश के अन्दर नहीं है। यह पिछले पांच वर्षों में हम सबको देखने को मिला है।

योजनाओं के बारे में अभी बात कर रहे थे कि हमने बहुत अच्छी योजनाएं चलाईं, बहुत अच्छा काम किया। अगर आपकी योजनाएं अच्छी होतीं तो आप उधर नहीं बैठे होते, आप इधर बैठे होते। आपकी योजनाएं भ्रष्टाचार से लिप्त थीं। आपकी योजनाओं के अन्दर और योजनाओं के माध्यम से आपने जो राजस्थान की जनता का पैसा खाया उसी का यह परिणाम है कि आज आप उधर बैठे हैं और आने वाले समय में मैं तो यह मानता हूं कि उधर के बैठने के लायक भी आप लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी जो घबराहट है इस समय पर कि जांच का क्या हुआ? जांच का क्या हुआ? निश्चित रहिये जांच होगी और आपने जो खाया है राजस्थान की जनता का, वह आपका निकलकर रहेगा, क्योंकि आपको उतावलापन है कि परिणाम कब आयेगा क्योंकि रातों की नींद हराम हो रखी है कि कब तक परिणाम आयेगा, कितनी जल्दी जांच होगी, क्योंकि आपको डर है, भय है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जांच होने के बाद में आपको राजस्थान में कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी क्योंकि आप लोग राजस्थान की मिट्टी तक को खा गये हो। आपने जिस प्रकार से, खनन हो, हर क्षेत्र के अन्दर इतना व्यापक रूप से जो भ्रष्टाचार किया है, उसका परिणाम और उसकी जांच का परिणाम आने वाले समय पर आपको देखना और भुगतना पड़ेगा।

(महन्त बालकनाथ)

अभी राम मन्दिर की भी बात हो रही थी कि राम मन्दिर का निमंत्रण या राम का, राम तो सबके हैं। हम तो आपको भी यह कहना चाहते हैं कि भज लो राम नाम, हो जायेगा आपका भी कल्याण और हमें प्रसन्नता है इस बात की कि इनके नेता भी मंदिरों में जाने लगे हैं। हम यह ही तो चाहते हैं कि आप लोग मन्दिर जाना सीखें और मैं तो ...(व्यवधान) नहीं, अब तो फोटो डालने लगे हैं, बताने लगे हैं मन्दिर के बाहर। ये जानबूझकर नाटक करते हैं कि मुझे मन्दिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। दिखा कर जाने लगे। काफी प्रमाण हैं इस बात के तो हम तो यह चाहते हैं कि सभी जायें, संस्कारों को सीखें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, विराजिये।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): संस्कारों को सीखें और अपने देश की परम्पराओं को, देश के लोगों के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करें, न कि उसमें भ्रष्टाचार कर देश को लूटने का काम करें।

श्री सभापति: विराजिये।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): मैं कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी, कि विपक्ष के लोगों को जरूर एक बार राम मन्दिर दर्शन के लिए ले जाना चाहिए। देखेंगे कि कौनसे में कितनी भक्ति है क्योंकि कोई दिल्ली से पूछेगा या बिना पूछ कर ही गाड़ी में बैठ कर राम मन्दिर जायेगा। यह पता स्पष्ट लग जायेगा राजस्थान की जनता को।

श्री सभापति: विराजें।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): सभापतिजी, थोड़ा-सा समय तो और दो। पहली बार बोल रहा हूं।

श्री सभापति: समय सीमा है।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अन्दर, यह आपको भी अनुभूति होगी कि राजस्थान विकास के पथ पर बहुत ही अच्छी गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन जिस प्रकार से आपने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है, उस धोखे का भी और आपने जो भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार के परिणामों को भी राजस्थान देखेगा। आपने राजस्थान के लोगों का जो पैसा तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों को बांटा है। किसी के साथ भी जब बुरा होता है, हम बुरा करने वाले के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन आपने तुष्टीकरण की राजनीति की जो

(महन्त बालकनाथ)
पराकाष्ठा की है, एक व्यक्ति सम्प्रदाय विशेष का किसी हादसे में मारा जाता है तो राजस्थान की कमाई के पैसे को इस प्रकार से लुटाया जाता है कि जैसे वह इनके परिवार का सदस्य हो। आपने विधायकों पर जिस प्रकार से पैसा लुटाया है, वह राजस्थान की जनता की कमाई का पैसा था। निश्चित रूप से उस पैसे को वर्तमान की सरकार निकालेगी और आपके किये की सज़ा, राजस्थान की जनता को आपने जिस दु:ख के मोड़ पर लाकर छोड़ा है, आपने राजस्थान को जिस बर्बादी के कगार पर लाकर छोड़ा है, उससे राहत देने का कार्य आने वाले समय में होगा।

श्री सभापति: धन्यवाद। विराजें माननीय सदस्य। श्रीमती शिमला देवी।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि बुद्धि सबके पास होती है। चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): सभापति महोदय, आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मेरा समय प्रारम्भ हो चुका है। मैं बोल रही हूं। माननीय सदस्य को बोलिए, वे बैठें।

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य, प्लीज। आपको समय से अधिक बुलवा लिया। समय सीमा निर्धारित है। (व्यवधान)

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं। (व्यवधान) मेरी बात शुरू हो चुकी है। माननीय सदस्य को बोलिए कि वे बैठें, नहीं तो मैं समय एक्स्ट्रा लूंगी। बैठिए, माननीय सदस्य।

सभापति महोदय, हम नये-नये आये हैं। पहली बार चुन कर विधान सभा में आई हूं। हमारी जनता ने हमको चुन कर जहां भेजा है 38 हजार वोट से जीत कर आई हूं। अब जब हम वहां गये थे तो मेरी विधान सभा क्षेत्र के जो प्रबुद्धजन थे, पूछ रहे थे कि विधान सभा में क्या होता है? महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में क्या था? जबसे विधान सभा चालू हुई है राम के नाम पर राजनीति हो रही है। मैं बताना चाहती हूं। जब हमारे घर पर बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बुआ या मौसी कान में बच्चे को कहती है राम-राम। जब अंतिम शय्या पर हम होते हैं, हमारी अर्थी सजाई जाती है, हमारे हिन्दू

(श्रीमती शिमला देवी)

रीति-रिवाज के अनुसार तब तक हम मुखाग्नि नहीं देते जब तक हम अर्थी के नीचे से 108 बार राम का नाम नहीं लेते। क्या आप बतायेंगे हमें राम नाम की भक्ति?

एक राजा का बेटा, एक राम घट-घट में बैठा, एक राम जगत बिसारा, एक राम सबसे न्यारा। कबीर दासजी ने क्या कहा है? मीराजी ने क्या कहा है? गुरुवाणी के अन्दर सैकड़ों बार राम का नाम आया है। कब मन्दिर जाना है और कब नहीं जाना है, वह हम खुद तय करेंगे। हम राम को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, उसके अन्दर सिवाय कांग्रेस की आलोचना के कुछ नहीं है। क्या पांच साल कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया? जनता से जाकर पूछिए कि हैल्थ के क्षेत्र में क्या किया, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या किया। आपका विजन क्या है? आप हमें बताइये, सभापति महोदय, मैं सत्तापक्ष से पूछना चाहती हूं कि आपका विजन क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? जनता का जनमत है। जनता चाहे जिसको विपक्ष में बिठाती है और जिसको चाहे सत्ता में बिठाती है।

सभापति महोदय, अभी कह रहे थे कि जिले आनन-फानन में बनाये। 10-12 साल से लोग संघर्ष कर रहे थे इसके लिए। पूर्व मुख्य मंत्री गहलोतजी और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने जिला बनाकर अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र को जो सौगात दी है, हमारी जनता को राहत दी है, वह सराहनीय कार्य है। मैं मेरी पार्टी को धन्यवाद देती हूं। आपके माध्यम से सत्तापक्ष से यह जानना चाहती हूं कि आप नये जिलों में कब डयूटी आफिस खोलेंगे? कब आप हमें नगरपालिका देंगे? कब आप हमें तहसील देंगे? उसके ऊपर क्या करना चाहते हैं? आज सी.एच.सी. घड़साना, रावला, अनूपगढ़ के अन्दर एक भी गायनी डाक्टर नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर गायनी डाक्टर की व्यवस्था कब करेंगे? ट्रोमा सेन्टर कब देंगे?

सभापति महोदय, सबसे बड़ा मुद्दा, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आती हूं, हम सिंचाई के पानी पर निर्भर हैं। किसानी से सम्बन्धित मेरा जिला है। भारत और पाक की सीमा पर बसा हुआ मेरी अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र है। अभी जो रेगुलेशन जारी किया गया, उसका क्या नियम था? किस कारण से हमारा वरीयता क्रम चेंज किया गया? हमें पानी पीछे मिलना चाहिए था, हमें आगे पानी इन्होंने 08 मार्च किया। अब जो बंदी ले रहे हैं 15 मार्च को, जो इर्रिगेशन विभाग है, मेरी बात नोट की जाए, क्योंकि हमारी सरसों और गेहूं की

(श्रीमती शिमला देवी)
जो फसल है, उसके पकाव के लिए हमें 15 अप्रैल तक पानी चाहिए आई.जी.एन.पी. नहर के अन्दर। सिवाय एक दूसरे पर छींटाकशी के, एक पार्टी की कमी गिनाने के बजाय, आपको जनता ने मौका दिया है तो आप लोग जनता के हित से जुड़े हुए काम कीजिए। अभी आप गेहूं की बात कर रहे थे।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र की बात थी। आप कह रहे थे न कि जिस भी विधायक ने मांगा उसको पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने दिया। बिलकुल आपकी बात सत्य है, क्योंकि अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लगातार बी.जे.पी. के विधायक थे, फिर भी गहलोत साहब ने बिना भेदभाव किये अनूपगढ़ को जिला बनाया था। उस आदमी की नीति बहुत अच्छी थी। इलाज बहुत अच्छा हो रहा था।

मेरे को लग रहा है कि विधान सभा का सेशन नहीं होकर लोक सभा का सेशन चल रहा हो। मोदीजी के सिवाय कोई बात नहीं, जनता के लिए अच्छी योजना या आप जनता के लिए क्या करेंगे या नहीं करेंगे, दूसरी कोई बात नहीं की। आप भ्रष्टाचार के ऊपर बात कह रहे थे। क्या हम भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान कर पायेंगे। शुरुआत हमारे घर से होती है। जब आपका बच्चा पढ़ रहा होता है, बच्चे को कहते हैं कि 80 परसेंट नम्बर लेकर आओ, मैं आपको मोबाइल दिलाता हूं। कैसे आप भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान करेंगे?

आप बात करते हैं महिलाओं पर अत्याचार की। हमारी पहलवान बहनें थीं। उनको बैठना पड़ा। मणिपुर के अन्दर घटना हुई। निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जा रहा था। उस पर सत्तापक्ष का क्या कहना है? आप लोग महिला की बात करते हो।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहती हूं कि राजस्थान सरकार का, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से यह विजन था कि जो सरसों का समर्थन मूल्य 2024-25 का है, 2,275 रुपये, मेरे से पहले मेरे भाई अभिमन्यु ने भी इस पर बात कही थी, उस समर्थन मूल्य पर 125 रुपये आप बोनस दे रहे हैं तो कुल मिलाकर 2,400 रुपये हो रहा है। आप 2,700 रुपये की बात कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है?

सभापति महोदय, आई.जी.एन.पी. की बंदी जो ली जा रही है 60 दिन के आगे, यह मेरा पाइन्ट नोट करने लायक है, क्योंकि वह मेरा सिंचित क्षेत्र है, उसमें 15 अप्रैल तक पानी दिया जाए, जिससे हमारी फसलों का पकाव हो

(श्रीमती शिमला देवी)

सके। सरकार से मेरा निवेदन है कि कांग्रेस की कमियां निकालने के बजाय अपने विजन पर ध्यान देना चाहिए। समय निकलते कोई देर नहीं लगती है। पांच साल का समय आया और गया। जनता पक्ष में बिठा सकती है तो जनता विपक्ष में भी बिठा सकती है। हमें आपसे कुछ न कुछ सीखना है तो अच्छी चीज सीख कर जाएं, ताकि हम हमारी जनता को बतायें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल (अनुपस्थित)।

श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): सभापति महोदय, 16वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद पर आपने मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश की मुख्य पंचायत में निर्वाचित सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। देश और प्रदेश के लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने इस राजस्थान में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ग्राम, ढाणी के लिए काम आने वाली योजना शिक्षा, सड़क से लगा कर अनेक योजनाएं बनायी थीं।

मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि प्रदेश में विकास को लेकर सरकार जो अपनी योजना बनाती है, वही महामहिम राज्यपाल द्वारा अभिभाषण पढ़ा गया। अभिभाषण हमारी सरकार का आईना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात रखूंगा कि राजस्थान प्रदेश की जनता के साथ में विगत सरकार द्वारा हर क्षेत्र में धोखा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जनता ने भा.ज.पा. को समर्थन दिया और विगत सरकार के खिलाफ अपना मत दिया। विगत कांग्रेस की सरकार ने मोदी सरकार द्वारा जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उनको समयबद्ध तरीके से लागू नहीं करने से प्रदेश की जनता को लाभ नहीं मिल सका। इनमें जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य ऊर्जा घरेलू कनेक्शन योजना, स्किल डवलपमेंट योजना, मृदा योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान

(श्री हमीर सिंह भायल)

निधि, जन धन योजना सहित कई योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचने नहीं दिया। मोदी सरकार द्वारा जारी बजट में भी हेराफेरी करके योजनाओं को खुर्द-बुर्द करने का काम भी विगत सरकार ने किया। आम जनता के कामों को गौण समझकर कांग्रेस सरकार ने अपने-अपने निजी हित को मुख्य मानकर कार्य किया, जिससे प्रदेश में अराजकता, भ्रष्टाचार, माफियाराज, गुंडागर्दी, हत्या, बलात्कार, तुष्टिकरण, खनन माफिया, भूमाफियाओं में बढ़ोतरी हुई। राज्य की जी.डी.पी. को भी देश के सबसे निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश को पिछड़े राज्यों वाली श्रेणी में खड़ा करने का काम विगत सरकार ने किया। विगत सरकार लगातार कुश्ती के अखाड़े में खड़ी रही। आपसी लड़ाई से सरकार अधिकतर समय आमने-सामने दो खेमों में नजर आयी, जिससे राज्य का विकास अवरुद्ध हुआ। सरकार को बचाने के उद्देश्य से वरिष्ठ कांग्रेसियों ने जो सरकार से कहा, वह चाहे उचित है या अनुचित है, करते रहे। सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर कार्य किया। सरकार ने भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य किया। भा.ज.पा. के विधायक जहां निर्वाचित थे, उस क्षेत्र में कार्य नहीं होने दिया, जबकि उस क्षेत्र की जनता का वह निर्वाचित सदस्य होता है, जिसकी सहमति या अनुशंसा से ही उस क्षेत्र में कार्य किये जाने चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात रखूं तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता सड़क, पानी, शिक्षा एवं चिकित्सा होती है, जिनमें विगत सरकार ने विधायक की सहमति से एक भी काम नहीं करवाया। यहां तक कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति देनी थी तो उसमें भी सड़क मार्ग, जयपुर से ही निर्धारित पूर्णरूप से भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य किया। जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भेदभाव, आज भी मेरा क्षेत्र वंचित रख रखा है। पिछले पांच सालों में एक भी पाइप नहीं लगाने से सिवाना की मुख्य योजना पोकरण-फलसूण्ड-बायतू-बालोतरा-सिवाना आज भी अधूरी पड़ी है। कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों को मेरी जनता झेल रही है। विगत सरकार ने तुष्टिकरण की नीति और वोटों की नीति से कार्य किया। बिना प्रावधान किये ही जातिगत बोर्ड, निगम और आयोग का गठन कर दिया, जिससे प्रदेश में जाति का जहर घोलने का कार्य किया। एक-दूसरी जाति में खींचतान, आपस में भाईचारा, पारम्परिक रिश्ते

(श्री हमीर सिंह भायल)

खतम करने का काम विगत सरकार ने किया। अपनी स्वयं की वोटों की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं के नाम बदले। माता अन्नपूर्णा के स्थान पर इंदिरा रसोई करना, ये तो राम को भी नहीं मानते। चार सौ वर्ष पूर्व 1528 से लगातार 2024 तक संघर्ष करके आज हम सभी ने रामजी के मन्दिर की प्राण-प्रतिष्ठा की, परंतु कांग्रेसी अपने आकाओं की खुशी के लिए रामलला को भी नकार रहे हैं। नाम बदलना तो इनके डी.एन.ए. में है। विगत पांच वर्षों में सरकार की नाकामियों से प्रदेश के युवा, उद्‌यमी और महिला, किसान, मजदूर एवं व्यापारी दु:खी रहे। इनके द्‌वारा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से स्टडी सेन्टर खोले गये जिनमें अपने चहेतों को बिठाया। इनके राज में पेपरलीक होते रहे। इस प्रकार के गोरखधंधे करना इनके जहन में है। इन्होंने तो गायों को भी नहीं छोड़ा। लम्पी जैसी महामारी में समय पर व्यवस्था नहीं करना, गायों के नाम की राजनीति करके दुधारू पशुओं की मौत पर 40 हजार रुपये अपने कार्यकर्ताओं के खाते में डालने का कार्य भी किया। पांच साल तक घोषणा-पर-घोषणा करते रहे। पंचायत समिति स्तर पर नन्दी गौशाला खोलेंगे, वह नन्दी गौशाला कहां गयी? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): देखा तो बोलते हुए शर्म महसूस होती है। कांग्रेस के विधायक कब कुकृत्य कर लेते हैं जो हमें बोलने में भी शर्म आती है। यह महिला सुरक्षा को लेकर विगत सरकार रक्षक ही भक्षक बनी। मोदीजी का जो विजन है, राजस्थान सरकार का जो विजन है, उस विजन को किसी भी योजना...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज विराजें। आपको दिया समय समाप्त हो गया। डॉ. प्रियंका चौधरी।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, जो सरकार की नीति है, राजस्थान सरकार जो अब अधूरे कार्य रहे हैं शिक्षा से लेकर पेयजल तक, ये सारे कार्य करने में, जो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने शुरुआती काम करके जल योजना से माही बांध को, हमारे पश्चिमी राजस्थान में भी माही बांध परियोजना का विस्तार करके जालौर, बाड़मेर सब जगह से जोड़ा जाये। धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। डॉ. प्रियंका चौधरी। सात मिनट में अपनी बात समाप्त करें। आपको सात मिनट दिये हैं।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, पहली बार बोल रहे हैं।

श्री सभापति: पहली बार के लिये सात मिनट। बोलें, अपना समय बर्बाद नहीं करें।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): प्रयास करेंगे।

जनतंत्र के इस पवित्र मन्दिर में सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में हुए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन के कीमती समय में से कुछ समय निकालकर बाड़मेर की इस बेटी को बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देती हूं।

इस सदन में सभी दल और निर्वाचित सदस्यों का भी मैं अभिवादन करती हूं और आप सबको भी बहुत-बहुत बधाई देती हूं। प्रथम बार सदन में अपना वक्तव्य रख रही हूं तो मैं सभापति महोदय का संरक्षण चाहूंगी और जितने मेरे वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, आपका मार्गदर्शन चाहूंगी और जो मेरे साथी माननीय सदस्यगण हैं, आप सबके सहयोग की भी मैं अपेक्षा करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में हमारे प्रतिपक्ष के नेता बैठे हैं, मैं आपको भी बहुत-बहुत बधाई देती हूं। सरकार में बिाजे सभी मंत्रियों को भी बहुत-बहुत बधाई देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात की शुरुआत परम श्रद्धेय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी, क्योंकि ये पंक्तियां हमेशा से ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं -

'न हार में, न जीत में,
किंचित नहीं भयभीत मैं,
कर्तव्य पथ पर जो भी मिला,
यह भी सही, वह भी सही,
वरदान नहीं मांगूंगा,
कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानूंगा।'

माननीय सभापति महोदय, मैं बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र से आती हूं। मैं 1957 की बात करती हूं जब गुढ़ामालानी के आदरणीय स्व. रामधन जी चौधरी 1957 में पहली बार जनता का आशीर्वाद पाकर इस सदन में आये और उन्होंने मृत्यु भोज निषेध जैसे कानून को यहां लागू करवाने का कार्य किया। उसके बाद मेरे दादाजी आदरणीय स्व. गंगाराम जी चौधरी, 1962 से लगातार

(डॉ. प्रियंका चौधरी)

जनता ने उनको आठ बार विधायक बनाकर आशीर्वाद दिया और उन्होंने लगातार इस सदन में आकर जनता की सेवा का कार्य किया।

माननीय सभापति महोदय, पिछले 20 सालों से मैं सक्रिय राजनीति में हूं और विभिन्न परिस्थिति और चुनौतियों का सामना करते हुए मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूं मेरी बाड़मेर की देवतुल्य जनता को, 36 कौम की जनता को, मेरी बहनों को और खास तौर से नन्हे-मुन्ने बच्चों को, क्योंकि मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ी और स्टार प्रचारक मेरी वे बहनें, मेरे वे युवा भाई और वे नन्हे-मुन्ने बच्चे ही थे, तो मैं उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देनी चाहती हूं।

सभापति महोदय, मैं यह संकल्प इस सदन के माध्यम से लेती हूं कि मैं अपने पड़दादा जी और दादा जी के पद चिन्हों और सिद्धांतों पर चलते हुए जनता की सेवा का कार्य करूंगी। यह आज संकल्प लेती हूं।

मैं बाड़मेर की जनता के इस ऐतिहासिक निर्णय का धन्यवाद देती हूं जिन्होंने लोकतंत्र की परिपक्वता का संदेश दिया। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। बाड़मेर की जनता वाकई, असली मायने में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, क्योंकि उन्होंने 15 साल की गुलामी, भय, आतंक और भ्रष्टाचार की बेड़ियों से मुक्ति पायी है। मैं बाड़मेर की जनता को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं।

सभापति महोदय, बहुत सारे विषय मेरे जेहन में आते हैं लेकिन चूंकि सीमित समय है और मैं मानती हूं कि मेरी इन कुछ बातों से यहां के सभी माननीय सदस्यगण हैं, वह सहमत होंगे। हमें गर्व है कि आज पंडित दीनदयाल जी के सिद्धांतों, उनके दर्शन को लेकर अंत्योदय की योजना के साथ अमृत महोत्सव मनाते हुए 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना करके केन्द्र और राजस्थान सरकार योजनाएं बना रही है।

इस सदन में मैं आई, तब से राम मन्दिर की बात सुन रहीं हूं और मैं मानती हूं कि हर भारतीय, वह चाहे भारत में हो या विदेशों में हो, आज वह गर्व और खुशी की अनुभूति महसूस कर रहा है कि राम मन्दिर 500 सालों के त्याग और तपस्या के बाद बना है। सभी को गर्व है कि हमारे हिन्दुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वह 5वें नम्बर पर आ गयी है, जिसे आने वाले समय में तीसरे नम्बर पर लाने का प्रयास है।

धारा 370, तीन तलाक, चंद्रयान ऐसे अनेकों-अनेक विषय हैं, जिनमें

मैं मानती हूं, मेरा विश्वास है कि हर एक भारतीय को गर्व है और होना भी चाहिए। इस सदन में हमने जब सुना, मोरिये की बात हुई कि मोरिया बोल गया, मोरिया बोल गया, मोरिया पता नहीं कहां बोला और कहां नहीं बोला, लेकिन मैं यह मानती हूं कि हमारे बाड़मेर की जनता को जब मैं देखती हूं तो निश्चित रूप से मुझे इस मोर की याद आती है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सभापति महोदय, अभी तो बोलना शुरू किया है।

श्री सभापति: समय इतना ही है। सदन के नियमों के अनुसार आनुपातिक रूप से समय बंटा हुआ है। आपको सात मिनट दिये हैं। सात मिनट होने वाले हैं।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): मेरे बाड़मेर के बारे में मैं अगर बात करूं तो बहुत विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बहुत जटिल सामाजिक संरचना है, बहुत संघर्षों और संतों की भूमि है।

श्री सभापति: जो निर्धारित समय है, उसमें बोलें।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): एक समय में जो काला पानी की सज़ा, जिसके लिए अधिकारियों को भी धमकाया जाता था कि काला पानी की सज़ा दे देंगे, बाड़मेर भेज देंगे। आज उस बाड़मेर को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। आज बाड़मेर ने विश्व के मानचित्र पर अगर अपना स्थान बनाया है तो उसके पीछे रिफाइनरी और यहां का जो हैंडीक्राफ्ट है, उसके कारण है। इस रिफाइनरी की बात मैं करूंगी, रिफाइनरी के साथ मेरे बाड़मेर के युवाओं के सपने जुड़े हुए थे, लेकिन एक सरकार आई, दूसरी गयी, पहली आई और युवाओं के सपने उन सरकारों के साथ ही कहीं मिट्टी में मिल गये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि युवाओं को वहां रोजगार मिले। मेरे से पूर्व किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि अपराध को कोई नहीं रोक सकता।

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): अपराध रोका जा सकता है। अगर मेरे युवा भाइयों को उचित शिक्षा दी जाये, उचित रोजगार दिया जाये तो निश्चित रूप से अपराध में कमी आ सकती है। मेरे वहां बाड़मेर जिले में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां काम कर रही हैं। उनमें प्राथमिकता से रोजगार दिया जाये।

श्री सभापति: श्री अंशुमान सिंह भाटी। प्लीज, आप विराजें।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): हमें पानी दिया जाये। हमें अच्छे डाक्टर दिये जायें। हमारी शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

श्री सभापति: विराजिये।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): जब मोदी जी कहते हैं कि इक्कीसवीं सदी के भारत में वूमैन डवलपमेंट होगा तो मेरे बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में शहर के अन्दर सिर्फ 2 गर्ल्स सीनियर्स स्कूल्स हैं। मुझे दु:ख होता है कहते हुए कि सिर्फ एक में साइंस फैकल्टी है तो वे बच्चियां, वे बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी। कैसे तरक्की करेंगी? मेरे बाड़मेर शहर की स्थिति देखें, विडम्बना देखिये।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): 000

श्री सभापति: श्री अंशुमान सिंह भाटी।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का मौका दिया है।

आजादी के अमृत महोत्सव में 75.45 प्रतिशत मतदान के सर्वाधिक आंकड़े को छूते हुए राजस्थान की जनता ने जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उसके लिए मैं पूरे राजस्थान की जनता को बारम्बार धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। कोलायत विधान सभा क्षेत्र की जनता को भी वन्दन करता हूं, अभिनन्दन करता हूं जिनके आशीर्वाद से आज आप सभी गणमान्य सदस्यों के बीच अपनी बात रखने का मौका मिला है।

विकसित राज्य राजस्थान और विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मंत्र रहेगा। मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास जताकर जनता ने जो ऐतिहासिक निर्णय दिया है, उसकी हम सब सराहना करते हैं। इसी निर्णय के साथ अराजकता के अंधकार से सुशासन के उजाले की ओर अग्रसर हो, बढ़ चुके हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान की भारत-पाक अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। हमारा सम्पूर्ण क्षेत्र थार रेगिस्तान के अन्दर आता है। मेरा खुद का गांव

(श्री अंशुमान सिंह भाटी)

अन्तरराष्ट्रीय सीमा से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। अत: मैं खुद पश्चिमी राजस्थान की समस्याओं, चुनौतियों से बखूबी वाकिफ हूं। यहां जीवन कृषि और पशुपालन पर आधारित है। यहां लोग गांवों में कम और खेत, ढाणियों में ज्यादा निवास करते हैं।

सन् 1987 में सीमान्त क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार बी.ए.डी.पी. योजना लेकर आई थी। इस योजना से राजस्थान के सादुलशहर, गंगानगर, करणपुर, अनूपगढ़, खाजूवाला, कोलायत, पोकरण, जैसलमेर, शिव, चौहटन, सांचौर जैसे सरहदी इलाके पिछले तीन दशकों से लाभान्वित हो रहे थे, परन्तु पिछली कांग्रेस सरकार में हुई अनियमितताओं के कारण यह योजना गत दो सालों से बंद पड़ी है। सीमावर्ती क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने एवं इलाके के सम्पूर्ण विकास के लिए इस योजना को पुन: चालू करवाना अति आवश्यक है।

अभिभाषण के पैरा संख्या 16, 17, 18, 19 में आर.डी.एस.एस. और सौभाग्य योजना का वर्णन है। इस योजना की शुरुआत हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी द्वारा देश के हर गांव और शहर में विद्युतीकरण से वंचित प्रत्येक गरीब परिवार को बिजली की सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य से की गयी, परन्तु बड़े दु:ख से कहना पड़ रहा है कि पूर्व की सरकार की कार्य प्रणाली के कारण हमारे प्रधान मंत्री जी का विजन धरातल पर नहीं उतर पाया।

पिछली सरकार की उदासीनता और गैर संवेदनशील रवैये के कारण आज भी धरातल पर हजारों परिवार रोशनी के उजाले से दूर हैं। यह योजना राजनीतिक भेदभाव, मतभेद और भ्रष्टाचार के ऐसे भेंट चढ़ी कि जरूरतमंद पात्र आज भी विद्युतीकरण से वंचित हैं। स्थानीय भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा मन मुताबिक सर्वे करे गये। ऐसे-ऐसे पात्र ग्रामीणों को चलते काम में छोड़ा गया, जिनकी कनेक्शन से मात्र दूरी एक पोल की थी। गौरतलब है कि उन भ्रष्ट ठेकेदारों के चहेतों के विद्युतीकरण कनेक्शन के लिए 20-20 खम्भों की विद्युत लाइन रातों-रात खड़ी कर दी गयीं। हठधर्मिता दिखाते हुए उन्होंने कहीं ट्रांसफार्मर नहीं दिये और कहीं तार नहीं दिये, और तो और कई स्थानों पर सिर्फ खम्भे खड़े करके काम अधूरा छोड़ दिया। लाइट और पानी दो ऐसी ज़रूरतें हैं जो ग्रामीण और युवाओं के स्वास्थ्य, पढ़ाई और रोजगार के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।

(श्री अंशुमान सिंह भाटी)

इसी प्रकार पैरा संख्या 20, 36 और 48 में भी जल जीवन मिशन की बात रखी गयी है। जल जीवन मिशन के तहत केन्द्र सरकार द्वारा सभी ग्रामीण नागरिकों तक घर-घर नल कनेक्शन से स्वच्छ जल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हर घर में नल से जल के संकल्प से इस योजना को लागू किया, परन्तु मुझे बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि विगत सरकार द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के कारण इस योजना का जो प्रारूप जमीनी स्तर पर उतरना चाहिए था, वह दुर्भाग्यवश वास्तविकता से कोसों दूर रह गया है।

भ्रष्ट ठेकेदारों और कर्मचारियों द्वारा जे.जे.एम. के नियम कायदों की खुले आम अनदेखी की गयी। सैकड़ों गांवों में जगह-जगह निम्न गुणवत्ता की पाइप लाइनों का उपयोग किया गया। जहां नियमानुसार पाइप लाइन की गहराई एक मीटर होनी चाहिए थी, वहां पाइप लाइन की गहराई मात्र 8 इंच रखी गयी है। परिणामस्वरूप अनेकों पाइप लाइनों का काम सम्पूर्ण होने से पूर्व ही वे क्षतिग्रस्त हो गयी हैं या उनमें लीकेज की शिकायत है। पानी की टंकियों की गुणवत्ता और लेवल भी मापदंडों के अनुसार नहीं है। नवनिर्मित टंकियों में भी रिसाव की शिकायत आम है। जो कि अस्वीकार्य है। कई जगह कार्य अधूरा होने के बावजूद भी ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है। कई गांव तो ऐसे हैं, जिनमें टंकी बनने के बाद दो साल में एक बार भी पानी नहीं भरा। अधिकारियों द्वारा मन मुताबिक घर व ढाणी को जोड़ा व छोड़ा गया। पुरानी सड़कें और चालू व्यवस्था पेयजल की योजनाओं को भी छोड़ दिया गया है। इन सभी कारणों से ग्रामीण आज आजादी के 75 साल बाद भी टैंकर्स से 500 और 1,000 रुपये में पानी डलवाने को मजबूर हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि जे.जे.एम. और सौभाग्य योजना में हुई अनियमितताओं में लिप्त दोषी कर्मचारियों और ठेकेदारों की उच्च स्तरीय जांच करवाकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये तथा धरातल पर जो अभाव है उनमें जल्द से जल्द सुधार किया जाये।

(समय: 16.00 बजे)

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और।

(श्री अंशुमान सिंह भाटी)

माननीय सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान में काफी लोग आज भी कच्चे आशियाने में रहते हैं जिनकी छत या तो खींप की होती है या फिर अन्य किसी स्थानीय लकड़ी की बनी होती है। भीषण गर्मी के वक्त या फिर किसी चिंगारी या बिजली स्पार्किंग की वजह से उनके आशियाने आगजनी के शिकार हो जाते हैं। ऐसी आगजनी की घटनाओं में इन लोगों के घर, मवेशी, फसल, नकदी और अन्य चीजें, उनकी जीवन भर की कमाई, सब नष्ट हो जाती हैं। न सिर्फ उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है वरन असहनीय मानसिक प्रताड़ना से भी गुजरना पड़ता है। उनकी उम्मीदें और सपने उनके आशियाने के साथ जलकर खाक हो जाते हैं। इसके बावजूद भी वे हार नहीं मानते हैं, अपने बचे एक जोड़ी कपड़े में अपनी शेष बची हिम्मत जुटाकर अपने परिवार के लिए संघर्ष पथ पर चल पड़ते हैं। कई महीने पटवारियों और थानों के चक्कर काट-काटकर अनेकों रिपोर्टें बनवाते हैं, परन्तु धोखा तो उन्हें तब होता है जब कई महीनों के बाद उन्हें मात्र 41 रुपये थमा दिये जाते हैं। 2015 की गर्मियों में हमारे विधान सभा क्षेत्र के भलूरी गांव में 40 पाक विस्थापित परिवारों के आशियाने जल गये थे। हमने तुरन्त उसी दिन सरकार से 95,100 रुपये के चैक प्रत्येक परिवार को दिलवाये। हमने भामाशाहों से मिलकर 17 दिनों में 40 पक्के मकान, कमरे, रसोई, लेट-बाथ और बरसाती टांके बनवाये।

श्री सभापति: समाप्त करें। आपका समय समाप्त हुआ। श्री जीवाराम जी।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, 10 मिनट का समय दिया था, 10 मिनट नहीं हुए हैं।

श्री सभापति: आपने दो मिनट मांगे थे, दो मिनट दिये हैं आपको। श्री जीवाराम जी।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): उनके पास दो जोड़ी कपड़े हैं, बिस्तर सोने के लिए नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। जीवाराम जी, बोलिए, आपका समय शुरू हो गया है।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): 000

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मैं आज पहली बार बोल रहा हूं इस विधान सभा सत्र के शुरू होने के बाद इसलिए सर्वप्रथम मैं सांचौर की उस देव तुल्य जनता को कोटि-कोटि नमन करता हूं

(श्री जीवाराम चौधरी)

जिन्होंने मुझे राजस्थान की विधान सभा में तीन बार भेजा है। इस विधान सभा में सभी माननीय सदस्य और आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में विश्व की सबसे बड़ी गोशाला पथमेड़ा में संचालित हो रही है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकारें, पूर्ववर्ती सरकार और राजस्थान सरकार और आगे आने वाली सरकारें भी जिस प्रकार से गोशालाओं का संचालन करती हैं उसके बावजूद भी सैकड़ों गायें और नन्दी पूरे प्रदेश में सड़कों पर घूम रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस महंगाई में जो अनुदान वर्तमान में गोशालाओं को दिया जा रहा है वह इस महंगाई के कारण कम पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह इस अनुदान राशि में बढ़ोतरी करने का काम करे।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र सांचौर में वर्तमान में काश्तकारों की सिंचाई चल रही है। हमारे यहां बिजली की बड़ी गम्भीर समस्या है। हम काश्तकारों को सिंचाई के लिए 6 घण्टे बिजली देते हैं, लेकिन वर्तमान समय में दो घण्टे बिजली भी काश्तकारों को मुश्किल से मिल रही है। उन दो घण्टों में भी इतनी ट्रिपिंग आती है कि काश्तकार इस सर्दी के मौसम में परेशान हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से आदरणीय बिजली मंत्रीजी को निवेदन है कि वे इसमें कुछ सुधार करें ताकि हमारे काश्तकार भाइयों को सहयोग मिले।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जल जीवन मिशन के बारे में अपने-अपने क्षेत्र में जो भी कार्य थे उनके बारे में चर्चा की है। मैं भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र सांचौर में जल जीवन मिशन में इतना भारी घोटाला हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस कम्पनी ने मूल ठेका लिया था उस कम्पनी ने वहां के लोगों को कार्य सब-लेट किया था, उन लोकल लोगों ने जो एस.डी.पी. के कीमती पाइप थे उनके बदले में बाजार में मिलने वाले दूसरे सस्ते पाइप लेकर जमीन के अन्दर गाड़ दिए। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन सारी पाइपों को खोदकर जांच करनी चाहिए और एजेंसी के माध्यम से जो भी दोषी हैं, जिन लोगों ने यह गलत काम किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा।

श्री सभापति: आप विराजें। श्रीमती गीता बरवड़।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: दो मिनट की जगह आपको चार मिनट दे दिये। आपने दो मिनट मांगे थे, मैंने आपको चार मिनट दे दिये। अब आप विराजें।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, शब्दों में ऐसा लिखा जाता है, दो मिनट। मैं अनुशासित सदस्य हूं। दोनों तरफ की चर्चा सुनकर मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं।(व्यवधान)

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं होगा। श्रीमती गीता बरवड़।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदयजी के भाषण पर अपने विचार प्रकट करने हेतु मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र से आई हूं जहां पर पहले दो बार बीजे.पी. का राज रहा और एक बार आर.एल.पी. का राज रहा। चौथी बार में मैं 15 साल से संघर्ष करते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 24 हजार 300 वोटों से जीतकर आई हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण सुना। पाया कि समूचे अभिभाषण में एक मुख्य बात को इंगित किया गया कि पूर्ववर्ती जन कल्याण के लिए हर पल, हर वक्त तत्पर रहने वाली जननायक सरकार के कार्यों का केवल विरोध के लिए विरोध करवाया गया है। इसमें कहीं भी आने वाले भविष्य में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने वाली सुनीति का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। सुनीति वही है जो सुव्यवस्था दे, सुव्यवस्था वही है जो सुशासन दे, सुशासन वही है जो समदर्शी हो, समदर्शी वही है जो सहिष्णु हो।

माननीय सभापति महोदय, मुझे एक जन-प्रतिनिधि होते हुए दुख होता है कि यह देश और यह राज्य किस ओर जाएगा क्योंकि बैर, ईर्ष्या को इस प्रकार, अब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जान बूझकर शब्दों में पिरोया जा रहा है। लोकतंत्र की परम्परा के हिसाब से यह ठीक तो नहीं लगता और मुझे बहुत दुख होता है जब उन योजनाओं को बंद करने या जान बूझकर रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि समूचे राजस्थान में ही नहीं बल्कि समूचे देश में लोगों की पसन्दीदा ये योजनाएं बनी रहीं। वित्तीय स्वीकृति के

(श्रीमती गीता बरवड़)

उपरांत योजनाओं और योजनाओं के स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रियाओं को रोक कर आखिर वर्तमान सरकार दिखाना चाहती है कि बस विरोध के लिए विरोध किया जाए। जन मत, जन हित ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य है, लेकिन यह लक्ष्य कमजोर होता हुआ परिलक्षित हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी बीमा योजना शायद आज तक की सबसे जन कल्याणकारी योजना थी। वह जान बूझकर कमजोर की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक बच्चे को हिन्दी माध्यम के अलावा अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिल सके उस उद्देश्य से पूर्ववर्ती जननायक सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलें खोलने का जो क्रांतिकारी काम किया था, उसका परिणाम यह हो रहा है कि आज गांव के गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी भाषा में संवाद कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। पिछली सरकार की विकास योजनाओं का परिणाम था कि राजस्थान राज्य की जी.डी.पी. 11.2 प्रतिशत पर पहुंची है। अब जो जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना या कमजोर करना, यह काम किया जा रहा है, इससे मुझे नहीं लगता कि आपका उद्देश्य जन हित रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार सर्व शक्तिमान होती है। वह सरकार समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण हेतु तत्पर रहती है, लेकिन बड़े दु:ख के साथ मुझे यह अभिभाषण पढ़ने के बाद लग रहा है कि इसमें उस अन्तिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाने का कोई जिक्र नहीं है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु राजीव गांधी युवा मित्र नाम के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ जनहित का कार्य दिया गया था। उस योजना को भी नयी सरकार ने आते ही इसलिए बंद कर दिया, क्योंकि वह स्व. राजीव गांधी के नाम से थी। यदि आपको राजीव गांधी जी के नाम से कोई आपत्ति थी तो योजना का नाम परिवर्तित कर देते, कम से कम पांच हजार युवा बेरोजगार नहीं होते।

वैसे भी नाम परिवर्तन की बड़ी विचित्र परम्परा वर्तमान सरकार ने आते ही शुरू कर दी है। मोदी जी की गारंटी, अब मुझे लग रहा है कि जो संविधान का फैडरल स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसे कमजोर करने का प्रयास है। इससे राष्ट्र मजबूत नहीं, कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो कभी लगता है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा हैं या

आदरणीय मोदी जी? यह बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसका उत्तर जनता की अदालत में जनता ही देगी। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मुझे एक बात बड़ी विचित्र और अटपटी लगी। महामहिम ने पूर्ववर्ती सरकार की अन्तर्कलह का जिक्र किया। एक ही झटके में 19 जिलों का निर्माण, यह अन्तर्कलह का तो परिणाम कतई नहीं हो सकता।

शासन और प्रशासन की शक्तियां, विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से सरकार द्वारा किये गये ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों का परिसीमन अन्तर्कलह तो नहीं हो सकता। सरकार, सत्ता, सिस्टम आपसी मतभेद और अन्तर्कलह से कभी काम नहीं कर सकते। यह भारतीय संविधान की पवित्र परम्परा है। अन्तर्कलह तो आदरणीय वसुन्धरा राजे जी के दिल से पूछिये। अन्तर्कलह तो सतीश जी पूनियां से पूछिये। आखिर में मैं यह कहूंगी कि आप बार-बार कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने राम मन्दिर का निमंत्रण नहीं लिया, लेकिन असम में मन्दिर में जाने की अनुमति लेने के बाद भी आपने राहुल गांधी जी को अन्दर नहीं जाने दिया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्या, कम से कम एक बार तो ऊपर देख लें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपके भी ऐसे ही बोले हैं लोग-बाग़। नये-नये सदस्य हैं। फर्स्ट टाइम बोलने वाले हैं। उन्हें बोलने दीजिये।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): आप बार-बार बातें कर रहे हैं, राम मन्दिर, राम मन्दिर। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिये कि जब राहुल गांधी जी ने असम में मन्दिर में जाने की परमिशन ली, उसके बाद भी आपने जाने नहीं दिया। राम मन्दिर का आपने सिर्फ एक मुद्दा बना दिया। आपकी पार्टी का मुद्दा बना हुआ है इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं किया। आप सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि हम राम के सेवक हैं, सिर्फ हमारे साथ ही राम हैं, हमारे घट-घट में राम हैं। राम तो पूरी दुनिया में बसे हैं और हर व्यक्ति के दिल में, हर व्यक्ति के मन में हैं। अत: आप सिर्फ राम के नाम पर राजनीति न करें।

श्री सभापति: श्री रविन्द्र सिंह भाटी। माननीय सदस्य, समय-सीमा की पालना करते हुए सात मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बाबा

(श्री रविन्द्र सिंह भाटी)

गरीबनाथ जी की नगरी शिव के 630 गांवों, 2000 ढाणियों के उन तीन लाख मतदाताओं को, जिन्होंने एक साधारण परिवार से आने वाले एक शिक्षक के 26 साल के बेटे को इस काबिल बनाया कि वह आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विचार रख पा रहा है। साथ ही साथ, सरहद की जनता की लोकतांत्रिक परिपक्वता व दूरदर्शी सोच को सलाम करता हूं, जिन्होंने संकल्पित होकर एक युवा को यहां तक पहुंचाया।

मुझे पूरा भरोसा है, अभिभाषण में जिन 83 बिन्दुओं को रखा गया, सरकार उन पर काम करेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान के उस कोने से मैं आता हूं, जहां के लोगों ने 1965 के, 1971 के युद्ध में सबसे ज्यादा अपनी भागीदारी निभायी, पर मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि सबसे ज्यादा आज के समय में अभाव में वे ही हैं। न वहां शिक्षा है, न पानी है, न रोजगार है। बिजली और चिकित्सा की बात तो न ही करें तो ठीक है। अगर मैं बिजली की बात करूं तो पिछले चार दिनों से 170 गांवों में चक्की तक नहीं चली, आटा तक नहीं पिसा। अगर मैं पानी की बात करूं तो पिछली सरकार ने पानी के मामले में सिर्फ लीपापोती की। पांच साल में हमारे एक भी घर तक पानी नहीं पहुंचा।

(समय: 16.14 बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

साथ ही साथ, अभी मुझसे पहले हरीश जी चौधरी साहब ने फरमाया कि शेरगढ़ में, सिवाना में कितने डिमांड भरे गये। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी शिव कान्स्टीट्यूएंसी भी पास में है, पचपदरा भी पास में है। पिछले पांच साल में हजार से ज्यादा पैंडेंसी मेरी शिव कान्स्टीट्यूएंसी की है और ऐसी की ऐसी उन तमाम कान्स्टीट्यूएंसीज की भी हैं। बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा, इन सब मामलों में अगर कोई सबसे ज्यादा पीछे है तो हम हैं। आपको बताना चाहूंगा, स्टेट को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से, विंड सोलर के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से, रिफाइनरी के माध्यम से, पेट्रोलियम के माध्यम से, हर तरीके से सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर कोई जनरेट करके देते हैं तो वह बाड़मेर और जैसलमेर देते हैं, पर उसके बदले उन्हें मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। कभी भी किसी तरीके से उनकी बात नहीं रखी जाती।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर एक डी.एन.पी. एरिया है, जहां के 80 गांवों में आज तक मोबाइल

(श्री रविन्द्र सिंह भाटी)

का नेटवर्क नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि पक्ष भी आया और विपक्ष भी, पर हमारे उन लोगों को कभी टावर तक नहीं दिया गया। शिक्षा और चिकित्सा की तो बात ही छोड़ दें। अगर किसी को बुखार आये तो सौ किलोमीटर से पहले कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। ऐसी स्थितियां क्यों बनीं, क्योंकि ये बातें सदन के भीतर किसी ने मजबूती से रखी ही नहीं। मेरा निवेदन है कि आप इस चीज का आगे तक ध्यान रखें और हमारे उन तमाम लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करें।

अध्यक्ष जी, मैं रोजगार के बारे में बात करना चाहूंगा। यहां लगभग सभी युवाओं की बात कर रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिये, भर्तियां ऐसे हो रही हैं। गवर्नमेंट की भर्तियां तो एक फिक्स्ड सैगमेंट में हैं, उसके अलावा नयी चीजें डवलप करने की बात हमने कितनी की, इस पर विचार करने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है, नयी चीजें डवलप करने का जमाना है, पर उसके लिए हमने क्या किया? समाधान की यहां कोई भी बात नहीं कर रहा है। आज युवाओं के साथ चारों तरफ से खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यहां पिछली सरकार थी, उस समय मैंने बतौर छात्र संघ अध्यक्ष विधान सभा का घेराव किया था, पर उस समय भी विद्यार्थियों की बात नहीं सुनी गयी।

आज मेरे क्षेत्र के कई सारे ऐसे गांव हैं, जहां लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, पर इस पर कोई बात नहीं करता है। आज इस अभिभाषण में पानी के मामले में मेरे विधान सभा क्षेत्र शिव में गूंगा, मीमला, हरसानी, गडरा, रामसेरा, हड़वा और हड़वेचा, ये वे गांव हैं, जिनमें अब तक पानी की एक बूंद नहीं पहुंची है। पिछली सरकार ने वादा किया था कि हम यह करेंगे, आपके लिए पानी लाएंगे, आपके लिए झीलें लाएंगे, पर आज वहां पीने के लिए भी पानी नहीं है। गांव के लोगों ने पानी की टंकी भरा-भराकर हजार-हजार, दो-दो हजार रुपये महीने का कर्जा कर लिया, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लाइट की यदि बात करें, अभी यहां बात हुई कि हजार-हजार कनेक्शंस पैंडिंग हैं, पर ट्रिपिंग और कटौती के कारण ऐसी स्थिति है कि किसान आत्महत्या करने की कगार पर हैं। कोई बात नहीं करता उनकी। (व्यवधान) बिल्कुल साहब, मैं आपके पांच सालों की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में नहीं, इधर देखकर बोलें।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): अक्षय ऊर्जा, बिजली, विंड और सोलर

(श्री रविन्द्र सिंह भाटी)

की जो बात कर रहे हैं, उस विंड और सोलर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हम करके देते हैं। दीये तले अन्धेरा है हुकुम, दीये तले अन्धेरा है। वहां के लोगों को लाइट नहीं मिल रही। किसान वहां रोजाना हड़तालें कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। उनकी बात कौन करेगा? यह रिफाइनरी, जो हमारे बाड़मेर में है, वहां के स्थानीय लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन युवाओं को वहां रोजगार में एक परसेंट भी वरीयता नहीं दी जा रही। कोई बात नहीं कर रहा इसकी। आज बाड़मेर और जैसलमेर की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, किसके सिर पर बैठें, लानत है जब कोई यह बात कहता है कि किसके सिर पर बैठें, जब कभी भी कोई बात आती है तो संयम धरकर छाती चौड़ी करके अगर कोई लड़ने के लिए सदा तैयार रहते हैं तो बाड़मेर और जैसलमेर के लोग तैयार रहते हैं।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के बाड़मेर और जैसलमेर में लगभग 70 परसेंट हर सेक्टर में हर विभाग के पद खाली हैं। पहले तो कहते थे कि हम आपको काले पानी की सज़ा दे रहे हैं। जैसे-तैसे करके हम उनकी सेवा-पानी भी खूब करते हैं। वहां अधिकारी तो लगाएं, पिछले पांच सालों में कोई अधिकारी वहां गया नहीं, तब ही तो अपन विपक्ष में गये, पर अब पक्ष के लोगों से भी निवेदन करता हूं, मंत्रियों से भी निवेदन करता हूं कि आप हमारी परेशानी देखें और आप खाली पदों को भरने की कृपा करें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)।

आप सबसे मेरा निवेदन है कि ग्रिल माइनिंग, जो मेरे बाड़मेर शिव में होने जा रही है, आसपास का पूरा क्षेत्र तो प्रदूषित है, जिसके कारण लोगों की उम्र 10-10 साल घट रही है। मेरा निवेदन है कि आप सब उनके स्वास्थ्य की चिन्ता करें। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत्बहुत आभारी हूं। साथ ही साथ, राजस्थान विधान सभा के चुनाव में प्रदेश की जनता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर सरकार बनाने के लिए जनादेश देने के लिए जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, गत कांग्रेस सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगलराज

(श्री अर्जुन लाल)
और इनकी घोषणा थी, एक से दस तक गिनती करके सम्पूर्ण कर्जा माफ करने की, बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा थी। पेपरलीक के मामले में सरकार की संलिप्तता, कई योजनाओं के नाम बदलने का काम, महिला दुष्कर्म, बढ़ते अपराध और कानून-व्यवस्था पर अंकुश नहीं रहना, साथ ही साथ अवैध खनन माफिया, ड्रग्स माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, जल माफिया में वृद्धि एवं इन पर गत सरकार का अंकुश नहीं रहने के कारण, जनता ने यह जनादेश दिया है।

इसके साथ ही साथ गत सरकार ने 5 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का कर्ज भार भी बढ़ा दिया। इससे पूरा प्रदेश एक बीमारू राज्य की श्रेणी में आ गया और बीमारू श्रेणी से बाहर निकालने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री भजन लाल जी अपने कुशल नेतृत्व से राज्य का ऋण भार कम करते हुए बीमारू श्रेणी से राज्य को बाहर निकालेंगे। हमारे 'आपणो अग्रणी राजस्थान' के सपने को साकार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर बिलाड़ा को कहा जाता था। मैं वहां से आता हूं। उसकी स्थिति आज ऐसी है कि गत सरकार के मुख्य मंत्री, पी.एच.ई.डी. मंत्री भी होते थे। उस समय 64 ट्यूबवैल खोदकर 24 घंटे तक 50 एच.पी. के पम्प लगाकर तीन वर्षों तक जोधपुर को पेयजल के लिए पानी की सप्लाई दी, नहीं तो उस समय जोधपुर का अस्तित्व भी खतम हो सकता था। हमारी स्थानीय जनता ने इसका विरोध किया। इस बात को लेकर कि जो एक मीटर के पाइप जोधपुर के लिए लेकर गये थे, 24 घंटे और तीन साल तक, निरन्तर जल दोहन से पूरा क्षेत्र सूख गया। वाटर लेवल 100 फीट पर था, वह करीब 700-800 फीट पर चला गया। आज की तारीख में वहां खारा और फ्लोराइडयुक्त पानी मिल रहा है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें। अभी जोधपुर के लिए दो मीटर की पाइप लाइन आ रही है। उस पाइप लाइन से, गत सरकार में तीन बार मुख्य मंत्री रहने के बाद भी बिलाड़ा को मीठा पानी नहीं दे सके, हिमालय का पानी नहीं दे सके।

हमारी तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने 308 करोड़ की योजना बनाई थी और उस योजना से दांतीवाड़ा तक पानी लेकर आ गये, लेकिन बिलाड़ा शहर एवं उसके आसपास के 119 गांवों में वह पानी नहीं पहुंच

(श्री अर्जुन लाल)

पाया। पिछली सरकार में जो मुख्य सचिव थे और मुख्य मंत्री जी के सलाहकार भी रहे, उन्होंने कुछ हिस्सा, जो हमारे कई गांवों को पानी मिल रहा था, उन्होंने उसको रोककर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते सोजत में डायवर्ट करवा दिया, जिसके कारण दोनों नगरपालिकाएं पीपाड़ शहर, बिलाड़ा एवं 119 गांवों को पानी मिलना बंद हो गया।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करवाई जाये। उस प्रोजेक्ट के अन्दर वह क्षेत्र सम्मिलित नहीं था, उसके बावजूद हमारे हक के पानी को सोजत विधान सभा क्षेत्र में कैसे ले गये।

इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि

"सचिव, बैद, गुरु तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस,

राज, धर्म तन तीनि कर होई बेगिहीं नास।"

उन्होंने पूरे राजस्थान का भट्टा बिठाया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दुबारा बोलें।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): "सचिव, बैद, गुरु तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस,

राज धर्म तन तीनि कर होई बेगिहीं नास।"

श्री अध्यक्ष: अब तो आ गई समझ में?

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): इसलिए आप जाकर विपक्ष में बैठे हो, यह उसका मुख्य कारण है। आपने जनता के हित का पानी दूसरी जगह दे दिया। वास्तविक जनता को जो पानी मिलना चाहिए था, वह उनको आज तक नहीं मिला। उस जनता की बद्दुआ से आपको उधर जाना पड़ा है।

इसके अलावा हमारी पूर्ववर्ती भा.ज.पा. सरकार ने उदय योजना के तहत ऋण माफ करके किसानों को सम्बल प्रदान करने के लिए विद्युत उत्पादन बढ़ाया और उस समय लाखों कनेक्शन दिये थे।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): लेकिन आज की स्थिति यह है कि वहां लोड शैडिंग के नाम पर, जब अधिकारी से पूछते हैं तो कहते हैं जयपुर से कटवा दी। लोड शैडिंग हो रहा है, शैडिंग के नाम से जनता को परेशान किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन्होंने जो परिपाटी अपनाई, उसको छोड़ें।

मंत्री जी से निवेदन है कि आप इस अघोषित कटौती पर पूर्ण

(श्री अर्जुन लाल)

प्रतिबन्ध लगायें और इनके कार्यकर्ताओं द्वारा वी.सी.आर. के नाम पर चुन-चुनकर लोगों के इतनी पैनल्टी करवाई कि वे लोग आज भी अपनी वी.सी.आर. करवाकर बैठे हैं। उस पर भी अंकुश लगाया है। साथ ही साथ हमारे मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा था कि सभी प्रधान मंत्री जी का नाम ले रहे हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो डेढ़ महीने में काम किये हैं, आप देखिये, गैस सिलेंडर साढ़े चार सौ में किया। आपने सिर्फ 6 महीने में घोषणा की। जो राज का इकबाल है, दोनों में अन्तर यह है कि हम सरकार बनते ही घोषणा करते हैं और आप जाते-जाते घोषणा करते हैं, जिससे आपके काम नहीं होते हैं। दूसरा, आप देखिये।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार रुपये से बढ़ा कर 12 हजार रुपये कर रहे हैं। पेपर लीक में एस.आई.टी. का गठन किया और अभी जो हाल में जो पेपर हुए हैं उनमें कोई ऐसी कहीं से शिकायत नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष: मैं अगला नाम पुकार रहा हूं।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): गेहूं का बोनस देकर सत्ताइस सौ रुपये प्रति क्विंटल देने का काम हमारे मुख्य मंत्री जी ने किया है। इसके साथ ही साथ अन्नपूर्णा रसोई योजना का जो आपने नाम बदला था...

श्री अध्यक्ष: हो गया। दो मिनट ज्यादा हो गये आपके।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): एक सैकण्ड। जो आपने इन्दिरा रसोई योजना नाम बदला था, वापस उन्होंने नाम बदलकर साढ़े चार सौ ग्राम से छह सौ ग्राम भोजन की क्वांटिटी करके उन मेहनतकश मजदूरों के लिए इन्होंने काम किया है, निश्चित रूप से और इसके अलावा कई जो कार्य किये हुए हैं जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने पहले घोषणा की है, सरकार आते ही घोषणा की है, डेढ़ महीने के अन्दर। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती है। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री ताराचन्द जैन।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जय श्रीराम। पूरे सदन को भारत के गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत काल की अनन्त शुभकामनाएं। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। वर्तमान

(श्री ताराचन्द जैन)

समय में जब राष्ट्र अपना अमृत काल मना रहा है, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने साल 2047 तक विकसित भारत और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया तो मैं सदन के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। इसी अमृत काल में भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और राम राज्य के लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। नारी शक्ति वन्दन कानून, चन्द्रयान और सुरक्षा बलों के सशक्तीकरण की सफलता हमारी सफलता का परिचायक है, लेकिन राम मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्राप्त निमंत्रण को ठुकरा कर कांग्रेस पार्टी ने सोमनाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा के समय पण्डित जवाहरलाल नेहरू की की गई भूल को न सिर्फ दोहराया है बल्कि अपनी तुष्टिकरण की नीति के पुख्ता होने के सबूत पेश किये हैं। जनता ने राजस्थान की भा.ज.पा. को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर कांग्रेस की नीतियों को करारा जवाब दिया है। मैं राजस्थान की वर्तमान सरकार, भजन लाल सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि बीस वर्षों से ई.आर.सी.पी. जो एम.पी., राजस्थान के बीच बीस वर्षों से लम्बित परियोजना, जिसका समझौता कल ही पूर्ण कर कालीसिंध और चम्बल नदियों को जोड़ने का तय किया है, 32 बांध भरेंगे और राजस्थान के करोड़ों कृषकों को उसका लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं उस उदयपुर शहर का प्रतिनिधित्व इस सदन में कर रहा हूं जो महाराणा की जन्म भूमि, कर्म भूमि होने के साथ भक्तिमय मीरा, राणा प्रताप, भामाशाह, हकीम खां सूरी की भूमि है। मेरी धरती को झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन 28 जून, 2022 को शान्त उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड की जो घटना हुई, एक आम शहरी युवक का गला जिस प्रकार काट लिया गया, वह न सिर्फ उदयपुर, बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान के लिए शर्मनाक होकर भविष्य की शान्ति के लिए कड़ी चेतावनी है। 'सर तन से जुदा' होने के नारे को मेरा उदयपुर किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। यह कांग्रेस की तुष्टिकरण की पिछले पांच वर्षों की नीति का परिणाम था।

अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर शहर को कन्हैया लाल के हत्याकांड की भूमि के नाम से पहचान नहीं देना चाहता हूं। इसका परिणाम यह रहा कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को जो 75 वर्षों के रिकार्ड मतों से, जिस आंकड़े तक सुखाड़िया साहब स्वयं भी नहीं पहुंच पाये, इतने बड़े बहुमत से मुझे इस

(श्री ताराचन्द जैन)

गलत नीति की वजह से जिताया, उसके लिए मैं उदयपुर की जनता का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली के बिलों में कटौती, बिजली के बिलों की माफी के नाम से सरकार में आये दिन गहलोत सरकार ने नौ बार बिजली दर वृद्धि कर जनता के साथ धोखा किया। गत पांच वर्षों में राजस्थान में 18 बलात्कार प्रतिदिन होना, 6 हत्या रोज होना कानून व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट करता है, लेकिन 2000 की तुलना में 2023 में 22 पाइंट और वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश वाले बयान से अघोषित रूप से घटना से प्रोत्साहित करने का काम किया है। उदयपुर में 24 जनवरी को रात्रि को एक विधवा महिला के साथ उसके देवर और भतीजे ने जमीन विवाद को लेकर मारपीट की। सूचना पुलिस को दी। रिपोर्ट होने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। बहुत विलम्ब से किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि विधवा के बेटे और उसके पिता की हत्या हो गयी। इस तरह की घटना बताती है कि राजस्थान में राज परिवर्तन जनता ने तो कर दिया है, लेकिन यह व्यवस्था परिवर्तन का काम बाकी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जब तक हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे तो यह राज की व्यवस्थाएं सुधरेंगी नहीं। राजस्थान की सरकार को धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि 25 जनवरी को राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने पहली बार जैन समुदाय के साधु-साध्वियों के लिए चातुर्मास विहार के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए भूमि आबंटन करने का विचार करने बाबत लिखित में प्रस्ताव लिया। यह राम मन्दिर प्रतिष्ठा के बाद तप और तपस्या के प्रति हमारे संतों और समाज के भक्तों में नयी ऊर्जा का संचार करेगा। पहली बार किसी सरकार ने साधु-साध्वियों के प्रति चिन्ता दर्शायी है। यह सरकार एवं उनके मुखिया मुख्य मंत्री जी के सनातन प्रेम को दर्शाता है। जैन समाज का प्रतिनिधि होने के नाते मैं सरकार को बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हम सभी को ज्ञात है कि उदयपुर धार्मिक नगरी है। करणी माता, नीमत माता, रोप वे निर्माण के साथ नगर के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, लेकिन एकलिंगजी, सहस्रबाहू रामेश्वर महादेव मन्दिर, नाथद्वारा मन्दिर, कमलेश्वर कल्याण कमलनाथ मन्दिर, जगत माता जी मन्दिर को जोड़ते हुए पर्यटन धार्मिक सर्किट बनाया जाये। उक्त सभी

(श्री ताराचन्द जैन)

स्थलों के आवागमन की सुविधा विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे न सिर्फ पर्यटकों को अपनी संस्कृति और गौरव से रूबरू होने का अवसर मिलेगा बल्कि आम व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर झीलों की नगरी की शान झीलों के संरक्षण के लिए अतिक्रमण से उनको मुक्त करने का आग्रह करता हूं। इसकी आवश्यकता है जिसके लिए गम्भीरतापूर्वक पहल करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

पिछली गहलोत सरकार ने अपने बजट में घोषणा की कि दस करोड़ की विधायकों को सड़कें दी जायेंगी। ऐसी कई घोषणाएं कर दीं और घोषणा करने के बाद सारा पैसा स्थानीय निकाय पर चुंगी पुनर्गठन में काट दिया। काटने के बाद आज तक कई ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है और वे सड़कें भी अधूरी पड़ी हैं, तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह जो पिछली सरकार ने घोषणा की, वे तो करने वाले थे नहीं, इसीलिये उनको ठुकराया, आप इसको पूरा करें।

आपको बहुत-बहुत धन्याद। आभार।

घोषणा

ई.आर.सी.पी. पर चर्चा के लिए समय व नाम निर्धारण

श्री अध्यक्ष: एक व्यवस्था देनी थी, ई.आर.सी.पी. के बारे में जो मैंने कहा था, कल जीरो ऑवर के बाद इस पर आधे घंटे की चर्चा करायी जायेगी और उसमें तीन विपक्ष के और तीन पक्ष के नाम मेरे को कल सुबह दे दें, ताकि वो इस बहस में भाग ले सकें और मंत्री महोदय उस पर अपना पक्ष रखेंगे।

कुमारी रीटा चौधरी।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। राज्यपाल के

(कुमारी रीटा चौधरी)

अभिभाषण में राज्य सरकार की योजना और कार्यक्रम जो सरकार आरम्भ करेगी उसका एक दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, परन्तु महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया वह केन्द्र परिवर्तित योजनाओं का एक खाका था। केन्द्र की योजनाओं को किस तरीके से राज्य में लागू किया जाये, उसके बारे में आधे से ज्यादा समय उस अभिभाषण में दिया गया। योजनाओं को राज्य में कैसे लागू किया जाये, केन्द्र की योजनाओं को इस पर...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय स्पीकर साहब, यह माननीय मुख्य मंत्री जी की गरिमा के खिलाफ है। चैम्बर में बैठते हैं तब चर्चा करें, एक-एक करके। यह इनकी गरिमा के खिलाफ भी है और सदन की गरिमा के खिलाफ भी है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): व्यवस्था दिलायें कि यहां बैठ कर बात नहीं करें।

श्री अध्यक्ष: यह उनको ध्यान है। आप बैठिए। यह पहले भी होता आया है। कभी कभार हो सकता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यहां चर्चा नहीं करें। ये चैम्बर में विराजें तब बैठें। यह मुख्य मंत्री जी की गरिमा के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। माननीय सदस्य, आपका सदस्य बोल रहा है, आप बैठिए। यह मुझे ध्यान है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेकिन क्या है यह?

श्री अध्यक्ष: यह आपका विषय नहीं है, मेरा विषय है। आप बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बताइये, यह चलेगा? अच्छी बात है?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चैम्बर मिला हुआ है वहां चर्चा करें।

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अध्यक्ष महोदय, कोई मंत्री मिल रहा है मुख्य मंत्री जी से।

श्री अध्यक्ष: यह आपका विषय नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): डोटासरा जी, आपके मुख्य मंत्री आपको लिफ्ट नहीं देते थे, उसका यहां क्यों दर्द निकाल रहे हो। हमारे मुख्य मंत्री जी हमको लिफ्ट दे रहे हैं, आपके मुख्य मंत्री आपको नहीं गांठते थे।

श्री अध्यक्ष: बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसको +++ बना लो।

श्री अध्यक्ष: यह शब्द एक्सपंज किया जाये। यह असंसदीय शब्द है। बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या तमाशा लगा रखा है। सीट पर बैठाओ इनको। (व्यवधान)

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): सदन को आप चलाओगे या अध्यक्ष जी चलायेंगे?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। बहुत हो गया। आप बैठिए। यह मेरा काम है। माननीय मंत्री जी। मेरा काम है यह। चलिये हां, कन्टीन्यू करें।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में समय का एक बड़ा हिस्सा केन्द्र परिवर्तित योजनाओं को राज्य में लागू करने पर ही खतम कर दिया। एक बार तो विधान सभा के सदन में लग रहा था कि हम संसद में बैठे हैं। यहां पर अभिभाषण में सरकार का खुद का कोई विजन नहीं था। डबल इंजन सरकार की बात की गई, रामराज की बात की गई और केन्द्र की योजनाओं को राज्य में कैसे लागू किया जाये, उस पर ज्यादा चर्चा की गई। बेहतर होता कि सरकार का खुद का विजन होता। मुख्य मंत्री महोदय यह बताने में सक्षम होते कि आने वाले एक साल में राज्य में क्या काम किये जायेंगे। पिछली सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं, चाहे वह चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे वह दुर्घटना बीमा योजना हो, चाहे किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा हो, चाहे मुफ्त राशन किट बांटने की योजना हो, चाहे 500 रुपये में सिलेण्डर देने की बात हो, चाहे महिलाओं को मोबाइल देने की बात हो, इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं पिछली सरकार ने लागू कीं। बेहतर होता इस अभिभाषण में यह कहा जाता कि हम उन तमाम योजनाओं को और ढंग से लागू करेंगे और अंतिम छोर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन पिछले 50 दिन में आपने ओ.पी.एस. बंद करने की घोषणा की। चिरंजीवी में कोई काम नहीं हो रहा है। राजीव गांधी युवा मित्र, जो धरने पर बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री

(कुमारी रीटा चौधरी)

महोदय अचानक रात को थाने में जाते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, वहां के थानेदारों और वहां के स्टाफ का रजिस्टर देखते हैं, कौन हैं, कौन नहीं हैं, लेकिन उतनी जरूरत नहीं समझी कि कुछ दूरी पर हमारे युवा मित्र इस कड़कड़ाती ठंड में धरने पर बैठे हैं, उनके पास अपना कोई नुमाइंदा भेज दें, उनके पास कोई अपना आदमी भेज दें, ताकि वे उनकी समस्या को सुनें और उसका समाधान करने का आश्वासन दें। औचक निरीक्षण के बाद भी आज राजस्थान में हालात ये हैं कि हम जनता की बात नहीं करते, जनता की बड़ी-बड़ी परेशानियां गायब हैं, सड़कों पर चारों तरफ ट्रैफिक जाम देख रहे हैं, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, और तो और हमारे सारे के सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं। पिछली सरकार की सड़कों का काम नहीं हो रहा। नगरीय विकास के बजट को रोक लिया, पंचायती राज में विकास के नाम पर जो बजट दिया, उसको रोक लिया। विधायकों के क्षेत्र में विकास कोष को रोक लिया। अध्यक्ष महोदय, इन कामों की समीक्षा करते हुए अभिभाषण आना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात तीन मुद्दों पर करना चाहूंगी। डबल इंजन की बहुत बात की है। हर कोई सदस्य खड़ा होकर डबल इंजन की बात करता है। मेरी जानकारी में डबल इंजन की आवश्यकता जब महसूस होती है, या तो इंजन खराब हो जाये या वह सक्षम नहीं हो। एक इंजन सक्षम नहीं हो तो दूसरा इंजन लगाकर उसको चलाया जाता है। हमारी पिछली सरकार चली, कहीं डबल इंजन की जरूरत नहीं पड़ी। पांच साल बहुत अच्छे चले, बहुत लोक कल्याणकारी योजनाएं आईं। आप लोगों को पता है कि हम इधर क्यों बैठे हैं और आप उधर क्यों बैठे हैं। हर बात में इस बात का जिक्र करना कि आप इसलिए वहां चले गये, आप भ्रष्टाचार का नाम लेते हैं। मेरा मंडावा विधान सभा क्षेत्र खारे पानी का इलाका है और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लड़कियों की एक भी कालेज नहीं है। अगर मैं पिछले पांच साल में लड़कियों की एक कालेज वहां पर लेकर गई तो इसका मतलब मैंने भ्रष्टाचार किया। वहां पर खारा पानी है, घर-घर पानी पहुंचाने का काम किया, इसका मतलब भ्रष्टाचार किया। वहां पर आई.टी.आई. कालेज खुली, इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ। वहां पर बच्चे पड़ोस के जिलों में पढ़ने जाते थे, वहां पर स्कूल-कालेज नहीं थी, चिकित्सालय नहीं था, वहां पर हास्पिटल गया, सी.एच.सी. गई, पी.एच.सी. गई, इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ। अध्यक्ष

(कुमारी रीटा चौधरी)

महोदय, कोई भी जन कल्याणकारी काम होता है तो उसकी सराहना करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण को पढ़ा, उसमें बहुत भारी-भरकम शब्द आये। डबल इंजन, राम राज, अटल बिहारी जी का आपने जिक्र किया। जीते जी उनको पूछा नहीं, मरने के बाद आप उनको याद कर रहे हैं। मैं पैरा नम्बर 20 पर अपनी बात रखना चाहूंगी, उसमें बहुत सारी गारंटियां लिखी गईं। हर गरीब को नि:शुल्क अन्न की गारंटी। मैं इस सदन में बता दूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार राइट टू फूड लेकर आई थी, इसलिए अभी तक यह योजना लागू है। हर हाथ को काम की गारंटी आपने बोला। नरेगा योजना जिसने हर हाथ को काम देने की गारंटी दी, वह कांग्रेस की लाई हुई है। आप लोग अग्निवीर जैसी योजना लेकर आये, युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम आपने किया। 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र बैठे हैं, उनका रोजगार छीनने का काम आपने किया। हर सिर छत की गारंटी, आप मुझे बताओ प्रधानमंत्री आवास योजना आज से चल रही है क्या? यह कांग्रेस राज की है। आपने हर घर में बिजली की बात की, यह कांग्रेस की देन है। हर महिला को सुरक्षा की गारंटी की बात आपने की। आप पहलवान बेटियों को भूल गये, जो दिल्ली की सड़कों पर न्याय मांगती रहीं और बृजभूषण को आपने पनाह दी। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और आप महिला सुरक्षा की गारंटी की बात करते हैं। आज सारे अख़बार गैंग रेप से भरे हुए हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप 100 दिन की कार्ययोजना को अभिभाषण में रखते तो हमें समझ में आता कि आपने महिलाओं की सुरक्षा की क्या गारंटी दी। आपने अपराधी को सज़ा देने की बात की। दिल्ली की सड़कों पर 700 किसान मारे गये। आपके एक केन्द्र के मंत्री के बेटे ने उनको कुचलने का काम किया, आपने आज तक उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की। डबल इंजन की सरकार जैसा केन्द्र में काम कर रही है, वैसा काम राजस्थान में करना चाहते हो तो हम यह होने नहीं देंगे। आपने योजनाओं की बात की, गारंटी की बात की। आपने गारंटी शब्द हमारे पूर्व माननीय मुख्य मंत्री महोदय से उधार ले लिया। आपके प्रधान मंत्री जी आते हैं, यहां एक गारंटी दे जाते हैं। 450 रुपये में सिलेण्डर की बात की, 500 रुपये में तो हम ही दे रहे थे। हम लोगों ने गारंटी दी थी कि आने वाले समय में हर वर्ग को 500 रुपये में सिलेण्डर मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। आप

(कुमारी रीटा चौधरी)
राम राज की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि राम राज में रोजगार नहीं होगा, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की बात नहीं होगी, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्यान्न, गरिमापूर्ण जीवन जीने के सरोकारों पर काम नहीं होगा, आप लोग केवल मन्दिर बनाने का काम करेंगे। उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्रों को भी आपने आयुष्मान मन्दिर का नाम दे दिया। आप लोगों ने सबको मन्दिर सफाई पर लगा दिया। हिन्दू राष्ट्र और हिन्दुत्व की बात आप लोग करते हैं। हमें भी हिन्दू होने पर गर्व है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो भी कट्टरता की बात करता है, जो देश कट्टरवाद में आता है, वह कभी पनप नहीं सकता, कभी विकास की तरफ नहीं बढ़ सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट का समय चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, आपको 10 मिनट दिये जा चुके हैं।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, ऐसे समय में मुझे एक बात याद आती है, आजादी के समय और आजादी के बाद इस देश में विकास में योगदान हर जाति ने दिया, हर लिंग ने दिया, हर प्रांत ने दिया और हर धर्म ने दिया, लेकिन हम एक धर्म की बात करके हम हमारे संविधान को नजरंदाज कर रहे हैं। गुलजार ने अपने शब्दों में कहा-

"गुलाम थे तो हम सब हिन्दुस्तानी थे,
आजादी ने हम सबको हिन्दू-मुसलमान बना दिया।"

जब शासन में उच्च स्तर पर बैठा व्यक्ति विचारविहीन हो जाता है तो वह अलग-अलग बात करता है, लोगों को गुमराह करने की बात करता है। कभी वह 15 लाख रुपये देने की बात करता है, कभी दो करोड़ रोजगार देने की बात करता है, कभी मन्दिर बनाने की बात करता है, लेकिन मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारा वह स्थान है जहां मनुष्य मानव जाति की भलाई के बारे में बात करता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं चार लाइन से अपनी बात खतम करूंगी। अभिभाषण पर हमारी वरिष्ठ सदस्या अनिता भदेल जी ने बात की और मैं हमेशा उनको बड़े ध्यान से सुनती हूं, क्योंकि वे बहुत अच्छी जानकारी के साथ बोलती हैं। लेकिन इस बार राम मन्दिर से वह बाहर नहीं निकलीं।

"आपका भव्य मन्दिर तो तैयार है राम, मगर मर्यादा आपकी तार-तार है राम।
जानकी इस आयोजन में कहीं नहीं है, इनका घर निकलना बरकरार है राम।
हर तरफ बन रही है सोने की लंका, लंकापति विकास का ठेकेदार है राम।

धर्म की ध्वजा है आसमान छू रही,

तुम्हारे भरोसे है 2024 का चुनाव-प्रचार राम।"

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, वह श्रीराम लला का मन्दिर है, छोटे लला का। वहां जानकी जी का काम नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठिए।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): 2014 का चुनाव अन्ना हजारे के नाम पर, टू-जी स्पेक्ट्रम के नाम पर आप लोगों ने लड़ा। 2019 का चुनाव शहीदों के नाम पर आपने लड़ा और 2024 का चुनाव आप राम मन्दिर के नाम पर लड़ना चाहते हैं, आपका कोई विजन नहीं है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय दो घंटे के लिये बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया गया।

माननीय सदस्य श्री बालमुकुन्दाचार्य।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम मेरे आराध्य प्रभु राम को प्रणाम करता हूं, श्रीहनुमान जी को प्रणाम करता हूं, मां भारती को प्रणाम करता हूं। मुझे यहां बोलने का जो समय दिया, उसके लिए आप सब का अभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, विशेषकर प्रथम बार आने के बाद, प्रथम बार मुझे अभिभाषण पर बोलने का अवसर मिला है, कहीं पर कोई त्रुटि हो तो पूर्व में क्षमा चाहता हूं।

सबसे पहले तो हमारे आराध्य भगवान राम, जिनकी वन्दना हम सबने की है और अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। कुछ सदस्यों को जरूर

(श्री बालमुकुन्दाचार्य)
इससे आपत्ति हो रही है। राम की बात आते ही बार-बार उछल-कूद मचाते हैं और फिर ऊटपटांग शब्द बोलने लगते हैं। खैर, यह अपना-अपना स्वभाव है। हम सबके इष्ट राम हैं, प्रभु राम हैं। कुछ लोग राम-राम बोलते हैं, मानते नहीं हैं। यहां राम-राम बोलते भी हैं, मानते भी हैं और राम को जानते भी हैं। श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरी दुनिया एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण क्षण का गवाह बनी। सदियों के संघर्ष के बाद राम मन्दिर का सपना साकार हुआ। राम मन्दिर के पवित्र दरवाजे खुलने पर आध्यात्मिक ज्ञान और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के एक नये युग की शुरुआत हुई है। राम मन्दिर और राम जन्मभूमि के उद्घाटन के साथ ही एक सदी पुरानी इच्छा वास्तविकता बन गयी है। यह दृढ़ता और विश्वास से भरी भावना भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और यह दृढ़ता और विश्वास के प्रतीक हमारे विश्व के नायक, दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधान सेवक, प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी हैं।

राम मन्दिर के निर्माण के समय से ही विरोधियों के बहुत चूंचपड़ के उपरान्त, विरोध के बाद भी राम प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा शासन के कठोर बंदोबस्त के चलते समयानुसार शांति और भव्यता के साथ हुई। आमंत्रण के बावजूद कुछ लोगों को नहीं आना था, वे सभी अनेक स्वयं के रचित कारणों से समारोह में नहीं आये। हो सकता है, राम की इच्छा नहीं थी। ऐसा लगता है कि जिन्ना के भूत अभी आजाद भारत से दफा नहीं हुए। कहीं न कहीं जिन्ना अभी मौजूद है और वह जिन्ना कइयों को राम से दूर रखता है। यह अफसोस और पीड़ा है। सभी सनातनियों को अपने ज्ञान चक्षु अब खोल लेने चाहिए। जिन लोगों को ऐसे अनुष्ठानों में राजनीति दिखती है, उन्हें राजनीति करते रहना चाहिए, परन्तु आज जनता को ऐसे राजनैतिक लोगों को चिह्नित कर अपने को उनसे शीघ्रातिशीघ्र अलग कर लेना उचित होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को साथ रखने से उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे लोग विक्षिप्त मानसिकता के रोगी हैं। प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव देश में अभी तक सम्पन्न हुए कार्यक्रमों में श्रेष्ठतम सभी आयामों में था। देश-विदेश पूरी दुनिया ने इसका आनन्द लिया। राम-राम, जय श्रीराम, जय सियाराम, पूरी दुनिया ने किया।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): पहली बार आये हैं, कुछ समझायें तो सही।

श्री अध्यक्ष: आप इनके पास चले जाना, आपको पूरा समझा देंगे।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): कुछ राम विरोधी और राम मंदिर

(श्री बालमुकुन्दाचार्य)

विरोधी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं आये और कारण गिनाते रहे। इस मंदिर की पुनः स्थापना असंख्य लोगों के बलिदानों के उपरांत पांच सौ वर्षों के उपरांत नसीब हो सकी है। बलिदानी तो हमारे ही कुटुम्बी थे। मन्दिर विरोधियों ने उस बलिदान को भी तिलांजलि दे दी। कुछ तथाकथित नेता यह कहते नहीं थकते कि पत्थर की मूर्ति को पूजने का क्या लाभ होगा? उन्होंने शास्त्र सम्भवतः पढ़े ही नहीं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। भगवान राम ने लंका अभियान से पूर्व समुद्र तट पर...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरा देखकर न बोलें, वैसे ही बोलें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, अगर पढ़कर ही बोलना है तो टेबल करा दें। सदन का समय बचेगा।

एक माननीय सदस्य: राम के नाम पर आप लोगों को क्या तकलीफ है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें राम का कहां लेना-देना है? इनके प्रचवन करा दो, महाराज के यहां। राम के नाम पर प्रवचन करा दो। राम के नाम पर आप लोगों ने क्यों मजाक बना रखा है? (व्यवधान) आप सदस्यों को बताइये, यहां पर कुछ तैयारी करके आएं और अभिभाषण पर बोलें।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): भगवान राम के गुणों की मैं बात करूं तो उनके गुणों में लोभ, ईर्ष्या, स्वार्थ से दूर रहना, मुश्किलों से हार न मानना, संकल्प को पूरा करने का निश्चय, विनम्रता, सबको साथ लेकर चलना, सबका विश्वास जीतना, सहनशीलता और धैर्य, दयालुता, मित्रता, नेतृत्व क्षमता के जो मुख्य गुण हैं, उनको हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने अपने जीवन में उतार रखा है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री लोभ, ईर्ष्या, स्वार्थ से दूर हैं और कोई भी लोभ उनको अपने मार्ग से नहीं डिगा सकता। मुश्किलों से हार न मानने के गुण का उदाहरण कोरोना काल है, जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था, परन्तु माननीय प्रधान मंत्री जी ने हार नहीं मानी और असम्भव-सा कार्य किया, जिसमें कोरोना की तीन-तीन वैक्सीन बनवाने का कार्य किया, जिससे न केवल भारतवर्ष को बल्कि दुनिया के कई देशों को वैक्सीन की सप्लाई कर इस महामारी से निकालने का प्रयास किया। मोदी जी का यह गुण दयालुता और मित्रता का प्रतीक है। भगवान राम से ही ये सारे गुण हम में सम्भव हो पा रहे हैं।

संकल्प को पूरा करने का निश्चय तो माननीय प्रधान मंत्री जी का

(श्री बालमुकुन्दाचार्य)

इतना है कि उन्होंने संकल्प लिया था कि कश्मीर से धारा 370 हटानी है और कश्मीर के लोगों को उनका हक, कश्मीर की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना है तो इस संकल्प को उन्होंने पूरा किया और आज कश्मीर का चहुंमुखी विकास का जो सपना-सा था, वह साकार हुआ। आज वहां पर पर्यटन बढ़ा है, शांति की स्थापना हुई है और निरन्तर तरक्की की ओर कश्मीर आगे बढ़ रहा है। वहां अब पत्थर नहीं, वहां कलम हाथ में है और विकास की ओर कश्मीर आगे जा रहा है। मित्रता के गुण का उल्लेख करें। जिन देशों में भी प्राकृतिक आपदाएं आईं, वहां पर हमारी केन्द्र सरकार द्वारा मानवीय आधार पर चाहे दवाइयां हों, चाहे खाने-पीने का सामान हो, दूसरी तरह की मदद हो। नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सब देशों का हर तरह से सहयोग किया है। हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान में भी जब आपदा आई तो हमारी सरकार, आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उन लोगों की भी भरपूर मदद की। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय प्रधान मंत्री जी से प्रेरणा पाकर ही प्रदेश विकास की गति पकड़ रहा है। सरकार आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और गति प्रारम्भ हो गयी। यह मानवीय विकास को पंख लगे हैं। माननीय मंत्री भजन लाल जी ने संकल्प लिया है, अगर मैं पूर्व सरकार की बात करूं तो पूरे पांच साल...

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्री?

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): मुख्य मंत्री ही बोला है।

आप दुबारा सुन लें माननीय मुख्य मंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी, भा.ज.पा. सरकार का एक संकल्प है, यह एक पूरा परिवार है। पिछली पांच साल की सरकार जैसलमेर की होटलों में AC की हवा खा रही थी और यहां जनता सड़कों पर त्राहि-त्राहि मचा रही थी। पिछली सरकार का कार्यकाल आप हम सबको पता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था। सरकारी आफिसों की अलमारियों में सोने के बिस्कुट पाये जा रहे थे। लगता था कि सरकार के जो मुखिया हैं, उनका जिस प्रकार से ढीला रवैया था, वे पूरे तंत्र को ढीलापन करके, तंत्र में भ्रष्टाचार फैल गया था। पूरे पांच साल कुर्सी की लड़ाई में ही गुजरे और इसका फायदा भ्रष्ट नेताओं, अफसरों ने खूब उठाया। सरकार का भी और पूर्व विधायकों का भी बहुत सारा समय जैसलमेर की होटलों में ही बिताया गया।

पूर्व मुख्य मंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में घोषणा पर

(श्री बालमुकुन्दाचार्य)

घोषणा करते रहे, एडवरटाइजमेंट की सरकार रही। जिस एम.एल.ए. ने जो मांगा, सो उसकी घोषणा कर दी, लेकिन धरातल पर कुछ हुआ नहीं। बजट कहां से आएगा, यह पता नहीं था।

श्री अध्यक्ष: आपका समय हो गया।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): साहब, दो ही मिनट लूंगा। प्रथम बार बोल रहा हूं, इसलिए कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: आधे मिनट में पूरा करिये। आपके सात की जगह आठ मिनट हो गये।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): 2018-19 के अनुसार 31 मार्च, 2019 को राज्य पर रुपये 3 लाख 11 हजार 3 सौ 74 करोड़ का ऋण भार था एवं प्रति व्यक्ति ऋण भार रुपये 40 हजार 300 था, जो बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार 31 मार्च, 2024 को राज्य पर रुपये 5 लाख 79 हजार 781 करोड़ का ऋण भार अनुमानित है तथा प्रति व्यक्ति ऋण भार बढ़कर रुपये 70 हजार 800 अनुमानित है।

सरकार जैसे युवाओं की शत्रु थी, पीछे ही पड़ गई और पता नहीं किस बात का बदला लिया। वैकेंसी निकाल देते, फार्म भरवा लेते, फार्म के पैसे इकट्ठे कर लेते, कोचिंग वालों से सांठ-गांठ कर लेते और जैसे ही परीक्षा होती तो पेपर लीक करवा देते और बच्चों का भविष्य अंधकार में बार-बार डाल दिया गया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: मैं अगला नाम पुकार रहा हूं। बैठिए।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): पुरानी सरकार के मंत्रियों ने अपने चहेतों, रिश्तेदारों को ही नौकरियां बांटने का काम किया। आर.पी.एस.सी., जिसकी साख, रेपुटेशन पूरे देश में थी, उसको मटियामेट कर दिया। पिछली सरकार ने काम ऐसा किया, जैसे मानो नाथी का बाड़ा हो। इस प्रकार का पूरी सरकार ने करके अपना समय बर्बाद किया और राजस्थान की जनता ने जो विश्वास दिया था, जो मत दिया था और टैक्स का जो रुपया दिया था, उसको बर्बाद किया। इसके अलावा कुछ नहीं किया।

(समय: 17.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्री जेठानन्द व्यास।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय,

(श्री गजेन्द्र सिंह)

महाराज ने विपक्ष का शुद्धिकरण भी कर दिया और फ्री प्रवचन भी दे दिया। इनको क्या आपत्ति है? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसे कितने +++ हैं, बता दो ...(व्यवधान) ऐसे कितने +++ हैं सत्ता पक्ष में? वह थोड़ा-सा नाम बता दो।

श्री अध्यक्ष: देखिए, यह शब्द उचित नहीं है। किसी माननीय सदस्य के लिए ऐसा शब्द उचित नहीं है।

श्री जेठानन्द व्यास। (व्यवधान) यह शब्द एक्सपंज होगा। एक्सपंज कर दिया, विराजो। एक्सपंज कर दिया। (व्यवधान) माननीय सदस्य, एक्सपंज कर दिया, विराजो। आगे से ऐसा शब्द, कोई भी अपने शब्दों में ना कहे।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माफी मांगें इन शब्दों पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कार्यवाही से निकाल दिया है। (व्यवधान) मैंने निर्देश दे दिये कि आगे से ऐसी शब्दावली का उपयोग सदन में नहीं किया जाए। विराजो। (व्यवधान)

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई बोलता है तो हमारे विपक्ष के सदस्य ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसी सदस्य के लिए कहना अपमानजनक है। कभी आपके लिए कहेंगे तो यह आपके लिए भी करूंगा। बैठिए। कोई आपके लिए कहेगा तो आपके लिए भी ...(व्यवधान) कभी आप +++ कह देते हो, कभी +++ यह शब्द ठीक नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माफी मांगनी चाहिए ... (व्यवधान)

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के सदस्य अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य की सुनो।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): जब भी कोई सत्ता पक्ष का

(श्री जेठानन्द व्यास)

बोलता है, कुछ सदस्यों की आदत बन गई है बीच में बोलना, उनको टोकना, वैल में आना। ये बड़े परेशान हैं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बना दी। बार-बार बीच में उठकर आते हैं, इसलिए इनको रोका जाए। मैं पहली बार जीत कर आया हूं और वह भी इनके एक भारी भरकम मंत्री, जिनके परिवार के लोगों ने, वहां गुण्डागर्दी कर रखी थी, अवैध नशा बेच रहे थे, उनका पक्ष ले रहे थे। उनके कार्यकर्ता और उनके परिवार भू-माफिया बने हुए थे। जनता ने उनको बीस हजार प्लस वोटों से हराया और बाहर किया। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलिए, बोलिए।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष जी, 16वीं विधान सभा के चुनाव में 75.45 प्रतिशत लोगों ने रिकार्ड मतदान किया है। यह कीर्तिमान और परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का एक अनुपम कार्य है। माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करने का पूरा प्रयास किया और जनता को लोभ दिया। जनता के पैसे को लुटाया, यहां तक कि नि:शुल्क मोबाइल देना। मेरे क्षेत्र में एक महिला के पास एक कांग्रेस का कार्यकर्ता गया, उसने कहा कि कांग्रेस ने आपको मोबाइल दिया है, इसलिए वोट तो दे दो, तो महिला ने कहा कि यह मोबाइल ले जाओ, वोट नहीं देंगे। जनता इनके लोभ में नहीं आई। गुण्डागर्दी का एक विशेष उदाहरण, चुनाव के समय कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, जो सरकार की तरफ से ही था, यह था कि कोई भी गाड़ी बिना नम्बर की जाए तो उसको चेक किया जाए। जब थानेदार जी चेक करने लगे तो उसमें से दो कार्यकर्ता उतरे और थानेदार के थप्पड़ लगा दी। पूर्व मंत्री जी, +++ ने उसको कहा कि हमारे कार्यकर्ता हैं इसलिए मुकदमा दर्ज मत करवाना। आई.जी., एस.पी. ने बीच में पड़कर, हमारे दबाव से उस पर एक मुकदमा दर्ज किया, लेकिन दूसरे दिन वह फिर एस.पी. के पास गये। ऐसे कार्यकर्ता जो जनता को परेशान करते हैं, जनता ने उस व्यक्ति को चुनाव से बाहर कर दिया और हमेशा के लिए उसको रिटायर भी कर दिया।

हमारी सरकार ने नीतिगत निर्णय लिये हैं। पिछली सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण को बंद नहीं किया जाएगा, यह कहा है, लेकिन उसकी समीक्षा की जाएगी कि उन्होंने उसमें कितना घोटाला किया है। उस योजना के पीछे उन्होंने क्या-क्या किया है, उसकी समीक्षा करने के लिए जरूर कहा है। ये

(श्री जेठानन्द व्यास)

बार-बार उछल रहे हैं कि हमारी योजनाएं बंद कर रहे हैं। कभी सरकार ने नहीं कहा कि आपकी योजनाएं बंद कर रहे हैं, इसलिए बहुत सोच-समझकर ही बोलें।

विगत कांग्रेस सरकार ने पांच साल में राजस्थान को सबसे ज्यादा कर्जदार की श्रेणी में ला दिया है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, प्रतिवेदन, वित्त लेखे, 2018-19 के अनुसार 31 मार्च, 2019 को राज्य का 3 लाख, 11 हजार, 374 करोड़ रुपये का ऋण भार था, जो प्रति व्यक्ति 40 हजार, 300 रुपये था। बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार 31 मार्च, 2024 को 5 लाख, 89 हजार, 781 करोड़ रुपये का अनुमान है, जो प्रति व्यक्ति ऋण भार बढ़कर 70 हजार, 800 रुपये होने का अनुमान है। यह जो बड़ा कर्ज है, इस कांग्रेस ने ऋण लेकर, उस ऋण को लूटा, जनता के बीच नहीं दिया। यह प्रति व्यक्ति भार उनकी लूट के कारण हुआ। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी जब बीकानेर आये, अधिकारियों की बैठक ली तो वहां भी एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। वहां इनकी सरकार की निराशा सामने आई।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे दो मिनट और दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आठ मिनट हो गए।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): पहली बार बोल रहा हूं, दो मिनट और दीजिए।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में समाप्त करिए।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): वे वहां आये तो पूछा कि जे.जे.एम. में 2019 में आपको कितने रुपये मिले? तो बताया गया कि 2 हजार 70 करोड़ रुपये मिले। उनको पूछा कि कब तक पूरा करना है, तो बताया कि 31 मार्च, 2024 तक। जब उनसे पूछा कि कितना खर्च किया, तो कहा 400 करोड़ रुपये। पूछा गया कि क्यों नहीं किया, तो उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि वहां के स्थानीय मंत्री जी थे उनका दबाव था। उन्होंने 400 करोड़ रुपये भी अपने परिवार, अपने भतीजे और कांग्रेस के भ्रष्ट कार्यकर्ताओं, उनकी योजना से उन्होंने खर्च किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं अगला नाम पुकार रहा हूं। आधे मिनट में खतम करिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कैसे-कैसे बुलवा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप भी ऐसे ही बोलते थे। (व्यवधान) बैठिए। टिप्पणी नहीं, बैठिए। जल्दी समाप्त करिए।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उनको समाप्त करने दे, आपकी सुनेंगे। (व्यवधान) दो मिनट विराजें।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): अपने वोट के लालच में एक धर्म विशेष को इन्होंने चुनाव से तीन महीने पहले जमीनें अलॉट की हैं, वे सब कैंसिल होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): यह हिन्दू मुस्लिम की बात करते हैं। मुसलमान का पक्ष आज तक कांग्रेस ने लिया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): हिन्दुओं को नुकसान पहुंचाया है। मैं खुलकर कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): ये बोल रहे हैं, इनसे पूछिए कि आपने क्या किया हिन्दुओं के साथ, मन्दिरों के साथ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह क्या परिपाटी है? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस तरह की बातें कर रहे हैं ...(व्यवधान) एक्सपंज करवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसा शब्द कहा नहीं ...(व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इस प्रकार की बातें हैं क्या ...(व्यवधान) राज्यपाल का अभिभाषण है। यह राज्यपाल का अभिभाषण है क्या?

श्री अध्यक्ष: आप तीन-तीन वरिष्ठ माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो जाते हो, आपके नेता खड़े हुए हैं। आप तो बैठिए। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह राज्यपाल का अभिभाषण है क्या? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी परम्परा मत डलवाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर नहीं हैं, वे अपना स्पष्टीकरण भी नहीं दे सकते। भ्रष्टाचार की जो 400 करोड़ की बात कही है, यह सब आप एक्सपंज करवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भ्रष्टाचार की बातें तो आप भी करते हो या नहीं करते हो? वह कोई असंसदीय शब्द नहीं है। श्री प्रशान्त शर्मा।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): वह व्यक्ति जो इस सदन में नहीं है, नाम लिया है इन्होंने, इन्होंने नाम लिया है। जो व्यक्ति सदन में नहीं है, वे अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यक्तिगत किसी का नाम है तो मैं इसकी समीक्षा करूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): इसको एक्सपंज करवाइये आप।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई व्यक्तिगत बात होगी तो मैं इसकी समीक्षा करूंगा। (व्यवधान)

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नाम लिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। आप बैठिए। आप बैठें। मैंने दो-तीन बार आपको कहा है, आप बैठें। आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप बैठिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ये हिन्दू-मुस्लिम की बात कर रहे हैं और मर्जी आये जो बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। कोई असंसदीय नहीं है। असंसदीय नहीं है। मैं इसकी समीक्षा करूंगा। मैंने कह दिया कि मैं इसकी समीक्षा करूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चीज तो गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया कि असंसदीय होगा तो हट जायेगा। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जो मर्जी आये वह बोल जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं इनके भाषण की समीक्षा करूंगा। आप बैठिए। तुष्टिकरण कोई असंसदीय नहीं है। तुष्टिकरण, तुष्टिकरण कहा जा सकता है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम कहा है। उन्होंने तुष्टिकरण नहीं कहा, हिन्दू-मुस्लिम कहा है। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम की बात कही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। हां, आप बोलिए। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप इनको ट्रेनिंग दीजिए कि यहां पर बोलना क्या है? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप भी आसन का सम्मान करना सीखिए।

श्री अध्यक्ष: कार्यवाही वृत्तान्त देखने के बाद मैं विचार करूंगा। माननीय सदस्य, कार्यवाही वृत्तान्त देखने के बाद मैं व्यवस्था दूंगा। आप बैठिए। आप बोलिए। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए। मैं भी आपका बारबार उठना बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बैठिए। आपका भी बारबार खड़े होना बर्दाश्त नहीं करूंगा। बैठिए। बैठिए। मुझे नाम पुकारना पड़ेगा। मुझे नाम पुकारना पड़ेगा। आप बोलिए। ...(व्यवधान) मुझे पता है, आप बैठिए। आप बोलिये। मैंने कह दिया कि मैं समीक्षा करूंगा। (व्यवधान)

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बात सुनिए। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, उसी टाइम से लगातार सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं, बात-बात पर सदन को गुमराह करते हैं। असंसदीय बातें करते हैं। जो परम्पराएं यहां पर नहीं रही हैं, उन पर बातें करते हैं। हिंदू-मुस्लिम की ये बात करते हैं। यह सदन जो है वह संविधान से चलता है। संविधान से चलता है और संविधान इस देश का धर्म-निरपेक्ष है, यह बात इनको भी समझनी पड़ेगी। ये एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, यह गलत बात है और ये हिंदू-मुस्लिम की बात कर रहे हैं, यह गलत है। इसको आप एक्सपंज भी कराइए और इनको प्रताड़ित करिए कि आगे से इस प्रकार की बात सदन में न करें। इससे सदन का समय जाया होता है। बराबर तीन दिन

(श्री टीकाराम जूली)
हो गये इनको समझाते हुए, आप लोगों की समझ में नहीं आता? अध्यक्षजी, आप इनको प्रताड़ित कीजिए। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सत्ता पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य को... (व्यवधान) मेरी बात के बीच में नहीं बोलें, ऐसे उठने से क्या हो जायेगा? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ऐसे नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। I Will name you. ...(व्यवधान) आप बैठें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मुझे मजबूर मत कीजिए। मैंने यह कहा है कि मैं इस कार्यवाही को देखूंगा। आप बैठिए। आपके सदस्य को बोलने दीजिए। अब आप बैठिए। मैंने यह व्यवस्था दे दी। आप बैठिए।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप मेरी बात को सुनें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। आपको बाद में अनुमति दे दूंगा, आप अभी बैठिए।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा कि आप अभी बैठिए। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूं, व्यवस्था की बात है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह आप मुझे लिखकर भेज दीजिए। मैं करूंगा।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): लिखकर नहीं, मैं बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको बोलने की अनुमति नहीं है। इनका अंकित नहीं करें। इनका अंकित नहीं करें। आप बोलिए।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): 000

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसे ही सदन चलाओगे तो बोलने की जरूरत ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप भी +++ कहोगे तो ऐसे में अनुमति नहीं है। आप बैठिए। आप भी बैठिए।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: आपको बीच में बोलने की अनुमति नहीं है। मैं देख लूंगा। मैंने यह कहा है कि समीक्षा करूंगा। बात खतम हो गयी। मैं इसको कार्यवाही के बाद शाम को देखूंगा, कोई शब्द होगा तो देखेंगे। आप बैठिए। हां, आप बोलिए।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय के बोलने के समय ये सारे माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं। यहां पर सदन के नेता बैठे हैं, जिस दिन वे वक्तव्य देंगे, उस दिन व्यवस्था हम बिगाड़ेंगे तो मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि यहां सदन की परम्परा बनी रहे, हमारे प्रतिपक्ष के नेता जब भी खड़े हों तो माननीय सदस्य उनका विरोध नहीं करें, नहीं तो फिर आने वाले समय में यह व्यवस्था बिगड़ेगी।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिए। यह बात संज्ञान में आ गयी। एक सैकण्ड। आप बैठिए। आप सीधी बात नहीं करेंगे। आप बैठिए।

माननीय सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि जब भी कोई सदस्य बोल रहा हो, बीच में कोई भी दूसरा टोकाटोकी बिना अनुमति के खड़े होकर नहीं करे। अब आप बोलिए।

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कोई गलत बात नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह गलत-सही का आप निर्णय करोगे? यह मेरा काम है। आप नहीं बोलोगे। गलत है या सही है, यह मैं तय करूंगा। आपने ठेका नहीं लिया है। आपने ठेका नहीं लिया है। आप विराजें। आप बैठिए। यह आप तय नहीं करोगे। मैंने यह कहा है कि मैं समीक्षा करूंगा, बात खतम हो गयी। मैं समीक्षा करूंगा। आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप आसन को धमका रहे हो क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमानजी, अब आप इनको बैठाइये, नहीं तो मुझे उनको बाहर करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस पर व्यवस्था दे दो कि इस प्रकार की बात नहीं करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया कि मैं इसकी समीक्षा करूंगा। बात खतम हो गयी। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पहले आप अपने माननीय सदस्य को समझाओ। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बर्दाश्त नहीं है। चाहे हमें जान भी देनी पड़े ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए। हां, आप बोलिए।

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन संविधान का पवित्र मन्दिर है तथा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है। आपने इस सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रखने के लिए मेरे को अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं जयपुर जिले के पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र आमेर से चुनकर आया हूं और मेरा यह मानना है कि यहां पर चुनकर आये सदस्य प्रदेश के करोड़ों सम्माननीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हम सभी पर बड़ा उत्तरदायित्व है तथा इस सदन में हमें बहुत ही संजीदगी व सकारात्मकता के साथ चर्चा करनी चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश इस सदन में प्रस्तुत अभिभाषण भारी नकारात्मकता का अनुभव करा रहा है। गत सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी कार्य किये, जिनसे राजस्थान की जनता को लाभ मिला किंतु उनके विषय में अभिभाषण में सकारात्मक चर्चा नहीं की गयी।

इस सन्दर्भ में सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से इस सदी का सबसे भयावह समय कोरोना काल खंड की याद दिलाना चाहूंगा, जब गत सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना का प्रबंधन किया, इसकी सराहना सम्पूर्ण देश में की गयी। इसी समय में तत्कालीन उप मुख्य मंत्री जो पंचायती राज के मंत्री थे, उन्होंने मनरेगा में राजस्थान को पहले नम्बर पर पहुंचाया था तथा इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे सभी किसान व मजदूर वर्गों को मिला था।

हमारे प्रदेशाध्यक्ष यहां पर बैठे हैं, जो उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के रूप में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय आरम्भ किये गये तथा इन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ विद्यालयों में प्रवेश का इतना दबाव है कि प्रवेश हेतु लाटरी निकालनी पड़ती है।

(श्री प्रशान्त शर्मा)

अभिभाषण के बिन्दु संख्या 51 में इनकी समीक्षा के बारे में कहा है, तो मेरा यह निवेदन है कि इनकी समीक्षा के दौरान इनके विस्तार व प्रगति के बारे चर्चा होनी चाहिये, उस बारे में विचार होना चाहिये।

मैं आपका ध्यान गत सरकार के द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को अनेक राहत प्रदान की गयी, उस ओर दिलाना चाहूंगा, जिससे अनेक लोगों को लाभ मिला है, इसका उल्लेख भी अभिभाषण में नहीं है। मेरा वर्तमान सरकार से यह आग्रह है कि संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस शीत ऋतु में कृषकों को दिन में विद्युत आपूर्ति के द्वारा राहत प्रदान करें तथा सायंकाल में घरेलू उपभोक्ताओं की आपूर्ति पर अघोषित कटौती नहीं हो, इस हेतु वर्तमान सरकार की क्या कार्ययोजना है, इसका अभिभाषण में कहीं पर उल्लेख नहीं है।

मैं आपका ध्यान बिन्दु संख्या 52 की ओर आकर्षित करूंगा जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दुग्ध उत्पादन में राजस्थान अव्वल है। मेरा वर्तमान सरकार से यह निवेदन है कि दुग्ध उत्पादकों हेतु गत सरकार द्वारा बढ़ाये गये बोनस की शीघ्र भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

हम आगे भी इस क्षेत्र में श्रेष्ठ बने रहें, इस हेतु क्या योजना है, इसका भी अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।

मैं इस सदन को एक बार पुन: आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मेरे विचार इस सदन में रखने का अवसर प्रदान किया तथा आपके माध्यम से आमेर की सम्पूर्ण जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिसने मुझे इस पवित्र सदन में भेजने का रास्ता तय किया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अतुल भंसाली।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, संयोग से आज जब राजस्थान प्रदेश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मन्दिर में, इस पूजनीय सदन में पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, माघ मास है। मेरे विधायक के रूप में बोलने का मंगलाचरण भगवान श्रीकृष्ण के नाम से कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से और इस मंगलमय सदन में उपस्थित प्रदेश की पौने आठ करोड़ जनसंख्या के निर्वाचित प्रतिनिधियों के आशीर्वाद से अपने प्रथम वक्तव्य के रूप में इस सोलहवीं विधान सभा में महामहिम राज्यपाल के प्रथम अभिभाषण पर चर्चा में सम्मिलित हो रहा हूं।

(श्री अतुल भंसाली)

आशा है, अध्यक्ष महोदय के साथ आप सभी का आशीर्वचन मुझे सम्बलता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

मैं संयोग से ऐसे शहर जोधपुर से आया हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पत्थरों का शहर है, जहां फूलों से दिल वाले लोग रहते हैं। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर अपने पत्थर, स्थापत्यकला, मीठी बोली और भोजन के स्वाद के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। संयोग से यह शहर पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकार के मुखिया अशोक गहलोतजी का भी नगर है, परन्तु कांग्रेस सरकार की विफलता की कहानी कहता है कि कांग्रेस केवल मुख्य मंत्री महोदय की सीट ही बचा पायी। शेष सभी सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जीती हैं। यह आमजन का भा.ज.पा. की विकास की राजनीति और मोदी की गारंटी पर विश्वास का मत है और भारी संख्या में मिले बदलाव की बयार प्रदेश में दिखाई देने लगी है।

राजस्थान के नव-निर्वाचित यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लालजी शर्मा द्वारा अपने 50 दिन के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हासिल की गयी हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि जो ई.आर.सी.पी. का समझौता किया है, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अशोक गहलोत सरकार की नाकामियों के सामने, पांच साल की नाकामियों के सामने यह 50 दिन का टाइम भी और उसकी उपलब्धियां भी बहुत बड़ा मायने रखती है।

प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अन्दर प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व में कलह बढ़ती गयी। वह जैसलमेर से अपना शासन चलाती रही। कोविड में जब लोग मर रहे थे, ये अपनी सरकार बचाने के लिए जैसलमेर और अन्य स्थानों पर होटलों में अपना समय निकाल रहे थे और जनता के साथ इनका सीधा संवाद खतम हो चुका था।

कांग्रेस की परिवारवादी नेतृत्व की वजह से नेतृत्व प्राप्ति की दौड़ में कांग्रेस लगी हुई थी तो अब भा.ज.पा. की सरकार राष्ट्र प्रथम एकमात्र संकल्प वाले श्यामाप्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, भैरोंसिंहजी शेखावत और नरेन्द्र मोदीजी की परम्परा और संस्कारों वाली सरकार है, जिसमें एक चाय बेचने वाला प्रधान मंत्री और एक संगठन का सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्य मंत्री बनता है। यहां किसी की बपौती नहीं है।

पहले कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को पहचान दी महिलाओं के अपराधों में सर्वप्रथम होने की और हमारी भा.ज.पा. की सरकार ने एक ही महीने में

(श्री अतुल भंसाली)

अपराधियों को सलाखों के पीछे बंद कर आमजन में सुरक्षा के अनुभव की पहचान दी है। पहले कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में नकल माफिया से सांठ-गांठ कर युवाओं के सपने को कुचलने की पहचान दी तो अब एक महीने में ही परीक्षाओं के सफल नकल रहित संचालन ने युवाओं के सपनों को उड़ने की पंख की पहचान दी है।

सभापति महोदय, मैं अर्थशास्त्र की छोटी-मोटी गणित जानता हूं। पहले भी पूर्ववर्ती सदस्यों ने भी इस बारे में कहा है। उसको नहीं दोहराता हुआ इतनी ही बात कहूंगा कि पांच साल तक यह निकम्मी पूर्ववर्ती सरकार संसाधनों, वित्तीय प्रबन्धन का कुशासन से प्रयोग किया और पूरे राज्य की जनता को ऋण में डुबोये रखा। ऋण में 76 परसेंट वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति ऋण भी बढ़ाये।

मैं जोधपुर शहर से आता हूं। आप भी भलीभांति परिचित हैं। वहां पर पिछले चार-छह महीने से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की पेंशन बाकी है। उनके अन्दर जबरदस्त रोष है। दूसरा, पी.डब्ल्यू.डी. के अकाउन्ट से पिछली सरकार ने 40 करोड़ और 30 करोड़ के जो टेंडर निकाले थे जोधपुर के अन्दर, वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए थे। सरकार बदलते ही काम बंद हुआ। उसकी पड़ताल करी तो मालूम पड़ा कि उसके लिए किसी भी तरह की वित्तीय स्वीकृति नहीं थी। जोधपुर के अन्दर कोई भी काम के लिए हम प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हैं तो वह एक ही बात कहते हैं कि सी.एम. हाउस से फोन आया था, फोन के आदेशानुसार हमने वर्क आर्डर इश्यू कर दिये। मैं इस सदन में आप सबसे इस बारे में जांच की मांग करना चाहूंगा, क्योंकि इस वित्तीय कुप्रबन्धन का शिकार इस पूरे प्रदेश की भोली-भाली जनता को होना पड़ा है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार 50 दिन पहले आयी। हम विद्युत में सुधार चालू कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले पांच साल में, जब कांग्रेस के मेनिफेस्टो में क्लियर था कि हम जनता को बिजली फ्री में उपलब्ध करायेंगे, दो हजार यूनिट की इन्होंने घोषणा की, पर कुप्रबन्धन यह था कि इन्होंने बिल के अन्दर अधिभार के नाम से कुछ कम्पनियों को फायदा देने के लिए, क्योंकि इनकी गलती से वह केस आगे नहीं बढ़ा, उस पैसे को उन्होंने जनता के ऊपर अधिभार डाल कर वसूला।

श्री अध्यक्ष: सम-अप करिए।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): एक ही मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): इनकी सरकार और अशोक गहलोत सरकार की वित्तीय कुप्रबन्धन का नमूना बताता हूं। पुलिस विभाग में पिछली सरकार का आबंटन 3 परसेंट था और राष्ट्रीय औसत 4.3 परसेंट था। कृषि विभाग में राष्ट्रीय औसत 5.8 परसेंट था और इनका 4.3 परसेंट था। सड़कों और पुलों में राष्ट्रीय औसत 4.5 था, राजस्थान सरकार का 3.6 था। कहने का मतलब यह है कि पूरे पांच साल तक क्षेत्रीय विधायक को मुख्य मंत्री बनाकर लूट-खसोट और चौथ वसूली के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। उसका जीता-जागता उदाहरण जोधपुर की एलिवेटेड रोड, जिसके लिए हमने संघर्ष किया और केन्द्रीय मंत्री ने उसके लिए पूर्ण बजट आबंटन किया। चूंकि केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र जी शेखावत पर पूरे पांच साल अशोकजी गहलोत, उनके ऊपर, आरोप लगाते रहे, जिसके कारण जोधपुर उसकी भेंट चढ़ गया तथा एलिवेटेड रोड नहीं होने दी।

मैं इस सदन से यही आशा करता हूं, इसी प्रकार आप हमारे ऊपर आशीर्वाद रखेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आपणो अग्रणी राजस्थान। मुख्य मंत्री भजन लालजी शर्मा के नेतृत्व में यह सरकार अपने नये कीर्तिमान हासिल करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ जय जिनेन्द्र, जय श्री राम।

श्री अध्यक्ष: श्री अरूण चौधरी।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं इस विधान सभा की उन महान विभूतियों को, स्वर्गीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब से लेकर के हरिशंकरजी भाभड़ा साहब और भी अन्य विभूतियों को नमन करता हूं कि उन्होंने इस सदन को बहुत ही गुंजायमान रखा। आज इस सदन के अन्दर बोलने का अवसर आपके मार्फत मुझे प्राप्त हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वक्ता के बीच में से न निकलें।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा 16वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण पर बोलने का जो मौका आपने मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं।

सर्वप्रथम राजस्थान के हमारे मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुख्य मंत्री बनते ही जो निर्णय किये और अभी हाल ही में ई.आर.सी.पी. पर जो निर्णय किया, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(श्री अरूण चौधरी)

इसके अलावा हमारे युवा साथियों के लिये भी RAS मैन्स के पेपर पोस्टपोन के लिए प्रयासरत थे, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस अभिभाषण के माध्यम से जिस तरह से कि के.जी. से लगाकर पी.जी. तक की शिक्षा को मुफ्त करने की जो घोषणा की, उसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

मान्यवर, बड़े दु:ख की बात है कि हमारे विपक्षी माननीय सदस्यगणों द्वारा बहुत-बहुत लम्बे-लम्बे विचार रखे गये, परन्तु किसी भी माननीय विपक्षी सदस्यों द्वारा पिछले पांच सौ वर्षों से लम्बित भगवान श्रीराम के मन्दिर से सम्बन्धित विवाद को खतम करने वाले हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नाम धन्यवाद प्रस्ताव की एक लाइन नहीं बोली गयी। अपने उद्बोधन में कटाक्ष की भाषा का ही उपयोग किया। बड़े शर्म की बात है कि हम सभी अपने आपको भगवान राम के अनुयायी होने का नाम लेते हैं, जब भगवान राम को टैंट से निकालकर एक भव्य मन्दिर में विराजमान किया है तो हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे प्रदेश की जनता का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 75.50 प्रतिशत वोटिंग करके एक रिकार्ड से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जीत दिलायी और हमें पूरा विश्वास है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक परियोजना रिफाइनरी के क्षेत्र पचपदरा की 36 कौम के आशीर्वाद से निर्वाचित हुआ हूं। मैं विपक्ष के हमारे सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आपके बजट भाषण के अन्दर आपने 2022 के अन्दर इस रिफाइनरी के कार्य को पूरा करने का निर्णय किया था, लेकिन आज दिन तक वह रिफाइनरी का कार्य पूरा नहीं किया और इसकी जो राशि है वह दुगुनी हो गयी है। अब इसका आर्थिक भार भी राजस्थान की जनता पर पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लिए यह बहुत खुशी की बात है कि हमारी केन्द्र सरकार ने 2023 वर्ष को अन्तरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है और राजस्थान के लिए यह भी खुशी की बात है कि हमारे यहां के जो अन्नपूर्णा केन्द्र हैं, इनके अंदर भी मिलेट को काम में लिया गया है। यह भी एक बहुत खुशी की बात है, विशेषकर बाजरे का उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है तो राजस्थान के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है।

(श्री अरूण चौधरी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी सदस्यगणों की जड़ें किसान के रूप में रही हैं, परन्तु आजादी के 75 वर्ष के बाद भी किसानों की कोई सुध नहीं ली गयी है। अब हमारी वर्तमान सरकार सुध ले रही है। उसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने किसानों को जो सम्बल राशि मिलती थी 6 हजार रुपये, उसको 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार किये हैं, उसके लिए भी मैं सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी वसुन्धरा जी की सरकार द्वारा डिस्कॉम को 62 हजार 400 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया था, परन्तु विगत कांग्रेस के कुप्रबन्ध का नतीजा यह रहा कि 88 हजार 700 करोड़ रुपये का भार लाद दिया गया है। यह कहते हैं कि हम विकासशील हैं तो इनका कुप्रबन्ध देखिए कि बिजली के अन्दर इन्होंने कैसी स्थिति की है। अभी हमारे यहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं। मैं आपके मार्फत मुख्य मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि मेरे पचपदरा क्षेत्र में पिछले पांच सालों में इन्होंने जो दुर्गति की है, जो स्थिति की है, खनन और बजरी माफियाओं ने पूरा आनन-फानन के अन्दर तांडव मचा रखा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस मेरे क्षेत्र में सुरक्षा देकर बजरी माफिया को वहां से हटाया जाए।

इसके अलावा, मेरे पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में पानी की भयंकर समस्या है। जैसा कि मेरे साथी भाटीजी ने बताया था कि हमारा क्षेत्र पश्चिम राजस्थान आज टैक्स के रूप में काफी पैसा देता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पानी की रहती है और इस पानी के लिए कोई भी सरकार, आज दिन तक यह कांग्रेस सरकार रही है, लेकिन इन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा जो योजना है, वहां पर दस-दस दिनों में पानी आता है, आये दिन वहां पर लीकेज हो जाता है। उसको ठीक करवाने के लिए तुरन्त निर्देश दिलाएं। इसके अलावा, जोधपुर से जो कल्याणपुर परियोजना है, उसको भी तुरन्त प्रभाव से वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित करावें कि वह पानी की समस्या दूर करावें।

इसके अलावा, हमारे यहां स्कूलों के अन्दर स्टाफ की भयंकर कमी है। हालांकि अधिकांश स्टाफ सीकर और झुन्झुनूं से आता है, लेकिन हमारे विपक्ष के सदस्य, पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी उस ओर इतना

(श्री अरूण चौधरी)

ध्यान नहीं दिया। यहां का जो स्टाफ अपने क्षेत्र में जाना चाहता था, उनको भी वहां नहीं लेकर गये।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां प्रदूषण की एक भयंकर समस्या है। हमारे पाली से लगाकर साइड-साइड में एक इस तरह का नाला बनाया जाये जिससे प्रदूषण रहित बालोतरा हो सके। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री डूंगरराम गेदर।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा पर मुझे बोलने का समय दिया। मैं पहली दफा जीतकर आया हूं और पहली दफा आपने और मेरी पार्टी ने समय दिया, आप सबका धन्यवाद।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुनने से पता चला कि राजस्थान की सरकार का अपना कोई विजन नहीं है और कोई भी नई कार्ययोजना नहीं है, क्योंकि जो 83 बिन्दु इन्होंने पढ़वाये हैं, उनमें से दो-तिहाई बिन्दु सिर्फ पिछली सरकार की कमियां गिनाने में लगाये हैं, जिसमें राजस्थान को बीमारू, पिछड़ा, आर्थिक आपातकाल आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके बजाय इन्होंने कभी आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजस्थान की जी.एस.डी.पी. की जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, वह जहां 2018-2019 में 2.37 प्रतिशत के साथ 31वें स्थान पर थी। वहीं 2021-2022 में 11.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर के साथ देश के अन्दर दूसरे नम्बर पर राजस्थान की वृद्धि दर काउंट की गयी है। इन तीन वर्षों के अन्दर जो 9.68 प्रतिशत हमारी वृद्धि दर रही है, जो कि भारत की जी.डी.पी. की औसत वृद्धि दर 8.10 प्रतिशत से भी अधिक थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि राजस्थान प्रदेश पूरे देश के अन्दर पहला राज्य बना, जहां 25 लाख की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लागू किया गया। राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य बना, जहां 10 लाख की चिरंजीवी बीमा योजना लागू की गयी। राजस्थान देश का पहला राज्य था, जहां लम्पी में 40-40 हजार रुपये कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत पशुओं के लिए दिये गये। राजस्थान देश का पहला राज्य बना, जहां हर जिला हैडक्वार्टर पर मेडिकल कालेज, राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां हर जिला मुख्यालय पर नर्सिंग कालेज, राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां 500 रुपये में

(श्री डूंगरराम गेदर)

सिलेण्डर, राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां नरेगा में 100 से 125 दिन किये। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां शहरी रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां अलग से कृषि बजट, राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां आर.टी.आई. जैसा कानून, राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां गौशालाओं को 9 माह का अनुदान, राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां न्यूनतम मजदूरी का कानून बना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण लिखने से पहले सरकार ने यह नहीं सोचा कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने, कोरोना काल के अन्दर जो सफल प्रबन्धन मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया और भीलवाड़ा मॉडल को, पूरे विश्व के अन्दर सराहने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरा नम्बर 16, 17, 18 और 19 में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही, अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार का जिक्र तो आपने किया है और 'अंधेर नगरी चौपट राजा' जैसे शब्दों का प्रयोग भी आपने किया है, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि पवन ऊर्जा के अन्दर केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान प्रथम पुरस्कार से सम्मानित, 15 जून, 2023 को केन्द्र सरकार ने नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट कार्य किये जाने हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार की ओर से प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग के भास्कर ए. सावंत ने केन्द्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बी.एस. भल्ला से यह सम्मान प्राप्त किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने फाइलों की पेंडेंसी के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं लेकिन 2012 से राजस्थान के अन्दर कृषि की फाइलें पेंडिंग थीं, जिसको 2018 तक पूरा करने का काम राजस्थान की पिछली सरकार ने किया और अकेले श्रीगंगानगर में 2013 से 2018 तक जहां बी.जे.पी. की सरकार में 5,400 कनेक्शन हुए, वहीं 2018-2023 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार में 17,248 कनेक्शन, लगभग साढ़े तीन गुना कनेक्शन अकेले श्रीगंगानगर जिले के अन्दर हुए हैं। महंगी बिजली का भी जिक्र किया, लेकिन 6 घंटे बिजली राजस्थान के किसानों को दी जाती थी, जिसमें हालात आज मात्र 40 दिनों में यह हो गये हैं कि 2-3 घंटे बिजली राजस्थान के अन्दर किसानों को मिलती है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ हर सर पर छत की गारंटी तो

(श्री डूंगरराम गेदर)

आपने दी है, लेकिन पिछले ढाई साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में एक भी पैसा, एक भी नया मकान नहीं आया है। इसका जिक्र आपने नहीं किया। किसान सम्मान निधि का जिक्र तो आपने किया है, लेकिन 10 वर्ष पहले जो किसानों की आय दुगुनी करने का वादा आपने किया था, वह 10 साल बाद भी हवा-हवाई है। इसका जिक्र आपने नहीं किया। आप 3 काले कानून लेकर आये। 700 किसान आपके कारण शहीद हुए, जिस पर एक भी भा.ज.पा. नेता के मुंह से अफसोस का शब्द नहीं निकला।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि श्रीगंगानगर के अन्दर शुगर मिल है। जो गन्ना उत्पादक किसान हैं, जो शुगर मिल से 50 किलोमीटर दूर हैं, उनको साढ़े 27 रुपये अलग से किराया मिलता था, लेकिन 2018 में उस किराये को बंद करने का काम पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। इस सरकार ने भी श्रीगंगानगर शुगर मिल के अन्दर देरी से पकने वाली जो किस्म है, उसको लेना पिछले एक माह से बंद कर दिया है, जिसे चालू कराने की जरूरत है।

इसके साथ-साथ श्रीगंगानगर जिले के अन्दर सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भाखड़ा व आई.जी.एन.पी. के पुराने जर्जर खालों को पक्का करने के लिए पिछले बजट में माननीय अशोक गहलोत साहब ने बजट दिया, जिसका कार्य तीन चरणों में पूरा होना था। प्रथम चरण के कार्य स्वीकृत हुए, टेंडर हुए, पूरे हुए, लेकिन अभी दो चरणों के बाकी हैं। इनके बारे में भी जिक्र अभी तक राजस्थान की सरकार ने नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने प्रदेश में, राजस्थान में गांधी के रामराज्य का जिक्र तो किया है, लेकिन हमारे सदस्यों द्वारा सम्प्रदाय विशेष, समुदाय विशेष, विचारधारा विशेष जैसे शब्दों का उल्लेख किया जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश का संविधान लिख करके 26 जनवरी, 1950 को जो इस देश में लागू हुआ, उसके अन्दर व्यवस्था की थी कि 26 जनवरी, 1950 के बाद इस देश में किसी भी तरह का कोई भेदभाव जाति, धर्म के आधार पर नहीं होगा। गुरु कबीर साहब ने कहा कि

'जात, पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई'।

गुरु रविदास ने कहा,

'जात, पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानवता को खात है रैदास जात के रोग'।

गुरु नानक देव जी ने कहा,

'अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजाया कौन भले को मंदें'।

गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु आदि महापुरुषों ने जिन विचारों को दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): जिन शिक्षाओं को दिया, उन शिक्षाओं और विचारों को कानूनी रूप देने का काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में किया। जिस संविधान की शपथ लेकर हम यहां आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साम्प्रदायिक और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके हम लोग साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं वे संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए। हो गया आपका।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट।

इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी व राजस्थान के तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह जी डोटासरा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज भी लाइन लगाकर के, लाटरी के माध्यम से वहां बच्चों का एडमिशन होता है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के माध्यम से हर गरीब से गरीब मां-बाप यह सपना देख रहा है कि मेरा बेटा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट ज्यादा हो गये हैं।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): इस सपने को साकार करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है, लेकिन इसके बारे में राजस्थान की मौजूदा सरकार ने एक शब्द भी नहीं बोला है। इसलिए ऐसी जो योजनाएं हैं, जो गरीब के कल्याण के लिए हैं, किसानों के कल्याण के लिए हैं, युवाओं के कल्याण के लिए हैं, ऐसी योजनाओं को लागू करके यह सरकार आगे बढ़ेगी तो हम भी कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे...

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अगर इनके साथ किसी तरह का

(श्री डूंगरराम गेदर)

भेदभाव हुआ तो हर चौराहे पर इस सरकार का विरोध करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री देवेन्द्र जोशी।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, इस प्रथम सत्र में आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए मौका दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि अभी प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष ढांचे को आंच नहीं आनी चाहिए। हम भी उससे सहमत हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अगर तुष्टिकरण होगा तो निश्चित रूप से विरोध करना पड़ेगा। पिछले 5 साल में हमने जो तुष्टिकरण का नंगा नाच राजस्थान में देखा है, आप भी उसके साक्षी हैं और हम भी उसके साक्षी हैं।

जोधपुर में जब 2 और 3 मई को बवाल हुआ तो उस समय जिस तरह से एक वर्ग के लोगों ने दूसरे वर्ग को घर में घुसकर पीटा, हम उसके साक्षी थे। मैं था, अतुल जी थे, हमारे केन्द्रीय मंत्री थे। हम 15 मिनट में वहां गये। वहां कांग्रेस का कोई नेता नहीं आया। उस समय जो मुख्य मंत्री थे, उन्होंने उनकी सुध लेना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे लोग हिन्दू थे। अगर कोई अल्पसंख्यक होता तो वे 2 घंटे में वहां पहुंच जाते।

इसी तरह से कोरोना काल में मुख्य मंत्री जी ने काम किया। निश्चित रूप से हम धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता तुष्टिकरण तक नहीं जाए। हम तुष्टिकरण का विरोध करते हैं। हम आगे भी करते रहेंगे। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि धर्मनिरपेक्षता तुष्टिकरण तक नहीं जाए। तुष्टिकरण और धर्मनिरपेक्षता के बीच में जो लाइन है, वह अगर कोई भी व्यक्ति रखेगा तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

आज प्रदेश में माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, मैं उसका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं। मैं अभिनन्दन इसलिए भी करता हूं कि प्रभु श्रीराम की मूर्ति स्थापना के बाद यह पहला सत्र है। मैं सभी सदस्यों का अभिवादन करता हूं कि हम प्रभु श्रीराम के दर्शन के बाद पहली बार इस सदन में आये हैं। सभी का अभिनन्दन है, स्वागत है।

प्रदेश में अब एक सुशासन की बसंती बहार प्रारम्भ हुई है। आमजन में विकास के प्रति विश्वास बढ़ा है। आमजन माफियावाद से मुक्ति का अनुभव

(श्री देवेन्द्र जोशी)

कर रहा है। राजस्थान की नारी में अब सुरक्षा का भाव है। सबसे बड़ी उपलब्धि राजस्थान का युवा अब नकल मुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन से भविष्य के प्रति आश्वस्त है। अब समाज का हर वर्ग तुष्टिकरण के स्थान पर संतुष्टिकरण के भाव के साथ समाज में जीवन यापन कर रहा है।

ऐसे सकारात्मक वातावरण में मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के सोलहवीं विधान सभा के प्रथम अभिभाषण पर चर्चा के लिए सम्मिलित होने पर बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहा हूं। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में यह सकारात्मकता, गौरवबोध कहीं खो गया था। ऐसा लगता था कि सरकार के मुखिया खुद की कुर्सी बचाने के चक्कर में पूरे प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं का भविष्य दांव पर लगा बैठे थे। सरकार का 60 प्रतिशत समय खुद की कुर्सी बचाने में ही बीता। जब लगा कि अब चुनाव सर पर हैं और जनता को जवाब देना पड़ेगा तो आमजन को छलने के लिए कुछ रेवड़ियां बांटने का प्रयास किया गया, लेकिन आम जनता ने उन रेवड़ियों को ठुकरा दिया और हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई जी मोदी की गारंटी को चुना।

मैं माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी का भी अभिवादन करता हूं कि सकारात्मकता के साथ उन्होंने कहा कि कोई भी कल्याणकारी योजना हम बंद नहीं करेंगे। राज्य सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको हम चालू रखेंगे। इसके लिए भी उनका अभिवादन करता हूं। उन्होंने राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए घोषणाएं कीं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं।

माननीय जादूगर जी को यह नहीं मालूम था कि जनता सब जानती है। पिछले चुनाव के समय की गयी सभी घोषणाओं को जनता ने नकार दिया। मैं माननीय जादूगर जी से यह भी जानना चाहता हूं कि उनकी कथनी और करनी में अन्तर क्यों था? आपने मुफ्त की गारंटी दी, जनता ने वह गारंटी नहीं मानी, क्योंकि आपने जनता का विश्वास खो दिया। जनता ने आपकी थोथी घोषणाओं को ठुकराया और मोदी की गारंटी को माना।

मैं पिछले पांच वर्षों का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि वैसे तो मेरा शहर मुख्य मंत्री जी का गृह क्षेत्र था, मोर जब अपने पंख फैलाता है तो देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब पैरों की तरफ देखता है तो रोता है। मेरा शहर आज पिछले 15 वर्षों से इसी तरह से त्रस्त रहा है। अशोक जी हमारे शहर के थे, लेकिन शहर में हुआ क्या? माननीय अध्यक्ष जी, आज भी शहर की स्थिति यह है कि जोधपुर जैसे शहर में जहां जिसने 3-3 बार मुख्य मंत्री चुना हो, उस

(श्री देवेन्द्र जोशी)

शहर में महिलाएं पानी लेने के लिए 4-4 किलोमीटर दूर तक की यात्राएं करती हैं। शर्म आती है क्योंकि वह पाक विस्थापित हिन्दुओं की बस्ती है, इसलिए उनके साथ भेदभाव किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि इस तरह का तुष्टिकरण जिस तरह से जोधपुर में हुआ है आम नागरिक उससे परेशान है। केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए जमीनें दे दी गयीं। उनकी संस्थाओं के लिए करोड़ों रुपयों के दान दिये गये। हमारी संस्थाओं को क्या मिला?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर में पिछले दो साल में जो भी कार्य हुए हैं, स्थिति तो यह थी कि जोधपुर का बहुत अच्छा विकास हुआ है मैं भी मानता हूं कि बहुत अच्छा विकास हुआ, क्योंकि मुख्य मंत्री जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करना पड़ा, यह विकास की अवधारणा है। मैं इसलिए मुख्य मंत्रीजी से भी, क्योंकि वो मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने जोधपुर की सड़कें देखी हैं, महीने भर तक हमारे साथ काम किया है, उनका भी विशेष ध्यान चाहता हूं क्योंकि जोधपुर में आपकी शिक्षा का कार्य हुआ है। आप जोधपुर से सीधा जुड़ाव रखते हैं इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर के लिए इस तुष्टिकरण में जिन-जिन क्षेत्रों में भेदभाव किया गया है, उनको चिह्नित कर उनके विकास की समन्वित योजनाएं बनाएं और विशेष रूप से पाकिस्तान से आये हुए भाईबहन जिस तरह का नारकीय जीवन जी रहे हैं, पाकिस्तान से भी वो नारकीय जीवन के कारण ही हिन्दुस्तान में आये, लेकिन यहां भी उनकी स्थिति नहीं सुधरी, आज वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से वो लोग वंचित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पूरे सदन के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह का एक विशेष पैकेज जो पूरे पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान से विस्थापित हमारे भाईबहन रहते हैं, उनके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने बजट घोषणा में लें, ताकि उन लोगों को लगे कि हमारी सरकार है और हमने इनके लिए कुछ किया।

धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत। एक बार पुनः, आपने समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महामहिम के उद्‌बोधन में उन्होंने हम सभी निर्वाचित विधायकों को, माननीय सदस्यगणों को शुभकामनाएं दीं, बधाई दी और साथ ही हमसे अपेक्षा भी की कि हम राजस्थान के सर्वांगीण और समग्र विकास के लिए कृत संकल्पबद्ध होकर कार्य करें। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता को भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रचण्ड बहुमत के साथ राजस्थान की जनता ने निर्विघ्न और शांतिपूर्वक मतदान किया और एक अच्छी सरकार राजस्थान को दी, एक स्थायी सरकार राजस्थान को दी, उसके लिए उन्होंने शुभकामनाएं भी दीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने गत सरकार के कार्यकाल पर भी चिंता व्यक्त की और जिस तरीके से राजस्थान की गत सरकार ने अकर्मण्यता के साथ फ्लॉप शो किया, उसकी भी उन्होंने जानकारी दी, जिसको मेरे साथी हमारे प्रतिपक्ष के लोग हैं, विधायकगण हैं, उनको इस बात का आब्जेक्शन हो रहा है, परन्तु जिस तरीके से जो विगत सरकार थी वो अन्तर्कलह और अन्तर्विरोध और अहम में उलझी रही और पूरे पांच साल तक जनता त्राहिमाम-त्राहिमाम करती रही। कोई सुध लेने वाला नहीं था, बिना विजन की सरकार, इतना ऋण। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि ऋण तो हर सरकार लेती है, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऋण सिर्फ विज्ञापन देने में खर्च किया जाए, जगह-जगह इश्तिहार चिपका दिये जाएं, जगह-जगह होर्डिंग्स लगा दिये जाएं और उससे लोगों को गुमराह किया जाए तो इस बात में ऋण किस बात के लिए लिया जाए? भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा यदि देखने को मिली, क्या ऋण इसलिए लिया जाए कि उन लोन के पैसों से, ऋण के पैसों से हम भ्रष्टाचार का खुला खेल खेल सकें। यह मैं पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप कहते थे कि हमारे पांच साल बेमिसाल, जगह-जगह इश्तिहार चिपके हुए थे, जगह-जगह विज्ञापन आपने लगा रखे थे। पांच साल बेमिसाल, वो पांच साल बेमिसाल, कैसे बेमिसाल थे? माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, आप इस बात को कृपया बताना कि ये पांच साल बेमिसाल बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के थे या फिर बलात्कार, अत्याचार, महिलाओं के ऊपर शोषण के मामलों में राजस्थान को देश का नम्बर वन प्रदेश बनाने के लिए पांच साल बेमिसाल थे? क्या 19 बार पेपर लीक कराकर राजस्थान के युवाओं से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए पांच साल बेमिसाल थे या अवैध

(श्री संदीप शर्मा)

खनन, पाक्सो एक्ट में इस राजस्थान को सबसे पहले नम्बर का देश में राज्य बनाने के आपके पांच साल बेमिसाल थे या उन गरीब किसानों को जिनसे आपने कर्जा माफी की बात की थी, ऐसे 19 हजार किसानों की जमीनों को कुर्क करने के आपके आदेश के पांच साल बेमिसाल थे? आपने जिस तरीके से असत्य घोषणाएं कीं, वादे किये, पूरे पांच साल तक आपके असत्य वादे, आपकी असत्य घोषणाएं प्रदेश में चलती रहीं और आप लगातार अपने असत्य वादों और घोषणाओं के चलते हुए लोगों को भरमाते रहे, लेकिन धरातल पर एक भी आपका वादा, एक भी घोषणा पूरी नहीं कर पाये। न आप सरकारी भर्तियां दे पाये, न आप बेरोजगारी भत्ता दे पाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां के हमारे सदस्य जब माननीय मुख्य मंत्रीजी या प्रधान मंत्रीजी के बारे में कोई बात कहते हैं तो हमारे इन माननीय सदस्यों को जो प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं, बड़ा आब्जेक्शन होता है। राम मन्दिर के नाम पर बड़ी परेशानी होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी को राजस्थान की जनता ने पलक-पांवड़े बिछाकर उनका स्वागत सत्कार नहीं किया? क्या भविष्य में कोई ऐसा मुख्य मंत्री बने जो समर्पित भाव से, निष्ठापूर्वक, नि:स्वार्थ रूप से अपने जीवन को समर्पित करके जन सेवा में लगा हुआ था, आपको भी ताली बजाकर स्वागत करना चाहिए था। क्या प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी जो आज विश्व के सर्वप्रिय, लोकप्रिय नेता हैं, वो लोक प्रिय नेता, जिसने देश का नाम, देश का गौरव, देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा दिया, ऐसे व्यक्ति पर कौन गर्व नहीं करेगा? वे हमारे भी प्रधान मंत्री हैं, आपके भी प्रधान मंत्री हैं। उनका तो जोरदार तरीके से आपको स्वागत करना होगा, वे देश के 140 करोड़ लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं। उन्होंने वह कर कर दिखाया है जो आप 75 साल की इस आजादी के बाद भी नहीं कर पाये। उन्होंने चांद पर, जहां पर आज तक कोई देश नहीं पहुंचा, उसके दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान उतार कर सिद्ध कर दिया कि भारत देश अब पिछड़ा हुआ देश नहीं है। भारत देश अब चन्द्रमा की उस जगह भी पहुंच सकता है तो सूर्य पर भी अपना अंतरिक्ष यान पहुंचाने का काम भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का जिसका पूरा विश्व सम्मान कर रहा है, पूरा विश्व आज भारत की ओर अपेक्षा भरी निगाहों से देख रहा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारे प्रधान मंत्रीजी ने, अपितु मैं कहता हूं कि जिस तरीके से क्रांतिकारी परितर्वन आप लोग देख रहे हैं, यह क्रांतिकारी परिवर्तन तभी सम्भव होता है जब मन में संकल्प होता है, ईमानदारी होती है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है और

कुछ करने की भावना होती है। उस करने की भावना के साथ ही जो दृश्य आप देख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, तकनीक में आगे बढ़ता भारत, हर क्षेत्र में आगे बढ़ता भारत, चाहे वह मेडिकल का क्षेत्र हो, किसानों का जीवन समृद्ध और सक्षम होते हुए आप देख रहे हो, यह तभी सम्भव हो पाता है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि बड़ी चुनौतियां आपने हमको दी हैं, लेकिन अभी आपने जो ई.आर.सी.पी. हो या जिस तरीके से परीक्षाओं की जांच करने के लिए जो कमेटी बैठी है, यह तो अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी का ट्रेलर देखा है, अभी आप पिक्चर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो प्रश्न पूछ रहे हो कि एक महीने के अन्दर आप प्रश्न पूछना भूल जाओगे, क्योंकि अभी एक माह ही हुआ है। उप मुख्य मंत्रीजी सही कह रही थीं कि बहुत बड़ी गंदगी फैलाकर आप लोग राजस्थान की जनता पर गये हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): आपने राजस्थान प्रदेश को गंदा कर दिया, इस गंदगी को साफ करने के लिए थोड़ा-सा समय चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये दर्जी की बात कर रहे हैं या टेलर की कर रहे हैं या ट्रेलर की कर रहे हैं?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मैं सत्य बोल रहा हूं। इस बात को मैं सदन में रखता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामकेश मीणा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जरूरी है क्या बेइज्जती करवाकर ही बैठना? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बिना अनुमति के न बोलें। आपके सदस्य बोल रहे हैं।

(समय: 18.00 बजे)

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, 19 जनवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह

(श्री रामकेश)

अभिभाषण पढ़ा। अभिभाषण में 83 पैराज हैं, जिन्हें मैंने गहनता से पढ़ा। पढ़ने पर यह ज्ञात हुआ कि ज्यादातर पैराज में पिछली सरकार की आलोचना के अलावा कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है, सरकार का विजन उसमें झलकता है। सरकार क्या काम करेगी, क्या उसकी योजनाएं हैं, क्या उसका विजन है, वह इस अभिभाषण में होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं होकर पिछली सरकार की आलोचना ही इसमें थी।

वाद-विवाद में भी मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों को सुन रहा हूं। सब लोग पिछली सरकार और उसकी योजनाओं की आलोचना कर रहे हैं। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि पिछली सरकार ने बहुत अच्छे काम किये, फिर भी जनता की सेवा में कोई न कोई कमी रही है। इस कारण से हम लोग यहां प्रतिपक्ष में हैं और आप सत्ता पक्ष में हैं। आपका दायित्व, आपका धर्म यह बनता है कि आपकी सरकार अगले पांच साल क्या काम करेगी, आप जनता की सेवा करने के लिए क्या योजनाएं लेकर आएंगे, यह इस अभिभाषण में होना चाहिये था। ये सब चीजें आपने दरकिनार करके राज्यपाल महोदय से बहुत सारी गलत बातें इसमें पढ़वा दीं। सरकार की योजनाओं के नाम पर आपने कई अनर्गल बातों को इसमें सम्मिलित करके उनसे पढ़वा दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था उस समय, जब राज्यपाल महोदय अभिभाषण पढ़ रहे थे, वे मन से बहुत दुःखी थे। वे यह भी अच्छी तरह जान रहे थे कि जिन योजनाओं की उन्होंने अपने मुंह से ही पहले वाले अभिभाषणों में तारीफ की, उन्हीं योजनाओं को आपने हमारी आलोचना के रूप में लिखकर उनसे पढ़वा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, वे बहुत दुःखी मन से इस अभिभाषण को पढ़ रहे थे।

श्री अध्यक्ष: आप मनोविज्ञान के भी डाक्टर दिखते हैं।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार की जो योजनाएं थीं, हम लोग तो यह सोच रहे थे कि नये-नये और निर्विवाद रूप से जो हमारे मुख्य मंत्री बने हैं, हमारे सम्भाग, पूर्वी राजस्थान से उन्हें मौका मिला है। हम तो यह उम्मीद कर रहे थे कि पूर्वी राजस्थान के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी चीजें लिखेंगे। उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी तरह यह पता है कि पूर्वी राजस्थान किस तरीके से पानी का अभाव झेल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर की समस्याएं हैं, इर्रिगेशन के लिए

(श्री रामकेश)

पानी उपलब्ध नहीं है। हमारे जो प्रयास भी हुए, पांचना बांध है, 17 साल से बंद पड़ा हुआ है। हमारी जो चम्बल, गंगापुर, नादौती की योजना 2005 में शुरू हुई थी, वह आज तक पूरी नहीं हुई।

जब ई.आर.सी.पी. की बात चली तो हमारे सामने एक नयी उम्मीद जगी थी कि ई.आर.सी.पी. के माध्यम से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों का भला होगा। प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में कहा, फिर जयपुर में जब उनका भाषण हुआ था, उस समय भी उन्होंने यह जिक्र किया था कि हम ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। चुनाव के समय तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री बाबूलाल गौर के समय में 25 अगस्त, 2005 को दोनों राज्यों के बीच अन्तरराज्यीय जल बंटवारा समझौता हुआ। इसके आधार पर 10 परसेंट पानी मध्य प्रदेश यील्ड से शामिल करते हुए 50 परसेंट डिपेंडेबिलिटी पर इस योजना को लागू करना था। इसकी डी.पी.आर. बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी। डी.पी.आर. 50 परसेंट डिपेंडेबिलिटी पर थी। इसी मांग को लगातार 2017 में जब दुबारा वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री बनीं, उन्होंने इस योजना को केन्द्र सरकार के यहां भेजकर इसे पास कराने की कोशिश की। पुन: जब कांग्रेस की सरकार बनी और गहलोत साहब मुख्य मंत्री बने तो कांग्रेस ने कभी यह नहीं कहा कि यह योजना हमारी है और कभी भी इस योजना का श्रेय लेने की कोशिश नहीं की।

आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने कई बार इस सदन में यह कहा कि सब साथियों को यदि दिल्ली तक भी चलना पड़े तो हम सब चलेंगे। हम यह श्रेय देना चाहते हैं कि यह वसुन्धरा जी की योजना है, भारतीय जनता पार्टी की योजना है, इस योजना को आप लागू करवाइए, इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराइये, लेकिन वह राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हुई। अभी मैं सुन रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली गये थे और दिल्ली जाकर मध्य प्रदेश से नया समझौता करके आये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2005 में दोनों स्टेट्स के मध्य समझौता हो गया तो फिर नये समझौते की क्या जरूरत पड़ रही है? उस समझौते के तहत मोहनपुरा और कुंडालिया, दो बांध मध्य प्रदेश पहले ही बना चुका है। मध्य प्रदेश उन दो बांधों से 2 लाख 30 हजार हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई के साधन विकसित कर

(श्री रामकेश)

चुका है। जो 2 लाख 40 हजार हैक्टेयर की हम यहां बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें पानी कहां से मिलेगा? यहां से जो डी.पी.आर. बनी थी और जिस वैपकॉस कम्पनी ने डी.पी.आर. बनायी थी, उसमें जो पानी की डिमांड थी, वह 1,723 एम.सी.एम. थी। इंडस्ट्रियल डिमांड 286 एम.सी.एम. थी और इर्रिगेशन डिमांड 1,500 एम.सी.एम. थी। इस तरह 3,510 एम.सी.एम. की डिमांड थी। ये वैपकॉस कम्पनी के आंकड़े हैं। हमें अभी इस समझौते के तहत मात्र 2,400 एम.सी.एम. पानी मिल रहा है।

अगर यह 2,400 एम.सी.एम. पानी हम पूर्वी राजस्थान के लोगों को मिला तो इर्रिगेशन तो भूल जाइये, 13 जिलों में ड्रिंकिंग वाटर के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी, पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। आप क्या समझौता करके आये हैं, कहीं हमारे राजस्थान के हितों की अनदेखी तो नहीं करके आये हैं, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। आज दीजिए या कल दीजिए। पूरा सदन आपसे यह अपेक्षा कर रहा है कि आप क्या समझौता करके आये हैं, उसे यहां स्पष्ट कीजिए। अगर आपने यह समझौता राज्य के हितों के खिलाफ किया है तो पूरी कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम बैरवा।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देकर इस सदन तक पहुंचाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, जो आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बारां-अटरू विधान सभा क्षेत्र के मतदाताओं को कोटि-कोटि नमन करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज मुझे सदन में बोलने का मौका मिला। मैं सदन के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को 22 जनवरी को अयोध्या में सम्पन्न हुई राम मन्दिर की प्राण-प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही, माननीय प्रधान मंत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूं, जिनके नेतृत्व में इतने बड़े स्तर पर सफल आयोजन सम्भव हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सरकार के अविवेकपूर्ण नीतियां, अदूरदर्शी निर्णयों व कुप्रबन्धन ने बीते पांच वर्ष राजस्थान को गर्त में ले जाने का कार्य किया है।

(श्री राधेश्याम बैरवा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि गेहूं उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। मेरा बारां-अटरू विधान सभा क्षेत्र कृषि में अग्रणी क्षेत्र है। इसको देखते हुए माननीय श्रीमती वसुन्धरा राजे जी के नेतृत्व वाली सरकार ने क्षेत्र की सिंचाई के लिए परवन वृहत् बहुउद्देशीय योजना को लागू किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पिछले पांच वर्ष में इसके लिए कोई कार्य नहीं किया। यह परियोजना अभी तक लम्बित है। किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक पानी नहीं मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी किसानों की बात तो करती है, लेकिन उन्होंने किसानों से सम्बन्धित सभी योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। यहां तक कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अटरू क्षेत्र में किसानों को डी.एल.सी. रेट से कम मुआवजा दिया गया है।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पेपरलीक से लेकर सड़क निर्माण, बिजली, पानी सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। पूर्ववर्ती भाज.पा. सरकार ने वर्ष 2017 के अन्तर्गत शहरों में हर घर तक पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'अमृत मिशन योजना' की शुरुआत की थी, लेकिन यह योजना कांग्रेस सरकार की कामचोरी की भेंट चढ़ गई और समय पर पूरी नहीं हो पाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' का अपने क्षेत्रों में सफलतापूर्वक आयोजन किया है तथा लोगों तक जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया है। यह एक राष्ट्रीय प्रयास है, जिससे अन्तिम व्यक्ति तक लाभकारी योजनाओं की सूचनाएं पहुंचेंगी।

माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में नई सरकार ने आते ही अपने किये हुए वादों को पूरा किया। जिसमें महिलाओं को चार सौ पचास रुपये में गैस सिलेंडर देना, सी.बी.आई. की शक्तियों को पुन: बहाल करना, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाना आदि शामिल है। इसके साथ ही माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार अनुसूचित जाति एवं अनूसचित जनजातियों के लिए भी प्रयास कर रही है, जिसमें सरकारी पदों को प्राथमिकता से भरना शामिल है।

मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि मुख्य मंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में विकास को एक नई दिशा और राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करेगी।

(श्री राधेश्याम बैरवा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में परस्पर अन्तर्विरोध और खींचतान के कारण शासन की गाड़ी बेपटरी ही बनी रही, लेकिन यह पूर्ण बहुमत एवं डबल इंजन की सुस्थिर सरकार राज्य में विकास के लिए नये कीर्तिमान स्थापित करके न केवल नये राजस्थान का निर्माण करेगी, अपितु विकसित राजस्थान व विकसित भारत, 2047 के संकल्प को साकार करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही हमारी सरकार का मूल मंत्र होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत पांच वर्षों में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही, अकर्मण्यता और संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आमजन, किसान विद्युत कटौती का लगातार दंश झेलने को मजबूर रहा। आमजन में अंधेर नगरी, चौपट राजा की कहावत चरितार्थ होती रही। पूर्ववर्ती भा.ज.पा. सरकार में प्रदेश के डिस्कॉम को आर्थिक सम्बल देने के लिए शुरुआत की गई उदय योजना के माध्यम से डिस्कॉम का 62 हजार 400 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया था। दुर्भाग्य से गत कांग्रेस सरकार के कुप्रबन्धन एवं भ्रष्टाचार के कारण यह ऋण फिर से बढ़कर 88 हजार 700 करोड़ रुपये को पार कर गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने निर्णय कर पेपरलीक मामलों की कड़ी जांच हेतु एस.आई.टी. का गठन कर दिया है। साथ ही, अब भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव और डी.जी.पी. लेवल के अधिकारियों से करवाने तथा नकल माफिया के खिलाफ केस आफिसर स्कीम के तहत मुकदमा चलाने का फैसला लिया गया है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार और माफियाराज का अन्त करने के लिए संकल्पशील है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवाओं में हताशा और अवसाद के कारण आत्यहत्या के बढ़ते हुए मामले चिन्ता का विषय हैं। युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से उनको तनावपूर्ण स्थिति से बाहर लाने एवं उनकी ऊर्जा का रचनात्मक कार्यों में उपयोग करने के लिए प्रदेश के मुख्य शहरों में युवा साथी केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गत सरकार में महिला उत्पीड़न एवं दुष्कर्म के मामले बड़े पैमाने पर सामने आये हैं, जिससे राजस्थान महिला दुष्कर्म के मामले में देश भर में पहले पायदान पर रहा। फलस्वरूप, वीरों और विभूतियों की यह गौरव भूमि बार-बार कलंकित एवं शर्मसार हुई।

हमारी मुख्य प्राथमिकता मातृ शक्ति को समुचित सुरक्षा देकर प्रदेश को ऐतिहासिक मान-सम्मान और गौरव पुन: लौटाना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हर सिर पर छत हो, इस उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा सभी को आवास, हाउसिंग फोर आल सुनिश्चित करने हेतु देश भर में प्रधान मंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। दुर्भाग्य है कि विगत सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों पात्रधारी आवेदन भारत सरकार के निर्धारित पोर्टल सिस्टम पर समय पर अपलोड नहीं होने के कारण 9 लाख से अधिक लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गये थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों की राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका होती है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) श्रमिकों को उनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक मिले, इसके लिए श्रमिकों का श्रम पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जायेगा। हमारी सरकार असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को आयुष्मान भारत, पी.एम. जीवन ज्योति बीमा योजना, पी.एम. श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से श्रम कल्याण की दिशा में संकल्पशील रहेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, अटरू नगरपालिका में ग्रेवल के नाम पर करीब 20 लाख के फर्जी टेंडर लगाये, फर्जी भुगतान उठाया। वास्तव में, ग्रेवल डाली ही नहीं गई। आज भी कई बस्तियां कीचड़ से सनी हैं, ग्रेवल की जगह मिट्टी डालकर खानापूर्ति की गई। नगरपालिका अटरू में सफाई और ठेके के कर्मचारियों के नाम पर भी फर्जी तरीके से भुगतान उठाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): पूर्ववर्ती कांग्रेस ने फर्जी टेंडर कर अपने चहेते ठेकेदारों से सांठ-गांठ करके भुगतान उठाया है अटरू खाल में खुदाई के नाम पर लाखों रुपये फर्जी उठाये गये हैं। जिसका कोई मैनेजमेंट, मेजरमेंट नहीं है, जबकि वहां पर एक रुपये का भी काम नहीं हुआ। नाला सफाई काम में 16 लाख रुपये उठा लिये, जबकि नाला सफाई हुई ही नहीं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करिए। बस, हो गया अब।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री आदू राम मेघवाल।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों एवं प्रदेशवासियों को प्रभु श्रीराम जन्म भूमि पर श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा पर शुभकामनाएं देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल जी के द्वारा राज्य की विकासपूर्ण नीतियों का प्रस्तुतीकरण किया गया है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मां भारती के अनन्य साधक हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र की बात हमेशा अपने उद्बोधन के अन्दर, जो भारत-पाक सीमा का पहला विधान सभा क्षेत्र है, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं सदस्य चुनकर आया हूं, पांडवों की तपोभूमि, डूंगरा सा परमेश्वरा, धर्म राखे भ्रम, मां वाकल विरात्रा माता शक्तिपीठ, भक्ति और शक्ति की स्थली मां वैर माता, जसनाथ जी का लीलसर धाम...

(समय: 18.19 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मालाणी के महादेव, मोहनपुरी महाराज जी की जन्मस्थली, धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से सम्पूर्ण विश्व में विख्यात कपालेश्वर महादेव मन्दिर, जहां मारवाड़ का अर्द्धकुम्भ सुंईया मेला भरता है।

मैं, माननीय सभापति महोदय, उसी चौहटन की पवित्र धरा, देवतुल्य जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस सदन के सदस्य रहे स्व. भैरोंसिंह जी शेखावत, श्री परसराम जी मदेरणा, श्री पूनम चन्द जी विश्नोई, श्री हरिशंकर जी भाभड़ा, श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी, श्री भंवरलाल जी शर्मा और अनेकों इसी सदन के सदस्य, जिन्होंने इस सदन की गरिमा बढ़ाई है, मैं उन सबको भी आज के दिन याद करता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): आज के दिन स्व. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करता हूं, जिन्होंने गांव और ढाणी तक सड़क पहुंचाने का काम किया। मैं आज के दिन भैरोंसिंह जी की सूझबूझ...। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जो जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं, वहां गांवों और ढाणियों में लोग बसते हैं, वहां राजस्व ग्राम बनाकर प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, उसका सबसे ज्यादा कोई फायदा मिला है वह बाड़मेर और जैसलमेर की जनता को मिला है, वहां के गांव और ढाणियों में रहने वाले लोगों को।

श्री सभापति: समाप्त करें। सहयोग करें, माननीय सदस्य।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर जिला देश और प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, जहां पर बिजली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, जहां पर लिग्नाइट, ग्रेनाइट, तेल के भण्डार हैं।

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्री मनोज कुमार।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): 000

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। प्लीज सहयोग करें। विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। इस अभिभाषण को सुनकर बेहद निराशा हुई है। जिस तरह से महामहिम के मुख से गलत तथ्य पेश करके सदन में बुलवाया गया उनसे और सिर्फ पिछली सरकार के कार्यों पर टीका-टिप्पणी, सिर्फ उन पर छींटाकशी का काम किया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर इस अभिभाषण में आने वाले पांच साल में सरकार का विजन क्या है, उसके बारे में कुछ बताते, रोजगार की बात करते, कहीं रोजगार का नाम नहीं पांच साल में कि सरकार आने वाले समय में रोजगार के लिए क्या कर रही है। सरकारी भर्तियों की जो प्रक्रिया चल रही है, उनको कब तक पूरा करने का है, उस पर कुछ नहीं बोला गया है। सिर्फ और सिर्फ पिछली सरकार के कामों पर छींटाकशी करने का काम किया गया है।

सभापति महोदय, बात रामराज्य की की जा रही है, पर इस शासन में हो क्या रहा है? मुख्य मंत्री जी बैठे थे, अभी चले गये। बताना चाहता हूं कि सुजानगढ़ में एक सड़क का निर्माण किया गया था पिछली सरकार के समय। टू लेन को फोर लेन किया गया, जिसमें एक गेट था उसको तोड़ कर दुबारा

(श्री मनोज कुमार)

उस गेट का निर्माण हुआ जिसका उद्घाटन हुआ और उसके बाद अभी 22 तारीख को जब अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी तो वहां के भी हिन्दू समाज के लोगों ने उस दरवाजे पर राम दरबार लगाने की घोषणा की कि राम दरबार स्थापित किया जाये। उसके लिए उन्होंने तारीख मुकर्रर कर दी कि इस तारीख को होगा, पर व्यक्ति विशेष का नाम न होकर 11 संतों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कराने का जब उन्होंने निर्णय लिया तो उस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की, जबकि वह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन कर रहे थे। जब उन्होंने उस कार्यक्रम को किया, राम दरबार की मूर्तियां उस गेट पर लगायीं, तो सरकार ने उन पर गलत एफ.आई.आर. दर्ज करा दी सरकारी अधिकारियों के वहां से। उनका दोष क्या था? दोष सिर्फ इतना सा कि उन्होंने वहां लाउड स्पीकर लगा कर चौबीस घंटे का अखण्ड रामायण का पाठ कर लिया या उनका दोष यह कि उन्होंने सड़क के किनारे, सड़क पर नहीं, सड़क के किनारे भूमि पर टेंट लगा लिया। वहां प्रसाद का कार्यक्रम हो गया। लोगों की भीड़ हो गयी। कार्यक्रम इस तरह का था तो भीड़ होनी ही थी। आज यू.पी. के मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि अयोध्या अभी रामलला के दर्शन करने मत आइये, भीड़ ज्यादा है। वहां भीड़ हो सकती है तो यहां गांव में क्यों नहीं हो सकती भीड़? उसके लिए एफ.आई.आर. दर्ज करा दी सरकारी अधिकारियों ने। सरकार को संज्ञान लेना चाहिये। जब मुख्य मंत्री जी जवाब दें तो उसके पहले जानकारी लेकर इस एफ.आई.आर. को निरस्त करायें। सरकारी मुकदमा जो दर्ज किया है उसको वापस लिया जाये।

सभापति महोदय, अभिभाषण में बिन्दु संख्या 8 में कहा कि चुनावी जनसभाओं के दौरान किये गये वादे और संकल्प पत्र है, उनको पूरा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, पर साथ में यह भी लिख देते कि कौन से वादे आप पूरे करोगे और कौन से आपके जुमले हैं, क्योंकि प्रधान मंत्री जी, आपकी पार्टी के नेता तो यही कहते हैं कि हमारे तो चुनावी सभा में जो हम वादे करते हैं वो तो जुमले होते हैं, तो वह लिस्ट दे देते, ताकि जनता कन्फ्यूज नहीं होती कि कौनसे वादे पूरे करोगे और कौनसे इनके जुमले हैं। आप लोगों ने उसमें कर्ज की बात की कि पांच साल में पिछली सरकार के समय कर्ज लगभग दुगुना हो गया। साथ में यह भी लिख देते कि केन्द्र सरकार में तो तीन गुना कर्ज हो गया। इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है। केन्द्र का उस पर नियंत्रण है तो कर्ज भी बढ़ रहा है और साथ में यह भी लिख देते कि उससे पिछली सरकार में कितना कर्ज छोड़ कर गये थे और कितना बढ़ा, ताकि तुलना हो जाती।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): लिखा हुआ है।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): हां। लिखा हुआ है, तभी तो कह रहा हूं कि जहां तीन गुना बढ़ रहा है यहां तो दो से भी कम है। आप लोगों ने जी.डी.पी. की बात की, 4.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे की आप लोगों ने बात की है, पर केन्द्र का 6.71 प्रतिशत राजकोषीय घाटा है जी.डी.पी. का, वह भी आप देख लें, ताकि तुलना हो जाती इस पांच साल के कार्यकाल की। 11 प्रतिशत की विकास दर इस दौरान सरकार ने दी है। एक ऐतिहासिक और पूरे देश में दूसरे स्थान पर थी विकास दर और अगर नोर्थ इंडिया की बात करें तो पहले नम्बर पर उस समय राजस्थान था विकास दर में। यह पिछली सरकार ने काम किया।

सभापति महोदय, इन्दिरा रसोई की आपने बात की कि इसकी समीक्षा करेंगे। इसका नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई करेंगे। नाम बदल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले की तरह जिस तरह से इस सरकार ने सम्मानजनक तरीके से उनको बैठा कर एक अलग ही स्थान देकर सम्मानजनक तरीके से खाना खाने की व्यवस्था की है, वह पुन: सड़क पर गाड़ियां लगा कर सड़कों पर खाने के लिए मत छोड़ देना। यह मेरा आपसे आग्रह है। उसमें आप जो रसोई है, आप सुधार करो, नाम बदलो, वह आपकी इच्छा, पर कम से कम वह ध्यान जरूर रखें।

सभापति महोदय, आप लोगों ने बात की कि गेहूं का एम.एस.पी. 2,700 रुपये करेंगे पर अभी 2,400 है, वह कब तक करने का है? जो घोषणा हुई है वह 2,400 रुपये की है, वह भी आप बता दें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पांच साल में।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): पांच साल में करेंगे, जरूरत तो किसान को आज है। पांच साल तक वह इंतजार करेगा आपका।

प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं। पिछले दो साल से केन्द्र से एक भी प्रधानमंत्री आवास के नहीं आ रहे हैं। सब पर रोक लगी हुई है आपको पता है। प्रधानमंत्री आवास जितने भी हैं सारे के सारे रोक रखे हैं। एक भी वहां से स्वीकृत नहीं हो रहा है। लगातार दो साल से यह हो रहा है।

सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना, जिसकी जगह आप लोगों ने बात की आयुष्मान योजना लेकर आ रहे हैं, बिलकुल लेकर आइए। जो चिरंजीवी योजना देश ही नहीं पूरी दुनिया का मॉडल बन गया, उसको आपने बंद किया है, पर उसमें जो पच्चीस लाख का इलाज है उसकी व्यवस्था तो आप कीजिए।

(श्री मनोज कुमार)

उन गरीबों की तरफ देखिए जिनके पास जेब में पैसा नहीं है। उनका कैसे इलाज होगा? आयुष्मान में पांच लाख का इलाज है। उस पच्चीस लाख के इलाज की आप कैसे व्यवस्था करेंगे? वह भी इसमें थोड़ा बताते, ताकि पता चलता।

सभापति महोदय, आज एक ऐसी योजना जिसको आप बंद करने की बात कर रहे हो और उसका विकल्प क्या है, उस पर कोई बात नहीं। आप लोगों ने पी.एच.सी., सी.एच.सी. का नाम बदल दिया। उनको मन्दिर का नाम दे रहे हैं। कोई बात नहीं पर रातोंरात नाम बदलने से वो मन्दिर नहीं बन जायेंगे। उनमें सुविधा क्या बढ़ा रहे हैं आप? जिस तरह से पिछली सरकार में पी.एच.सी., सी.एच.सी., सब सेन्टर खोले गये, एक इतिहास बना है, उनको आगे बढ़ाने का, उनमें और सुविधा जुटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वह आप बताते, उनको करते, खाली नाम बदलने से कुछ नहीं होगा।

बिन्दु संख्या 71 में आपने बात की कि युवा शक्ति को नशे से दूर रखने का माननीय सदस्य प्रयास करें। माननीय सदस्य क्या प्रयास करेंगे, सरकार क्या प्रयास करने जा रही है? वह भी इसमें लिखते कि सरकार का भी कोई विजन है। जो नशे की बीमारी इस राजस्थान में बढ़ रही है, उसको दूर करने का क्या कोई प्रयास है? हम सदस्य बिलकुल उसमें करेंगे, लेकिन इस बारे में एकदम आप मौन, कुछ भी नहीं कहा जा रहा। पिछली सरकार की एक से एक बेहतरीन योजनाएं हैं, जिनको गारंटी से लागू किया था। चाहे 100 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, जो हर उपभोक्ता को मिल रही है, आपको भी मिल रही है। 2,000 यूनिट किसानों को फ्री मिल रही है। गेहूं के साथ राशन फ्री योजना हो, नरेगा 125 दिन की योजना हो। इन योजनाओं को और आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, क्या इसके बारे में आप लोगों ने सोचा, इस पर आप बिलकुल मौन हैं।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): आप लोगों ने कहा, पशु के लिए कुछ नहीं किया। तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी ने 40 हजार रुपये की पशु बीमा योजना लागू की थी और वह उन सब पशुधारकों को उस समय मिली थी, जिनके लम्पी बीमारी में पशु मर गये थे। उसमें आगे क्या सुधार करेंगे, आप लोगों का विजन यह होना चाहिये। 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन, 1,000 से कम किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगी। जब-जब कांग्रेस की सरकार आई है,

(श्री मनोज कुमार)
उसमें इसको बढ़ाया ही है। इस बार आप देते कि हम 1,000 से कितनी पेंशन बढ़ाने जा रहे हैं, इस पर भी आप मौन। धन्यवाद सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम विश्नोई। माननीय सदस्य, आपको बोलने के लिए 7 मिनट दिये गये हैं। माननीय सदस्य, 7 मिनट में आप अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): फिर मैं बैठ ही जाता हूं, आप बुलवा दीजिए।

श्री सभापति: मैंने नहीं, आपके चीफ-व्हिप साहब ने दिये हैं। यह मेरा डायरेक्शन नहीं है।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): पारीक साहब, आप जब भी आते हो, मुझे टोकने में आपको आनंद आता है। इसलिए मैं बैठ ही जाता हूं। आप दूसरे को समय दे दीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह मेरी तरफ से तय नहीं किया हुआ है। यह टाइम आपके स्पीकर साहब ने तय किया है, मैंने नहीं किया है। 7 मिनट का समय दिया है आप सभी को। श्री पब्बाराम विश्नोई।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): पिछले सत्र से ही यह चलता आ रहा है, मुझे याद है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी 16वीं विधान सभा में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। पिछली कांग्रेस सरकार अन्तर्विरोधों की सरकार थी। होटलों में चलने वाली सरकार और एक तरफ बोर्डर पर, मानेसर में चलने वाली सरकार थी। घोषणाओं की सरकार है, जिसने हमेशा घोषणाओं के आधार पर तालियां पिटवाने का काम इस विधान सभा में किया। विद्यालयों की जो स्थिति हुई, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी शिक्षक थे, उनको उठाकर आप शहरी क्षेत्र में ले आये और हमारे वहां पर बच्चों की स्थिति खराब कर दी। पूर्व में हमारे वासुदेव देवनानी जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने स्टाफिंग पैटर्न के द्वारा स्टूडेंट्स के हिसाब से स्टाफ देने की व्यवस्था लागू की और काउंसलिंग की व्यवस्था की। उसको भी आपने बिलकुल धराशायी कर दिया। आपकी कानून-व्यवस्था बेपटरी हो गई थी। गैंगस्टर दिन-दहाड़े लोगों को मार कर छिप जाते थे और आप उनका संरक्षण करते थे, ऐसी सरकार थी।

(श्री पब्बाराम विश्नोई)

फिर बाद में गारंटियों की सरकार आई, लास्ट के 6 महीने पहले गारंटियां देना शुरू कीं। उस समय बेपनाह घोषणाओं की गारंटी थी, जो कभी कार्य रूप में परिणीत नहीं हो पाई। तुष्टिकरण की सरकार थी और तुष्टिकरण का एक उदाहरण मैं मेरे क्षेत्र का देता हूं। मेरे यहां होपावड़ी बड़ा गांव है। उसके पास में एक लाल खां की ढाणी है। आपके शिक्षा मंत्री जी ने वहां पर आपके अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय को एक नेता की ढाणी में, एक व्यक्ति की ढाणी में ले जाकर कर दिया। क्या उस ढाणी में दूसरी बेटियां पढ़ने के लिए जायेंगी? कौन जा सकता है वहां पर? इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करके उस विद्यालय को गांव में शिफ्ट किया जाए, अन्यथा उसको बिलकुल हटा दिया जाए, कोई आवश्यकता नहीं है।

इसी प्रकार से पेपर लीक की जो गारंटी आपने दी थी, पूरे पांच साल तक 19 पेपर लीक हुए थे और हमारे युवाओं का भाग्य आपने बिलकुल बरबाद करके छोड़ दिया था। उस समय में भ्रष्टाचार बेलगाम था। सचिवालय में करोड़ों रुपये और सोने की शिलाएं वहां मिली थीं, यह स्थिति थी। विभिन्न माफियाओं को संरक्षण की गारंटी आपने दी थी। बजरी-खनन माफिया, नशा माफिया को आपने गारंटी दी थी, गैंगस्टरों को खुली छूट दी थी, यह आपके समय की गारंटी थी। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी आज ही आपके सामने ई.आर.सी.पी. लेकर आये। पांच साल तक आप इस पर राजनीति करते रहे। उस राजनीति को सिर्फ 50 दिनों में यहां धरातल पर उतारने का काम हमारे मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने किया। पेपर माफियाओं के ऊपर एस.आई.टी. गठित की। आज सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है और एक-एक को पकड़ा जा रहा है। हम उनकी जड़ों तक भी जायेंगे, यह आप समझ लेना। जो कोचिंग सेन्टर हैं, वहां पर भी जाने का काम हम लोग करने वाले हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस। आयुष्मान भारत में 25 लाख की गारंटी है और आपकी चिरंजीवी तो यहां पर भी हांफ रही थी। महिलाओं के साथ थानागाजी जैसी घटना न हो, इसके लिए भी हमारी सरकार की गारंटी है। आपके पूर्व मंत्री जी, जो अभी यहां नहीं हैं, जो अपनी अंतिम पारी खेलने आये हैं, उन्होंने इस पवित्र सदन में जैसा बयान दिया कि यह राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बयान हो नहीं सकता। इस प्रकार के बयान को सभी को निन्दा करनी चाहिये।

जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ। इन्दिरा रसोई में न तो आप गरीब को भूखा सोने देते थे और न ही उसको भरपेट भोजन देते थे। अब अन्नपूर्णा में 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम देकर भरपेट भोजन देने का काम हमारी सरकार कर रही है।

हमारा सीमावर्ती जिला बना है और आपने जितने भी जिले बनाये हैं, उनमें 17 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जीत कर आये हैं और एक आपका जीत कर आया है। यह स्थिति है आपके जिलों की। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की भी गारंटी है। मैं उन पांच-सात गारंटियों का यहां जिक्र करना चाहूंगा।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): दो मिनट में ही पूरा कर रहा हूं।

जब राम जी का नाम लेते हैं तो इधर से बिदकते हैं, इनका पेट फूलता है, हालत खराब हो जाती है। आपको क्या तकलीफ होती है? हमारी यह पीढ़ी कितनी भाग्यशाली है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, हमारे अनेक योद्धाओं ने अपने मस्तक वार दिये उस भूमि के लिए, आज हम देख रहे हैं कि रामलला उसमें विराज रहे हैं। यह हमारी पीढ़ी को देखने को मिला है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसमें भी आपको दर्द होता है।

धारा 370 हटी तो उसमें भी आपको दर्द है। पहले जगह-जगह बम फूट रहे थे, अब वह बम फूटने बंद हो गये। जयपुर में बम फूटते थे, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बंगाल में फूटते थे। आज कहां गये वे लोग?

स्वच्छ भारत मिशन से लेकर स्वास्थ्य की गारंटी, उज्ज्वला योजना में 450 रुपये में सिलेण्डर...।, आपने तो, जब सरकार अंतिम सांस गिन रही थी, उस समय 500 रुपये किये और हमने सरकार के शुरुआत में ही 500 से घटाकर 450 में करने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी को बधाई देता हूं। जन औषधि केन्द्रों में 90 परसेंट से लेकर 50 परसेंट कम पर आपको औषधि मिल रही है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में आप भी सोलर प्लांट लगा लीजिए। सूर्योदय योजना के तहत आपको 54 हजार रुपये की सब्सिडी हम दिलवायेंगे और इससे आपका बिजली का भी संकट मिटेगा। विदेश में काम करने वाले भारतीयों की जीवन की सुरक्षा की गारंटी भी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी दे रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): सर, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं।

सर्जिकल स्ट्राइक करने की भी गारंटी, आतंकियों की कब्रगाह बनाने की भी गारंटी नरेन्द्र मोदी की गारंटी है। पाकिस्तान को भिखमंगा बनाने की भी गारंटी नरेन्द्र मोदी की गारंटी है। चीन जैसा दुर्दान्त शत्रु है, उसको अपनी औकात में रखने की गारंटी भी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी है। अभिनन्दन को अभिनन्दन करने की गारंटी है।

श्री सभापति: समाप्त करें। अंकित नहीं हो। प्लीज विराजिये। श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सोलहवीं विधान सभा में प्रथम बार बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं।

सबसे पहले धन्यवाद ही मैं मेरे मकराना विधान सभा क्षेत्र की जनता को देना चाहता हूं, जिसने मुझे बहुत भारी मतों से जिताकर इस सदन में भेजा। मकराना शहर, वह शहर है, जहां हिन्दू-मुसलमान की एक मिसाल पैदा होती है। मकराना सिटी एक वह सिटी है, जहां मुसलमान भाई मन्दिर बनाते हैं और हिंदू भाई मस्जिदों का काम करते हैं। ऐसी मिसाल पूरे भारत वर्ष में कहीं नहीं मिलेगी, जो मकराना विधान सभा क्षेत्र में मिलती है। मकराना विधान सभा क्षेत्र के सभी मजदूरों ने पूरे भारतवर्ष में एक नाम कमाया, चाहे बिरला मन्दिर हो, अभी राम मन्दिर की चर्चा बार-बार सभी सदस्य कर रहे हैं। इस राम मन्दिर का जो निर्माण हुआ, रामलला के गर्भ गृह का जो काम हुआ है, वह मुसलमान भाइयों ने मिलकर, मकराना के वासियों ने किया है। चाहे देश-विदेश में जो मन्दिर बने हैं, उसका काम मकराना की सभी जनता ने किया है। मैं ऐसे विधान सभा क्षेत्र से आप लोगों के बीच में आया हूं।

मैं तीन दिनों से देख रहा हूं, राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद हो रहा है। यह वाद-विवाद न होकर इधर-उधर की बातें हो रहीं है। वे इसलिए हो रही हैं, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के 26 पेज में 83 पैरा हैं जिनमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मुद्दे की बात हो। इसमें मात्र केन्द्र सरकार की योजना है या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना थी, उसको बंद भी नहीं करना चाहते, उसको समीक्षा के बहाने से...। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह दर्शाया गया है। यही राज्यपाल जी, कलराज जी मिश्र साहब, जिन्होंने अभी पिछले तीन-चार भाषण कांग्रेस के पक्ष में दिये,

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)
उन्होंने गुणगान किये। आप पिछले अभिभाषण के अन्दर देखिए, उन्होंने क्या-क्या चर्चा की। आज मजबूर होकर आप लोगों के समक्ष यह अभिभाषण निकाला है। इस अभिभाषण के ऊपर लोगों को उम्मीद थी कि जब आपकी यह सरकार बहुत भारी मतों से बनी तो लोगों को उम्मीदें थीं कि डीजल-पेट्रोल की रेट आप कम करेंगे, लेकिन इसमें राजस्थान की जनता को निराशा मिली। इस अभिभाषण में किसानों की आय दोगुनी करने की उम्मीद थी। इसमें किसानों की कोई चर्चा नहीं है। इस अभिभाषण के अन्दर किसानों के लिए कोई कार्ययोजना नहीं बनायी गयी है कि पांच साल में हम क्या करेंगे।

इस अभिभाषण में प्रदेशवासी युवाओं को रोजगार देने की बात की उम्मीद थी, लेकिन इसमें नहीं। एक बात जरूर है कि जब बी.जे.पी. सरकार बनी तो राजीव गांधी युवा मित्र, जो पांच हजार युवा मित्र राजीव गांधी युवा मित्र में भर्ती हुए थे, उन सभी को हटा दिया गया। वे इसलिए हटा दिये गये हैं, क्योंकि उसका नाम राजीव गांधी युवा मित्र रखा गया है। अगर आपको इनको रखना था तो आप नाम चेंज करके रख देते, जैसे आप हमेशा की तरह नाम चेंज करते हैं। उनकी गलती क्या है? उन्होंने अपना फार्म भरा, इन्टरव्यू, सलेक्शन हुआ, प्रचार-प्रसार किया। आपकी सरकार की यदि योजना अच्छी आती तो आपका भी ये लोग प्रचार करते।

मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करके आपको यह कहना चाहता हूं कि आपने पैरा 22 के अन्दर इंदिरा रसोई का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई करने की घोषणा की है। आप पहले अन्नपूर्णा के नाम से चलाते थे, लेकिन अन्नपूर्णा रसोई एक बस के अन्दर चलती थी, जो आम आदमी, गरीब किसान या जो बाहर से आदमी आता था, वह ढूंढता था कि बस कहां गयी, लेकिन हमारे पूर्व लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने इसको इंदिरा रसोई का नाम देकर एक स्थान चिह्नित किया कि यह बस स्टैण्ड पर रहेगी, यह रेलवे स्टेशन पर रहेगी, यह कोर्ट के बाहर रहेगी, यह नगरपालिका में रहेगी। आपकी अब मंशा यह है कि 200 की संख्या की जगह 100 की संख्या में खाना दिया जाए। अभिभाषण के अन्दर आपकी यह झलक दिखती है।

इसी तरह से आपने पूर्व में 'राजीव गांधी सेवा केन्द्र' का नाम बदलकर 'अटल सेवा केन्द्र' नाम रखा। जब हमारे पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने 10 हजार ग्राम पंचायतों में 10-10 लाख रुपये के राजीव गांधी सेवा केन्द्र खोले थे, आपने 10 रुपये का एक काला रंग पोतकर उसका नाम अटल सेवा केन्द्र में बदल दिया। आपकी हमेशा यही मंशा रही है।

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

आपने पैरा 51 में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के बारे में भी कहा। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी, जो अध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने हर गरीब किसान की बात सुनी, पैसे वाला बच्चा तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था या बाहर हॉस्टलों में जाता था, लेकिन गरीब किसान का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने से वंचित था। हमारी सरकार ने हर गांव के अन्दर करीब 3 हजार 741 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलें खोलीं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता था।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): आपने पैरा नम्बर 52 के अन्दर गायों का जिक्र किया। आपने गायों के नाम से वोट तो हमेशा मांगे हैं, लेकिन जब लम्पी की बीमारी हुई थी, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 40-40 हजार रुपये गायों के लिए मुआवजा दिया और 9 महीने का अनुदान दिया।

पैरा 67 के अन्दर आपने दर्शाया है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्मार्ट सिटी करने की घोषणा की, जिसमें उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा शहरों का नाम दिया गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने स्मार्ट सिटी का जो मॉडल बनाया है, आप कोटा जाकर देखिए, कितनी सुन्दर स्मार्ट सिटी, हमारे पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री श्री शान्ती धारीवाल जी और मुख्य मंत्री जी ने बनायी। जयपुर को कितनी बढ़िया स्मार्ट सिटी बनाया, आप इन्हीं का मॉडल अगर और जगह शहरों में बनाते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जब पूर्व में प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी ने, जब दस साल पहले प्रधान मंत्री थे, हर सांसद को एक ग्राम पंचायत गोद लेने की बात कही थी। यहां पर भी पूर्व सांसद बैठे होंगे, आप एक भी सांसद बता दें कि हमने इस ग्राम पंचायत को गोद में लेकर एक मॉडल बनाया है। ये खाली आपकी बातें हैं, केवल किताबी बातें होती हैं, बाकी और कुछ नहीं है।

आपने पैरा नम्बर 23 के अन्दर सिलेण्डर 450 रुपये में देने की बात कही है। यह तो हमने पहले 500 रुपये में देने की घोषणा कर दी। आपकी स्मृति ईरानी, जो कि केन्द्र में मंत्री हैं, जब मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, गैस की टंकी माथे पर लेकर घूमती थीं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री गोपीचन्द मीणा।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): सभापति महोदय, एक मिनट।

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

जब स्मृति ईरानी गैस की टंकी लेकर घूमती थीं। 'बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार'। गैस की टंकी की रेट 1100-1200 बढ़ गयी तो हमारे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के अन्दर निकले थे। प्रतिपक्ष के नेता के क्षेत्र के अन्दर वहां घोषणा की थी कि गैस की टंकी 500 रुपये में देंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री गोपीचन्द मीणा। प्लीज, अंकित नहीं होगा।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): 000

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे सोलहवीं विधान सभा में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, जोगेश्वर गर्ग जी ने सदन का समय नहीं बोलकर, समय का सदन बोल दिया, उसको संशोधित करा लें।

श्री सभापति: सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

प्लीज आप विराजिए। आसन ने व्यवस्था दे दी। आसन की व्यवस्था हो गयी। आप आसन पर व्यवस्था मत दीजिए। सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

श्री गोपीचन्द मीणा।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री चुनाव के समय भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी में आये थे और उन्होंने सभा में अपने उद्बोधन में कहा था कि भीलवाड़ा जिले से कांग्रेस मुक्त करनी है तो उनके आशीर्वाद से, कोटड़ी चारभुजा नाथ के आशीर्वाद से भीलवाड़ा जिले में सात की सात सीटें भारतीय पार्टी के पक्ष में आयीं, आशीर्वाद मिला, क्योंकि भीलवाड़ा और मेवाड़ में कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार किया था, भ्रष्टाचार का इतना तांडव पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। इन्होंने फर्जी ज़मीनें आबंटित कीं, निजी संस्थानों को आबंटित कीं। माफिया राज, भ्रष्टाचार, लूट इतना अत्याचार किया, उसकी सज़ा जनता ने कांग्रेस को दी जो विपक्ष में सामने बैठे हैं, इनको दिख रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में, देश में, वर्तमान में आमजन के जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कार्य हो रहे हैं। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, हर घर नल योजना, जनजाति, अनुसूचित जनजाति दलित या पिछड़ों के उत्थान कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा महत्व दिया जा रहा है।

22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्रीराम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन ऐतिहासिक रहा। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में भव्य समारोह मनाया गया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने डी.एम.एफ.टी. फंड के घोटाले, भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताएं की हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन कार्यों की जांच होनी चाहिए। विकास कार्य को गति देने का हमारी सरकार काम करेगी। वर्तमान में हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री भजनलाल जी द्वारा भ्रष्टाचार पर मजबूत प्रहार करने की दिशा में दृढ़ इच्छाशक्ति से निर्णय लेते हुए, भ्रष्टाचार के प्रकरणों में सी.बी.आई. द्वारा अनुसंधान की शक्ति बहाल कर दी गयी है। साथ ही प्रदेश में एस.आई.टी. का गठन किया गया है।

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पात्र गरीब लोगों को लाभान्वित किया गया है। हमारी सरकार विकसित भारत संकल्प, 2047 के साथ विकसित राजस्थान बनाने के लिए कटिबद्ध है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं के इशारे पर, पूर्ववर्ती सरकार के इशारे पर, मेरे जहाजपुर कोटड़ी विधान सभा क्षेत्र में मुकदमा नम्बर 104/2010, मुकदमा नम्बर 145/2015, 15 साल होने के बाद भी अपराधियों को ऐसे भ्रष्ट

(श्री गोपीचन्द मीणा)

नेताओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, गरीब को न्याय नहीं मिला। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब को न्याय दिलाया जाए दोषियों की गिरफ्तारी की जाए।

भीलवाड़ा जिले में सात की सात सीटें भाजपा को दी हैं। दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक द्वेषता से, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया था पर पूर्ववर्ती सरकार ने एन.ओ.सी. नहीं दी। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया जाए और भीलवाड़ा के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। कोटा की तर्ज पर भीलवाड़ा शहर को भी विकसित किया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में गाड़ोली महादेव का स्थान, धोड महादेव का स्थान, कोटड़ी चारभुजा नाथ का स्थान, घटाणी माता जी का स्थान, चोलेश्वर जी का स्थान, कोटा श्याम का स्थान, बीजासण माता जी के कुतलवाड़ा के स्थान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की मांग करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में तुष्टिकरण को बढ़ावा देने के लिए देवनारायण-बनी का जो स्थान था अमरगढ़ पंचायत में, इन्होंने उसको कब्रिस्तान के लिए आबंटित कर दिया, उसको निरस्त करने की मैं मांग करता हूं।

राजकीय महाविद्यालय, जहाजपुर में सैट-अपार्ट 30 बीघा जमीन थी, उस जमीन को निजी संस्थान को दे दिया। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्ट नेता उसमें लिप्त, उसमें बड़ा घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। करोड़ों रुपये की जमीन को इन्होंने कुछ अंशदान लेकर निजी संस्थान को आबंटित कर दिया। मैं उसको निरस्त करने की मांग करता हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: दो मिनट और बोल सकते हैं आप।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): हो गया।

श्री सभापति: दो मिनट और बोल सकते हैं, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): कोई बात नहीं, हो गया।

श्री सभापति: श्रीमती इन्द्रा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी और कांग्रेस पार्टी को भी, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चल रही है, सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको बार-बार यूज किया गया है। मुझे लगता है कि इनको यह वर्ड लिखकर दिये गये हैं। जो शब्द बार-बार इन्होंने यूज किये हैं, 'तुष्टिकरण बार-बार यूज किया है, भ्रष्टाचार का नाम बार-बार यूज किया है, भगवान राम का नाम बार-बार लिया है। इन तीनों से विकास का क्या सम्बन्ध है? इन तीनों शब्दों पर इन्होंने जोर दिया है। इन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर निबन्ध लिख दिया। सारे लोगों ने कांग्रेस पर ही बोला है। यह निबंध प्रतियोगिता कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि तुलनात्मक होनी चाहिए। पिछली बार इन्होंने क्या किया, हमने क्या किया और अब यह क्या करना चाहते हैं, तीनों पर निबन्ध होना चाहिए। इन्होंने एक ही, पांच साल पर निबन्ध लिखा है। मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि आपने विपक्ष में बैठकर यह तीन शब्द सीखे हैं, जो बार-बार इनका यूज किया है। विकास से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

मैं बात करना चाहूंगी कि विकास की तुलना इन्होंने राम मन्दिर से की है। सभापति महोदय, मुझे ऐसी आशंका होती है, आपकी कुर्सी पर अशोक स्तम्भ लगा हुआ है, पीछे गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है मुझे लगता है कि किसी दिन ये दोनों हटने वाले हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की बात नहीं करते, ये संविधान की बात नहीं करते हैं, ये तुष्टिकरण की बात करते हैं।

सभापति महोदय, मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सरपंच है। पिछले दस सालों पहले रहा, भा.ज.पा. की सरकार में रहा। वह बार-बार आता है और कहता है, साहब, फलां मस्टररोल मंगवाओ, चोरी हो रही है। उसने खुद ने मस्टररोल में चोरी की, बार-बार चोरी की बात करता है। इसलिए इनको भ्रष्टाचार की बात याद आती है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हैं। हमारी कांग्रेस सरकार ने कई प्रतिष्ठान बनाये, उनको बेचने को भ्रष्टाचार कहते हैं। इन्होंने उद्योगपतियों के साथ क्या कमिटमेंट कर रखा है, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, ये ज़िलों की बात करते हैं कि ज़िले तोड़ दिये, यह कर दिया। इसी सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री के पांव छुए हैं इनके विधायकों ने, जिन्होंने ज़िले बनाने की मांग की, मांग पूरी की उस पर।

विधान सभा में उसके फोटोग्राफ भी होंगे, खड़े होकर अभिवादन किया है कि मेरे ज़िले बना दिये। उस बात को यह क्यों नहीं बोलते?

ई.आर.सी.पी. की बात करते हैं। पूर्वी राजस्थान से माननीय मुख्य मंत्री है, हम ई.आर.सी.पी. की बात करना चाहेंगे। अब तो श्रेय भी आप ले लो, केन्द्र में सरकार आपकी, राज्य में भी आपकी, अब क्या चाहिए आपको? अब तो आप हमारी ई.आर.सी.पी. को लागू कर दो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कर दिया।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): लागू करेंगे, जब होगा। उसको तोड़-मरोड़कर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: शान्त रहें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): उसमें क्या किया है, हम उसकी जानकारी चाहते हैं। सभापति महोदय, जिस तरीके से बहस चल रही है, यह विकास के स्तर पर बढ़ने वाली बहस नहीं है। एक मंत्री महोदय ने तो अपने आफिस से, जहां मंत्री का आफिस है, वहां से डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो हटा दी, वहां से महात्मा गांधी जी की फोटो हटा दी। यह कौनसी राजनीति करते हैं? भगवान राम पर ये वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, बिजली की क्या स्थिति हो रही है? किसान खेत में जाता है, एक क्यारी पिलाता है और दो घंटे बैठे रहता है। बिजली की क्या स्थिति हो रही है? उसके बारे में एक भी माननीय सदस्य ने नहीं बोला।

माननीय सभापति महोदय, हमने ओ.पी.एस. लागू की। मैंने ओ.पी.एस. का सवाल लगाया, 22 तारीख को वह लिस्टेड हुआ। सूचीबद्ध हुआ। आज उसका आना था, लेकिन उसको कटवा दिया, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। यह जवाब नहीं देना चाहते। सवालों के जवाब तो इनको फिर देने पड़ेंगे, फिर सदन चलेगा,फिर हम पूछेंगे।

गोशाला की बात करते हैं। गाय के नाम पर कई बार इन्होंने वोट लिये। हमारी सरकार ने पिछली बार नन्दी गोशाला खोलने की बात की, इन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में यह लिखकर दिया कि गोशालाओं में कुछ नहीं किया। मेरे बौंली और बामनवास दो ब्लाक है। बौंली के अन्दर नन्दी गोशाला

स्वीकृत हो गई, जमीन अलाट हो गई और उसका काम चालू हो गया है। मैं चाहती हूं कि इतने ही गौभक्त हैं बामनवास में गोशाला बनाकर दिखाएं। चिरंजीवी योजना की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमने जमीन गिरवी रखते, गहने गिरवी रखते हुए देखा है।

(समय: 19.00 बजे)

श्री सभापति: आप दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): आने वाला समय ऐसा ही आने वाला है जिसके अन्दर लोगों को यह झेलना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो क्या मेरे विधान सभा क्षेत्र में कालेज खोलना भ्रष्टाचार था? क्या गरीबों को एक हजार रुपये, बुज़ुर्गों को पेंशन दी, विधवाओं को पेंशन दी, ये भ्रष्टाचार था? ये सारी चीजें, जितनी भी योजनाएं, चिरंजीवी योजना में क्या भ्रष्टाचार था? ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि किस तरीके की राजनीति ये कर रहे हैं? फ्री बिजली हमने किसानों को दी। ये किसानों की बात करते हैं। फ्री बिजली, दो हजार यूनिट दी तो किसान समझ चुका है और अभी दो महीने के अन्दर इन्होंने काम चालू नहीं किया। किसी भी योजना का ये काम चालू नहीं कर रहे हैं। ये जवाब नहीं देना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, कोई दवाई लेने जाता है तो दुकान वाला उनको दवाई नहीं देता है। हास्पिटल में दवाई नहीं मिलती है। मुख्य मंत्रीजी ने 22 तारीख को एक घोषणा की है। उसके अन्दर छह श्रीराम जानकी औद्योगिकी क्षेत्र क्रियाशील करने की बात कही है, जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र का भी एक औद्योगिकी क्षेत्र जो हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दिया है, पहले ही उसके अन्दर 80 परसेंट काम हो चुका है तो अगर यह करना चाहते हैं तो बामनवास में करें, अभी तक वहां पर औद्योगिकी क्षेत्र घोषित नहीं हुआ है तो उसके अन्दर करें, लेकिन पहले वाले का नाम बदलकर उसको करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, ये कहते हैं कि हर घर को छत मिलेगी तो आज भी गांवों में जाकर पूछो तो वे क्या नाम लेते हैं? इंदिरा आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, इन्होंने कितना ही नाम बदल दिया लेकिन वहां आज भी गांव की महिलाएं यह कहती हैं कि मैडमजी, इंदिरा आवास दिलवा दो। इंदिरा आवास का नाम लेती हैं। हमारे द्वारा चलायी गयी योजना का ये बार-बार नाम बदलते हैं। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, इंदिरा रसोई मेरे नाम से खोली। कई सारी योजनाएं मेरे नाम से हैं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आज पता चला कि आपके नाम से है।

श्री सभापति: उन्हें बोलने दें। माननीय सदस्य, प्लीज। विराजिए। विराजिए। माननीय सदस्य, आप कन्क्लूड करिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज में प्रधानमंत्री आवास बनाने की बात ये कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): प्रधानमंत्री आवास का दो साल से कोई काम नहीं चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये पोर्टल बंद कर चुके हैं। उसके लिए भी मैंने सवाल लगाया है तो उसके अन्दर इन्होंने बहुत सारा लम्बा-चौड़ा जवाब दे दिया, लेकिन उसका अर्थ ही समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाह रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, इनसे कितने ही सवाल हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने पूछे हैं, हम लोगों ने पूछे हैं, लेकिन एक सवाल का भी ये ढंग से जवाब नहीं दे पाये हैं। लगातार हम इनसे प्रश्न पूछते रहेंगे और जनता उसको सुनती रहेगी लेकिन इस सदन के अन्दर जनता सुन रही है, इनको देख भी रही है। ये बार-बार मजाक उड़ाते हैं कि आप इधर क्यों बैठ गये, इधर क्यों बैठ गये? क्या ये पिछली बार इधर नहीं थे? ये भी तो थे इधर, लेकिन हम इधर इसलिए बैठ गये, क्योंकि आप लोग फ्री थे, आप प्रचार-प्रसार करने में थे, हम लोग विकास कराने में थे, इसलिए हम लोग विकास की राजनीति कर रहे थे, हम लोग विकास कराने में थे और आप लोग भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार करने में थे...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज। समाप्त करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): इसलिए लोगों को गुमराह करके, दुष्प्रचार करके आप लोग इधर आ गये हैं। आप लोग होर्डिंग्स, बैनर लगाने में माहिर हैं। आप लोगों ने नोटबंदी की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): आप लोगों ने राम मन्दिर के नाम पर चंदा इकट्ठा किया, उन सबको मिलाकर आप लोग प्रचार-प्रसार में लगा रहे हो और हम विकास कराने में और ईमानदार ...(व्यवधान)

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): हम ईमानदारी की वजह से इधर बैठे हुए हैं, लेकिन जनता जल्दी ही समझ जायेगी आप लोगों को।

श्री सभापति: प्लीज, विराजिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय सभापति महोदय, सोलहवीं विधान सभा में राज्यपाल महोदय के पहले अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

गत 19 जनवरी, 2024 को महामहिम ने अपना अभिभाषण सदन में रखा और 23 जनवरी, 2024 से इस पर वाद-विवाद हो रहा है। इसी मध्य 22 जनवरी, 2024 को भारत के सांस्कृतिक एवं गौरवमय इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ और जुड़ा है। हमारे कोटि-कोटि जन के आराध्य भगवान श्रीराम लला के मन्दिर का बहु-प्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पूर्ण हुआ है। मैं इस सफल आयोजन के लिए केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्म भूमि न्यास व सभी राम भक्तों को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं।

मैं राजस्थान की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि प्रदेश की जनता ने विगत चुनाव में भा.ज.पा. को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता सम्भालने का जनादेश दिया है। मैं माण्डलगढ़ क्षेत्र की जनता व भा.ज.पा. संगठन के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे सामान्य परिवार के व्यक्ति को भी दूसरी बार सदन में प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्रदान किया।

पिछले विधान सभा चुनाव में जनता ने भा.ज.पा. व माननीय प्रधान मंत्री की नीतियों व विकास योजनाओं पर अपनी मुहर लगायी है। अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों के वक्तव्य सुन रहा हूं। मुझे इनके वक्तव्यों में निराशा व हताशा दिख रही है। मुझे यह लगता है कि अब इनकी बेचैनी भी स्वाभाविक है। लोक सभा चुनाव, 2024 सामने है। देश व प्रदेश की जनता फिर मोदीजी के नेतृत्व में जनादेश देने को आतुर है। विगत विधान सभा चुनाव तो सेमी फाइनल था, अब 2024 फाइनल है। मेरे प्रतिपक्ष के मित्रों की बेचैनी ऐसी है जैसे जल बिन मछली जो तड़पती रहती है। लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि है। आज वार्ड के पार्षद व गांव के सरपंच से लेकर प्रधान मंत्री तक भी हमारे दल के हैं।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

देश में सर्वाधिक सांसद और विधायक हमारे दल के हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्वाधिक सांसद और विधायक हमारे दल के हैं। यह सारा चमत्कार अचानक नहीं हुआ है। 1952 में जनसंघ के दो सांसद थे। राजस्थान विधान सभा में जनसंघ के आठ विधायक थे, वहां से हमारी यह यात्रा शुरू हुई है। 1984 के लोक सभा चुनाव में भा.ज.पा. के दो सांसद, हमें केवल दो सीटें ही मिली थीं, तो हमने जनादेश को स्वीकार किया तो आप भी जनादेश को स्वीकार करना सीखें। हमारा संगठन व हमारे कार्यकर्ता निरंतर सक्रिय रहे हैं और हमारा यह सौभाग्य है कि हमारी पार्टी और देश को माननीय मोदीजी जैसा नेतृत्व मिला है। पिछले चुनाव परिणाम के बाद मेरे प्रतिपक्ष के मित्रों के लिए एक शेर याद आ रहा है कि- "जिंदगी ने हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि न तो हम जी पा रहे हैं और न ही मर पा रहे हैं।"

पन्द्रहवीं विधान सभा में मैं और मेरे साथी विधायक प्रतिपक्ष में बैठते थे तो हमने हर मुद्दे पर, हर विषय पर सरकार को समय रहते हुए चेताया था और जनाक्रोश के प्रति आगाह किया था, लेकिन सरकार में बैठे लोग अपने अन्तर्विरोधों में, आपसी खींचतान में यह सरकार उलझी रही। पहले वाली राज्य सरकार की पहचान बाड़ेबंदी वाली सरकार के रूप में रही है। सरकार रिसोर्ट्स में जाकर बस गयी। पेपर लीक, महिला अत्याचार, कानून-व्यवस्था सहित कई मोर्चों पर पिछली सरकार असफल रही है। ऋण माफी के लिए दस दिन की गिनती गिनकर सत्ता पाने वाले वादे और सारे नारे खोखले साबित हुए हैं। प्रदेश में 19 हजार किसानों की ऋण पेटे जमीन कुर्क हो गयी है।

मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए महामहिम महोदय के प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं। अभिभाषण में वस्तुस्थिति का चित्रण व वर्णन है। विगत विधान सभा चुनावों में राजस्थान की जनता ने माननीय प्रधान मंत्रीजी में विश्वास व्यक्त किया है और मैं उन जन भावनाओं को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं कि-

"उबलते हुए खून की रवानी है मोदी,
इस देश के युवा की जवानी है मोदी,
अब तक सोये हुए हिन्दुस्तान को जगाने की कहानी है मोदी।"

केन्द्र सरकार ने अपनी विभिन्न विकास योजनाओं से आम जनता के

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

बेहतर जीवन जीने की बुनियादी सुविधाओं को जोड़ने का प्रयास किया है, यह जनादेश उसी की परिणति है। हर घर को नल जैसी भागीरथी योजना माननीय प्रधान मंत्रीजी लेकर आये हैं। जल जीवन मिशन का पिछली सरकार ने क्या हश्र किया है, वह आपके सामने है। प्रदेश इस योजना में 33वें स्थान पर चला गया है। इस योजना के घोटाले खुल रहे हैं, जांचें हो रही हैं, सब आपके और हमारे सामने है। आये दिन अख़बार में फ्रंट पेज पर यही आता है जो आपके सामने है। जिन्होंने पेयजल में भ्रष्टाचार किया है, जनता उसको कैसे माफ करेगी? पिछले पांच साल में मुख्य मंत्रीजी ई.आर.सी.पी. का राग जपते रहे और लास्ट में तो उन्होंने यह घोषणा की कि हम राजस्थान सरकार के लेवल पर ही ई.आर.सी.पी. लागू करेंगे, परन्तु कुछ भी नहीं किया। चार साल होटलों में आराम से घूमते रहे, एक-दूसरे की कुर्सी को खींचते रहे और लास्ट में चार साल बाद यह याद आया कि चुनाव होने को हैं, तो फिर रेवड़ी बांटने का काम चालू किया, वह आपके सामने है।

पिछली सरकार में डी.एम.एफ.टी. के फण्ड को ठीक तरह से व्यय नहीं किया गया। इसमें भेदभाव हुआ। बिना बजट के जिले व सम्भाग बना दिये। छोटे-छोटे गांवों में सम्भाग बना दिये। मेरे भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा जिला बना दिया। उसमें मेरी 13 पंचायतों को जोड़ दिया, जबकि उनका कोई विकास नहीं हुआ। एक पंचायत उप खण्ड कार्यालय से पांच किलोमीटर दूर है। शाहपुरा में उसको जोड़ दिया, वह 60 किलोमीटर दूर है। कोई हिसाब-किताब नहीं है। देखा ही नहीं, केवल घोषणा कर दी। जो आपके सामने है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरी 13 पंचायतें हैं, शाहपुरा जिले में गई हैं। जालिन्द्री, मांगठड़ा, सरकला, जंजोला, जसूजियाखेड़ा, काछोला, थल, सरथला, राजगढ़, ककोलिया घाटी, नन्दराई, झावल, मनसा, गंवली ये 13 पंचायतें हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनको वापस लिया जाए। पहले वाली सरकार के निर्णय को तुरन्त कैंसिल करके इन पंचायतों को भीलवाड़ा जिले में रखा जाए।

मेरा मानना है कि लोकतंत्र में विजय हमेशा दायित्व व जिम्मेदारी बढ़ाती है। आपकी पराजय चिन्तन की ओर जाने का संकेत करती है। यह तथ्य हम सभी को समझना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में बनी नयी सरकार ने काम संभालते ही गरीब माता, बहनों को चार सौ पचास रुपये में गैस सिलेण्डर देने का निर्णय लिया है। पहले वाले मुख्य मंत्रीजी ने चार साल तक कुछ नहीं किया। केवल वायदे करते रहे। जब चुनाव आये तो फिर

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

घोषणा करने लगे कि पांच सौ रुपये में सिलेण्डर देंगे। इन्होंने जो सिलेण्डर दिये, वे आपके सामने हैं।

दस हजार अपराधियों के विरुद्ध लम्बित कानून सम्मत कार्यवाही को मुख्य मंत्रीजी ने आगे बढ़ाया है। विगत सरकार ने केन्द्र की आयुष्मान योजना को चिरंजीवी के नाम से लागू किया। प्रदेश से बाहर काम करने के लिए जाने वाले व सीमावर्ती जिले के निवासियों को पड़ोसी प्रदेश में चिकित्सा नहीं मिल पाती थी। अब आयुष्मान योजना का लाभ पूरे देश में, आप कहीं भी इलाज कराओ, हर जगह इलाज होगा।

सरकार का प्रदेश में 350 प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र खोलने का संकल्प भी सराहनीय है। यह निर्णय राहत प्रदान करने वाला है। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री भजन लालजी के नेतृत्व वाली सरकार केन्द्र की सहयोगी बन कर डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से डबल विकास करेगी और जनता को राहत देगी। हम भा.ज.पा. और मोदीजी के नेतृत्व व मार्गदर्शन से 2047 तक विकासशील राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री चेतन पटेल।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय श्रीराम।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): सभापति महोदय, सबसे पहले तो आज मुझे यहां पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका तहेदिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे इतनी कम उम्र में पंचायत समिति सदस्य से सीधे विधान सभा में अपनी बात रखने का मौका दिया, उनकी आवाज उठाने का अवसर दिया।

सभापति महोदय, जब मैं अभिभाषण सुन रहा था तो मैंने देखा कि किसी भी प्रकार से सरकार का विजन दिखाई नहीं दिया, कोई रोड मैप दिखाई नहीं दिया और कोई प्लानिंग नहीं दिखाई दी।

सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 42 में मैंने देखा कि अनुसूचित जाति व जनजाति को नौकरी देने की बात कही गयी है। नौकरी बाद में, पहले बच्चों को पढ़ाया जाए। उन गरीबों की मदद की जाए। मैं आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा कि राजस्थान के सभी अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र

(श्री चेतन पटेल कोलाना)

छात्राओं के पिछले छह माह से छात्रवृत्ति का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जाति व जनजाति के गरीब छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है और आर्थिक तनाव में रहता है। इस सम्बन्ध में मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि अतिशीघ्र उनकी छात्रवृत्ति चालू की जाए।

सभापति महोदय, 22 तारीख को हम सभी के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मैंने जब अभिभाषण सुना तो बिन्दु संख्या 43 में रामराज्य की बात कही गयी परन्तु हम सब यहां पर राजस्थान के राजनेता हैं, चुन कर आये हैं। एक बहुत ही ऐसी समस्या, जिसके लिए मैं आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा। जितने भी देवी-देवता हैं, उनके पुजारी होते हैं, सेवक होते हैं। अभी-अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में आठ लेन का काम चल रहा है, जो दिल्ली-मुम्बई हाई-वे से निकला है। दिल्ली-मुम्बई की आठ लेन की जो सड़क है, केन्द्र सरकार ने जमीनों का अधिग्रहण तो कर लिया है मगर उनको मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है। मंदिरों की जमीन का मुआवजा यह कहकर प्रदान नहीं किया जा रहा है कि इन डोली के पुजारी मात्र संरक्षक हैं न कि मन्दिर के जमीन के मालिक। पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी, जिसमें ब्राह्मण भी आ गये और अन्य जाति भी आ गईं, जो भी उनके सेवक हैं, मंदिरों की पूजा करते चले आ रहे हैं। उन पुजारियों के परिवारों का जीवन-यापन इन डोली की आमदनी से हो रहा है। मुआवजा प्रदान नहीं करने से कई परिवार डिप्रेशन के शिकार हैं।

माननीय, मैं समझता हूं कि भगवान श्रीराम अयोध्या में ही नहीं हैं जहां भी मन्दिर हैं, जहां भी उनके सेवक हैं, पुजारी हैं, तब तक वे खुश नहीं हो सकते जब तक उनको सुविधाएं नहीं मिल सकतीं। मैं यह समझता हूं कि यह रामराज्य हो सकता है और भगवान श्रीराम खुश रह सकते हैं।

आदरणीय, दु:ख होता है, मैं खुद भी आदिवासी समुदाय से आता हूं। जिस तरीके की खबरें सुनने को मिलती हैं, मणिपुर में अभी तक भी स्थिति काबू में नहीं है। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और वह भी सोशल मीडिया के माध्यम से खबर निकल कर आती है, न कि मीडिया के माध्यम से। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज तारीख तक भी हमारे आदिवासी भाई-बहनों के साथ अत्याचार वहां पर हो रहा होगा।

मध्य प्रदेश में पेशाब किया जाता है। आदिवासी भाई की इस तरीके की खबर निकलकर आयी। मैं टी.वी. में वीडियो देख रहा था तो रामलला की

(श्री चेतन पटेल कोलाना)
प्राण प्रतिष्ठा के दिन जब वीडियो देखा तो इस तरीके से पूंजीपतियों को वहां पर वी.आई.पी. का दर्जा दिया गया, जिनके ऊपर हजारों करोड़ का कर्जा चल रहा है। जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस हैं, उनको वी.आई.पी. का दर्जा दिया गया। आज स्थिति यह है कि हम भगवान श्रीराम के सामने तो अपने विचार रख सकते हैं और वे सुनते भी हैं। हम उनके सामने अपनी बात तो रख सकते हैं, पर देश के प्रधान मंत्री के सामने अपने मन की बात नहीं रख सकते। नॉट ईवन ए सिंगल प्रेस कान्फ्रेंस। इन्टरव्यू भी लेना हो तो यही सेलिब्रिटीज इनके इन्टरव्यू लेते हैं। मीडिया वाले तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। यही सेलिब्रिटीज उनसे यह पूछते हैं कि आम गुठली के साथ खाते हैं या बिना गुठली के साथ। न कोई महंगाई पर चर्चा, न बेरोजगारी पर चर्चा, न महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार पर चर्चा। यह आज देश का दुर्भाग्य है।

आदरणीय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में भारत सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कार्यरत ठेकेदारों ने मिट्टी उठाने हेतु अपने वाहनों के आवागमन हेतु ग्राम मण्डावरा व आसपास के क्षेत्र के किसानों की भूमि पर बने धोरे व ड्रैन को नष्ट कर मिट्टी से भर दिया गया। धोरे व ड्रैन को नष्ट करने के कारण फसलों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। कई किसानों के रास्ते बंद हो जाने के कारण उनके अपने खेतों पर पहुंचने व फसल काटने की परेशानी हो रही है। आपसे अनुरोध है कि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के समस्याग्रस्त किसानों के खेतों का मौका अवलोकन करवाकर भारतमाला प्रोजेक्ट के किसानों की समस्या को हल करवाने का श्रम करें।

सभापति महोदय, अभी मैंने आपको बताया कि सेलिब्रिटीज को वी.आई.पी. का दर्जा दिया गया। ऐसे-ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने दर्शकों को बेवकूफ बना सकते हैं। गुटखे का एड करते हैं। गुटखे पर बड़ा-बड़ा लिखा है कि दिस इज इंज्युरियस फोर हैल्थ। जब वे अपने स्वार्थ के लिए दर्शकों को पागल बना सकते हैं, उसी तरह अपने स्वार्थ की दलगत राजनीति के लिए ई.आर.सी.पी. को रोका गया।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): उस पर अड़चन लगायी गयी। पिछली जब हमारी सरकार थी, इसी मंशा के साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी स्टेट हाईवे 120 का इन्द्रगढ़-गोठरा रोड पर गोठड़ा कलां के यहां नदी में नाव के डूबने से अनेक व्यक्तियों की मौत हुई थी। यह ऐसा हादसा था जो सभी

(श्री चेतन पटेल कोलाना)

न्यूज पेपरों में फ्रंट न्यूज थी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में गोठड़ा कलां में चम्बल नदी पर पुलिया की स्वीकृति हुई थी। वर्तमान में केन्द्र सरकार के वन विभाग के पास एन.ओ.सी. हेतु पत्रावली पेंडिंग है। जितनी भी एन.ओ.सी. केन्द्र सरकार के यहां से वन विभाग के थ्रू रोकी गयी है, मेरा आपसे निवेदन है कि उन सभी प्रोजेक्ट्स को दुबारा चालू करवाया जाए और केन्द्र सरकार की स्वीकृति के अभाव में यह पुलिया बन नहीं पा रही है। इस सम्बन्ध में पूर्व में सरकार को अवगत कराया हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अब डबल इंजन की सरकार है तो हम आपसे यह उम्मीद जरूर करते हैं, ताकि इस प्रकार के जो हादसे हैं, ये हादसे रूकें। अभी कल भी उसी पुलिया के वहां क्रोसिंग करने के लिए इन्द्रगढ़ माताजी के यहां जाने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि डबल इंजन की सरकार में यह कार्य हो।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार हमेशा युवाओं के प्रति बहुत चिन्तित रही है और किसानों के प्रति भी बहुत चिन्तित रही है। यह पूरे राजस्थान की एक बहुत बड़ी समस्या है जो आपके सामने लाना चाहता हूं। कुछ गौण मंडियों को, हमारी सरकार के दौरान, कुछ गौण मंडियां थीं, जिनको पूर्ण मंडी का दर्जा दिया गया था। राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 21.07.2023 से पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र की खातोली गौण मंडी को भी पूर्ण मंडी बनाया गया। इस मंडी में दिनांक 12.09.2023 को राज्य सरकार द्वारा सदस्यों का मनोनयन किया गया। दिनांक 12.09.2023 को मंडी में चुनाव की घोषणा की गयी और नियमानुसार मंडी के चुनाव करवाकर प्रथम मंडी बोर्ड का गठन किया गया। मंडी बोर्ड की कार्यप्रणाली से स्थानीय किसानों को अपनी जिंसों को बेचना सुलभ हो गया। पूर्व में खातोली के किसान अपनी जिन्स को श्योपुर, मध्य प्रदेश की मंडी में बेचने जाते थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): दिनांक 05.01.2024 को राजस्थान सरकार के विभाग के उप सचिव श्री कुंतल विश्नोई जी के आदेश से इन निर्वाचित बोर्ड की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है, जोकि वैधानिक नहीं है। यह कार्य पूर्णतया राजनीतिक रहा है। नियमानुसार मंडी बोर्ड के गठन को चुनाव करवाकर ही भंग किया जाना चाहिये। मैं आपसे अनुरोध करता हूं,

(श्री चेतन पटेल कोलाना)

माननीय, कि खातोली मंडी बोर्ड के अलावा राजस्थान की अन्य मंडियों के निर्वाचित बोर्डों को आगामी चुनाव करवाने के उपरांत ही भंग किया जाए। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री लालाराम बैरवा।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वाद-विवाद पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं नवनिर्मित जिला शाहपुरा और विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा से निर्वाचित होकर पहली बार सदन में आया हूं। यह विधान सभा क्षेत्र क्रांतिकारियों की भूमि है और तपोभूमि है। केसरीसिंह बारहठ, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारहठ ने देश को आजाद कराने के लिए पूरा बलिदान दिया, यह वह विधान सभा क्षेत्र है। अन्तरराष्ट्रीय रामस्नेही समुदाय वहां पर स्थापित है। ऐसे विधान सभा क्षेत्र से मैं राजस्थान की चौथी बड़ी जीत के साथ में यहां सदन में आया हूं। शाहपुरा की जनता को मैं बहुतबहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, भारत का गौरवशाली इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र रहा है। हमारे संविधान में श्रीराम का पुष्पक विमान में सीता का लक्ष्मण के साथ अयोध्या की ओर जाते हुए रेखाचित्र संविधान के भाग 3 के प्रारम्भ में दिया गया है। सत्ता पाकर अहंकारी होने के विपरीत 14 वर्ष तक सत्ता में रहकर भी सत्ता के प्रति मोह न होने का विश्वास दिलाने वाले भाई भरत के पास उसी विश्वास के साथ भाई राम का जाना एक आदर्श और अद्भुत घटना है। संत कवि तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में इसी भ्रातृप्रेम की तुलना करते हुए हनुमान जी को श्रीराम जी से कहलवाया कि 'तुम मम प्रिय भरत सम भाई' एक दूसरे के प्रति यह विश्वास ही रामराज्य की ऊंचाई और उसकी मजबूत नींव है। रामराज्य भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की आदर्श शासन प्रणाली है। असत्य पर सत्य की विजय सुनिश्चित करने वाले राम ही भारत की आत्मा हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि त्रेता युग में भगवान राम का राज्य रामराज्य के नाम से विख्यात रहा है, जिसको पूज्य महात्मा गांधीजी ने भी अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाया था, जिसमें सामान्य से सामान्य व्यक्ति के मद का

(श्री लालाराम बैरवा)

भी सम्मान किया जाता था और उसके अधिकारों की रक्षा की जाती थी। उस कालखण्ड में जब विश्व के अनेक हिस्सों में मनुष्य पाषाणकालीन अवस्था में जी रहा था, उस समय भी राम राजा नहीं बल्कि लोकनायक बनकर रहते थे। 14 साल तक राम पत्नी सहित जनता के बीच में रहते हैं। घास पर सोते हैं। पैदल चलते हैं और कंद-मूल फल खाते हुए वनवासी और आदिवासियों को गले लगाते हैं। संविधान भाग 3 पर इस चित्र का होना संविधान निर्माता के मन की इसी बात का द्योतक है कि उन्हें भारत में रामराज्य की पुन: प्रतिष्ठा की कामना है। भारत की आत्मा जागृत हो, यही उनका सपना है। इस सपने को साकार करने की प्रेरणा देने वाले इस चित्र को शत-शत बार नमन।

विश्व के महान नेता आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी ने इन 10 वर्षों में रामराज्य की इसी संकल्पना को साकार करने के लिए भारत माता के चरणों में अपने पल-पल को न्योछावर कर दिया है। आज भारत का जनमानस ही नहीं, बल्कि विश्व के सभी देश भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देखने लगे हैं। राजस्थान में भी एक सामान्य कार्यकर्ता से मुख्य मंत्री बने आदरणीय भजन लाल जी रात-दिन सामान्य जनता के मध्य रहकर उनके सुख-दु:ख में सहभागी होकर इस सपने को साकार करने में लगे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज भारतीय संविधान के भाग 4 की चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ राज्य की कार्यपालिका, लोक प्रतिनिधियों की भूमिका, न्यायपालिका की भूमिका तथा देश के प्रशंसकों के कर्तव्य आदि का उल्लेख है। इस प्रसंग को संविधान के भाग 4 पर अंकित करने का उद्देश्य स्पष्ट है। संकेत स्पष्ट है, संदेश भी स्पष्ट है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद पूरे देश में कहीं...

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): गम का वातावरण था, उस गम को खुशी में तब्दील करना जरूरी था। निराशा को आशा में, हताशा को प्रत्याशा में बदलना आवश्यक था। देश को दुविधाग्रस्त मानसिकता से उबारना जरूरी था। यही काम युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण को करना पड़ा था। इस अवसर पर हमारे महान संविधान निर्माता का पुण्य स्मरण करते हुए याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान की नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य वाले इस चतुर्थ भाग के प्रारम्भ में इस चित्र के चयन का अर्थ है -

(श्री लालाराम बैरवा)

"यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।"

जहां नीति-निर्धारक कृष्ण उपस्थित हों और जहां उसका पालन करने वाला पार्थ जैसा निपुण सेनापति उपस्थित हो, वहां विजय निश्चित है। यही चतुर्थ भाग का निचोड़ अपेक्षित है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में भी ऐसी विध्वंसकारी शक्तियों को समाप्त करने के लिए हमने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है, जो चुन-चुनकर ऐसी विध्वंसकारी शक्तियों को समाप्त करेगी।

अंत में आज संविधान के भाग 8 की चर्चा करना चाहूंगा। प्रशासन से सम्बन्धित इस आठवें भाग पर फलों से लदे वृक्ष, ऊंचे-ऊंचे मकान एवं छलांग लगाता हुआ एक सुसम्पन्न पुरुष चित्रांकित है। गुप्त काल की परिस्थितियों को दर्शाने वाले इस चित्र में उड़ान भरने वाला यह पुरुष कुबेर है। ज्ञात हो कि कुबेर हनुमान के पराक्रम के अनुप्रमाणित एवं प्रभावित रहे हैं। उन्होंने अपनी चमत्कारिक गदा हनुमान को दी थी। युद्ध के संघर्ष से दूर रहकर धनार्जन करने के लिए उन्होंने अपनी ऊर्जा खपा दी थी।

श्री सभापति: सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 30 जनवरी 2024 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.30 बजे मंगलवार, 30 जनवरी 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

मनोहर थाना के गांवों को सड़क से जोड़ने की कार्ययोजना

42. **श्री गोविन्द प्रसाद** (मनोहर थाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में विगत तीन वर्षों में कौन-कौन सी पुलिया, मिसिंग लिंक, हाई लेवल ब्रिज का कार्य अपूर्ण रहा है? उक्त को कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में कौन-कौन से कार्य अब तक पूर्ण हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के सड़कों से वंचित गांवों व ढाणियों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में विगत 3 वर्षों में स्वीकृत पुलिया, मिसिंग लिंक सड़कों एवं हाई लेवल ब्रिज में से सात मिसिंग लिंक, तीन पुलिया एवं दो हाई लेवल ब्रिज के कार्य अपूर्ण हैं, जिनमें 7 मिसिंग लिंक कार्य 30 अप्रैल, 2024 तक; अकलेरा बाईपास सड़क पर 3 पुलिया कार्य 30 जून, 2024 तक; एक हाई लेवल ब्रिज का कार्य दिसम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है। छापी नदी पर अप्रारम्भ हाई लेवल ब्रिज हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करवाई जा रही है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में विगत 3 वर्षों में कुल 114 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई, जिनमें से 88 कार्य पूर्ण कर लिये गये एवं 24 कार्य प्रगति पर हैं तथा 2 कार्य वन क्षेत्र में होने के कारण लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में कुल 74 गांव व 56 ढाणियां डामर सड़क से वंचित हैं, जिनमें से 5 गांव डामर सड़क से जोड़ने हेतु स्वीकृत हैं। शेष 125 गांव/ढाणियों (69 गांव एवं 56 ढाणियों) को डामर सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

डूंगरपुर के पात्र आदिवासी परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ

52. श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में पात्र आदिवासी परिवारों के खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं होने से उक्त योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना से वंचित परिवारों के नाम जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त वंचित परिवारों को योजना में नाम जुडने तक राशन डीलरों से राशन सामग्री उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में विभागीय आदेश दिनांक 05.11.2015, 29.09.2017 एवं 11.04.2022 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाये जाने के लिए अपीलीय प्रक्रिया है।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित होने से वर्तमान में खाद्य सुरक्षा सूची में नवीन आवेदन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र व्यक्तियों को ही खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराया जाता है। वंचित परिवारों को योजना में नाम जुड़ने तक राशन डीलरों से राशन सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

जाने की सीलिंग निर्धारित होने से वर्तमान में खाद्य सुरक्षा सूची में नवीन आवेदन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

नीम का थाना के ग्रामदानी गांव

53. श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामदानी गांवों के कृषकों हेतु संचालित योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में कितने गांव अब भी ग्रामदानी में हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामदानी गांवों को पंचायतों में समायोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामदानी गांवों में निवास करने वाले किसानों को किसानों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है।

विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में ग्रामदानी में कुल 25 ग्राम/ढाणियां अधिसूचित हैं, जिनमें से 02 ग्रामदानी गांव क्रमश: अजमेरी और नीमावली ढाणी परिसीमन अनुसार तहसील एवं विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में चली गयी है एवं शेष 11 ग्रामों/ढाणियों (नृसिंहवाला, ढाणी मिंडावली, ढाणी धोबाला तन डोकन, ढाणी नाथूवाला तन डोकन, नारदा तन न्यौराणा, न्यौराणा, घाटा मय गुंवार, होला की ढाणी, फूटा, फूटाला तन मोकलवास, भीतरली गांवडी) में ग्रामदान ग्रामसभा के नाम कोई भूमि दर्ज रिकार्ड नहीं है। विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना के शेष 12 ग्रामदानी ग्रामों/ढाणियां जिनकी भूमि ग्रामसभा/ग्रामदान के नाम दर्ज हैं। उक्त 12 ग्रामदानी गांवों की सूची परिशिष्ट -अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजोरगढ़ ग्राम पंचायत (थानागाजी) में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

54. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत राजोरगढ़ तहसील टहला में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है?

(2) उक्त ग्राम पंचायत को वन विभाग द्वारा भविष्य में विस्थापित करने की क्या कोई योजना है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना का संचालन

55. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना एवं किसान मित्र ऊर्जा योजना प्रारम्भ की गई थी? यदि हां, तो कब से? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजनाओं को यथावत रखने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना का लाभ दिनांक 01 मई, 2023 अर्थात् बिलिंग माह जून, 2023 से एवं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ बिलिंग माह मई, 2021 से दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना एवं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में उक्त योजनाओं का यथावत लाभ दिया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर के पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं विकास पर व्यय

33. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में माह जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर, 2023 तक कितने देशी-विदेशी पर्यटक आये तथा उनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में सरकार द्वारा जयपुर के आमेर, नाहरगढ़ व जयगढ़ महल, सागर एवं मावठा जलाशय, हवामहल, जन्तर-मन्तर, अल्बर्ट हॉल आदि पर्यटन स्थलों एवं पुरातत्व स्मारकों के संरक्षण एवं संवर्धन व विकास पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2023 तक की गई देशी-विदेशी पर्यटक यात्राओं का वर्षवार संख्या विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	देशी पर्यटक यात्राएं	विदेशी पर्यटक यात्राएं
2020	1,51,17,239	4,46,467
2021	2,19,88,734	34,806
2022	10,83,28,156	39,684
2023	17,90,51,925	16,99,869

प्रदेश में की गई देशी-विदेशी पर्यटक यात्राओं से प्राप्त राजस्व का संकलन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

(2) जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2023 तक जयपुर के संरक्षित स्मारकों, यथा आमेर महल, नाहरगढ़, हवामहल, जन्तर-मन्तर, अल्बर्ट हाल आदि पर्यटक स्थलों एवं पुरातत्व स्मारकों के संरक्षण एवं संवर्धन व विकास पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर के मंदिरों को पर्यटन स्थल का दर्जा

34. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामनिवास गावड़िया)

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के कौन-कौन से जिले में किन-किन मंदिरों को पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र परबतसर के गांव हरियाजून स्थित शिव मंदिर, खुडियांस स्थित रामदेव मंदिर, हरणांवा स्थित राणाबाई मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश के जिलों में सरकार द्वारा मंदिरों को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई घोषणा नहीं की गई थी।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र परबतसर के गांव हरियाजून स्थित शिव मंदिर, खुडियांस स्थित रामदेव मंदिर, हरणांवा स्थित राणाबाई मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उल्लेखनीय है कि स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित करने का कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है। स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वतः ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

बगरू के सड़क विहीन राजस्व ग्राम

35. श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू के कितने राजस्व ग्राम प्रधानमंत्री सड़क योजना से वंचित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना से वंचित गांवों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशानुसार जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर सामान्य क्षेत्रों में 500 व अधिक एवं मरु व जनजातीय क्षेत्रों में 250 व अधिक की आबादी की बसावटों को डामर सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान था, जिसके अनुसार बगरू (सामान्य क्षेत्र) विधान सभा क्षेत्र में जनगणना वर्ष 2001 पर आधारित सभी राजस्व ग्राम, जिनकी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जनसंख्या 500 व अधिक है, उन सभी गांवों को डामर सड़क से जोडा जा चुका है। वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र बगरू के कुल 03 राजस्व ग्राम सर्वकालिक पक्की सडक से वंचित हैं-

1. चक नम्बर-12, ग्राम पंचायत कपूरावाला, जनसंख्या (31)
2. चक शेरावाली, ग्राम पंचायत पवालिया, जनसंख्या (11)
3. चक वाटिका, ग्राम पंचायत मोहनपुरा, जनसंख्या (160)

(2) इन वंचित गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अंतर्गत नहीं आता है। इन गांवों को राज्य सरकार की अन्य योजना में जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

राष्ट्रीय पोषण अभियान योजना

36. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण अभियान योजना कब से संचालित है? उक्त योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में केन्द्र सरकार से कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई एवं किस-किस मद में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत एजेन्सियों के माध्यम से कार्मिकों को लगाया गया था? यदि हां, तो वर्षवार एवं जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा एजेन्सी को वर्क आर्डर देने के उपरांत भी कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में राष्ट्रीय पोषण अभियान योजना वर्ष 2018-19 से संचालित है। उक्त योजना का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना में केन्द्र सरकार से प्राप्त केन्द्रांश राशि का विवरण निम्नानुसार है-

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

वित्तीय वर्ष	केन्द्र सरकार से राशि प्राप्ति दिनांक	प्राप्त राशि (लाखों में)
2018-19	दिनांक 01.04.2018 को अवशेष केन्द्रांश राशि	4216.26
	27.04.2018	3158.22
	02.08.2018	3761.92
	28.02.2019	118.00
	19.03.2019	735.24
	22.03.2019	1907.61
2019-20	28.02.2020	8941.00
2020-21	04.09.2020	992.32
2021-22	----	0.00
2022-23	29.03.2023	1018.68
2023-24	30.09.2023	5920.49

भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार पूर्व में संचालित कार्यक्रम- आई.सी.डी.एस. सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग एण्ड न्यूट्रेशन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट (आई.एस.एस.एन.आई.पी.) को पोषण अभियान (एन.एन.एम.) में सम्मिलित किया गया तथा इसके अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश राशि का उपयोग पोषण अभियान की गतिविधियों के लिए किया गया।

उक्तानुसार प्राप्त केन्द्रांश राशि तथा उसके अनुपात में राज्यांश राशि का व्यय पोषण अभियान अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों यथा समुदाय आधारित गतिविधियों (सी.बी.ई.एस.), पोषण पखवाड़ा एवं पोषण माह, आई.ई.सी. गतिविधियां, मानव संसाधन सेवाएं, वृद्धि निगरानी उपकरण एवं स्मार्ट फोन का उपापन, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए वन टाइम यूनीफोर्म, नवाचार गतिविधियां, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मोबाइल डाटा प्लान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि के लिए किया गया है। व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

			राशि (लाखों में)
वित्तीय वर्ष	**व्यय राशि (केन्द्रांश)**	**व्यय राशि (राज्यांश)**	**कुल व्यय राशि**
2018-19	3078.70	618.80	3697.50
2019-20	4236.26	1059.07	5295.33
2020-21	2968.87	742.21	3711.08
2021-22	5761.10	1440.28	7201.38
2022-23	7393.90	2061.91	9455.81
2023-24 (दिसम्बर, 2023 तक)	1990.81	807.98	2798.79

(3) जी हां। उक्त योजना के तहत एजेन्सियों के माध्यम से कार्मिकों को लगाया गया था। भारत सरकार से प्राप्त सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की नवीन गाइड लाइन दिनांक 01.08.2022 के अनुसार जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में 02 मानव संसाधन जिला समन्वयक एवं जिला परियोजना सहायक के रूप में तथा प्रत्येक परियोजना कार्यालय में 01 मानव संसाधन ब्लाक समन्वयक के रूप में लगाये गये हैं। जिलावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जी हां। एजेन्सियों को कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं, परन्तु अभी तक मानव संसाधन नहीं लगाये गये हैं क्योंकि पूर्व में अनुबन्धित फर्मों से लगाये गये मानव संसाधनों द्वारा उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14030/2023 में स्थगन आदेश होने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

शाहपुरा में देवनारायण आवासीय विद्यालय की स्थापना

37. श्री मनीष यादव (शाहपुरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में देवनारायण आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में देवनारायण आवासीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। देवनारायण योजनान्तर्गत शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय पीपलोद, शाहपुरा में निर्मित भवन में संचालित है। इसकी स्वीकृत क्षमता 280 छात्राओं की है।

थर्ड जेण्डर बच्चों के विकास की योजना

38. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) यह सही है कि प्रदेश में थर्ड जेन्डर बच्चों के लिए शिक्षा एवं अन्य सामाजिक विकास योजनाओं के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के लिए कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार के लावारिस व बेघर बच्चों हेतु आवासीय गृह, विशेष गृहों की सुविधा का प्रावधान नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के संरक्षण के लिए विशेष होम संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में 10 करोड़ रुपये की राशि से ''ट्रांसजेण्डर उत्थान कोष'' का गठन किया गया है। इस कोष के अन्तर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों को पहचान पत्र, शिक्षा, अध्ययनरत बच्चों के लिए आर्थिक सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वरोजगार/व्यवसाय, चिकित्सा (लिंग परिवर्तन सर्जरी), काउन्सलिंग, ट्रांसजेण्डर दिवस, वृद्धाश्रम व एकल खिड़की सेवा आदि गतिविधियों/कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। ट्रांसजेण्डर उत्थान कोष के दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। थर्ड जेण्डर बच्चों के लिए पृथक से पूर्व मैट्रिक व उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं अध्ययनरत बच्चों के लिए आर्थिक सहायता योजना संचालित है।

(2) जी हां। इस प्रकार के लावारिस व बेघर बच्चों के लिए अलग से आवासीय गृह, विशेष गृहों की सुविधा का प्रावधान नहीं है। उक्त बच्चों के संरक्षण के लिए विशेष होम चलाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राज्य में 41 राजकीय एवं 92 गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थान संचालित हैं। इन गृहों में ही उक्त बच्चों को भी प्रवेश दिया जाता है, जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बहरोड़ में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

39. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राशन की कितनी दुकानें संचालित हैं तथा उक्त पर क्या-क्या एवं कितनी मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने बी.पी.एल. कार्ड धारक हैं तथा कितनों ने आवेदन कर रखा है? क्या सरकार सभी पात्र आवेदकों के कार्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने राशन डीलर किन कारणों से निलम्बित हैं तथा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कुल 95 राशन की दुकानें संचालित हैं। उक्त उचित मूल्य दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत ऑनलाइन दर्ज राशन कार्डों में अन्त्योदय श्रेणी के राशन कार्डों पर 35 किलोग्राम प्रति कार्ड एवं बी.पी.एल. एस.बी.पी.एल. एवं अन्य चयनित पात्र परिवारों के कार्डों पर 05 किलोग्राम प्रति यूनिट नि:शुल्क गेहूं एवं माह अगस्त, 2023 से प्रति परिवार एक फूड पैकेट का वितरण कराया जा रहा है। उचित मूल्य दुकानवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कुल 2,448 बी.पी.एल. राशन कार्ड धारक हैं तथा बी.पी.एल. लम्बित आवेदनों की संख्या शून्य है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में एक उचित मूल्य दुकानदार श्री सुभाष चन्द्र, खोहर राशन सामग्री का गबन किये जाने के कारण निलम्बित है। उक्त डीलर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

किशनगंज में सहरिया परियोजना में आवास निर्माण

40. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक सहरिया परियोजना क्षेत्र में क्या-क्या विकास कार्य करवाये गये तथा उक्त कार्यों हेतु विभागों को कितनी राशि आबंटित की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक कौन-कौन से गांवों में सहरिया परिवारों के लिए कितने आवासों का निर्माण करवाया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा उक्त निर्मित आवासों का निरीक्षण किया गया है? यदि हां, तो निरीक्षण करने पर क्या-क्या कमियां पाईं गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2019 से 2023 तक सहरिया क्षेत्र में किये गये विकास कार्यों हेतु विभागों को आबंटित धनराशि का विवरण परिशिष्ट-अ तथा परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में वर्ष 2019 से 2023 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कुल 2,789 सहरिया आवासों का निर्माण कर सहरिया परिवारों को लाभान्वित किया गया है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) हां। जिला कलेक्टर एवं अति. जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण किये गये है। निरीक्षण में उल्लेखनीय कमियां नहीं पाई गई हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नव क्रमोन्नत तहसील प्रतापगढ़ (थानागाजी) का भवन निर्माण

41. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कान्ति प्रसाद)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में क्रमोन्नत तहसील प्रतापगढ़ के नवीन भवन का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में नव क्रमोन्नत तहसील प्रतापगढ़ के नवीन भवन का निर्माण किया जायेगा।

देवली-उनियारा की नवीन उप तहसीलों व तहसीलों के भवन निर्माण

42. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में कितनी तहसीलें, उप तहसीलें खोली गयीं एवं उक्त में से कितनों के भवन निर्माण हो चुके हैं व कितने प्रगतिरत हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में उक्त अवधि में खोली गई तहसीलों/उप तहसीलों में से किसी का भी भवन निर्माण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सभी नव तहसीलों/उप तहसीलों के भवन निर्माण का विचार रखती है? यदि हां. तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

छबड़ा में अवैध बजरी परिवहन में जब्त वाहन

43. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में जनवरी, 2019 से नवम्बर, 2023 तक अवैध मिट्टी व रेत भरने पर ट्रैक्टर, ट्रोली, ट्रक, डम्पर आदि कब-कब पकड़े गए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) अवैध वाहन पकड़े जाने पर उन्हें छोड़ने के क्या नियम व प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबडा में जनवरी, 2019 से नवम्बर, 2023 तक अवैध मिट्टी व रेत भरने पर ट्रैक्टर, ट्रोली, ट्रक, डम्पर आदि पकड़े गए तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 32, 33 व 41, 42 के उल्लंघन होने पर इस अधिनियम की धारा 52 (1) के अन्तर्गत वाहन व वन उपज को जब्त किया जाता है एवं पकड़े गये वाहन व वन उपज पर धारा 52 के तहत कार्यवाही की जाती है, जिसके नियम की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं।)

सुन्धा माता कन्जर्वेशन रिजर्व वन क्षेत्र में पौधारोपण पर व्यय

44. श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक सुन्धा माता कन्जर्वेशन रिजर्व वन क्षेत्र तहसील जसवन्तपुरा में विभिन्न योजनान्तर्गत क्षेत्र विकास, रख-रखाव, पौधारोपण, वन सुरक्षा में कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों के प्रयोजनार्थ स्वीकृत की गई? उक्त में से किन-किन कार्यों के पूर्ण होने पर संवेदकों को कितना-कितना भुगतान कब-कब किया गया? कार्यादेश, स्वीकृत बजट राशि, संवेदक/संवेदक फर्म का नाम, भुगतान की गई राशि, कार्य की पूर्णता/अपूर्णता की स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में स्वीकृत अधिकांश कार्य अपूर्ण अथवा प्रारम्भ ही नहीं करवाये गये हैं? यदि हां, तो ऐसे प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2021 से 2023 के दौरान सुन्धा माता कन्जर्वेशन रिजर्व वन क्षेत्र तहसील जसवन्तपुरा में विभिन्न योजनान्तर्गत क्षेत्र विकास, रख-रखाव, पौधारोपण, वन सुरक्षा में हुए व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस अवधि में सभी कार्य पूर्ण करवा लिये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ के ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित राजस्व ग्राम

45. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की कितनी ग्राम पंचायतें ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित हैं? क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने हेतु सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो उक्त सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की कई सहकारी समितियों के गोदाम व भवन निर्मित नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का भवन व गौदाम बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की 66 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्वीकृत नहीं हैं।

प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर निर्धारित मानदंड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

(2) शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 38 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने हेतु सर्वे करवाया गया है। सूची सहित सर्वे रिपोर्ट परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की कई सहकारी समितियों में गोदाम एवं भवन निर्मित नहीं हैं।

उक्त समितियों के पास विवाद रहित भूमि उपलब्ध होने, गोदाम की उपयोगिता एवं समिति से सम्बन्धित बैंक के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण के लिए प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति जारी की जाती है।

(रिपोर्ट पुस्तकालय में रखी गयी)

डूंगरपुर में किसानों को लेम्पस द्वारा ऋण वितरण

46. श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्ष 2019 से माह दिसम्बर, 2023 तक कितने किसानों को लेम्पस द्वारा ऋण दिया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर के किसानों द्वारा ऋण नहीं लेने के उपरान्त भी ऋण माफी में उनके नाम लिखे हुए हैं? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने प्रकरण हैं? उक्त प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 (दिसम्बर 2023) तक ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की कुल संख्या 48,777 है।

(2) जिला डूंगरपुर के किसानों द्वारा ऋण नहीं लेने के उपरांत भी ऋण माफी में नाम अंकित होने के 23,015 प्रकरण ऋण माफी योजना, 2018 के तहत उजागर हुए थे जिनकी प्रकरणवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

विद्युत की दरों में वृद्धि

47. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़) : क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विगत चार वर्षों में बिजली की दरों में वृद्धि की गई है? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं पर कब-कब व कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बिजली दरों को घटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में विगत चार वर्षों में फरवरी, 2020 में विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई थी। विभिन्न श्रेणियों में की गई विद्युत दरों में बढ़ोतरी का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वैर में नवीन जी.एस.एस. की स्थापना

48. श्री बहादुर सिंह (वैर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में कितने जी.एस.एस. हैं? विगत पांच वर्षों में उक्त क्षेत्र की बिजली समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने कृषि विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतों के निवारण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नवीन जी.एस.एस. स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में 220 के.वी. का एक एवं 132 के.वी. के तीन ग्रिड सब-स्टेशन तथा 33/11 केवी के 33 सब स्टेशन स्थापित है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2023 तक पांच वर्षों में बिजली की समस्या के समाधान हेतु एक 132 के.वी. चीखरू ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण किया गया है। 220 के.वी. जी.एस.एस. छौकरवाड़ा से 132 के.वी. जी.एस.एस. भुसावर को जोड़ने का 132 के.वी. लाइन का कार्य प्रगतिरत है।

उक्त अवधि में 33/11 के.वी. के नवनिर्मित सब-स्टेशनों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

33/11 के.वी. के 13 सब-स्टेशनों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाकर उनकी क्षमता में वृद्धि की गई है, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

132 के.वी. चीखरू ग्रिड सब स्टेशन से 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों को जोड़ने हेतु 33 के.वी. लाइनों का कार्य प्रगतिरत है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माह अप्रैल, 2023 से 15 जनवरी, 2024 तक कुल 542 कृषि विद्युत ट्रांसफार्मर खराब व जले होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनको निगम द्वारा नियमानुसार बदल दिया गया। वर्तमान में ट्रांसफार्मर खराब व जले होने की कोई शिकायत लम्बित नहीं है। शिकायतों का निवारण निगम नियमानुसार निर्धारित समयावधि में किया जा रहा है।

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

(3) उक्त क्षेत्र में आमजन को बिजली की समस्या से निजात दिलाने हेतु समय-समय पर विद्युत भार के अनुरूप निगम द्वारा नये जी.एस.एस./ सब स्टेशनों का निर्माण किया जाता है।

वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में 132 के.वी. जी.एस.एस. बरखेड़ा का निर्माण कार्य वर्ष 2024-25 में किया जाना लक्षित है। 33/11 के.वी. खानखेड़ा के निर्माण का कार्य वर्ष 2023-24 में एवं दीवली का निर्माण वर्ष 2024-25 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं को देय छूट

49. श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत सरकार द्वारा प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को कृषि कार्य हेतु फ्री यूनिट की सब्सिडी दी गई थी? यदि हां, तो कब से तथा उक्त योजना में अब तक कुल कितनों को लाभान्वित किया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में उक्त योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2023 तक कुल कितने घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना को यथावत रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट घोषणानुसार मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना का लाभ दिनांक 01 मई, 2023 अर्थात् बिलिंग माह जून, 2023 से दिया जा रहा है।

उक्त योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2023 तक निगमवार लाभान्वित उपभोक्ताओं की संख्या सूची का विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना				
विवरण	वितरण निगम			
	अजमेर	जयपुर	जोधपुर	कुल
घरेलू लाभान्वित उपभोक्ताओं की संख्या	3950829	4202215	3871640	12024684
कृषि लाभान्वित उपभोक्ताओं की संख्या	644916	652947	477055	1774918

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2023 तक निगमवार लाभान्वित शून्य बिजली बिल उपभोक्ताओं की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना				
विवरण	वितरण निगम			
	अजमेर	जयपुर	जोधपुर	कुल
शून्य राशि के घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या	2326955	2244809	2416524	6988288
शून्य राशि के कृषि उपभोक्ताओं की संख्या	399242	442340	167428	1009010

(3) वर्तमान में उक्त योजनाओं का यथावत लाभ दिया जा रहा है।

विद्युत कम्पनियों को घाटे से उबारने की कार्ययोजना

50. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार की विभिन्न विद्युत कम्पनियां घाटे में चल रही हैं? यदि हां, तो कम्पनीवार वास्तविक घाटे का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में विद्युत कम्पनियों को घाटे से उबारने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विद्युत कम्पनियों को घाटे से उबारने हेतु जन

(श्री हनुमान बेनीवाल)

प्रतिनिधियों से कोई सुझाव मांगने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रस्तावित कार्ययोजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत कम्पनियों के वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित लाभ/हानि एवं संचित कुल लाभ/हानि का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) विगत पांच वर्षों में विद्युत कम्पनियों को घाटे से उबारने के लिए किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यद्यपि विद्युत दरों के पुन:निर्धारण हेतु समय-समय पर विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष जो याचिका प्रस्तुत की जाती है, उस समय सभी हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) से सुझाव मांगे जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू)

बगरू में मांस की अवैध दुकानों पर कार्यवाही

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अनार्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि-

विधान सभा क्षेत्र बगरू में खासकर मुहाना, खो-नागोरियान, जगतपुरा क्षेत्र में प्रमुख सड़कों पर ही दुकानों पर खुले में मांस की बिक्री की जाती है। इसके कारण वातावरण दूषित हो रहा है, जिससे उत्पन्न परेशानियों का सामना आमजन को करना पड़ता है। अधिकांशतः विद्यालयों के एवं धार्मिक स्थलों के पास खुले में मांस बिक्री होने से दुर्गन्ध, गन्दगी तो रहती है, साथ ही इन दुकानों के पास आवारा जानवरों का जमावड़ा भी रहता है। इस कारण विद्यार्थियों, श्रद्धालुओं एवं आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों एवं व्यापारियों के द्वारा इस समस्या को प्राथमिकता के साथ रखकर समाधान हेतु बार-बार जनसम्पर्क के दौरान कहा जाता है। निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बगरू में अवैध रूप से संचालित मांस बिक्री की दुकानों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आमजन को राहत प्रदान करवाने का श्रम करायें।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना)

मनोहर थाना में पेयजल व सिंचाई हेतु समुचित पानी की उपलब्धता

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना की भौगोलिक स्थिति उबड़-खाबड़ एवं पठारी क्षेत्र की है, जिसके कारण किसानों को पेयजल एवं सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जब गरीब किसानों को पीने का स्वच्छ पानी एवं सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी नहीं मिलेगा तो स्वतः ही आर्थिक स्थिति में

पिछड़ना स्वभाविक है। मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में पलायन के मुख्य कारण भी सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होना एवं अन्य स्रोतों द्वारा आय नहीं होना ही हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में करीबन 300 गांव व ढाणियां पहाड़ी क्षेत्र में बसी हुई हैं, जिनके लिए मैंने पूर्व में भी सदन को काफी बार अवगत करवाया है। विधान सभा क्षेत्र में माइक्रो एवं मिनी डैम बनाये जाए, जिनका सर्वे भी कराया गया था, लेकिन पिछली राज्य सरकार द्वारा विशेष पैकेज नहीं देने के कारण कार्य रूका हुआ पड़ा है। क्षेत्र की स्थिति हाल ही में जस की तस बनी हुई है। अगर राज्य सरकार क्षेत्र में निवास करने वाली जातियों, भील, मीणा, तंवर, गुर्जर, बंजारा, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष पैकेज या दर्जा देकर उनकी मांग को ध्यान में रखकर नये माइक्रो डैम, मिनी डैम एवं पेयजल व कृषि विभाग के द्वारा कृषि सम्बन्धी उपकरण, जैसे फव्वारा सिंचाई, तारबंदी, पाइपलाइन पर विशेष ध्यान दें तो क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सकता है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

रामगढ़ की नवगठित नगरपालिकाओं में कर्मचारियों का पदस्थापन

महोदय,

प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की नवगठित नगरपालिकाओं नौगावां एवं मुबारिकपुर में आज दिनांक तक आवश्यक कर्मचारियों के पदस्थापन तथा उक्त नगरपालिकाओं के आवश्यक बैंक खाते भी अभी तक ऑनलाइन नहीं किये गये हैं, जिसके कारण उक्त नगरपालिकाओं के सम्बन्धित क्षेत्रों में राजकीय कार्य एवं नित्य प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य सम्पादित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे यहां के निवासियों में आक्रोश व्यक्त हो रहा है। उल्लेखनीय यह भी है कि नगरपालिकाओं के खाते ऑनलाइन नहीं होने से जरूरी कार्यों की राशि का भी फण्ड उक्त खातों में नहीं डल पा रहा है, जिससे उक्त नगरपालिकाओं एवं सम्बन्धित क्षेत्रों में रोजमर्रा के कार्य, जैसे सफाई एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य चालू नहीं हो पा रहे हैं।

अतः इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उक्त वर्णित नगरपालिकाओं में कर्मचारियों के पदस्थापन एवं आवश्यक

बैंक खातों को ऑनलाइन का कार्य शीघ्रातिशीघ्र कर एवं उक्त खातों में आवश्यक फण्ड भी ट्रांसफर करने की कृपा करें।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा)

डी.डी.पी. क्षेत्र के जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में समुचित जलापूर्ति की व्यवस्था

महोदय,

जल जीवन मिशन से पूर्व भारत सरकार द्वारा पोषित नेशनल रुरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत राजस्थान के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों से 40 एल.पी.सी.डी. की मात्रा निर्धारित की गई थी तथा डी.डी.पी. क्षेत्र में 70 एल.पी.सी.डी. से जलापूर्ति का प्रावधान निर्धारित किया गया था, जिसमें पशुधन की 70 एल.पी.सी.डी. की मांग भी सम्मिलित थी। जल जीवन मिशन में भारत सरकार द्वारा 55 एल.पी.सी.डी. की मात्रा निर्धारित की गई थी तथा इसके अतिरिक्त यदि किसी क्षैत्र मे मांग हो तो राज्य सरकार उसका वहन कर सकती है।

गत राज्य सरकार द्वारा इसका संज्ञान नहीं लेने के कारण सम्पूर्ण राजस्थान में एक ही मापदण्ड 55 एल.पी.सी.डी. से समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में एल.पी.सी.डी. 40 से बढ़कर 55 हो गया, लेकिन डी.डी.पी. क्षेत्र में आ रहे पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में जो पूर्व निर्धारित 70 एल.पी.सी.डी. से घटकर 55 एल.पी.सी.डी. हो गया।

पश्चिमी राजस्थान में डी.डी.पी. क्षेत्र में गांव, बिखरी ढाणियां एवं पशुधन की अत्यधिक मात्रा है। अतः आपसे निवदेन है कि डी.डी.पी. क्षेत्र में पूर्व निर्धारित जलापूर्ति 70 एल.पी.सी.डी. करने हेतु आग्रह किया जाता है, जिससे इस क्षेत्र के पशुधन एवं बिखरी आबादियों को जल जीवन मिशन का पूर्ण लाभ मिल पायेगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)

सादुलपुर में जल जीवन मिशन के कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग

मान्यवर,

प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से

सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में जो कार्य हुए हैं, उनमें अभी तक जनता तक जल जीवन मिशन का कार्य जो 1/5 वर्ष में पूरा होना चाहिए था, लेकिन दो वर्ष से अधिक समय के बाद भी कार्य नहीं कर पाये। ठेकेदार फर्म द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा इस कार्य को करना चाहिए था, लेकिन दोनों सरकारों की अनदेखी एवं भ्रष्टाचार में डूब कर समय पर कार्य नहीं किया गया जिससे जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठेकेदार एवं पी.एच.ई.डी. के अधिकारियों द्वारा मिलकर पाइप लगाने चाहिए थे, लेकिन मिलीभगत करके नकली पाइप डाले गये हैं, गाइड लाइन अनुसार गहराई में नहीं डाले गये हैं। गांवों में जनता को सप्लाई करने के लिये पानी की टंकिया बननी थीं, लेकिन अभी तक 13 टंकियां नहीं बनी हैं। जो टंकियां बनी हैं उनमें कंक्रीट, सीमेंट, सरिया इत्यादि सामग्री घटिया स्तर की डली है। घर घर नल पहुंचाने का काम होगा, लेकिन जल पहुंचने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जल जीवन मिशन के जलदाय विभाग एवं ठेकेदारों की मिलीभगत एवं भ्रष्टाचार की जांच कर ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड कर आगामी कार्य सुचारु करवाया जाए, जिससे जनता को पीने का पानी मिल सके।

मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ठेकेदार एवं भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सख्त कार्यवाही कर कार्य पूर्ण करवाये जाने की कृपा करें।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा)

पचपदरा में पेयजल की समस्या का समाधान

महोदय,

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा पचपदरा में पीने के पानी एवं टूटी सड़कों की भयंकर समस्या है। पोकरण, फलसूण्ड, बालोतरा जलदाय परियोजना में पाइप लाइन में बार-बार लीकेज होता है। लीकेज से बालोतरा शहर एवं आस-पास कई दिनों तक पानी से महरूम रहना पड़ता है। इसी तरह उम्मेदसागर, धबा, कल्याणपुर योजना से भी कल्याणपुर पंचायत समिति के कई गांवों में पानी की विकराल समस्या हो रही है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पीने के पानी की समस्या से

निजात दिलाने हेतु बालोतरा शहर में पानी के स्टोरेज की समस्या तथा नर्मदा के पानी को पचपदरा विधान सभा तक लाने की योजना बनावें, जिससे आने वाले वर्षों में पीने के पानी को सब तक पहुंचाया जा सके।

इसी तरह महोदय, मेरे विधान सभा में विभिन्न सड़कों की बहुत ही खराब दुर्दशा है। अतः शीघ्र ही सड़कों की मरम्मत की घोषणा करावें। धन्यवाद।

श्री बहादुर सिंह (वैर)

वैर में वल्लभगढ़-वैर रोड से श्री देव बाबा मन्दिर तक की सड़क का चौड़ाईकरण

महोदय,

माननीय अध्यक्ष जी, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया सचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र वैर की ग्राम पंचायत जहाज में स्थित विश्व प्रसिद्ध गुर्जर समाज के आराध्य देव श्री देव महाराजजी के मंदिर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष में कई बार देव बाबा मंदिर पर लक्खी मेला लगता है, जिसमें भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों सहित मध्य प्रदेश एवं देश के तमाम हिस्सों से गुर्जर समाज के लाखों श्रद्धालु आते हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के आने के कारण वल्लभगढ़ से, वैर मार्ग से श्री देव बाबा मंदिर के लिए जाने वाले तकरीबन 10 किलोमीटर मार्ग पर जाम लगा रहता है, जिससे दर्शनार्थियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह मंदिर पूरे भारत के गुर्जर समाज की आस्था का केन्द्र है, किन्तु वल्लभगढ़-वैर रोड से श्री देव बाबा मंदिर को जाने वाले रास्ते के अत्यधिक सकड़ा होने के कारण जाम लगा रहता है। इस मंदिर से गुर्जर समाज की आस्था जुड़ी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदया से निवेदन है कि गुर्जर समाज की आस्था के केन्द्र श्री देव बाबा मंदिर तक जाने वाले लगभग 10 किलोमीटर के मार्ग को 100 फीट तक चौड़ा करवाया जाकर इसमें डिवाइडर लगवाये जाएं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

अंत में मेरा आपके माध्यम से एक बार फिर माननीया मत्री महोदया से निवेदन है कि गुर्जर समाज की आस्था को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब इस मार्ग को 100 फीट चौड़ा कर डिवाइडर लगवाने का श्रम करावें। सादर।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर)

जहाजपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत सरकार से विशेष आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की अग्रलिखित क्षतिग्रस्त सड़कें पिछले पांच वर्षो से क्षतिग्रस्त अवस्था के कारण, इन सड़क मार्गों से सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन दूभर हो गया है। आये दिन इन सड़क मार्गों पर दुर्घटनाएं घटित होने से जानमाल की क्षति हो रही है। अतः प्राथमिकता से निम्नांकित क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनःनिर्माण करवाकर आमजन को राहत देने की कृपा करें-

राजकीय चिकित्सालय देवली से ग्राम कुचलवाड़ा माताजी तक 15 मीटर विस्तारीकरण; सम्पर्क सड़क सरसिया से भुंवार, ग्राम धौड़ से नाडिया एन.एच. 148 डी तक, ग्राम रजवास से दधिमाता गेरूटा बरडा तक सम्पर्क सड़क; सम्पर्क सड़क बीरधोल से सक्तपुरिया के बीच पुलिया की ऊंचाई बढ़ाना, सम्पर्क सड़क छाबड़िया से देवपुरा सड़क, सम्पर्क सड़क खजूरी से गडबोदिया तक, मुख्य सड़क से बिजेठा 1.5 किमी; उदलियास से कोदु कोटा 08 कि.मी.: पारोली अमरापुरा 5 कि.मी: पारोली से माताजी का खेड़ा 01 किमी: लखमणियास से भैरू जी की बनी 3 कि.मीः बिसनिया से नराणा ग्राम तक 3 कि.मी.: आसोप बोरडा के बीच 3 कि.मी.: पारोली से काछोला (असावरी) छापरेल से बेल्वा 3 किमीः सम्पर्क सड़क छापरेल से काटी मोड़ 03 कि.मीः. सम्पर्क सड़क साकड़ा 1.5 कि.मी.; बड़ला से अमरतीया 3 किलोमीटर।

श्री कुलदीप (विराटनगर)

विराटनगर के बांधों का ई.आर.सी.पी. में सम्मिलन

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विराटनगर विधान सभा क्षेत्र के बांधों को ई.आर.सी.पी. में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कर उल्लेख किया जाना है कि विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में अतिप्राचीन छींतोली, बूचारा बांध है। इस क्षेत्र में त्रिवेणी नदी से पानी जवानपुरा धाबाई बांध से होता हुआ छींतोली बांध और बूचारा बांध में आता है। वर्तमान में पानी की आवक के अभाव में ये बांध सूखे पड़े हुए हैं।

उल्लेख किया जाना है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना

(ई.आर.सी.पी.) के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल उपलब्धता और 02 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और पूर्ववर्ती सरकार ने महत्वपूर्ण और जनकल्याणकारी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के बहाने इस पर गंदी राजनीति की और इसे 2051 तक पूरा करने की बात कही थी।

उक्त परियोजना का उद्देश्य मोड़दार संरचनाओं की सहायता से अंतर-बेसिन जल अंतरण चैनलों को जोड़ने तथा मुख्य फीडर चैनलों को जल आपूर्ति हेतु वाटर चैनलों का एक नैटवर्क तैयार करना है, जो राज्य की 41.13 प्रतिशत आबादी के साथ राजस्थान के 23.67 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करेगा।

उक्त क्रम में मेरा राज्य सरकार से विशेष उल्लेख किया जाना है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के अतिप्राचीन छींतोली, बूचारा बांध, जवानपुरा धाभाई बांध और त्रिवेणी नदी को उक्त ई.आर.सी.पी. में सम्मिलित किया जाए जिससे कि विराटनगर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा ग्रामीण इलाकों में भूजल स्तर में सुधार के साथ ही लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का सकारात्मक रूप में परिवर्तन सम्भव हो सकेगा।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर)

ब्यावर की ग्राम पंचायतों के निवासियों से रायल्टी के नाम पर अवैध वसूली

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की कुछ ग्राम पंचायतों (देवाता, सुरडिया, अतीतमण्ड, पाखरियावास) सहित और अन्य पंचायतों में क्षेत्र के गरीब लोग अपने खेतों की खातेदारी भूमि अथवा पड़त भूमि पर से काले पत्थर तोड़ कर उनकी पट्टियां एवं चिनाई पत्थर बनाकर बेचते हैं। इस कार्य से इन गरीब लोगों की आजीविका चलती है तथा अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं। इनकी आजीविका चलाने का एकमात्र यही साधन है। इस कार्य से ये लोग सिर्फ अपनी आजीविका मात्र चला पाते हैं, करोड़ों रुपये नहीं कमाते हैं।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इन गरीब लोगों को खान विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी बेवजह परेशान कर रहे हैं। आये दिन रायल्टी के नाम पर अवैध वसूली करते है। अवैध वसूली नहीं देने पर इनके खिलाफ लाखों रुपयों का चालान कर दिया जाता है। इस कारण ये गरीब लोग मानसिक तनाव में अपनी जिन्दगी जी रहे हैं।

अवैध रायल्टी के खिलाफ मैंने पूर्व में भी सरकार को अवगत कराया कि इस क्षेत्र में कुछ लाख रुपये की रायल्टी के लिए इन गरीब लोगों की रोजी रोटी नहीं छीननी चाहिए। मैंने स्वयं ने भी मौके पर जाकर अवैध रायल्टी बंद कराई है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्षेत्र के गरीब लोगों को पुलिस एवं खान विभाग के अधिकारियों द्वारा परेशान नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाए।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा)

चिकित्सा विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्तियों की प्रदायगी

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में नर्सिंग आफिसर, महिला स्वा. कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्निशियन, रेडियोग्राफर के पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की थी।

बाद में इन पदों में बढ़ोतरी कर नर्सिंग आफिसर, महिला स्वा. कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्निशियन, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, दंत सहायक, ई.सी.जी. टेक्निशियन के लगभग 20,546 पदों पर माह अप्रैल, 2023 में विज्ञप्ति जारी की गई। माह अगस्त व सितम्बर में लगभग डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को पास कर डोक्यूमेन्ट्स वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया। माह अक्टूबर, 2023 में फार्मासिस्ट के पदों को छोड़कर अन्य सभी भर्ती की अंतरिम सूची जारी कर दी गई।

दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 से लेकर आज 4 माह बाद नई सरकार के गठन के बाद भी शेष अभ्यर्थियों के डोक्यूमेन्टस का वेरिफिकेशन एवं अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी नहीं की गई। राज्य सरकार द्वारा डोक्यूमेन्ट्स वेरिफिकेशन का कार्य सीफू एजेन्सी को दिया हुआ है।

दिनांक 18 जनवरी, 2024 से रोजगार की आस लगाएं अभ्यर्थी जयपुर के झालाना क्षेत्र में सीफू एजेन्सी के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। इन अभ्यर्थियों में महिलाएं अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ धरने पर हैं। कड़कड़ाती सर्दी में सरकार द्वारा अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कोरोना महामारी में इन स्वा. कर्मियों ने संविदाकर्मी के रूप में अपनी जान पर खेलकर सेवाएं प्रदान की थीं।

शीघ्र ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की घोषणा होने वाली है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार से मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा कर्मियों की जारी विज्ञप्ति के तहत 20,546 चिकित्सा कर्मियों को अविलम्ब नियुक्ति देकर रोजगार प्रदान करे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन)

मारवाड़ जंक्शन में निर्मित सड़कों में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा मारवाड़-जंक्शन में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न मदों में स्वीकृत सड़कों का विगत 5 वर्षों से जो भी निर्माण कार्य किया गया, वह बहुत ही घटिया किस्म का किया गया है। ग्राम कन्टालिया में गौरव पथ बना हुआ था। उस पर ग्रामीण गौरव पथ और बनाया गया, जबकि वहां पर पहले से ही सीमेंट सड़क बनी हुई थी। इसी तरह इसाली ग्राम से धनला की तरफ जाने वाले रास्ते पर सीमेंट की सड़क बनाई गई, वह बनाते ही टूट गई थी, जिस पर डामर से पेचवर्क किया गया जो बहुत ही घटिया किस्म की है। क्षेत्र में डामर सड़कें बिल्कुल घटिया किस्म की बनाई हैं जो निम्न हैं-

1. सिरयारी से मायली सिरयारी
2. चिपरटीया से बडी तक
3. मारवाड़-जंक्शन से एफ.सी.आई. गोदाम तक
4. रडावास से बेरा रेल तक
5. इूठारिया से जवाली, अधूरी है, मगर गुणवत्ता खराब है।
6. नरसिंहपुरा चौराहे से डिगोर चोराहे तक
7. जैतपुरा चौराहे से जोजावर वाया धनला एस.एच. 61
8. मामावास, खिवाडा घेनडी सावलता मेगा हाईवे तक
9. खारडा से राबडीया अधूरी है, राबड़ीया से बिजोवा तक घटिया निर्माण किया गया है।
10. सिरयारी से बाघोल तक एस.एच. 62

क्रम संख्या 1 से 5 तक निर्माण कार्य घटिया हुए हैं जो बहुत ही कम समय में टूट गये हैं। क्रम संख्या 6 से 10 सभी सड़कें घटिया निर्माण होने की वजह से अभी से ही बड़े-बड़े पेचवर्क किये जा रहे हैं। ये सड़कें लम्बे समय तक नहीं चल पाएंगी।

अतः मैं मांग करता हूं कि उक्त सड़कों की जांच करवाई जाए तथा ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड किया जाए तथा सम्बन्धित ए.ईएन. को सस्पैण्ड कर विभागीय कार्यवाही करने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा)

माही भीखा भाई नहर से पेयजल व सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि बांगड़ क्षेत्र की भीखा भाई नहर क्षेत्र की एक वृहत योजना है, जिस पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की राशि का व्यय किया गया है। इस नहर के अंतिम छोर पर लम्बे समय से कार्य अपूर्ण है और यह नहर बस्तियों एवं गांवों के बीच से होकर गुजरती है। जहां-जहां पाइप लाइन डली हुई है वहां 30 से 40 फुट की गहराई के खड्डे पड़े हुए हैं। विभाग द्वारा पाइप लाइन डालने के बाद समुचित भराव नहीं किया गया है, जिसके कारण विजयपुरा बंजारा बस्ती में आये दिन मवेशियों एवं आमजन की दुर्घटना होने की सम्भावना बनी हुई रहती है। साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत जिन धोरों का निर्माण किया जाना था, वे अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। इस क्षेत्र में भयंकर अकाल की स्थिति है। समुचित वर्षा नहीं होने के कारण मवेशियों एवं आमजन के लिए समुचित पेयजल की व्यवस्था नहीं है। यह स्थानीय किसानों की मांग है कि इस परियोजना के धोरों का निर्माण कर छोटे-छोटे तालाबों में इसका जल उपलब्ध करवाया जाए, जिससे आमजन को राहत मिल सके।

मेरा इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बागड़ क्षेत्र की विस्तृत माही भीखा भाई नहर परियोजना की उपरोक्त समस्याओं का समाधान कर स्थानीय किसानों को एवं जनता को जल उपलब्ध करवाकर समस्या का समाधान करें।

डॉ. शिखा मील बराला (चौमूं)

चौमूं शहर में सुभाष सर्किल, रावण गेट से तेजाजी मन्दिर की मुख्य सड़क के अधूरे कार्य की पूर्णता

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि चौमूं शहर में सुभाष सर्किल रावण गेट से तेजाजी मन्दिर रेनवाल रोड का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आचार संहिता के कुछ महीनों पहले शुरू किया गया था, जो भी काफी धीमी गति से चला। आचार संहिता लगने के साथ ही निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। यह चौमूं के अति व्यस्त मार्गों में से एक है। आधी चौड़ाई सी.सी. सड़क बनने की वजह से दोनों तरफ के लेवल में ऊंचाई का काफी फर्क है। दिन में कितनी ही बार घंटों तक जाम लग जाता है व इमरजेंसी वाहनों को भी रास्ता नहीं मिल पाता। इसी मार्ग पर कुछ विवाह स्थल भी स्थित हैं। शादियों के दिनों में जाम की स्थिति और भी विकट हो जाती है। अधिकारी फण्ड नहीं होने का हवाला देते हैं। जगह-जगह सड़क की खुदाई व संकेतक बोर्ड नहीं होने की वजह से यह एक दुर्घटना क्षेत्र बन चुका है।

अतः मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करती हूं कि उक्त मामले में विशेष संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही करें।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा)

गंगापुर की बंद धागा मिल का पुनः प्रारम्भीकरण

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत उल्लेख किया जाना है कि प्रदेश में भीलवाड़ा जिला कपड़ा उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। प्रमुख उद्योग कपड़ा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर में धागा मिल संचालित थी, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था।

उक्त मिल में 5,000 कार्मिक कार्य करते थे, जिससे क्षेत्र की 30 हजार लोगों की आजीविका चलती थी। क्षेत्र में उक्त मिल को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में रॉ मैटेरियल मिल जाता है, इसलिए रॉ मैटेरियल तैयार करवाने वाले 20 हजार लोगों की आजीविका और जुड़ जाती है। इस प्रकार इस

क्षेत्र में जो धागा मिल बंद कर दी गई है, उससे क्षेत्र के कुल 50 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा था और उनकी आजीविका चल रही थी। ऐसी स्थिति में उक्त धागा मिल को पुनः प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है, जिससे कि क्षेत्रवासियों के लिए रोजगार के सुअवसर मिल सकेंगे।

मेरा इस पवित्र सदन में राज्य सरकार को विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर में बंद पड़ी धागा मिल को पुनः शुरू करवाने के सम्बन्ध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।